सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण कैसे हुआ

सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण कैसे हुआ

पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण विश्व इतिहास में एक सर्वाधिक जटिल युग है। यह संक्रमण सबसे पहले सोवियत जनता ने ही पूरा किया। इसके दौरान उसे कैसी कठिनाइयां झेलनी पड़ीं और कैसी विजयें पायी गयीं, प्रस्तुत पुस्तक इसका वर्णन करती है।

पुस्तक में सोवियत संघ के इतिहास में संक्रमणकालीन दौर – अक्तूबर १६१७ की समाजवादी क्रांति से चौथे दशक के अंत तक, जब देश में समाजवादी समाज मुख्यतया पूरा हो चुका था – की आधारभूत समस्याओं का सुबोध विवरण दिया गया है।

सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण कैसे हुआ

प्रगति प्रकाशन
मास्को

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
५ ई, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-११००५५

अनुवादक : ददन उपाध्याय

लेखकगण :
प्रो० अ० बबायान्त्स – अध्याय ६, ७
प्रो० व० कोन्युखोव्स्की – अध्याय १, २
डा० ग० पोजिदायेव – अध्याय ४, ८
प्रो० अ० उग्र्यूमोव – अध्याय ३, ५
व० फ़िलातोव – भूमिका और उपसंहार
संपादक – प्रो० व० कोन्युखोव्स्की

КАК В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
БЫЛ ПОСТРОЕН СОЦИАЛИЗМ

На языке хинди

SOCIALISM IN THE USSR:
HOW IT WAS BUILT

In Hindi

© Progress Publishers, 1982

© हिन्दी अनुवाद ० प्रगति प्रकाशन ० १९८५

सोवियत संघ में मुद्रित

K $\frac{0505030100-708}{014(01)-85}$ 358-85

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रस्तावना ७

अध्याय १. **रूस में अक्तूबर समाजवादी क्रांति – समाजवाद के युग का आरंभ** ११

१. क्रांति के कारण ११

२. शांतिपूर्ण विकास की परिस्थितियों में बुर्जुआ जनवादी क्रांति के समाजवादी क्रांति में रूपांतरण के लिए संघर्ष (मार्च-जुलाई १९१७) १७

३. बुर्जुआ वर्ग के प्रतिक्रांतिकारी अधिनायकत्व की परिस्थितियों में समाजवादी क्रांति की विजय के लिए संघर्ष ३२

अध्याय २. **क्रांति अपनी रक्षा करने में समर्थ होनी चाहिए** . . ४३

१. अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद – हस्तक्षेप और गृहयुद्ध का संगठनकर्ता ४३

२. देश का एक सैनिक शिविर में रूपांतरण ५०

३. सैनिक क्षेत्र में संगठनात्मक कार्य ६१

अध्याय ३. **आर्थिक स्वतंत्रता का आधार** ७९

१. पहले आर्थिक सुधार ७९

२. समाजवाद का भौतिक और तकनीकी आधार . ८६
३. महती औद्योगिक शक्ति में सोवियत संघ का रूपांतरण ६६
४. समाजवादी औद्योगीकरण की विजय का महत्व . . १२२

अध्याय ४. **सहकारिता का मार्ग – जीवन की समृद्धि का मार्ग** . १२७

१. किसानों का सोवियत सत्ता का समर्थन . . . १२७
२. मेहनतकशों की क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा में किसानों का योगदान . . १३५
३. मज़दूरों और किसानों का सहबंध – समाजवाद के निर्माण का आधार . . १३८

अध्याय ५. **युगों पुराने पिछड़ेपन से संस्कृति की ऊंचाइयों तक** . १५६

१. विचारधारात्मक और सांस्कृतिक क्रांति – पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की नियमसंगत प्रक्रिया . १५६
२. जनगण की साक्षरता और शिक्षा . १६६
३. मेहनतकश जनगण के बुद्धिजीवी . . १७३
४. समाजवाद की सेवा में विज्ञान का उपयोग . १७८
५. समाजवादी साहित्य और कला का प्रस्फुटन . १८२

अध्याय ६. **समाजवादी जनवाद का विकास** १६४

१. समाजवादी राज्य की स्थापना और समाजवाद के निर्माण में उसकी भूमिका . . . १६४
२. समाजवाद के निर्माण के काल में सामाजिक संबंध . . २१८

अध्याय ७. **समाजवाद के निर्माण की अवधि में जातीय संबंध** . . २२६

१. जातियों के बीच मैत्री और बिरादराना सहयोग की नीति २२६
२. जातीय प्रश्न के बारे में लेनिनीय नीति की विजय . . २३६

अध्याय ८. **शांति के लिए संघर्ष – समाजवाद के लिए संघर्ष** . २४६

१. सोवियत राज्य की विदेशनीति का लेनिनीय सिद्धांत . २४६

२. सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण को सुनिश्चित बनाने हेतु सोवियत राज्य के विदेशनीतिक कार्यकलाप . . . २५४

उपसंहार . २७६

प्रस्तावना

हमारे समय में तेज़ी से बदलती दुनिया में अधिकाधिक लोग इस बात पर गंभीरतापूर्वक सोच-विचार करने लगे हैं कि कल, अगले दस-बीस सालों में उनके और उनके बच्चों के लिए कैसा भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है, उनके देशों के जनगण के लिए कैसे संदर्श हैं, कौन-सी चीज़ मानवजाति की प्रतीक्षा कर रही है, जब अत्यंत विनाशकारी हथियारों के विशाल भंडार जमा किये जा चुके हैं, जब प्रदूषण के कुपरिणामों के अलावा ऊर्जा, खनिज संसाधनों और खाद्य-सामग्रियों की कमी तीव्रतापूर्वक महसूस की जा रही है।

ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रमिक के दैनिक जीवन में पेश होते हैं।

ये सवाल विकासमान देशों के जनगण के समक्ष बड़े ही विकट रूप से प्रस्तुत हैं, जिन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और अब अपने पिछड़ेपन – साम्राज्यवादी औपनिवेशिक प्रभुत्व का परिणाम – के उन्मूलन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके बिना विकासमान देशों में तेज़ी से बढ़ती आबादी के लिए खाद्य-सामग्रियों की सप्लाई सुनिश्चित नहीं की जा सकती, निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन नहीं किया जा सकता, आवश्यक डाक्टरी सहायता नहीं प्रदान की जा सकती, व्यक्ति के लिए मानवोचित जीवन-परिस्थितियों के निर्माण की तो बात ही क्या, ताकि वह श्रम कर सके, अपनी योग्यताओं को विकसित कर सके तथा मानव सभ्यता और संस्कृति की संपूर्ण उपलब्धियों का उपयोग कर सके।

हथियारों की होड़, जिसे आक्रामक साम्राज्यवादी शक्तियां हर तरीक़े से प्रोत्साहित कर रही हैं, और विकासमान देशों की क़ीमत

पर आर्थिक, वित्तीय, ऊर्जा, आदि संकटों पर क़ाबू पाने की औद्योगिक रूप से विकसित पूंजीवादी देशों की इच्छा पिछड़ेपन के उन्मूलन की समस्या के समाधान को कठिन बनाती है।

अतः साम्राज्यवाद की विस्तारवादी योजनाओं के ख़िलाफ़ संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों के शोषण से निजात पाना और शांति, सच्ची राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा जनवाद को सुनिश्चित करना विकासमान देशों के लिए पहले की तरह ही मुख्य समस्याएं बने हुए हैं।

विकासमान देश पिछड़ेपन को दूर करने और प्रगति प्राप्त करने के लिए अलग-अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों की भागीदारी से पूंजीवादी आधुनिकीकरण के ज़रिये और दूसरे साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद से अनम्य संघर्ष, विकास के ग़ैर-पूंजीवादी मार्ग के ज़रिये, आर्थिक स्वतंत्रता और समाजवादी रुझान के मार्ग के ज़रिये।

विकास के इस या उस मार्ग का चयन और मूल्यांकन करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मानवजाति को ऐतिहासिक रूप से संक्षिप्त अवधि में पिछड़ेपन का उन्मूलन करने और जीवन तथा कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में श्रमिक जनता के लिए प्रगति सुनिश्चित करने संबंधी समय की कसौटी पर खरी उतरी विधियां उपलब्ध हैं। यह समाजवादी समाज के निर्माण का विज्ञान है, जो सोवियत संघ और दुनिया के विभिन्न देशों के जनगण के श्रम के नतीजों से प्रमाणित हो चुका है। सोवियत संघ ने समाजवादी समाज का निर्माण करते हुए ऐतिहासिक रूप से अल्पतम अवधि में एक विशाल देश में पिछड़ेपन को दूर कर दिया। कुछ सोवियत जातियां – मध्य एशिया, कज़ाखस्तान और देश के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में रहनेवाली जातियां – पूंजीवादी विकास की अवस्था से कतराकर समाजवाद में पहुंच गयी हैं।

अब सोवियत संघ में विकसित समाजवादी समाज का निर्माण हो चुका है, जिसकी मुख्य विशेषताएं उद्योग और कृषि में सबल उत्पादक शक्तियां, जनगण के जीवन का उच्च भौतिक और सांस्कृतिक स्तर, व्यापक नागरिक स्वतंत्रताएं, जातियों की दोस्ती, संपूर्ण समाज की निरंतर प्रगति और समृद्धि हैं। अधिकांश समाजवादी देशों की उपलब्धियों के साथ यह प्रगति समाजवाद की ओर मानवजाति की प्रगति के अविपर्यय स्वरूप का प्रमाण है।

पूंजीवाद के संकटों और मानवजाति के समक्ष प्रस्तुत अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में उसकी असमर्थता की पृष्ठभूमि में समाजवाद की अविवादास्पद उपलब्धियां वास्तविक समाजवाद के अनुभव के प्रति विश्व के प्रगतिशील जनगण की अधिकाधिक दिलचस्पी जगा रही हैं। यह अपनी ओर से साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भयभीत करता है जो देख रही हैं कि कैसे समाजवाद बढ़ और सुदृढ़ हो रहा है, कैसे नये-नये जनगण समाजवाद का मार्ग अपना रहे हैं और साम्राज्यवादी प्रभुत्व का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन संकुचित हो रहा है। अतः बुर्जुआ और सामंती प्रतिक्रियावादी हलक़े अस्तित्वमान समाजवाद को बदनाम करने, समाजवादी विचारों के आकर्षण पर कुठाराघात करने, जनगण को समाजवादी रुझान के मार्ग से विचलित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। सैनिक-औद्योगिक समुच्चय, सूचना-साधनों के शक्तिशाली मालिक, विभिन्न कम्युनिस्ट-विरोधी संगठन और तरह-तरह के प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादी समाजवादी प्रणाली पर मिलकर हमले कर रहे हैं।

अस्तित्वमान समाजवाद को बदनाम करने के प्रयासों में साम्राज्यवादी प्रचार का मुख्य साधन झूठ और समाजवाद के ऐतिहासिक अनुभव को झुठलाया जाना है। कम्युनिस्ट-विरोधी प्रचारकों द्वारा लिखी एक भी पुस्तक या लेख में, उनके द्वारा समाजवाद के बारे में तैयार किये गये एक भी संवाद में समाजवादी देशों में क़ायम स्थिति और घट रही प्रक्रियाओं का सही चित्रण नहीं होता।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के अनुभव से परिचय ही समाजवाद के संबंध में साम्राज्यवादी प्रचार के झूठे दावों को स्पष्टतः देखने की संभावना प्रदान करता है।

इसके साथ ही इस अनुभव से परिचय यह समझने की भी संभावना देता है कि कैसे सोवियत संघ में समाजवादी समाज का वास्तव में निर्माण हुआ और क्यों समाजवाद ही पिछड़ेपन पर क़ाबू पाने और समाज की प्रगति तथा समृद्धि को सुनिश्चित करने का एकमात्र और सबसे छोटा मार्ग है। सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण से परिचय समाजवाद के निर्माण के मूल सिद्धांतों और विधियों, निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों पर क़ाबू पाने के तरीक़ों तथा समाजवाद के व्यावहारिक सिद्धांत "प्रत्येक से उसकी योग्यताओं के

अनुसार, प्रत्येक को उसके श्रम के अनुसार" के कार्यान्वयन से समूचे जनगण और प्रत्येक श्रमिक को लाभों को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता देता है।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के अनुभव से परिचय शांति की रक्षा के लिए विद्यमान समाजवाद के महत्व और साम्राज्यवाद तथा उसकी आक्रामक नीतियों का मुक़ाबला करनेवाली मुख्य शक्ति के रूप में उसकी भूमिका का सही मूल्यांकन करने में सहायता करता है। यह दुनिया में सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रियाओं पर समाजवाद के प्रभाव और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, पिछड़ेपन के उन्मूलन और सामाजिक प्रगति के लिए, सभी शांतिप्रिय, प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियों की एकजुटता के लिए संघर्ष में जनगण के दुर्ग के रूप में उसके महत्व को समझने में सहायता करता है।

प्रस्तुत पुस्तक में पाठक सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के अनुभव से परिचित हो सकता है, यह देख सकता है कि कैसे एक भूतपूर्व पिछड़ा देश एक पीढ़ी के जीवन-काल में ही एक औद्योगिक शक्ति में बदल गया और कैसे इस आधार पर सामाजिक समस्याओं को हल किया जा सका, ऐसा समाज अस्तित्व में आया, जो भौतिक कल्याण के अलावा, सामाजिक तथा जातीय समानता, सच्चे जनवाद, दृढ़ शांति और स्वाधीनता को सुनिश्चित करता है।

अध्याय १

रूस में अक्तूबर समाजवादी क्रांति – समाजवाद के युग का आरंभ

१. क्रांति के कारण

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण की पहली और मुख्य राजनीतिक शर्त थी। यह क्रांति लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शन में रूस के मज़दूरों और किसानों द्वारा अक्तूबर १९१७ में संपन्न हुई। तूफ़ान की भांति वह पूरे देश में फैल गयी, बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकत्व का उन्मूलन करके मज़दूर वर्ग और निर्धनतम कृषक वर्ग की सत्ता क़ायम की तथा सभी श्रमिकों की राजनीतिक, आर्थिक और जातीय समानता की घोषणा की। क्रांति ने सामाजिक विकास में एक नयी ऐतिहासिक अवस्था – पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवस्था – का शुभारंभ किया।

अक्तूबर क्रांति के लगभग सात दशकों के इतिहास का चहुंमुखी अध्ययन किया जाता रहा है। प्रगतिशील कार्यकर्ता, अपने देशों के बेहतर भविष्य के लिए संघर्षरत योद्धाओं की नयी पीढ़ियां शोषकों पर रूस के मज़दूरों और किसानों की विजय के कारणों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अक्तूबर क्रांति के विचार-धारात्मक विरोधी उसके अनुभव का एक भिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। वे रूस में समाजवादी क्रांति के इतिहास द्वारा पूर्वनिर्धारित और नियमसंगत स्वरूप पर विवाद खड़ा करने, उसे एक शुद्ध राष्ट्रीय परिघटना, ऐतिहासिक संयोग मात्र और षड्यंत्रकारी क्रांतिकारियों के एक ग्रुप द्वारा सत्ता पर क़ब्ज़ा करने का परिणाम घोषित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे दावों से वे अक्तूबर क्रांति के विचारों की शक्ति को क्षीण करने और लोगों की क्रांतिकारी चेतना के विकास को

अवरुद्ध करने का इरादा रखते हैं। ऐसे विचारों की ग़लती और निराधारिता सुस्पष्ट हो जाती है अगर उनकी तुलना समाजवादी क्रांति के कारणों तथा क्रांतिपूर्व रूस में विद्यमान परिस्थितियों के वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ की जाये।

समाजवाद द्वारा पूंजीवाद का स्थान ग्रहण करने की नियम-शासित प्रक्रिया

मार्क्स और एंगेल्स ने पूंजीवाद के पतन और उसके समाजवाद द्वारा प्रतिस्थापन की अनिवार्यता को वैज्ञानिक रूप से पुष्ट किया। एक प्रणाली के नाते पूंजीवाद का सांगोपांग अध्ययन करते हुए उन्होंने उसके अनम्य अंतर्विरोधों को प्रकट किया, जो अनिवार्यत: समाजवादी क्रांति की ओर ले जाते हैं। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के संस्थापकों ने समाज का क्रांतिकारी रूपांतरण संपन्न करने में समर्थ शक्ति – सर्वहारा – को भी दिखाया। पूंजीवाद में सबसे उत्पीड़ित वर्ग के रूप में वह दमन और शोषण के पूर्ण उन्मूलन में दिलचस्पी रखता है।

नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों में समाजवादी क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत को विकसित करते हुए लेनिन ने सिद्ध किया कि साम्राज्यवादी अवस्था में पूंजीवाद के अंतर्विरोध और तीव्र बन जाते हैं और सीधे क्रांति के ज़रिये समाजवाद द्वारा उसका प्रतिस्थापन आवश्यक बन जाता है। इस आधार पर लेनिन ने साम्राज्यवाद को समाजवादी क्रांति की पूर्ववेला कहा। नये युग की वास्तविकता का विश्लेषण करते हुए लेनिन ने निष्कर्ष निकाला कि साम्राज्यवाद की परिस्थितियों में, जब अलग-अलग पूंजीवादी देशों का विकास असमान रूप से होता है, समाजवादी क्रांति सभी देशों में एकसाथ विजयी नहीं हो सकती, वह शुरू में कुछ देशों या एक अलग देश तक में विजयी होती है और आवश्यक नहीं कि यह देश, लेनिन के विचार में, सबसे विकसित पूंजीवादी देश हो। समाजवादी क्रांति उस देश में विजयी होती है, जो विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में साम्राज्यवादी ज़ंजीर में अत्यधिक कमज़ोर कड़ी होता है, जहां वर्ग अंतर्विरोध अत्यंत उग्र बन गये होते हैं, जहां मज़दूर वर्ग समूचे श्रमिकों का नेतृत्व करनेवाला

एक सक्रिय वर्ग होता है और जिसके संघर्ष का नेतृत्व जुझारू क्रांतिकारी पार्टी करती है।

१६१७ में रूस ऐसा ही एक देश था। उसके भाग्य में विजयी समाजवादी क्रांति के युग का शुभारंभ करना बदा था।

रूस में समाजवादी क्रांति के वस्तुगत पूर्वाधार

रूस का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास अत्यंत विरोधात्मक था। कृषि-प्रधान देश होते हुए भी रूस ने औद्योगिक विकास का तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था और १६वीं सदी के अंत में अन्य देशों की भांति रूस में पूंजीवाद साम्राज्यवाद में परिवर्तित होने लगा था। इजारेदार संघ उद्योग में प्रभुत्वकारी स्थिति प्राप्त करने लगे थे, जो धातु, तेल, कोयला, रेलवे वैगनों, आदि उत्पादों के उत्पादन और विक्रय के ७५–१०० प्रतिशत का नियंत्रण करते थे। इस प्रकार, छः सबसे बड़ी कंपनियां निजी स्वामित्व में रेल लाइनों के ८० प्रतिशत और १२ बैंक देश की बैंक-परिसंपत्तियों के ८० प्रतिशत का नियंत्रण करते थे। देश की अर्थव्यवस्था की अनेक शाखाओं का नियंत्रण करनेवाले विदेशी पूंजीपतियों की घुसपैठ अधिकाधिक गहरी होती गयी।

देश में मज़दूर वर्ग का गठन हो चुका था। कल-कारखानों, फ़ैक्टरियों और खनन-उद्योग के लगभग ३५ लाख मज़दूर उसका मर्म बनाते थे। लगभग ६० प्रतिशत औद्योगिक मज़दूर बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करते थे। ५० लाख से अधिक मज़दूर परिवहन, संचार, निर्माण और छोटे कुटीर उद्योग में लगे हुए थे। इसके अलावा, ५० लाख से अधिक खेतिहर, मोटिया मज़दूर और दिहाड़ीदार भी थे। इस तरह, नगरों और देहातों में सभी वर्गों के लगभग एक करोड़ ५० लाख सर्वहारा थे।

यह सही है कि रूसी सर्वहारा वर्ग देश की संपूर्ण आबादी का एक नगण्य हिस्सा था, लेकिन, जैसा कि लेनिन ने दिखाया, उसकी शक्ति आबादी में उसके अंश से कहीं बहुत अधिक थी। उसने यह शक्ति सामाजिक उत्पादन में अदा की गयी अपनी भूमिका, अपनी क्रांतिकारिता तथा कुशल संगठन से प्राप्त की।

लेकिन रूस में पंजीवाद के नवीनतम रूपों के साथ-साथ भूदास-

प्रथा और पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था के अवशेष भी विद्यमान थे। मध्य एशिया, कज़ाखस्तान, काकेशिया, साइबेरिया और सुदूर उत्तर की कुछ जातियां अब भी विकास की सामंती अवस्था में ही थीं और उनमें से बहुतों के बीच, जो खानाबदोशी या अर्ध-खानाबदोशी पशु-पालन में लगी हुई थीं, पितृसत्तात्मक और गोत्र संबंध के काफ़ी बड़े अवशेष सुरक्षित थे।

२०वीं सदी के प्रारंभ में रूस में अधिकांश ज़मीन बड़ी जागीरों वाले ज़मींदारों के स्वामित्व में थी। करोड़ों किसान, जो देश की आबादी का ७५ प्रतिशत बनाते थे, भूमिहीनता से पीड़ित थे और निर्मम शोषण के शिकार थे। रूस के तीन हज़ार बड़े ज़मींदारों के पास उतनी ज़मीन (७ करोड़ देस्यातिना*) थी जितनी लगभग एक करोड़ किसानों के पास।

रूस की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए लेनिन ने लिखा: "एक ओर, भूस्वामित्व की अत्यंत पिछड़ी प्रणाली और अत्यंत बर्बर देहात और, दूसरी ओर, अत्यंत विकसित औद्योगिक और वित्तीय पूंजीवाद।"**

सामंती भूदास-प्रथा के अवशेष विकासमान पूंजीवादी देशों से रूस के पिछड़ेपन के मूल कारण थे। वे कृषि और उद्योग में देश की उत्पादक शक्तियों के विकास में मुख्य अवरोध थे। १६१३ में रूस का औद्योगिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन का क्रमशः १२.५ और ७ प्रतिशत, २१.७ और ७ प्रतिशत तथा १६.७ और ७.७ प्रतिशत था।

बुर्जुआ वर्ग द्वारा मज़दूरों और किसानों का निर्मम शोषण निरंकुश तानाशाही सरकार के राजनीतिक उत्पीड़न से और बदतर हो गया। ज़मींदारों की तानाशाही के रूप में ज़ारशाही ने बड़ी पूंजी के हितों की भी रक्षा की, उसे बढ़ते मज़दूर आंदोलन से बचाया और क्रांतिकारी विद्रोहों को बर्बरतापूर्वक दबा दिया। रूस में राजनीतिक सत्ता के

---

* देस्यातिना – भूमि मापने की एक पुरानी रूसी इकाई, जो १.०६ हेक्टर या २.७ एकड़ के बराबर होती थी। – सं०

** व्ला० इ० लेनिन, 'राजनीतिक टिप्पणियां', १६०८।

सारतत्व को स्पष्ट करते हुए लेनिन ने कहा: "निकोलाई द्वितीय के नेतृत्व में मुट्ठीभर अर्ध-सामंती ज़मींदार सत्तारूढ़ थे और वित्तीय पूंजी के उन धन्नासेठों के साथ घनिष्ठ गंठजोड़ बनाये हुए थे, जो यूरोप में अभूतपूर्व मुनाफ़े कमा रहे थे और जिनके लाभ के लिए विदेशों के साथ लुटेरी संधियां की गयीं।"*

इस सबने रूस के आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक संबंधों को असमाधेय विरोधी स्वरूप प्रदान किया। किसी भी देश में वर्ग अंतर्विरोध उतने उग्र और व्यापक नहीं थे, जितने कि रूस में।

जातीय संबंध रूस की अत्यंत जटिल समस्या थे। रूस एक बहु-जातीय राज्य था और रूसी देश की आबादी के आधे से भी कम बनाते थे। वास्तव में, देश में रहनेवाली सभी अन्य जातियां और नृजातीय समूह – देश की आबादी का ५७ प्रतिशत – राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित थे और बर्बर जातीय तथा धार्मिक उत्पीड़न के शिकार थे। स्थानीय और रूसी पूंजीपति तथा ज़मींदार रूस के सीमांत उपनिवेशी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों का दुहरा शोषण करते थे। उत्पीड़ित जातियों के छोटे से छोटे जन-विद्रोह को भी ज़ारशाही तुरंत दबा देती थी। जातीय उत्पीड़न ने रूस में सामाजिक विरोधों को और उग्र तथा जनवादी और क्रांतिकारी संघर्ष के मोर्चे को व्यापक बनाया।

रूस में समाजवादी क्रांति के ऐसे ही वस्तुगत सामाजिक-आर्थिक पूर्वाधार थे।

सामाजिक क्रांति के आत्मगत पूर्वाधार

इस समय तक समाजवादी क्रांति की विजय के लिए अनुकूल विभिन्न आत्मगत पूर्वाधार भी बन गये थे।

पहला, क्रांति का नेतृत्व करनेवाले रूसी सर्वहारा वर्ग की संगठन-बद्धता, चेतना और दृढ़ता का उच्च स्तर, जो शोषण और उत्पीड़न के सभी रूपों के ख़िलाफ़ संघर्ष में किसानों और खेतिहर मज़दूरों की अगुआई करने में समर्थ था। उसने वर्ग संघर्ष की अग्नि-परीक्षाएं पास की थीं और रूसी जनता तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग की शानदार परंपराओं को साकार किया था।

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'वर्ग स्थानांतरण', १९१७।

दूसरा, मज़दूर वर्ग और सभी मेहनतकश लोगों को समाजवादी क्रांति की विजय की ओर ले जानेवाली एक नये प्रकार की पार्टी—बोल्शेविक पार्टी थी, जिसने सर्वहारा वर्ग के ईमानदार, चिंतनशील, साहसी और आत्मत्यागपूर्ण गुणों को आत्मसात् किया तथा रूसी क्रांतिकारियों की पीढ़ियों द्वारा क़ायम भव्य परंपराओं को बढ़ाया। उसने मज़दूर वर्ग को जनवादी और समाजवादी क्रांति के वैज्ञानिक कार्यक्रम से लैस किया और उसे ज़मींदारों तथा पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष के लिए उठ खड़ा होने के लिए राजनीतिक रूप से संगठित किया।

तीसरा, सच्चे क्रांतिकारी और मेधावी विचारक व्लादीमिर इल्यीच लेनिन पार्टी और महान क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। वह पार्टी और व्यापक जन समुदाय के क्रांतिकारी संघर्ष के वैचारिक नेता और संगठनकर्ता थे।

चौथा, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच लेनिनीय स्कूल के सच्चे और साहसी क्रांतिकारियों की उपस्थिति। ये क्रांतिकारी असाधारण संगठनकर्ता और प्रचारक थे, जो जनता के बीच काम करते थे और उसे वीरतापूर्ण क्रांतिकारी संघर्ष के लिए प्रेरित करते थे।

इस प्रकार, रूस में समाजवादी क्रांति के वस्तुगत और आत्मगत पूर्वाधारों का विश्लेषण उसके सांयोगिक और संकीर्ण राष्ट्रीय स्वरूप के बारे में दावों का पूर्णतः खंडन कर देता है। क्रांतिकारी विस्फोट के लिए आर्थिक, राजनीतिक और जातीय कारण पर्याप्त से अधिक थे। लेकिन ये कारण शुद्धतः रूसी स्वरूप के नहीं थे, उन्होंने संपूर्ण विश्व पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्विरोधों और टकरावों को प्रतिबिंबित किया। रूस में वे केवल अत्यधिक उग्र तथा अनम्य रूप में प्रकट हुए। वह मार्ग, जिसने रूस को क्रांति की ओर लाया, संपूर्ण विश्व इतिहास का मार्ग था और अतः उसकी विजय समूचे विश्व के क्रांतिकारी रूपांतरण का समारंभ थी।

पहले विश्वयुद्ध* में रूस की भागीदारी ने उसके सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अंतर्विरोधों को अत्यंत उग्र बना दिया। युद्ध ने देश के संपूर्ण आर्थिक जीवन को नष्ट कर दिया। उसके औद्योगिक

---

* पहला विश्वयुद्ध १ अगस्त, १९१४ को विश्व और प्रभाव-क्षेत्रों के पुनर्विभाजन के लिए साम्राज्यवादी राज्यों के दो विरोधी

उत्पादन, परिवहन और वित्त में ज़बर्दस्त गिरावट आयी। मज़दूरों और किसानों की भौतिक स्थिति बद से बदतर बन गयी। लेनिन ने लिखा: "युद्ध ने ऐसा अपरिमित संकट पैदा कर दिया है, जनता की भौतिक तथा नैतिक शक्तियों को इतना खींच कस दिया है, पूरे आधुनिक सामाजिक संगठन पर ऐसे प्रहार किये हैं कि मानवजाति को अपने सामने दो विकल्पों में से एक को चुनना होगा: या तो मर जाना या फिर उत्पादन की अधिक श्रेष्ठ विधि में द्रुततम तथा सर्वाधिक आमूल-गामी संक्रमण के लिए अपने भाग्य की बागडोर सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग को सौंपना।"*

इसने जनता की क्रांतिकारी शक्तियों के ज़बर्दस्त विद्रोह को भड़काया। मज़दूरों और सैनिकों ने, जो ज़्यादातर किसान ही थे, बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में फ़रवरी १९१७ में घृणित, रक्तपातपूर्ण निरंकुश सरकार का तख़्ता उलट दिया। उन्होंने अपनी पहल पर मज़दूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें – क्रांतिकारी सत्ता के अवयव – क़ायम कीं। रूस एक जनवादी देश बन गया।

२. शांतिपूर्ण विकास की परिस्थितियों में बुर्जुआ जनवादी क्रांति के समाजवादी क्रांति में रूपांतरण के लिए संघर्ष (मार्च-जुलाई १९१७)

फ़रवरी क्रांति की विजय के बाद देश में स्थिति

फ़रवरी १९१७ में बुर्जुआ जनवादी क्रांति के बाद देश में अत्यंत विरल ऐतिहासिक स्थिति क़ायम हो गयी। उसकी मुख्य विशेषता

गुटों के बीच हुआ था। एक गुट में जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी और दूसरे गुट में इंगलैंड, फ़्रांस और रूस थे। आगे चलकर युद्ध में दूसरे देश भी शामिल हो गये। – सं०

* व्ला० इ० लेनिन, 'आसन्न विपदा और उसका मुक़ाबला कैसे किया जाये', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ७, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८४, पृ० २१२।

यह थी कि तख्ता उलट दी गयी निरंकुश सरकार के स्थान पर दो सत्ताएं, दो अधिनायकत्व प्रकट हुए: अस्थायी सरकार के रूप में बुर्जुआ वर्ग और बुर्जुआ बन गये ज़मींदारों का विशाल अधिनायकत्व तथा सर्वहारा वर्ग और किसानों के क्रांतिकारी-जनवादी अधिनायकत्व का अवयव – मज़दूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें।

इस ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व परिघटना का वर्गगत कारण यह था कि फ़रवरी क्रांति ने न केवल राजतंत्र का तख्ता उलटकर सत्ता बुर्जुआ वर्ग को हस्तांतरित कर दी, बल्कि वह आगे भी गयी और सोवियतों के रूप में सर्वहारा वर्ग और किसानों के क्रांतिकारी-जनवादी अधिनायकत्व की स्थापना की।

फ़रवरी क्रांति की विजय के बाद बनी ऐतिहासिक स्थिति की दूसरी विशेषता यह थी कि पेत्रोग्राद सोवियत ने, जिसका नेतृत्व तब टुटपुंजिया वर्ग की समझौतेपरस्त पार्टियों के प्रतिनिधि – मेंशेविक तथा समाजवादी-क्रांतिकारी – कर रहे थे, स्वेच्छापूर्वक सत्ता बुर्जुआ अस्थायी सरकार को सौंप दी। सोवियतें सशस्त्र मज़दूरों और किसानों सहित अधिकांश जनता पर भरोसा करते हुए हथियारों का सहारा लिये बिना ही सत्ता पूरी तरह अपने हाथों में संकेंद्रित कर सकती थीं। पर उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनके समाजवादी-क्रांतिकारी और मेंशेविक नेता यह मानते थे कि चूंकि रूस में बुर्जुआ-जनवादी क्रांति विजयी हुई है, इसलिए सत्ता बुर्जुआ वर्ग के हाथों में ही होनी चाहिए। सोवियतों ने २ मार्च, १९१७ को बनी अस्थायी सरकार के कार्यकलाप पर महज़ नियंत्रण करने का अधिकार बनाये रखा।

फ़रवरी क्रांति की विजय के बाद यह विशिष्ट ऐतिहासिक स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई कि रूस की आबादी में टुटपुंजिया संस्तरों की प्रधानता थी। ज़ारशाही के भयंकर दमन द्वारा राजनीतिक अधिकारों से वंचित करोड़ों-करोड़ लोग जाग्रत होकर राजनीतिक रूप से सक्रिय बन गये। "एक विराट टुटपुंजिया लहर ने," लेनिन ने लिखा, "सब कुछ को अपनी लपेट में ले लिया है, तादाद में ही नहीं, अपितु विचार-धारा में भी सर्वहारा वर्ग को अपने वश में कर लिया है, यानी मज़दूरों की अत्यंत व्यापक मंडलियों को टुटपुंजिया राजनीतिक दृष्टिकोण से संदूषित कर दिया, उससे जकड़ दिया।"* यह स्थिति कुछ हद तक इस

---

* वही, खंड ६, पृ० ३५१।

वजह से पैदा हुई थी कि साम्राज्यवादी युद्ध के दौरान मज़दूर वर्ग की संरचना गुणात्मक रूप से बदल गयी थी, जब वर्गचेतन औद्योगिक मज़दूरों को सेना में बुला लिया गया था और कल-कारख़ानों तथा फ़ैक्टरियों में उनका स्थान मध्यम और टुटपुंजिया वर्गों के अधिक लोगों ने ले लिया था। इस सबने सोवियतों के गठन पर अनिवार्यतः प्रभाव डाला जिसके परिणामस्वरूप उनमें मेंशेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों को प्रधानता प्राप्त हो गयी।

चूंकि बुर्जुआ अस्थायी सरकार को सोवियतों का समर्थन प्राप्त था, मेहनतकश लोगों ने शुरू में उसमें विश्वास किया। उन्होंने आशा की कि सरकार क्रांति के कार्यों को पूरा करेगी, यानी वह घृणित युद्ध को समाप्त करेगी, किसानों को ज़मीन देगी, आठ घंटे का कार्य-दिवस लागू करेगी, जातीय उत्पीड़न का उन्मूलन करेगी तथा आर्थिक तबाही, भूख और ग़रीबी दूर करेगी।

लेकिन अस्थायी सरकार ने जनता की आशाओं पर पानी फेर दिया। उसकी घरेलू नीति जन-विरोधी स्वरूप की थी और बुर्जुआ वर्ग की स्थितियों को मज़बूत बनाने की ओर लक्षित थी। उसने ज़ारशाही नौकरशाही राजकीय कार्ययंत्र को लगभग ज्यों का त्यों बनाये रखा। हालांकि राजतंत्र का तख़्ता उलट दिया गया था, अस्थायी सरकार ने रूस को जनतंत्र घोषित नहीं किया। क्रांतिकारी अवाम के दबाव का अनुभव करते हुए बुर्जुआ वर्ग ने टालमटोल का रास्ता अपनाया और कोरे आश्वासन देने में कोई कंजूसी नहीं की। लेकिन वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बिगड़ती गयी, खाद्य-संकट तेज़ हो गया और क़ीमतों में अंधाधुंध वृद्धि जारी रही।

विदेशनीति में अस्थायी सरकार ने निरंकुश ज़ारशाही द्वारा अपने मित्रराष्ट्रों – ब्रिटेन और फ़्रांस के साम्राज्यवादियों – को दिये गये सैनिक वचनों के प्रति वफ़ादारी की पुष्टि की। जारी युद्ध ने विशाल भौतिक साधनों की मांग की, देश की अर्थव्यवस्था को और भी तहस-नहस कर दिया और विदेशी पूंजी पर रूस की निर्भरता को बढ़ा दिया।

अस्थायी सरकार की घरेलू और विदेशनीतियां रूस के अधिकांश मेहनतकशों के हितों से तनिक भी मेल नहीं खाती थीं। उन्होंने देश के ऐतिहासिक भाग्य, उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए बड़ा ख़तरा पेश कर दिया। इस नीति का एकमात्र विकल्प था बुर्जुआ-जनवादी

क्रांति से समाजवादी क्रांति में संक्रमण। बुर्जुआ शासन का उन्मूलन और मज़दूरों तथा ग़रीब किसानों द्वारा सरकार की स्थापना ही देश को उस गतिरोध से निकाल सकते थे, जिसमें वह शोषक वर्गों के कुकृत्य से आ फंसा था।

रूस के राजनीतिक मंच पर क्रियाशील सभी जनवादी और क्रांतिकारी पार्टियों में से केवल बोल्शेविक पार्टी ही आसन्न राष्ट्रीय विनाश से देश को बचाने के लिए जन संघर्ष का नेतृत्व करने में समर्थ थी। बुर्जुआ वर्ग से समझौतापरस्ती का मार्ग अपनानेवाले मेंशेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी जनता का विश्वास दिन-प्रतिदिन खोते जा रहे थे। बोल्शेविकों ने १९१७ में ऐतिहासिक पहल की शानदार मिसाल पेश की। वे लेनिन के मार्गदर्शन में बुर्जुआ-जनवादी क्रांति को समाजवादी क्रांति में रूपांतरित करने लगे।

लेनिन की 'अप्रैल थीसिसें'

फ़रवरी क्रांति की ख़बर लेनिन को स्विट्ज़रलैंड में मिली, जहां वह उत्प्रवास में रह रहे थे। 'दूर देश से पत्र' में लेनिन ने क्रांतिकारी घटनाओं का गहन विश्लेषण दिया और नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों में सर्वहारा वर्ग के कार्यभार निर्धारित किये। लेनिन यथासंभव शीघ्र रूस लौटना चाहते थे। २७ मार्च को वह स्विट्ज़रलैंड से रवाना हो गये और ३ अप्रैल को रात को ११ बजकर १० मिनट पर पेत्रोग्राद पहुंचे। उनके आगमन की ख़बर सारे नगर में पहले ही फैल गयी थी। मज़दूर, सैनिक और नौसैनिक उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। रेलवे स्टेशन के आसपास के चौक और सड़कें स्वदेश लौटनेवाले अपने नेता का स्वागत करने आये पेत्रोग्राद के मेहनतकशों से भर गयी थीं। पेत्रोग्राद के मज़दूरों, सैनिकों और नाविकों के समक्ष अपने पहले भाषण में लेनिन ने उनके क्रांतिकारी पराक्रम का हार्दिक स्वागत किया और उनका समाजवादी क्रांति संपन्न करने का आह्वान किया।

पेत्रोग्राद पहुंचने के दूसरे दिन ही लेनिन ने 'वर्तमान क्रांति में सर्वहारा वर्ग के कार्यभार' रिपोर्ट पेश की। ७ अप्रैल को उनकी रिपोर्ट की थीसिसें समाचारपत्र 'प्राव्दा' में प्रकाशित हुईं, जो आगे चलकर

'अप्रैल थीसिसें' के नाम से सुप्रसिद्ध हुईं। इन 'थीसिसों' का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि उनमें लेनिन ने बुर्जुआ-जनवादी क्रांति को समाजवादी क्रांति में विकसित करने की ठोस योजना पेश की।

इस पूर्वाधार से आगे बढ़ते हुए कि किसी भी क्रांति का मूल प्रश्न सत्ता का प्रश्न है, लेनिन ने दिखाया कि चूंकि ज़ार और ज़मींदारों का तख़्ता उलट दिये जाने के बाद सत्ता बुर्जुआ वर्ग के हाथ में आ गयी थी, इसलिए बुर्जुआ-जनवादी क्रांति पूरी हो गयी है। चुनांचे 'अप्रैल थीसिसों' ने समाजवादी क्रांति में संक्रमण का एक नया रणनीतिक कार्यभार पेश किया। उनमें कहा गया: "रूस में मौजूदा घड़ी की विलक्षणता यह है कि देश क्रांति की पहली मंज़िल से, जिसने सर्वहारा वर्ग की अपर्याप्त वर्ग-चेतना तथा उसके अपर्याप्त संगठन के कारण सत्ता बुर्जुआ वर्ग को सौंप दी थी, **दूसरी मंज़िल में संक्रमण** कर रहा है, जिसे सत्ता सर्वहारा वर्ग तथा किसानों की सबसे ग़रीब श्रेणियों के हाथों में सौंपनी होगी।"*

लेनिन ने क्रांति के महान ध्येय – सत्ता पर क़ब्ज़ा करना – को सुस्पष्ट और सहज ढंग से सूत्रित किया ताकि अवाम उसे समझ सकें। पेरिस कम्यून के सबक़ों तथा रूस में क्रांतिकारी मज़दूर आंदोलन के अनुभव के आधार पर लेनिन ने निष्कर्ष निकाला कि सोवियतों का जनतंत्र रूस में मेहनतकशों की राज्य-सत्ता का सबसे उपयुक्त रूप है। उन्होंने घोषणा की: "संसदीय जनतंत्र नहीं – मज़दूर प्रतिनिधि सोवियत से संसदीय जनतंत्र की ओर लौटना पीछे की ओर पग होगा – अपितु पूरे देश में, नीचे से ऊपर तक मज़दूर, खेत-मज़दूर, किसान प्रतिनिधि सोवियतों का जनतंत्र।"**

जनता की पहल पर क़ायम की गयी सोवियतें समाजवादी क्रांति के लिए निर्णायक महत्व रखती थीं। आगे चलकर लेनिन ने लिखा कि "यदि क्रांतिकारी वर्गों की सृजनात्मक प्रेरणा ने सोवियतों को न पैदा किया होता, तो रूस में सर्वहारा क्रांति का हेतु एक आशाहीन हेतु बन जाता"।***

---

* वही, पृ० ३१५।

** वही, पृ० ३१६।

*** वही, खंड ७, पृ० २६४।

'अप्रैल थीसिसों' ने समाजवादी क्रांति की प्रेरक शक्तियों और उनके विन्यास का सांगोपांग विश्लेषण दिया। मज़दूर वर्ग समाजवादी क्रांति का एकच्छत्र नेता बना रहता है, जिसे आबादी के नगरीय और ग्रामीण अर्ध-सर्वहारा संस्तरों की अगुआई करनी चाहिए।

निरंकुश तानाशाही के पतन के बाद देश के राजनीतिक जीवन पर मज़दूर वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया। उसने उच्च संगठनबद्धता और क्रांतिकारिता प्रदर्शित की तथा किसानों और उत्पीड़ित ग़ैर-रूसी जातियों के मेहनतकशों के व्यापक संस्तरों से सुदृढ़ संपर्क रखे हुए था।

लेनिन 'अप्रैल थीसिसों' में समाजवादी क्रांति में सर्वहारा वर्ग के मित्रों के बारे में प्रश्न को नये ढंग से हल करते हैं। अगर बुर्जुआ-जनवादी क्रांति की अवस्था में संपूर्ण कृषक वर्ग सर्वहारा वर्ग का मित्र होता है, तो समाजवादी क्रांति में संक्रमण के दौरान वर्ग शक्तियों का पुनर्समूहन होता है। अब सबसे ग़रीब किसान, जो १९१७ में कृषक आबादी का ६५ प्रतिशत और देश की आबादी के आधे से अधिक थे, सर्वहारा वर्ग के मित्र बन जाते हैं। समाजवादी क्रांति के लिए संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के दूसरे मित्र उत्पीड़ित ग़ैर-रूसी जातियों के मेहनतकश, मुख्यतः किसान थे। बोल्शेविकों की नीति सभी जातियों के शोषकों के ख़िलाफ़ मज़दूर वर्ग, ग़रीब किसानों और उत्पीड़ित जातियों के संघर्ष को एकजुट करने की ओर लक्षित थी।

क्रांति और प्रतिक्रांति के दो ध्रुवों के बीच मध्यम संस्तर था, जो मध्यम किसानों और शहरी टुटपुंजिया वर्ग से बना था। अपने वर्ग-स्वरूप के अनुसार ये संस्तर द्वैधता, राजनीतिक ढुलमुलपन के लिए विशिष्ट थे और बुर्जुआ वर्ग से समझौते की ओर प्रवृत्त थे। फ़रवरी क्रांति के दौरान इन संस्तरों की राजनीतिक सक्रियता तथा ग़रीब किसानों और वर्ग-अचेतन मज़दूरों पर उनका प्रभाव बढ़ गया। मेंशेविक पार्टी और समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी ने इन वर्ग शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया।

इन पार्टियों की नीति, बुर्जुआ वर्ग से उनके समझौते का पर्दाफ़ाश करते हुए बोल्शेविकों ने मध्यम किसानों और शहरी मध्यम संस्तरों पर अपने प्रभाव के लिए संघर्ष किया। समाजवादी क्रांति की अवस्था में बोल्शेविकों ने इन सामाजिक संस्तरों के प्रति तटस्थता की नीति

चलायी, जिसका उद्देश्य उन्हें क्रांति से विमुख करना नहीं, बल्कि बुर्जुआ वर्ग और समझौतेपरस्त पार्टियों से उन्हें पृथक करके व्यापक रूप से अपने पक्ष में लाना था।

लेनिन की 'अप्रैल थीसिसों' में जारी साम्राज्यवादी युद्ध से निकलने के प्रश्न के प्रति बोल्शेविक पार्टी के रुख की सुस्पष्ट रूप से व्याख्या की गयी। ज़ारशाही के पतन के बाद यह रूस के लिए सबसे ज्वलंत प्रश्न था और वह समाजवादी क्रांति की विजय के लिए संघर्ष में मुख्य प्रश्न बन गया। जनता ने पूंजीपतियों और ज़मींदारों के हितों में लड़े जानेवाले तीनवर्षीय रक्तपातपूर्ण युद्ध से थककर उसे तुरंत बंद करने की मांग की। यह संयोग की बात नहीं है कि लेनिन की 'अप्रैल थीसिसें' युद्ध के प्रति बोल्शेविकों के रुख के विश्लेषण से आरंभ होती हैं।

शीघ्रातिशीघ्र शांति कैसे प्राप्त करें, इसका लेनिन ने स्पष्ट उत्तर दिया। साम्राज्यवादी युद्ध को समाप्त करने के लिए बुर्जुआ वर्ग की सत्ता का अंत करना आवश्यक था। मज़दूर और ग़रीब किसान, जो दूसरी जातियों की लूट-खसोट में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, सत्तारूढ़ होकर जनवादी और न्यायसंगत शांति संपन्न कर सकते हैं।

'अप्रैल थीसिसों' में राजनीतिक कार्यभारों के अलावा एक सुस्पष्ट आर्थिक कार्यक्रम भी शामिल था जो जनसाधारण के हितों के अनुरूप और उनके लिए बोधगम्य था। इस कार्यक्रम में देश में ज़मींदारों की सभी भूसंपत्तियों की ज़ब्ती तथा सभी ज़मीनों के राष्ट्रीयकरण, सभी बैंकों के एक राष्ट्रीय बैंक में विलय, आठ घंटे का कार्य-दिवस लागू करने, उत्पादन और उत्पादों के वितरण पर मज़दूरों के नियंत्रण की स्थापना की मांगें शामिल थीं। आर्थिक क्षेत्र में ये सभी क्रांतिकारी क़दम समाजवाद के समारंभ का द्योतक नहीं थे, लेकिन वे देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना में गहन परिवर्तन लाने, पूंजीवाद के आधारों को कमज़ोर बनाने और समाजवाद में संक्रमण के लिए परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाने की ओर ले जाते।

समाजवादी क्रांति लाने की नीति का सफल कार्यान्वयन बहुत हद तक पार्टी की विचारधारात्मक, राजनीतिक और संगठनात्मक एकता और मेहनतकश जनसाधारण का नेतृत्व करने की क्षमता पर निर्भर करता था। यही कारण है कि 'अप्रैल थीसिसों' में लेनिन ने पार्टी

की आंतरिक संरचना में सुधार के लिए विभिन्न कार्यभार पेश किये। उन्होंने नया कार्यक्रम और नियमावली स्वीकृत करने तथा पार्टी का नाम सामाजिक-जनवादी पार्टी से बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी* रखने के लिए पार्टी कांग्रेस बुलाने का प्रस्ताव किया।

'अप्रैल थीसिसों' में लेनिन ने समाजवादी क्रांति की विजय के लिए संघर्ष की ऐसी ही योजना पेश की थी। इसके साथ ही उनमें इस योजना को अमल में लाने के मार्ग निर्धारित किये गये थे, रूस में विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप क्रांति के अत्यंत उपयुक्त रूप और विधियां पेश की गयी थीं।

१९१७ के वसंत में क्रांति के विकास के दौरान मज़दूर वर्ग और ग़रीब किसानों को सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की इतिहास में अत्यंत विरल, लेकिन अत्यंत अनुकूल संभावना प्रकट हुई। बोल्शेविकों के कार्यनीतिक नारे "सारी सत्ता सोवियतों को!" का कार्यान्वयन बुर्जुआ वर्ग की सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण, सत्ता के पुराने कार्ययंत्र के उन्मूलन और उसके स्थान पर सोवियतों के सच्चे जनवादी कार्ययंत्र की स्थापना की ओर ले जाता था। परंतु यह अब भी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व नहीं होता, क्योंकि अधिकांश सोवियतें समझौते-परस्त समाजवादी-क्रांतिकारी और मेंशेविक पार्टियों के नियंत्रण में थीं।

तब समाजवादी क्रांति की विजय के लिए संघर्ष सोवियतों के

---

* १८९८ में पहली कांग्रेस से सातवीं कांग्रेस (१९१८) तक पार्टी का आधिकारिक नाम रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी था। प्राग में हुए छठे पार्टी सम्मेलन के बाद, जिसने पार्टी शक्तियों की एकता को सूत्रबद्ध किया और पार्टी को अवसरवादी अंशकों से मुक्त कर दिया था, "बोल्शेविक" शब्द उसके नाम में जोड़ दिया गया – रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी (बो०)। सातवीं कांग्रेस (१९१८) में पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) रखा गया। १४वीं कांग्रेस (१९२५) में पार्टी को नया नाम – अखिल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) दिया गया और १९वीं कांग्रेस (१९५२) में उसे वर्तमान नाम – सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी दिया गया। – सं०

अंदर फैल गया। बुर्जुआ वर्ग की नीतियों से जुड़े मेंशेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी मेहनतकशों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे, जिससे उनके समक्ष उनका असली चेहरा प्रकट हो जाता। दूसरी ओर, मेहनतकशों की आवश्यकताओं और आशाओं से मेल खानेवाली बोल्शेविकों की नीतियों को उनका अधिकाधिक विश्वास और समर्थन मिलता। सोवियतों की जनवादी चुनाव प्रणाली और प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का उपयोग करते हुए मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों के समूह सोवियतों में समझौतेपरस्त, उनके विश्वास की कसौटी पर खरे न उतरनेवाले प्रतिनिधियों के स्थान पर बोल्शेविकों को भेजते, जो उनकी मांगों को वास्तव में पूरा करने में समर्थ थे। इस प्रकार, सोवियतों में बहुमत प्राप्त करके बोल्शेविक पार्टी उनकी नीति को बदल देती और उन्हें सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में परिवर्तित करती। ऐसे क्रांति की पहली अवस्था से दूसरी अवस्था – बुर्जुआ-जनवादी क्रांति से समाजवादी क्रांति में अग्रगति की प्रक्रिया – में शांतिपूर्ण संक्रमण पूरा होता।

समाजवादी क्रांति की विजय के लिए संघर्ष की लेनिन की रणनीतिक और कार्यनीतिक योजना समाजवादी क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण क़दम थी। वह एक ऐसा विचारधारात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम था, जिसके आधार पर समाजवादी क्रांति की विजय के लिए संघर्ष फैल गया।

बुर्जुआ-जनवादी क्रांति को समाजवादी क्रांति में बदलने की बोल्शेविक पार्टी की नीति का बुर्जुआ और समझौतापरस्त पार्टियों ने द्वेषपूर्वक विरोध किया। समाजवादी-क्रांतिकारियों और मेंशेविक पार्टियों के नेताओं ने दावा किया कि रूस अभी समाजवादी क्रांति के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके सर्वहारा वर्ग की संख्या थोड़ी है, किसान आबादी का अधिकांश बनाते हैं तथा समाजवाद में संक्रमण के लिए आवश्यक सांस्कृतिक पूर्वाधार अभी नहीं बने हैं।

बोल्शेविक पार्टी के भीतर ही कामेनेव, रीकोव, प्याताकोव और उनके समर्थकों के एक छोटे गुट ने दक्षिणपंथी-अवसरवादी स्थिति अपनाते हुए 'अप्रैल थीसिसों' का विरोध किया। उनका दावा था कि रूस समाजवादी क्रांति के लिए अभी परिपक्व नहीं हुआ है। पर पार्टी में कुछ ऐसे वामपंथी तत्व भी थे, जिन्होंने अस्थायी सरकार का

तुरंत तख़्ता उलटने की मांग की। यह ग़लत मांग थी, क्योंकि इसका अर्थ विद्रोह के लिए आह्वान था, जो क्रांति के शांतिपूर्ण विकास की पार्टी की नीति के प्रतिकूल था।

अप्रैल के अंत में पेत्रोग्राद में हुए बोल्शेविक पार्टी के सातवें अखिल रूसी सम्मेलन ने खुली बहस के बाद बुर्जुआ-जनवादी क्रांति के समाजवादी क्रांति में संक्रमण की लेनिनीय योजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

समाजवादी क्रांति के झंडे के नीचे जनसाधारण को एकजुट करना

अप्रैल सम्मेलन के बाद पार्टी की केंद्रीय समिति और बोल्शेविक अख़बारों ने संगठन और प्रचार कार्य आरंभ कर दिया, ताकि पार्टी के सदस्यों और उनके ज़रिये आम मज़दूरों, सैनिकों, नाविकों और मेहनतकश किसानों को सम्मेलन के प्रस्ताव समझाये जा सकें।

पार्टी के सभी संगठनों में सम्मेलन के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। उनका सर्वत्र पूर्ण समर्थन तथा अनुमोदन किया गया। संपूर्ण पार्टी लेनिनीय कार्यक्रम के मंच पर एकजुट हो गयी और उसकी पांतों में मज़दूरों, सैनिकों और नौसैनिकों के सचेत प्रतिनिधि शामिल होते गये।

बोल्शेविक पार्टी और उसके नेता लेनिन ने जनसाधारण में अथक काम किया और उन्हें अपने झंडे के नीचे एकजुट किया। 'प्राव्दा' और अन्य बोल्शेविक अख़बारों में लेनिन के लेख तथा भाषण प्रकाशित किये गये। कांग्रेसों, सम्मेलनों और सभाओं में अपने भाषणों में लेनिन ने मेहनतकशों को युद्ध समाप्त करने, उनकी जीवंत मांगों को पूरा करने के मार्ग को बड़े ही स्पष्ट और विश्वासप्रद ढंग से दिखाया। अप्रैल से जुलाई १९१७ तक लेनिन ने १७० से अधिक लेख और दस्तावेज़ लिखे, जो 'प्राव्दा' के ज़रिये व्यापक जनसाधारण को उपलब्ध होते थे।

पार्टी ने क्रांति के अधिनायक, निर्णायक शक्ति के रूप में मज़दूर वर्ग की राजनीतिक शिक्षा और संगठन में अपना मुख्य प्रयास लगाया।

मज़दूर वर्ग के सहारे पार्टी ने सभी मेहनतकश और शोषित जनसाधारण को अपने पक्ष में करने के लिए संघर्ष चलाया।

सोवियतों के अंदर, जो मेहनतकश लोगों का सबसे व्यापक संगठन थीं, जनसाधारण पर प्रभाव के लिए संघर्ष लेनिन के नारे "सारी सत्ता सोवियतों को!" के तहत चलाया गया। मई–जून १९१७ तक बहुत-से नगरों में सोवियतें सच्ची क्रांतिकारी सत्ता के अवयव बन गयी थीं।

कारख़ाना और फ़ैक्टरी समितियों में कार्य जनसाधारण को अपने पक्ष में लाने के लिए संघर्ष की दूसरी महत्वपूर्ण दिशा थी। ये समितियां जनसाधारण के क्रांतिकारी उत्थान की प्रक्रिया में बनीं तथा मज़दूरों के एकीकरण का नया रूप थीं। उनका आविर्भाव रूसी सर्वहारा वर्ग की प्रखर राजनीतिक जागरूकता और संगठनबद्धता का ज्वलंत प्रमाण है। कारख़ाना और फ़ैक्टरी समितियां निर्वाचित अवयव थीं, जो पेशों का ख़्याल किये बिना दत्त औद्योगिक प्रतिष्ठान के मज़दूरों को एकजुट करती थीं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष चलाना था, जिन्होंने भुखमरी, मज़दूरों की बर्ख़ास्तगी और तालाबंदी के ज़रिये क्रांति का गला घोंट देने की कोशिश की। कारख़ाना और फ़ैक्टरी समितियों ने प्रतिष्ठानों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, मज़दूरों की भर्ती और बर्ख़ास्तगी, कच्चे मालों की सप्लाई, उत्पादों के निर्माण और विक्रय तथा प्रतिष्ठानों की रक्षा का संचालन किया।

जनसाधारण को अपने पक्ष में करने के लिए संघर्ष करते हुए बोल्शेविकों ने ट्रेड-यूनियनों का समर्थन पाने और मज़दूर वर्ग की पांतों की एकता को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिये। फ़रवरी क्रांति की विजय के बाद ट्रेड-यूनियन आंदोलन का विकास बड़ी तेज़ी से हुआ। मेंशेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों ने ट्रेड-यूनियनों की स्थापना के पहले महीनों में बहुत-सी ट्रेड-यूनियनों पर, ख़ास तौर से छोटे प्रतिष्ठानों में ट्रेड-यूनियनों पर क़ब्ज़ा कर लिया था। समाजवादी क्रांति की विरोधी इन पार्टियों ने ट्रेड-यूनियनों पर "तटस्थता" का विचार थोपने की कोशिश की, ताकि उन्हें क्रांतिकारी संघर्ष में सक्रिय भाग लेने से रोका जा सके। ट्रेड-यूनियन आंदोलन के भीतर समझौतेपरस्त तत्वों ने ऐसी संगठनात्मक संरचना की हिमायत की, जो मज़दूर वर्ग की पांतों के बिखराव की ओर ले गयी। औद्योगिक

प्रतिष्ठानों में सभी मज़दूरों को एकजुट करनेवाली कारख़ाना और फ़ैक्टरी समितियों के विपरीत ट्रेड-यूनियनें व्यावसायिक आधार पर क़ायम की गयीं। परिणाम यह हुआ कि एक ही कारख़ाने या फ़ैक्टरी में कई ट्रेड-यूनियनें क़ायम हो गयीं।

बोल्शेविकों ने ट्रेड-यूनियनों को मेंशेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए, उनके बिखराव पर क़ाबू पाने के लिए, उन्हें सक्रिय राजनीतिक और क्रांतिकारी संघर्ष में खींचने के लिए अनम्य और सिद्धांतनिष्ठ संघर्ष शुरू किया।

बोल्शेविक पार्टी ने सर्वहारा वर्ग की सशस्त्र सेना के निर्माण के लिए कारख़ाना और फ़ैक्टरी समितियों तथा ट्रेड-यूनियनों के प्रयासों का व्यापक प्रयोग किया। १९०५ की क्रांति के अनुभव का सहारा लेते हुए बोल्शेविक पार्टी जुझारू दस्तों, मज़दूर मिलिशिया और लाल रक्षकों की सेना का गठन करने लगी। यह शांतिपूर्ण साधनों से क्रांति का विकास करने की नीति के प्रतिकूल नहीं था, क्योंकि उसका कार्यान्वयन प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों का विरोध करने, क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा करने की सर्वहारा वर्ग की क्षमता पर निर्भर करता था।

अपने झंडे के नीचे क्रांतिकारी जनसाधारण को एकजुट करते हुए बोल्शेविकों ने मज़दूरिनों जैसी सर्वहारा वर्ग की बहुसंख्यक पांतों पर बड़ा ध्यान दिया। पार्टी संगठनों ने मज़दूरिनों को सक्रिय राजनीतिक संघर्ष में, सोवियतों, ट्रेड-यूनियनों और कारख़ाना और फ़ैक्टरी समितियों के कार्यकलाप में खींचने के लिए उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षित किया तथा अधिक वर्ग-सचेत मज़दूरिनों को भर्ती किया।

बोल्शेविकों ने युवा मज़दूरों पर अपने प्रभाव के लिए समझौतेपरस्त पार्टियों के साथ दृढ़तापूर्वक और अनम्यतापूर्वक संघर्ष चलाया। उन्होंने युवा मज़दूर संघ क़ायम करने में सहयोग किया, मज़दूर वर्ग की युवा पीढ़ी को अपनी राजनीतिक चेतना बढ़ाने और क्रांतिकारी योद्धाओं की पहली पांतों में होने में सहायता की।

समाजवादी क्रांति की नीति को अमल में लाते हुए बोल्शेविक पार्टी ने मेहनतकश किसानों और उत्पीड़ित ग़ैर-रूसी जातियों के व्यापक हिस्सों को अपने पक्ष में करने के लिए संघर्ष तेज़ कर दिया। केवल बोल्शेविकों के पास ही भूमि संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए एक सुसंगत क्रांतिकारी कार्यक्रम था। उन्होंने समाजवादी-क्रांतिकारियों और

मेंशेविकों का पर्दाफ़ाश किया, जिन्होंने किसानों द्वारा ज़मींदारों की ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करने का विरोध किया और संविधान सभा के बुलाये जाने तक भूमि संबंधी प्रश्न को स्थगित करने का प्रस्ताव किया। लेकिन बोल्शेविक पार्टी ने ज़मींदारों की ज़मीनों पर तुरंत क़ब्ज़ा करने की किसानों की इच्छा का समर्थन किया। किसानों को संबोधित करते हुए लेनिन ने कहा: **"अगर आप क़ानून के लिखे जाने तक इंतज़ार करेंगे और स्वयं क्रांतिकारी पहल विकसित नहीं करेंगे, तो आपके पास न क़ानून होगा, न ही ज़मीन।"** *

बोल्शेविक पार्टी ने ज़मीन के लिए किसानों के जनवादी संघर्ष को समाजवादी क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग के संघर्ष से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि मज़दूर वर्ग और गांव के ग़रीबों का ऐसा सुदृढ़ सहबंध क़ायम किया जा सके, जो क्रांति संपन्न करने में समर्थ हो। 'किसान प्रतिनिधियों की अखिल रूसी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के नाम खुली चिट्ठी' में लेनिन ने लिखा: "जब तक ऐसा सहबंध नहीं बन जाता, पूंजीपतियों को पराजित नहीं किया जा सकता। और अगर वे पराजित नहीं किये जाते, तो जनता के हाथों में ज़मीन का कोई भी हस्तांतरण उसे ग़रीबी से नहीं मुक्त करा सकेगा।" **

जनसाधारण को भूमि संबंधी प्रश्न पर पार्टी की नीति समझाने के लिए बोल्शेविक प्रचारक, वर्ग-सचेत मज़दूर, क्रांतिकारी सैनिक और नाविक भेजे गये। उन्होंने ज़मींदारों और बुर्जुआ वर्ग के ख़िलाफ़ संघर्ष में किसानों को एकजुट करने में सहायता की। धीरे-धीरे मेहनतकश किसान बोल्शेविकों के विचारों की सचाई समझने लगे।

ज़ारशाही के पतन ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में प्रचंड उत्थान ला दिया। अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार उत्पीड़ित ग़ैर-रूसी जातियां मुख्यतः किसान थीं। इसलिए जातीय और भूमि संबंधी प्रश्न एक दूसरे से सघन रूप से गुंथे हुए थे। उनके सही समाधान पर ही

---

* व्ला० इ० लेनिन, **रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी (बो०) का सातवां (अप्रैल) अखिल रूसी सम्मेलन**, २४-२६ अप्रैल (७-१२ मई), १६१७।

** व्ला० इ० लेनिन, 'किसान प्रतिनिधियों की अखिल रूसी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के नाम खुली चिट्ठी', ७ (२०) मई, १६१७।

रूसी और देश के जातीय इलाक़ों के करोड़ों ग़रीब किसानों के बीच सुदृढ़ सहबंध की संभावना निर्भर करती थी।

बोल्शेविक पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जिसके पास भूमि संबंधी प्रश्न पर भी और जातीय प्रश्न पर भी जुझारू, क्रांतिकारी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी कार्यक्रम था। बोल्शेविकों ने खुले रूप से घोषणा की कि केवल समाजवादी क्रांति ही उत्पीड़ित जातियों को जातीय उत्पीड़न से मुक्ति दिलायेगी। उन्होंने पृथक होने तक जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की अनम्यतापूर्वक और सुसंगत ढंग से हिमायत की। लेनिन के शब्दों में इसका अर्थ यह है कि "महान रूसी न पोलैंड, न कुरलैंड, न उक्राइना, न फ़िनलैंड, न आर्मेनिया, न ही किसी और जाति को ज़बर्दस्ती दबाये रखेंगे। महान रूसी सभी जातियों के साथ बिरादराना सहबंध और प्रत्येक जाति की स्वैच्छिक सहमति से और किसी भी हालत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव से नहीं एक साझे राज्य की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं।"* बोल्शेविकों ने महाशक्तिवादी अंधराष्ट्रवाद के ख़िलाफ़, बुर्जुआ और टुटपुंजिया राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ तथा सभी मेहनतकशों की अंतर्राष्ट्रीयतावादी एकता के लिए अनम्य संघर्ष चलाया।

बोल्शेविकों ने सेना और नौसेना में बड़े ही सक्रिय ढंग से काम किया, जिनमें सैनिकों की संख्या लगभग एक करोड़ थी। सैनिक टुकड़ियों और यूनिटों में पार्टी संगठनों द्वारा चलाये गये प्रचार-कार्य का एक ही उद्देश्य था—सेना को क्रांति के पक्ष में लाना। बोल्शेविकों द्वारा मोर्चे पर सैनिकों के लिए प्रकाशित अख़बारों 'ओकोप्नाया प्राव्दा' और 'सोल्दात्स्काया प्राव्दा' ने सैनिकों तथा नाविकों की क्रांतिकारी मनोदशा को व्यक्त किया। लेनिन अक्सर सैनिकों की सभाओं में भाषण देते थे।

लेनिन की 'अप्रैल थीसिसों' को अमली जामा पहनाने के लिए बोल्शेविक पार्टी के संघर्ष की ये ही मुख्य दिशाएं थीं।

क्रांति के ख़िलाफ़ संघर्ष में बुर्जुआ वर्ग ने सर्वहारा वर्ग और उसकी पार्टी को अपना मुख्य शत्रु माना तथा उनके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा दी। प्रतिक्रांति अपने को अधिकाधिक संगठित और एकजुट कर

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'फ़ैक्टरियों और रेजिमेंटों में चुनी गयी सोवियत के प्रतिनिधियों को समादेश', मई १९१७।

रही थी तथा अपने रिज़र्वों को जमा करके क्रांतिकारी शक्तियों पर निर्णायक प्रहार करने की तैयारी कर रही थी।

अस्थायी सरकार ने जारी साम्राज्यवादी युद्ध से जनसाधारण के व्यापक असंतोष की उपेक्षा करते हुए १८ जून, १९१७ को मोर्चे पर आक्रमण कर दिया। यह सैनिक और राजनीतिक दोनों ही उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। अगर आक्रमण सफल हो जाता, तो वह उसका उपयोग अपनी जन-विरोधी नीति को और भी बड़े पैमाने पर जारी रखने के लिए करती, लेकिन अगर वह असफल हो जाता, तो सरकार सेना के विघटन के लिए बोल्शेविकों को दोषी ठहराते हुए सारी ज़िम्मेदारी उनके मत्थे मढ़ देती और उनके ख़िलाफ़ दमनकारी अभियान शुरू कर देती।

ख़राब ढंग से तैयार आक्रमण असफल रहा, ६० हज़ार सैनिक या तो मारे गये या घायल हुए। अस्थायी सरकार की नीतियों से क्रुद्ध क्रांतिकारी जनसाधारण ने सत्ता सोवियतों को हस्तांतरित करने की मांग की। यह स्वतःस्फूर्त जन क्रांतिकारी उत्थान था, जिसका अराजकतावादी तत्व सशस्त्र विद्रोह भड़का करके लाभ उठाना चाहते थे, जिसके लिए परिस्थितियां अभी परिपक्व नहीं हुई थीं।

बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति, पेत्रोग्राद समिति और स्थानीय पार्टी संगठनों ने जनसाधारण को समझाने-बुझाने का बड़ा कार्य चलाया ताकि बुर्जुआ वर्ग और उसके गुर्गों को मज़दूरों, सैनिकों और नौसैनिकों को असमय सशस्त्र विद्रोह के लिए भड़काने न दिया जाये। वे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आयोजन के बारे में निर्णय की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल हुए।

४ जुलाई, १९१७ को पेत्रोग्राद में पांच लाख लोगों का विशाल प्रदर्शन आरंभ हुआ। सारे नगर में मज़दूरों, सैनिकों और नौसैनिकों के सुव्यवस्थित जुलूस निकले। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और बच्चे भी थे और यह प्रदर्शन के शांतिपूर्ण स्वरूप को और भी उजागर कर देता था। लेकिन युद्ध समाप्त करने तथा सत्ता सोवियतों को हस्तांतरित करने की मांग करनेवाले प्रदर्शनकारियों पर अस्थायी सरकार की सैनिक टुकड़ियों ने गोलियों की वर्षा की। इसके साथ ही बोल्शेविकों, क्रांतिकारी मज़दूरों, सैनिकों और नौसैनिकों के ख़िलाफ़ आतंकवादी कार्रवाइयां आरंभ हो गयीं। 'प्राव्दा' के संपादकीय कार्यालय पर भीषण

हमला किया गया। बुर्जुआ वर्ग, समाजवादी-क्रांतिकारियों और मेंशेविकों के अखबारों ने बोल्शेविक पार्टी तथा उसके नेता लेनिन के विरुद्ध निंदा अभियान तेज़ कर दिया।

बुर्जुआ वर्ग ने अपना नक़ाब उतार फेंका और क्रांतिकारी जनसाधारण के विरुद्ध गृहयुद्ध शुरू कर दिया। समझौतेपरस्त पार्टियों ने इन कार्रवाइयों का अनुमोदन किया और प्रतिक्रांति के शिविर में शामिल हो गयीं। शांतिपूर्ण साधनों से क्रांति विकसित करने की संभावना नहीं रही। अब मेहनतकश लोग केवल हथियारों के बल से ही सत्ता पर क़ब्ज़ा कर सकते थे।

३. बुर्जुआ वर्ग के प्रतिक्रांतिकारी अधिनायकत्व की परिस्थितियों में समाजवादी क्रांति की विजय के लिए संघर्ष

सशस्त्र संघर्ष का मार्ग

४ जुलाई, १९१७ को मेहनतकशों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली वर्षा के बाद रूस में क्रांति के विकास में तेज़ी से मोड़ आया।

लेनिन ने जुलाई के बाद की अवधि में देश में बनी राजनीतिक स्थिति का गहन विश्लेषण किया और पार्टी की नयी कार्यनीति तैयार करने की आवश्यकता प्रदर्शित की। इस अवधि की मुख्य विशेषता यह थी कि प्रतिक्रांतिकारी बुर्जुआ वर्ग ने पूर्ण राज्य-सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और इस तरह देश में दोहरी सत्ता का अंत हो गया था। मेंशेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी क्रांति के ध्येय के प्रति ग़द्दारी करके प्रतिक्रांति के शिविर में लुढ़क गये थे, जबकि उनके द्वारा नेतृत्व की जानेवाली सोवियतें बुर्जुआ अस्थायी सरकार का असहाय पुच्छल्ला बनकर रह गयी थीं।

इन परिस्थितियों में रणनीतिक कार्यभारों के समाधान के लिए संघर्ष के दूसरे रूपों की आवश्यकता थी। लेनिन ने पार्टी को नयी कार्यनीतिक लाइन से सज्जित किया, जिसका सारतत्व निम्नलिखित था:

पहला, चूंकि अब शांतिपूर्ण साधनों से सत्ता पाना असंभव था, लेनिन ने फ़रवरी क्रांति के बाद पहली बार सशस्त्र विद्रोह की तैयारी

करने का अत्यावश्यक कार्यभार पेश किया। उन्होंने लिखा: "रूसी क्रांति के शांतिपूर्ण विकास की सभी आशाएं सदा के लिए समाप्त हो गयी हैं। वस्तुगत स्थिति यह है: या तो सैनिक अधिनायकत्व की पूर्ण विजय या मज़दूरों के सशस्त्र विद्रोह की विजय..."*

सशस्त्र विद्रोह का नारा पेश करते हुए लेनिन ने समयपूर्व विद्रोह के ख़िलाफ़ चेताया। उन्होंने बारंबार कहा कि बुर्जुआ वर्ग के ख़िलाफ़ निर्णायक धावा तभी संभव होगा जब जनसाधारण के व्यापक हिस्से नये क्रांतिकारी उत्थान में शामिल हों।

दूसरा, लेनिन ने दोहरी सत्ता की परिस्थितियों में पेश किये गये "सारी सत्ता सोवियतों को!" नारे को अस्थायी रूप से स्थगित करने का प्रस्ताव किया। इसका यह अर्थ नहीं था कि पार्टी ने नये प्रकार के राज्य के राजनीतिक रूप के तौर पर सोवियत जनतंत्र के लिए संघर्ष से, सामान्यत: सोवियतों से मुंह मोड़ लिया था। इस प्रसंग में चर्चा थी समाजवादी-क्रांतिकारियों और मेंशेविकों द्वारा नियंत्रित सोवियतों की। लेनिन को पूर्ण विश्वास था कि सोवियतें बुर्जुआ वर्ग से समझौते करने-वाली संस्थाओं से उसके ख़िलाफ़ क्रांतिकारी संघर्ष करनेवाली संस्थाओं में बदल जायेंगी।

तीसरा, लेनिन ने जनसाधारण के बीच पार्टी कार्य के रूपों और विधियों को बदलने की आवश्यकता दिखायी। नयी परिस्थितियों में पार्टी ने क्रांतिकारी कार्य में क़ानूनी और ग़ैर-क़ानूनी विधियों के जांचे-परखे समन्वय का उपयोग किया। यह, एक ओर, पार्टी और उसके नेताओं की सुरक्षा के लिए और, दूसरी ओर, क्रांतिकारी शक्तियां जुटाने के लिए आवश्यक था।

लेनिन द्वारा तैयार की गयी कार्यनीतिक लाइन को १९१७ की जुलाई के अंत और अगस्त के शुरू में हुई रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी (बो०) की छठी कांग्रेस ने पुष्ट किया। लेनिन पेत्रोग्राद के बाहर भूमिगत थे, वह कांग्रेस में उपस्थित नहीं हो सके, पर उन्होंने उसके कार्य को निदेशित किया। बोल्शेविक पार्टी ने जनसाधारण में राजनीतिक प्रचार नये उत्साह से चलाना शुरू कर दिया और उन्हें

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'राजनीतिक परिस्थिति', जुलाई १९१७।

प्रतिक्रांतिकारी बुर्जुआ वर्ग का तख़्ता सशस्त्र ढंग से उलटने के लिए तैयार किया।

न ही प्रतिक्रांतिकारी शक्तियां निष्क्रिय थीं। उन्होंने हथियारों के बल से क्रांति को कुचल देने के लिए देश में खुल्लमखुल्ला सैनिक अधिनायकत्व क़ायम करने का निर्णय किया। सभी क्रांतियों का अनुभव दिखाता है कि बुर्जुआ वर्ग इसका तब अंतिम सहारा लेता है जब उसके सामने उसके ऐतिहासिक पटाक्षेप का खतरा प्रस्तुत हो जाता है। राजतंत्र के कट्टर समर्थकों ने जनरल कोर्नीलोव को प्रतिक्रांति का नेता चुना। २५ अगस्त, १९१७ को उन्होंने ब्रिटेन, अमरीका और फ़्रांस की साम्राज्यवादी सरकारों की सहायता के आश्वासन पर भरोसा करते हुए सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सर्वहारा वर्ग के हरावल दस्ते – बोल्शेविक पार्टी – को कुचलना, बोल्शेविक नेताओं की हत्या करना, सोवियतों को भंग करना, क्रांतिकारी सैनिक टुकड़ियों को निरस्त्र करना और उन्हें पेत्रोग्राद से हटाना तथा फ़ौजी अधिनायकत्व क़ायम करना।

बोल्शेविक पार्टी ने क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा संगठित की। उसने श्रमिक जनसाधारण का प्रतिक्रांति का मुंहतोड़ जवाब देने और संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा क़ायम करने का आह्वान किया। वह मज़दूरों, सैनिकों और किसानों तथा टुटपुंजिया पार्टियों के आम सदस्यों को भी एकजुट करने में सफल हुई। विद्रोह को कुचल दिया गया और क्रांतिकारी जनसाधारण ने एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की।

कोर्नीलोव से संघर्ष ने मज़दूरों और किसानों को समझौतेपरस्त भ्रमों से मुक्त होने तथा जनसाधारण की क्रांतिकारी पहल को सक्रिय बनाने में सहायता की।

प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह को दबाने के बाद बोल्शेविकों ने समूचे देश में सर्वहारा जन संगठनों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। बोल्शेविकों का नारा "सारी सत्ता सोवियतों को!" पुनः जनसाधारण की क्रांतिकारी लामबंदी का नारा बन गया। परंतु अब इसका आशय अस्थायी सरकार का तख़्ता सशस्त्र ढंग से उलटने और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व क़ायम करने से था।

रूसी क्रांति अपने विकास के एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गयी थी। राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी संकट तेज़ी से बढ़ रहा था। बोल्शेविक नारों

के तहत चलनेवाला मज़दूर आंदोलन दिन-प्रतिदिन व्यापक बनता जा रहा था। अगस्त से अक्तूबर १९१७ तक की अवधि में २० लाख से अधिक मज़दूरों ने राजनीतिक हड़तालों में हिस्सा लिया और ज़मींदारों के ख़िलाफ़ किसानों का युद्ध फैल गया। ग़रीब किसान मज़दूर वर्ग के साथ संयुक्त मोर्चे में एकजुट हो गये और यह इस बात का वस्तुगत प्रमाण था कि वे बोल्शेविकों के पक्ष में आ गये थे।

सैनिकों में भी बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था। अक्तूबर १९१७ तक सेना में बोल्शेविकों का प्रभाव ऐसा हो गया था कि उसने निर्णायक क्षण में और निर्णायक स्थान पर शक्तियों की प्रहारक श्रेष्ठता को सुनिश्चित किया।

देश के दूर-दराज़ के क्षेत्रों में मुक्ति संघर्ष व्यापक बनता गया। उत्पीड़ित जातियों का आंदोलन रूसी सर्वहारा वर्ग के संघर्ष के साथ-साथ चल रहा था।

टुटपुंजिया समझौतेपरस्त पार्टियों के संकट और विघटन ने देश में आम राजनीतिक संकट को प्रतिबिंबित किया। मेंशेविक पार्टी मज़दूरों में अपना प्रभाव वस्तुतः खो चुकी थी। समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी भी क्रांतिकारी घटनाओं के दबाव में बिखर रही थी। मज़दूर और किसान उसकी पांतों को छोड़ रहे थे और वह विभिन्न धाराओं में बंट गयी थी। इस पार्टी के वामपक्ष ने एक नयी राजनीतिक पार्टी – वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी – बनायी।

मुख्य बुर्जुआ पार्टी – सांविधानिक-जनवादी पार्टी ("कैडेटों") – का प्रभाव तेज़ी से घट रहा था। "कैडेट" शब्द का अर्थ करोड़ों-करोड़ मेहनतकशों के लिए "क्रांति का शत्रु" था।

अस्थायी सरकार ने मेहनतकशों की उन मुख्य मांगों में से एक को भी पूरा नहीं किया, जिनको लेकर उन्होंने ज़ारशाही पर धावा बोला था। १९१७ की शरत् तक देश की आर्थिक स्थिति भयंकर रूप से बदतर हो गयी थी। पेत्रोग्राद, मास्को और अन्य नगरों को रोटी की सप्लाई दिन-प्रतिदिन कम होती गयी। देश के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति, प्रति दिन रोटी राशन घटकर २०० ग्राम हो गया। देश वित्तीय दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया था। प्रतिकूल शर्तों पर लिये गये विदेशी ऋणों को और भी कटुतापूर्वक महसूस किया जा रहा था।

स्वयं जीवन ने उचित ही मज़दूरों, ग़रीब किसानों और उत्पीड़ित

जातियों के आंदोलन को शांति और ज़मीन के लिए, सामाजिक और जातीय मुक्ति के लिए संघर्ष से मिला दिया। समाजवादी क्रांति का सामाजिक आधार अद्‌भुत रूप से विस्तृत हो गया था।

बोल्शेविक पार्टी का बढ़ता प्रभाव और प्रतिष्ठा जनसाधारण के जुझारू क्रांतिकारी कार्यकलाप की ज्वलंत अभिव्यक्ति थी। प्रतिक्रिया के अंधकारमय वर्षों में बोल्शेविक ग़ैर-क़ानूनी मार्क्सवादी पार्टी को सुरक्षित रखने में सफल रहे। ज़ारशाही के पतन के बाद क़ानूनी मान्यता पाकर बोल्शेविक पार्टी ने जनसाधारण में अपने कार्य को व्यापक बनाया, अपने संगठनों का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण किया तथा जुझारू जन पार्टी बन गयी। उसकी पांतों में तपे-तपाये, वर्ग-सचेत मज़दूर शामिल हुए। छठी कांग्रेस के बाद ही पार्टी की सदस्य-संख्या में एक लाख की वृद्धि हुई। अक्तूबर १६१७ तक उसकी सदस्य-संख्या ३ लाख ५० हज़ार हो गयी थी, जिसका ६० प्रतिशत मज़दूर थे।

१६१७ की शरत्‌ तक क्रांति के विकास का मुख्य राजनीतिक परिणाम यह था कि मेहनतकश जनसाधारण का समाजवादी-क्रांतिकारी और मेंशेविक पार्टियों की नीति से मोह भंग हो चुका था, वे उन्हें छोड़कर बोल्शेविक पार्टी के पक्ष में आ गये। बोल्शेविक पार्टी देश में मुख्य राजनीतिक पार्टी बन गयी थी। घटनाओं में परिवर्तन का सामान्यीकरण करते हुए लेनिन ने निष्कर्ष निकाला: "संकट परिपक्व हो चुका है"।*

बोल्शेविक पार्टी सशस्त्र विद्रोह के लिए व्यावहारिक तैयारियां करने लगी।

अक्तूबर सशस्त्र विद्रोह की विजय

१६१७ की शरत्‌ में सर्वहारा वर्ग और ग़रीब किसानों द्वारा चलाया जा रहा वर्ग संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष – सशस्त्र विद्रोह – पर पहुंच गया। "इतिहास ने," लेनिन ने लिखा, "**सैनिक** प्रश्न को अब मूल **राजनीतिक** प्रश्न बना दिया है।"** अतः पार्टी के सभी कार्यकलाप सशस्त्र विद्रोह

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'संकट परिपक्व हो चुका है', १६१७।

** व्ला० इ० लेनिन, 'फ़िनलैंड की सेना, नौसेना और मज़दूरों की प्रादेशिक समिति के अध्यक्ष इ० त० स्मिल्गो को पत्र', २७ सितम्बर, १६१७।

की तैयारी की ओर लक्षित थे। इस कार्य की मुख्य दिशा थी संपूर्ण पार्टी, सभी क्रांतिकारी शक्तियों को सशस्त्र विद्रोह के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत समझाना। इस कार्यभार को पार्टी ने बहुत बढ़िया ढंग से पूरा किया। इस कार्य में लेनिन ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया, जिन्होंने इस प्रश्न पर मार्क्स और एंगेल्स के दृष्टिकोणों की रक्षा की, उनका आगे विकास और पूर्ववर्ती सशस्त्र क्रांतिकारी विद्रोहों के अनुभवों का सामान्यीकरण किया।

पार्टी की केंद्रीय समिति ने सशस्त्र विद्रोह के संचालन के लिए नेतृत्वकारी संस्थाओं की एक कारगर और सुव्यवस्थित प्रणाली क़ायम की। ये संस्थाएं थीं: लेनिन की अध्यक्षता में राजनीतिक ब्यूरो, सैनिक-क्रांतिकारी केंद्र तथा मज़दूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्रोग्राद सोवियत की क्रांतिकारी-सैनिक समिति। बोल्शेविक पार्टी समितियों ने पूरे देश में विद्रोह के संचालन के लिए सैनिक-क्रांतिकारी संस्थाएं क़ायम कीं।

लेनिन ने पेत्रोग्राद में सशस्त्र विद्रोह की ब्यौरेवार योजना तैयार की, जिसके संघटक अंग निम्नलिखित थे:

१. नगर के अंदर और बाहर से, मज़दूर मुहल्लों से पेत्रोग्राद पर एकसाथ, यथासंभव अचानक और तीव्र आक्रमण।

२. तीन मुख्य शक्तियों – नौसैनिक बेड़े, मज़दूरों तथा फ़ौजी इकाइयों – को इस तरह मिलाना ज़रूरी है कि क) टेलीफ़ोन एक्सचेंज, ख) तारघर, ग) रेलवे स्टेशनों, घ) सर्वोपरि पुलों पर अपरिहार्य रूप से क़ब्ज़ा कर लिया जाये तथा उन्हें हर क़ीमत पर अपने पास रखा जाये।

३. सबसे संकल्पशील तत्वों (हमारी "तूफ़ानी" शक्तियों तथा नौजवान मज़दूरों, साथ ही सबसे अच्छे नौसैनिकों) को सब महत्वपूर्ण स्थानों पर क़ब्ज़ा करने के लिए और सारी महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए छोटे-छोटे दस्तों में संगठित करना ज़रूरी है।

४. शत्रु के प्रतिरोध "केंद्रों" (जंकर स्कूलों, टेलीफ़ोन, तारघर, आदि) पर "सभी मर मिटेंगे, पर शत्रु को नहीं गुज़रने देंगे" के नारे के साथ आक्रमण करने और उनकी घेरेबंदी करने के लिए सर्वोत्तम मज़दूरों के दस्तों का गठन करना, उन्हें सशस्त्र करना।

लेनिन और बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति ने मास्को, उराल,

दोन्बास और देश के अन्य बड़े औद्योगिक केंद्रों में पार्टी संगठनों तथा मोर्चे पर सैनिक टुकड़ियों में बोल्शेविक संगठनों के लिए ठोस सैनिक-राजनीतिक कार्यभार तैयार किये।

१० अक्तूबर को रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी (बो०) की ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें जुलाई घटनाओं के बाद लेनिन ने पहली बार भाग लिया। विद्यमान स्थिति पर उनकी रिपोर्ट पर बहस करने के बाद एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया: "सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है और उसके लिए परिस्थिति बिल्कुल परिपक्व है... केंद्रीय समिति सभी पार्टी संगठनों को आदेश देती है कि वे इसी के अनुसार अपना मार्ग निर्धारित करें और सभी व्यावहारिक प्रश्नों के बारे में विचार तथा निर्णय इसी दृष्टिकोण से करें..."*

१६ अक्तूबर को केंद्रीय समिति की विस्तृत बैठक हुई, जिसमें पेत्रोग्राद समिति, सैनिक संगठन, पेत्रोग्राद सोवियत के बोल्शेविक ग्रुप तथा कारख़ाना और फ़ैक्टरी मज़दूर समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक ने १० अक्तूबर को पास किये गये प्रस्ताव की पुष्टि की और सभी मज़दूरों तथा सैनिकों का विद्रोह की चहुंमुखी तैयारी करने के लिए आह्वान किया। केंद्रीय समिति और सोवियत अनुकूल घड़ी और समुचित कार्य-पद्धतियों का बाक़ायदा निदर्शन करेगी।** लेनिन की लाइन के विरोध में ज़िनोव्येव और कामेनेव*** ने दावा किया

---

* व्ला० इ० लेनिन, रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी (बो०) की केंद्रीय समिति की बैठक, १० (२३) अक्तूबर, १९१७।

** व्ला० इ० लेनिन, रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी (बो०) की केंद्रीय समिति की बैठक, १६ (२९) अक्तूबर, १९१७।

*** ग० ये० ज़िनोव्येव (रादोमीस्ल्स्की) (१८८३-१९३६)– १९०१ से रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी के सदस्य, १९०७ से पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य। महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की तैयारी के दौरान ढुलमुल रहे, सशस्त्र विद्रोह का विरोध किया। अक्तूबर १९१७ में अर्ध-मेंशेविक अख़बार 'नोवाया जीज़्न' ('नया जीवन') में सशस्त्र विद्रोह संबंधी केंद्रीय समिति के प्रस्ताव के प्रति असहमति के बारे में कामेनेव के साथ वक्तव्य प्रकाशित कराया। यह गोपनीय प्रस्ताव का भंडाफोड़ तथा क्रांति के प्रति ग़द्दारी था।

कि रूस में सशस्त्र विद्रोह के लिए परिस्थितियों का अस्तित्व नहीं है, कि वह समयपूर्व होगा और अतः पराजित होकर रहेगा।

पार्टी की केंद्रीय समिति ने इस अवसरवादी और पराजयवादी लाइन को दृढ़तापूर्वक ठुकरा दिया। केंद्रीय समिति की बैठक में असफल होने के बाद ज़िनोव्येव और कामेनेव ने सीधी ग़द्दारी का रास्ता अपनाया। १८ अक्तूबर को उन्होंने अर्ध-मेंशेविक अख़बार 'नोवाया जीज़्न' में एक पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय समिति के विद्रोह संबंधी गोपनीय निर्णय की चर्चा की तथा विद्रोह के ख़िलाफ़ अपने "तर्कों" की व्याख्या की।

लेनिन ने ज़िनोव्येव और कामेनेव की इस हरकत को ग़द्दारी कहा तथा उन्हें पार्टी से निकाल देने की मांग की। इस बात को स्वीकार करते हुए कि सशस्त्र विद्रोह की तैयारी के कार्य को बड़ा नुक़्सान पहुंचा है, लेनिन ने पार्टी का सारी शक्ति से विद्रोह की तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने उसकी सुनिश्चित सैनिक-तकनीकी तैयारी की आवश्यकता का मुख्य ध्यान दिलाया। इसके अनुसार लाल रक्षकों को अपने बैरकों में तैनात होने और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार

अक्तूबर क्रांति के बाद पार्टी की लनिनीय नीति का विरोध किया, जिसके लिए उन्हें पार्टी से एकाधिक बार निकाल दिया गया : नवम्बर १९२७ में (भूल स्वीकार करने के बाद १९२८ में फिर पार्टी में ले लिये गये), १९३२ में (१९३३ में पुनः पार्टी में ले लिये गये)। १९३४ में पार्टी-विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें तीसरी बार पार्टी से निकाला गया। – सं०

ल० ब० कामेनेव (रोज़ेनफ़ेल्द) (१८८३-१९३६) – १९०१ मे रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी के सदस्य। १९१७ से केंद्रीय समिति के सदस्य। १९१७ में समाजवादी क्रांति की लेनिनीय नीति का विरोध किया। अक्तूबर क्रांति के बाद पार्टी की लेनिनीय नीति का बारंबार विरोध किया, जिसके लिए उन्हें कई बार पार्टी से निकाला गया : १९२७ में (१९२८ में फिर पार्टी में ले लिये गये), १९३२ में (१९३३ में फिर पार्टी में ले लिये गये)। १९३४ में पार्टी-विरोधी गतिविधियों के लिए तीसरी बार पार्टी से निकाल दिये गये। – सं०

रहने का आदेश किया गया। सारे देश में विद्रोह एकसाथ ही शुरू हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्रांतिकारी-सैनिक समिति ने अपने कमिसारों को मोर्चों पर, मास्को और दूसरे औद्योगिक केंद्रों में भेजे।

अस्थायी सरकार ने विद्रोह की तैयारी के बारे में ग़द्दारों द्वारा आगाह होकर क्रांतिकारी शक्तियों पर पहले ही प्रहार शुरू करने का प्रयास किया। २४ अक्तूबर की सुबह को जंकरों ने बोल्शेविक अख़बार 'राबोची पूत' ('मज़दूरों का मार्ग') के छापेख़ाने पर धावा बोल दिया। सरकार ने बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्यों और क्रांतिकारी सैनिक समिति के सदस्यों को गिरफ़्तार करने, विद्रोह के मुख्यालय स्मोल्नी पर क़ब्ज़ा करने का प्रस्ताव पास किया तथा क्रांति को कुचलने के लिए अन्य क़दम निर्धारित किये।

परंतु क्रांति अदम्य रूप से बढ़ी और जनगण के शत्रुओं का कोई भी षड्यंत्र पुरानी सरकार के पतन को नहीं रोक सका। पेत्रोग्राद समिति ने सरकार का तख़्ता तुरंत उलटने तथा देश की राजधानी और अन्य स्थानों में मज़दूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों को सत्ता हस्तांतरित करने के बारे में एक प्रस्ताव पास किया।

लेकिन क्रांतिकारी शक्तियों ने सर्वत्र एकसाथ आक्रमण शुरू करने में सक्रियता नहीं प्रदर्शित की। पार्टी के कुछ नेताओं ने विद्रोह को सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस के उद्घाटन तक स्थगित करने का प्रस्ताव किया, जो २५ अक्तूबर को आरंभ होनेवाली थी। इस स्थिति में केंद्रीय समिति के सदस्यों के नाम लेनिन के पत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। पत्र में उन्होंने कहा: "मैं ये पंक्तियां २४ तारीख़ की शाम को लिख रहा हूं, स्थिति बेहद नाज़ुक है। यह नितांत स्पष्ट हो चुका है कि अब, दरअसल, विद्रोह में विलंब करना मौत के समान होगा।

"मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ साथियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि अब सब कुछ कच्चे धागे पर लटका हुआ है, कि सामने ऐसे सवाल हैं, जो सम्मेलनों से हल नहीं होंगे, कांग्रेसों (सोवियतों की कांग्रेसों तक) से हल नहीं होंगे, अपितु अन्य रूप से जनता द्वारा, जनसाधारण द्वारा हथियारबंद जनसाधारण के संघर्ष द्वारा हल होंगे ...

"इतिहास क्रांतिकारियों को विलंब के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा, जो आज विजयी हो सकते हैं (और वे आज यक़ीनन विजयी होंगे),

जबकि कल उनके लिए बहुत-कुछ खो बैठने का खतरा है, सब-कुछ खो बैठने का खतरा है।"*

२४ अक्तूबर की रात को लेनिन स्मोल्नी पहुंचे ताकि विद्रोह का नेतृत्व सीधे अपने हाथ में ले सकें। विद्रोह की लेनिनीय योजना को तेजी से और कारगर ढंग से अमल में लाया गया। नगर के पुलों, टेलीग्राफ़, टेलीफ़ोन, रेलवे स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों पर क़ब्ज़ा कर लिया गया।

अस्थायी सरकार अब भी शीत प्रासाद में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी घड़ी निकट आ गयी थी। वास्तविक सत्ता उसके हाथ में नहीं रह गयी थी। प्रधानमंत्री केरेंस्की अमरीकी झंडा लगी कार में शीत प्रासाद से भाग गये।

२४-२५ अक्तूबर की रात को स्मोल्नी में बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति की लेनिन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक ने विद्रोह की प्रगति के बारे में रिपोर्ट सुनी और इंगित किया गया कि राजधानी में वह विजयी हो चुका है। केंद्रीय समिति ने क्रांतिकारी सरकार – सोवियत सत्ता – की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया। बैठक ने इसे जन कमिसारों की परिषद का नाम देने और सरकार के सदस्यों को पेरिस कम्यून के उदाहरण पर जन कमिसार के नाम से पुकारने के लेनिन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

२५ अक्तूबर, १९१७ को दस बजे सुबह क्रांतिकारी-सैनिक समिति ने लेनिन द्वारा लिखी अपील 'रूस के नागरिकों के नाम!' प्रकाशित की। उसमें कहा गया था: "अस्थायी सरकार का तख़्ता उलट दिया गया है। राज्य-सत्ता मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्रोग्राद सोवियत के निकाय – क्रांतिकारी-सैनिक समिति, जो पेत्रोग्राद के सर्वहारा-वर्ग तथा गैरिज़न की अगुआई कर रही है – के हाथों में पहुंच चुकी है।

"ध्येय की, जिसके लिए जनता लड़ी है – जनवादी शांति का तात्कालिक प्रस्ताव, ज़मीन पर ज़मींदारों के स्वामित्व का उन्मूलन,

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'केंद्रीय समिति के सदस्यों को पत्र', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ७, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८४, पृ० २९१।

उत्पादन पर मज़दूरों का नियंत्रण तथा सोवियत सत्ता का गठन – इस ध्येय की सिद्धि हो चुकी है।

"मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों की क्रांति ज़िंदाबाद!"*

२५ अक्तूबर की शाम को सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। अधिकांश जनगण के समर्थन से उसने राज्य-सत्ता अपने हाथ में ली और सारे देश में संपूर्ण सत्ता मज़दूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों को सौंप दी। कांग्रेस ने शांति और भूमि संबंधी ऐतिहासिक आज्ञप्तियां स्वीकार कीं तथा इतिहास में मज़दूरों और किसानों की पहली सरकार की स्थापना की। लेनिन को जन कमिसार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

अक्तूबर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी और संचालन इतनी कुशलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक किया गया था कि उसे उचित ही इतिहास में महान रणनीति और कार्यनीति का उदाहरण माना जाता है। पेत्रोग्राद में प्रज्वलित क्रांति की ज्वाला समूचे देश में, उसके दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक में फैल गयी। रूस में समाजवाद का उदय हो चुका था, जिसने विश्व इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात किया।

---

* वही, पृ० ३५६।

अध्याय २

क्रांति अपनी रक्षा करने में समर्थ होनी चाहिए

१. अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद – हस्तक्षेप और गृहयुद्ध का संगठनकर्ता

समाजवादी राज्य की युद्धों पर प्रतिबंध लगाने की अपील

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय के साथ इतिहास में पहली बार एक ऐसे राज्य का आविर्भाव हुआ, जिसने जनगण के बीच शांति, दोस्ती और समानाधिकारपूर्ण सहयोग के महान मानवतावादी सिद्धांतों के आधार पर विदेशनीति की घोषणा की। नयी क्रांतिकारी सरकार की सर्वोच्च संस्था – सोवियतों की दूसरी कांग्रेस – ने उन्हें शांति संबंधी आज्ञप्ति में साकार किया, जो मज़दूरों और किसानों के राज्य की पहली विधायी कार्रवाई थी। उसने युद्ध को मानवजाति के खिलाफ़ सबसे बड़ा अपराध घोषित किया और रूस तथा अन्य देशों के जनगण को साम्राज्यवादी युद्ध से निकलने का रास्ता दिखाया।

क्यों सोवियत राज्य ने अपना कार्य शांति के लिए सक्रिय, अनम्य संघर्ष के साथ शुरू किया?

वस्तुगत ऐतिहासिक स्वरूप के दो तथ्य इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं।

पहला, अपने उद्‌भव और सामाजिक-आर्थिक स्वरूप के अनुसार समाजवाद को युद्धों की आवश्यकता नहीं होती। समाजवाद सामाजिक विकास की वह मंज़िल है, जिस पर समाज के जीवन से युद्ध का उन्मूलन करने संबंधी मानवजाति के युगों पुराने सपने को साकार करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। समाजवादी राज्य में आक्रामक युद्धों में दिलचस्पी रखनेवाले कोई वर्ग या सामाजिक संस्तर नहीं होते। दो विरोधी सामाजिक प्रणालियों में विभाजित विश्व की परिस्थितियों में समाजवाद ने मानवजाति के समक्ष राज्यों के बीच संबंधों का एकमात्र वास्तविक सिद्धांत – शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का

सिद्धांत – पेश किया। समाजवाद ने घोषणा की कि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के उपाय नहीं हो सकते। इस सिद्धांत की सत्यता आज की परिस्थितियों में और भी स्पष्ट हो जाती है, जब जन-संहार के अभूतपूर्व साधन प्रकट हो गये हैं।

दूसरा, अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय हुई तो पहला विश्व साम्राज्यवादी युद्ध अभी चल ही रहा था और जर्मनी के साथ युद्ध ने नयी, सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण में बड़ी बाधा पहुंचायी। देश और क्रांति को बचाने के लिए शांतिपूर्ण मोहलत की आवश्यकता थी। आर्थिक, सैनिक, तकनीकी, नैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से युद्ध जारी रखना असंभव था। मेहनतकशों को क्रांति की उपलब्धियों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना, सोवियत सत्ता को मज़बूत बनाना, अर्थव्यवस्था को बहाल करना तथा साम्राज्यवादी आक्रामकों से देश की रक्षा करने में समर्थ नयी सेना का गठन करना आवश्यक था।

रूस के प्रतिक्रांतिकारी और एंटेंट के साम्राज्यवादी – युद्ध में रूस के भूतपूर्व मित्र-देश – युद्ध जारी रखना चाहते थे। वे जर्मन साम्राज्य की सहायता से क्रांति का गला घोंटना और रूस में पुरानी व्यवस्था क़ायम करने की आशा करते थे।

शांति संबंधी आज्ञप्ति और सोवियत सरकार के पहले विदेशनीतिक क़दमों ने उनकी इन आशाओं पर पानी फेर दिया।

न केवल रूस में मेहनतकश लोगों, सैनिकों और नौसैनिकों ने, बल्कि अनेक देशों के जनगण ने शांति संबंधी आज्ञप्ति का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ब्रिटेन, फ़्रांस और अमरीका में शांति की और सोवियत रूस को समर्थन प्रदान करने की मांगों के साथ प्रदर्शन और सभाएं हुईं।

लेकिन एंटेंट देशों की सरकारों की प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न थी। उन्होंने सोवियत सरकार के प्रस्तावों का कोई जवाब नहीं दिया और १० नवम्बर, १९१७ को रूसी सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय में स्थित एंटेंट के सैनिक मिशनों के प्रधानों ने शांति-वार्ताओं, युद्ध बंद करने के ख़िलाफ़ औपचारिक रूप से प्रतिवाद किया और सोवियत रूस को गंभीरतम सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणामों की धमकी दी।

साम्राज्यवादी युद्ध से रूस के अलग हो जाने से एंटेंट के साम्राज्यवादियों में खलबली और घबराहट पैदा हुई। अब तक रूसी मोर्चे

पर आधी से अधिक जर्मन सेनाएं लड़ रही थीं। अब एंटेंट इस समर्थन से वंचित हो गया।

११ नवम्बर, १९१७ को ग्रेट ब्रिटेन के विदेशमंत्री र० सेसिल ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार सोवियत सरकार को नहीं मानती। १८ नवम्बर को अमरीकी विदेशमंत्री राबर्ट लांसिंग ने रूस स्थित अमरीकी राजदूत को सोवियत सरकार से कोई वार्ता न करने, शांति-वार्ता न चलाने का आदेश दिया। फ़्रांसीसी विदेशमंत्री पिशों ने कहा कि उनका देश सोवियत सरकार से न तो कोई संबंध रखेगा, न ही कोई शांति-वार्ता चलायेगा।

इसके साथ ही जर्मनी सोवियत रूस पर अत्यंत प्रतिकूल शर्तें थोपते हुए शांति-वार्ता चलाने के लिए राज़ी हो गया, ताकि अपनी सेनाओं को पश्चिमी मोर्चे पर जमा कर सके और युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ सके।

एंटेंट देशों द्वारा वार्ताएं शुरू करने से इन्कार को ध्यान में रखते हुए सोवियत सरकार जर्मनी के साथ वार्ता आरंभ करने के लिए विवश हो गयी।*

शांति के आंतरिक और विदेशी विरोधियों के कड़े विरोध पर क़ाबू पाने के लिए बड़ा प्रयास करते हुए जर्मनी के साथ शांति-संधि हुई।** "**पहली बोल्शेविक क्रांति ने,**" लेनिन ने लिखा, "पृथ्वी के **पहले दस करोड़ लोगों को** साम्राज्यवादी युद्ध से, साम्राज्यवादी दुनिया के चंगुल से छुड़ा लिया है।"*** सोवियत रूस ने शांति की मोहलत प्राप्त कर ली थी, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं बनी रह सकी। सोवियत राज्य को युद्ध में खींचते हुए विदेशी और आंतरिक शत्रुओं ने शांतिपूर्ण समाजवादी निर्माण को स्थगित करने के लिए विवश कर दिया।

---

* देखें अध्याय ८।

** ब्रेस्त शांति-संधि – ३ मार्च, १९१८ को ब्रेस्त-लितोव्स्क में सोवियत रूस और जर्मनी के बीच रूस के लिए प्रतिकूल शर्तों पर शांति-संधि पर हस्ताक्षर हुए। – सं०

*** व्ला० इ० लेनिन, 'अक्तूबर क्रांति की चौथी वर्षगांठ', १९२१।

विदेशी सैनिक हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के कारण

बुर्जुआ इतिहासकार साम्राज्यवादी राज्यों द्वारा सोवियत रूस में हस्तक्षेप तथा मज़दूरों और किसानों की सरकार का तख़्ता उलटने के लिए आंतरिक प्रतिक्रांति के साथ उनके सहयोग के असली कारणों को तोड़ते-मरोड़ते हैं। परंतु वस्तुगत ऐतिहासिक तथ्य और दस्तावेज़ इन आक्रामक जालसाज़ी भरी कार्रवाइयों के सही कारणों को प्रकट कर देते हैं।

सोवियत जनतंत्र के विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप और गृहयुद्ध का राजनीतिक कारण यह था कि अक्तूबर क्रांति ने पूंजीवादी शासन का अस्थायित्व और शोषकों के अत्याचार से मेहनतकशों की मुक्ति की संभावना प्रदर्शित की। इसने शोषकों के मन में सोवियत रूस के प्रति भय और घृणा पैदा कर दी और उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। पूंजीवादी देशों के शासक हलक़े क्रांतिकारी मज़दूर आंदोलन और उत्पीड़ित जातियों के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष पर क्रांति के प्रभाव से भयभीत हो गये थे।

नवम्बर १६१८ में अमरीकी राष्ट्रपति वूड्रो विल्सन ने घोषणा की कि मित्र-देश बोल्शेविज़्म को एकमात्र ऐसा शत्रु मानते हैं, जिसके ख़िलाफ़ हथियार उठाने की आवश्यकता है, कि सोवियत राज्य कई ओरों से मित्र-देशों की सेनाओं के आक्रमण के लिए खुला है।* अमरीका ने बाल्टिक क्षेत्र, बेलोरूस, उक्राइना, क्रीमिया, काकेशिया और मध्य एशिया को सोवियत रूस से छीनने की योजना पेश की।

दोनों ही साम्राज्यवादी गुटों के शासक हलक़ों को भय था कि सोवियत रूस की शांतिप्रिय विदेशनीति सभी देशों में शांति के प्रति इच्छा बढ़ा देगी।

आर्थिक कारणों ने भी विदेशी साम्राज्यवादियों और आंतरिक प्रतिक्रांति को क्रांतिकारी रूस के ख़िलाफ़ हस्तक्षेप करने और गृहयुद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। वे ज़ारशाही और अस्थायी सरकार को दिये गये अरबों रूबल के ऋणों तथा रूस के मेहनतकशों के शोषण

---

* अमरीका ६ अप्रैल, १६१७ को एंटेंट की ओर से पहले विश्व-युद्ध में शामिल हुआ। – सं०

से प्राप्त होनेवाले विशाल मुनाफ़ों की क्षति को बर्दाश्त नहीं कर सके। १९१७ तक रूस का राजकीय ऋण १२ अरब रूबल से अधिक हो गया था जिसका लगभग ४८ प्रतिशत विदेशी ऋणदाताओं से लिया गया था।

सोवियत राज्य के प्रति साम्राज्यवादियों की कट्टर शत्रुता अक्तूबर क्रांति की विजय के पहले दिनों से ही शुरू हो गयी थी। लेकिन वे तुरंत खुल्लमखुल्ला सैनिक हस्तक्षेप नहीं कर सके, क्योंकि जारी विश्वयुद्ध में उनकी शक्तियों और साधनों का एक बड़ा भाग लग रहा था। लेकिन अकाट्य ऐतिहासिक तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि दिसम्बर १९१७ में ही एंटेंट देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक विशेष बैठक में सशस्त्र हस्तक्षेप की योजना पर विचार-विमर्श किया था। ब्रिटेन और फ़्रांस ने 'रूसी भूक्षेत्र पर ब्रिटिश और फ़्रांसीसी सेनाओं की भावी कार्रवाइयों के क्षेत्रों के बारे में' एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये थे।

सोवियत रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्त शांति-संधि के हस्ताक्षर के बाद, जब जर्मन सेना की सहायता से सोवियत जनतंत्र का गला घोंटने की योजना असफल हो गयी थी, एंटेंट देशों के साम्राज्यवादियों ने हस्तक्षेप की तैयारी तेज़ कर दी। लंदन में प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में रूस और जर्मनी के बीच शांति-संधि को मान्यता न देने तथा सोवियतों के देश के विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप शुरू करने का निर्णय किया गया।

एंटेंट देशों के साम्राज्यवादियों ने आक्रमण के लिए रूस के अत्यंत सुगम क्षेत्रों – उत्तर और सुदूर पूर्व के क्षेत्रों – को चुना। ६ मार्च, १९१८ को ब्रिटिश फ़ौजें मूर्मांस्क में उतरने लगीं। कुछ समय बाद एक फ़्रांसीसी और एक अमरीकी युद्धपोत भी वहां आ पहुंचे। मास्को और पेत्रोग्राद पर क़ब्ज़ा करने की आक्रामकों की योजनाओं में उत्तर का एक महत्वपूर्ण स्थान था और वे उसे आंतरिक प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को सप्लाई के एक अड्डे में बदल देना चाहते थे।

साइबेरिया और सुदूर पूर्व पर क़ब्ज़ा करके साम्राज्यवादी इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को हथियाना और मध्य रूस में आगे बढ़ने के लिए एक अड्डा क़ायम करना चाहते थे। ५ अप्रैल, १९१८ को जापानी सेना की टुकड़ी और उसके पीछे ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी व्लादी-

वोस्तोक में उतरीं। आगे चलकर अमरीकी, फ़्रांसीसी और इतालवी सैनिक टुकड़ियां भी वहां आ पहुचीं।

सोवियत सत्ता के खिलाफ़ लड़ने और रूस के भीतरी प्रदेशों पर आक्रमण करने के लिए एंटेंट ने एक चेकोस्लोवाक कोर का इस्तेमाल किया। पहले विश्वयुद्ध के दौरान युद्धबंदियों और रूस का पक्ष लेनेवाले चेकों और स्लोवाकों से ४० हज़ार से अधिक सैनिकों का एक कोर बनाया गया था। शुरू में एंटेंट उसे जर्मनी के खिलाफ़ पश्चिमी मोर्चे पर तैनात करना चाहता था। अक्तूबर क्रांति तथा युद्ध से रूस के निकलने के बाद सोवियत सरकार ने कोर को साइबेरिया और सुदूर पूर्व से होकर फ़्रांस जाने की अनुमति दे दी।

एंटेंट के नेताओं ने कोर का सोवियत-विरोधी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। कोर के सामान्य सैनिक क्रांतिकारी रूस के मेहनतकशों के खिलाफ़ हथियार उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन कोर के ज़रखरीद कमांडरों ने निर्लज्जतापूर्वक अफ़वाह फैलाते हुए सैनिकों को धोखा दिया कि सोवियत सरकार कोर को आस्ट्रिया-हंगरी के हाथों सुपुर्द करना चाहती है। १९१८ की मई के अंत और जून के आरंभ में चेकोस्लोवाक कोर ने, जो ६० ट्रेनों में व्लादीवोस्तोक जा रहा था और जो वोल्गा से साइबेरिया तक फैला था, सोवियत सत्ता के खिलाफ़ विद्रोह कर दिया। स्थानीय प्रतिक्रांतिकारियों, समाजवादी-क्रांतिकारियों और मेंशेविकों की सहायता से विद्रोहियों ने सोवियतों को सत्ताच्युत कर दिया और उनकी जगह पूंजीपतियों तथा ज़मींदारों की सत्ता बहाल कर दी।

इस तरह, विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध का एक व्यापक मोर्चा क़ायम हुआ, जो १९१८ की गर्मी और शरत् में क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा के लिए संघर्ष का मुख्य मोर्चा बन गया। १९१८ के अंत तक साइबेरिया और सुदूर पूर्व में हस्तक्षेपकारी सेनाओं में सैनिकों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक हो गयी।

साथ ही एंटेंट के साम्राज्यवादियों और आंतरिक प्रतिक्रांति ने देश के दक्षिण-पूर्वी भाग में सोवियतों के खिलाफ़ सशस्त्र संघर्ष आरंभ कर दिया। ब्रिटिश हस्तक्षेपकारियों ने बाकू तेल-क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा करने के मुख्य उद्देश्य से तुर्किस्तान और ट्रांसकाकेशिया पर आक्रमण कर दिया।

जर्मन साम्राज्यवादियों ने विश्वासघात करके ब्रेस्त शांति-संधि

भंग कर दी। उन्होंने फ़िनलैंड पर क़ब्ज़ा करके वहां मज़दूरों की सरकार को सत्ताच्युत कर दिया, बाल्टिक क्षेत्र, बेलोरूस और उक्राइना पर अधिकार कर लिया, दोन क्षेत्र पर हमला कर दिया तथा जार्जियाई मेंशेविकों की मिलीभगत से जार्जिया पर क़ब्ज़ा कर लिया।

हस्तक्षेपकारी फ़ौजों के आक्रमण और चेकोस्लोवाक कोर के प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह ने आंतरिक प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों का मनोबल बढ़ा दिया। सत्ताच्युत शोषक वर्गों ने गृहयुद्ध छेड़ दिया। बुर्जुआ और टुटपुंजिया पार्टियों तथा बुर्जुआ राष्ट्रवादियों ने विदेशी साम्राज्यवादियों के साथ समझौते किये, देश के कुछ क्षेत्रों में क़ायम प्रतिक्रांतिकारी सरकारों में शामिल हुए और उनका नेतृत्व तक किया। वे मेहनतकशों से सत्ता छीन पाते, इसके लिए रूस को टुकड़े-टुकड़े करके उसे एक उपनिवेश में बदल देने को भी तैयार थे।

सोवियत जनतंत्र ने अपने को एक अत्यंत कठिन स्थिति में पाया, वह अपने इतिहास की एक अत्यंत कठिन अवधि से गुज़र रहा था। प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों ने उसकी चारों ओर से घेरेबंदी कर दी थी। शत्रुओं ने देश के बड़े भूभाग पर क़ब्ज़ा कर लिया था और उसके केंद्रीय क्षेत्रों को खाद्य-सामग्रियों तथा कच्चे मालों की सप्लाई करनेवाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से काट दिया था।

२७ जुलाई, १९१८ को क्लारा ज़ेटकिन को पत्र में लेनिन ने लिखा: "अब हम संपूर्ण क्रांति के संभवत: सबसे कठिन सप्ताहों से गुज़र रहे हैं। वर्ग संघर्ष और गृहयुद्ध आबादी में गहराई से पैठ गये हैं: सर्वत्र गावों में फूट पड़ गयी है—ग़रीब हमारे पक्ष में हैं, कुलक प्रचंड रूप मे हमारे खिलाफ़ हैं। एंटेंट ने चेकोस्लोवाकों को ख़रीद लिया है, प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह क्रोधोन्मत्त है, संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग हमें सत्ताच्युत करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहा है।"* परंतु लेनिन को बुर्जुआ वर्ग पर अंतिम विजय में पूर्ण विश्वास था।

इस प्रकार, अक्तूबर क्रांति का ऐतिहासिक अनुभव प्रमाणित करता है कि गृहयुद्ध ऐसी अवश्यम्भावी परिघटना नहीं है, जो मानो समाजवादी क्रांति और उससे जनित नयी सामाजिक प्रणाली की विशिष्टता हो। अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद और सत्ताच्युत शोषक ही विश्व के पहले

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'क्लारा ज़ेटकिन को पत्र', १९१८।

समाजवादी राज्य के खिलाफ़ फ़ौजी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के लिए ज़िम्मेदार थे। यह ऐतिहासिक सत्य है।

तब सोवियत राज्य हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांतिकारियों की संयुक्त शक्तियों पर विजय पाने में कैसे सफल हुआ?

२. देश का एक सैनिक शिविर में रूपांतरण

समाजवादी पितृभूमि और उसकी रक्षा के बारे में लेनिन का सिद्धांत

समाजवादी क्रांति की उपलब्धियों की सैनिक रक्षा संगठित करने में कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार समाजवादी पितृभूमि की रक्षा के बारे में लेनिनीय सिद्धांत से मार्गदर्शित होती थी।

लेनिन ने बुर्जुआ वर्ग और उसके सिद्धांतकारों का पर्दाफ़ाश किया, जो जनगण की देशभक्तिपूर्ण भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए एक जाति को दूसरी जातियों के खिलाफ़ भड़का रहे थे तथा उनके मन-मस्तिष्क को राष्ट्रवाद और अंध-राष्ट्रवाद से विषाक्त बना रहे थे।

पितृभूमि की लेनिनीय अवधारणा ने ऐसे विचारों पर विनाशकारी प्रहार किया। १९०८ में लिखित अपने लेख 'युद्धप्रिय सैन्यवाद तथा सामाजिक-जनवाद की सैन्यवाद-विरोधी कार्यनीति' में लेनिन ने दिखाया कि "स्वदेश, याने संबद्ध राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश सर्वहारा के वर्ग संघर्ष में सबसे सशक्त कारक होता है"।*

अगर एक व्यक्ति के लिए "मातृभूमि" की धारणा सहज प्राकृतिक विशिष्टताओं में निहित है, तो एक वर्ग या पार्टी के लिए यह सबसे पहले एक सामाजिक धारणा है, यह वह सामाजिक-राजनीतिक वातावरण

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'युद्धप्रिय सैन्यवाद तथा सामाजिक-जनवाद की सैन्यवाद-विरोधी कार्यनीति', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ४, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८२, पृ० ४२।

है, जो राज्य में मेहनतकशों का स्थान निर्धारित करता तथा उनके जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। अतः लेनिन ने शिक्षा दी कि सर्वहारा वर्ग अपने संघर्ष की राजनीतिक और सांस्कृतिक परि-स्थितियों के प्रति, अपने देश के भाग्य के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। 'रूसियों का राष्ट्रीय गौरव' शीर्षक लेख में लेनिन ने विश्वासपूर्वक और भावपूर्ण ढंग से कहा कि वर्ग-सचेत महान रूसी सर्वहाराओं के लिए राष्ट्रीय गौरव की भावना परायी नहीं है, कि वे अपनी भाषा और मातृभूमि से प्रेम करते हैं और आबादी की बहुसंख्या बनानेवाले मजदूरों और मेहनतकशों को सचेत जनवादी और समाजवादी बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयत्नशील हैं।

लेनिन ने पितृभूमि पर मार्क्सवादी विचारों की जालसाज़ी का पर्दाफ़ाश किया। मार्क्स और एंगेल्स ने 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र' में लिखा कि पूंजीवाद के अंतर्गत "श्रमजीवियों का कोई स्वदेश नहीं है। जो उनके पास है ही नहीं उसे उनसे कौन छीन सकता है?"* मार्क्सवाद के विरोधी यह दावा करते हुए इस मार्क्सवादी प्रस्थापना को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश करते हैं कि मज़दूर वर्ग और उसकी पार्टी पितृभूमि को नहीं मानते, कि वे राष्ट्र-विरोधी शक्ति हैं और राष्ट्रीय नाशवाद की हिमायत करते हैं।

लेनिन ने दिखाया कि 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र' में इस प्रस्थापना का पितृदेश के प्रति नकारात्मक रुख से कोई वास्ता नहीं है, वह सिर्फ़ बुर्जुआ राज्य के प्रति सर्वहारा वर्ग के रुख को प्रकट करती है, क्योंकि पूंजीवादी दुनिया में उसका आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न किया जाता है। लेनिन के अनुसार, मार्क्स और एंगेल्स की इस प्रस्थापना का मूल अर्थ यह है कि मज़दूर वर्ग को बुर्जुआ वर्ग का तख्ता उलट देना चाहिए और शोषकों से मातृभूमि को छीनकर अपनी राजनीतिक सत्ता और इस तरह अपने समाजवादी पितृदेश की स्थापना करनी चाहिए।

लेनिन का यह विचार कि क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा पूंजीवाद

---

* का० मार्क्स और फ़्रे० एंगेल्स, 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र', संकलित रचनाएं, तीन खंडों में, खंड १, भाग २, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९७८, पृ० १५१।

से समाजवाद में संक्रमण की प्रक्रिया का एक सामान्य महत्व रखनेवाला नियमसंगत अंग है, क्रांतिकारी सिद्धांत के विकास में उनका असाधारण योगदान है। मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों को अपने हाथों में हथियार उठाकर अपनी समाजवादी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए।

लेनिन ने समाजवादी मातृभूमि की रक्षा में युद्धों की विशिष्टताओं का चहुंमुखी विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि ये युद्ध सच्चे क्रांतिकारी और उच्चतः न्यायसंगत स्वरूप के होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य सबसे प्रगतिशील सामाजिक संरचना – समाजवाद – की रक्षा करना होता है। ऐसे युद्ध सच्चे देशभक्तिपूर्ण स्वरूप के होते हैं, जनसाधारण में वीरता की भावना, उच्च संघबद्धता और अनुशासन पैदा करते हैं।

लेनिन की ऐतिहासिक सेवा यह है कि उन्होंने समाजवादी मातृभूमि की हथियारों के बल से रक्षा करने की आवश्यकता की सैद्धांतिक पुष्टि करने के साथ मज़दूरों और किसानों के राज्य की सैनिक रक्षा से संबंधित व्यावहारिक प्रश्नों को भी विशद बनाया।

समाजवादी राज्य के लिए सशस्त्र सेनाओं के गठन की आवश्यकता, उनके निर्माण के ऐतिहासिक उद्देश्य, स्वरूप और सिद्धांतों के बारे में प्रस्थापना समाजवादी पितृभूमि की रक्षा की लेनिनीय शिक्षा का महत्वपूर्ण संघटक अंग हैं।

लेनिन ने युद्ध और अर्थव्यवस्था के सहसंबंध के मार्क्सवादी सिद्धांत को कुशलतापूर्वक विकसित करके समृद्ध बनाया और सिद्ध किया कि साम्राज्यवादी युग के युद्धों में देश की अर्थव्यवस्था का संगठन सर्वोपरि महत्व रखता है। "**सच्चे ढंग से** युद्ध चलाने के लिए," उन्होंने कहा, "हमें मज़बूती से संगठित चंदावल की आवश्यकता है। अच्छी से अच्छी सेनाएं भी, क्रांतिकारी ध्येय के प्रति अत्यधिक समर्पित लोग भी शत्रु द्वारा तुरंत नष्ट कर दिये जायेंगे, अगर वे पर्याप्त रूप से सशस्त्र नहीं होंगे, खाद्य-सामग्रियों की सप्लाई नहीं पायेंगे, प्रशिक्षित नहीं होंगे।"*

"चंदावल" से लेनिन का अभिप्राय न केवल अर्थव्यवस्था, बल्कि सामाजिक-आर्थिक संरचना, जनगण की संगठनबद्धता और चेतना तथा विज्ञान और टेक्नोलाजी की स्थिति से भी था। ये सभी कारक सैनिक कार्रवाइयों पर चहुंमुखी प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा: "युद्ध में

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'कामकाजी आधार पर', १ मार्च, १९१८।

विजय अंतिम विश्लेषण में उन जनसाधारण के मनोबल पर निर्भर करती है, जो रणक्षेत्र में अपना खून बहाते हैं।"*

लेनिन ने युद्ध के स्वरूप और राष्ट्र तथा उसकी सेनाओं के मनोबल के बीच सीधा और प्रत्यक्ष संबंध प्रकट किया। केवल न्यायसंगत युद्ध ही जनगण में उच्च मनोबल जगाता है और उसके प्रेरक लक्ष्य सच्ची जन-वीरता, सैनिक तथा श्रम पराक्रम पैदा करते हैं। लेनिन के शब्दों में "उस राष्ट्र को, जिसमें अधिकांश मज़दूर और किसान जानते, महसूस करते और देखते हैं कि वे अपनी सोवियत सत्ता, मेहनतकशों की सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कि वे उस ध्येय के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी विजय उनके और उनके बच्चों के लिए सांस्कृतिक संपदाओं, मानव-श्रम की सभी कृतियों के उपयोग की संभावना को सुनिश्चित बनायेगी – उस राष्ट्र को कभी पराजित नहीं किया जा सकता।"**

आधुनिक युद्धों के कारणों और परिणामों को निर्धारित करनेवाले ये तथा अन्य वस्तुगत नियम अपने आप क्रियाशील नहीं होते। वे लोगों की सचेत कार्य-प्रक्रिया में प्रकट होते हैं और यह समाजवादी पितृभूमि की सैनिक रक्षा संगठित करने में कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार की नेतृत्वकारी भूमिका को निर्धारित करता है।

समाजवादी पितृभूमि की रक्षा संबंधी लेनिनीय सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद और आंतरिक प्रतिक्रांति की शक्तियों के ख़िलाफ़ संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत जनगण का जुझारू झंडा बन गया।

इस सिद्धांत के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने अक्तूबर क्रांति और गृहयुद्ध के दौरान विदेशी दखलंदाज़ों तथा आंतरिक प्रतिक्रांति को पराजित करने का कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें देश के जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, विचारधारात्मक, सैनिक, आदि पहलुओं को शामिल किया गया था।

---

* व्ला० इ० लेनिन, मास्को के रोगोज्स्को-सिमोनोव्स्की ज़िले में मजदूरों और लाल सैनिकों के विस्तारित सम्मेलन में भाषण, १३ मई, १६२०।

** व्ला० इ० लेनिन, मास्को जंक्शन के रेलकर्मचारियों की सभा में भाषण, १६ अप्रैल, १६१६।

देश के सैनिक शिविर में रूपांतरण के लिए राजनीतिक क़दम

राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध ने राज्य के संचालन में अधिक केंद्रीयकरण की मांग की। ऐसा अवयव क़ायम करना आवश्यक था, जो सभी सैनिक, सोवियत और आर्थिक संस्थाओं के कार्यकलाप को एकीकृत और लामबंद कर सके तथा हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति की पराजय को सुनिश्चित कर सके। लेनिन के नेतृत्व में मज़दूर और किसान रक्षा परिषद एक ऐसा ही अवयव बनी। यह मज़दूर-किसानों के राज्य का असाधारण अवयव थी, जिसके हाथों में बाहरी और भीतरी शत्रुओं पर विजय के लिए देश की सभी शक्तियों को लामबंद करने की पूर्ण सत्ता संकेंद्रित थी।

इसके साथ ही राजकीय कार्ययंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बहुत से क़दम अमल में लाये गये। मज़दूरों और किसानों ने राजकीय संचालन के कौशल सीखे।

कम्युनिस्ट पार्टी मेहनतकशों के बीच बड़ा विश्वास प्राप्त करती जा रही थी। मिसाल के लिए, अगर जुलाई १९१८ में सोवियतों की गुबेर्निया (प्रांतीय) कांग्रेसों के प्रतिनिधियों में कम्युनिस्टों का हिस्सा ५२ प्रतिशत था, तो दिसंबर १९१८ में उनका हिस्सा बढ़कर ९०.३ प्रतिशत हो गया। अधिकांश प्रतिनिधि अग्रिम मज़दूरों और देहातों में क्रांति के मुख्य समर्थक अधिक वर्ग-चेतन ग़रीब किसानों के बीच से आये थे।

मंझोले किसानों को सोवियत सत्ता के पक्ष में लाना, जो अक्तूबर क्रांति के बाद देश में प्रमुख सामाजिक संस्तर बन गये थे, सोवियत राज्य के सामाजिक-राजनीतिक सुदृढ़ीकरण तथा देश के एक सैनिक शिविर में रूपांतरण का महत्वपूर्ण कारक था।

सुविदित है कि मंझोला किसान अपनी वस्तुगत स्थिति के कारण सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच डांवांडोल था। मेहनतकशों के रूप में वह सोवियत सत्ता के प्रति सहानुभूति रखे बिना नहीं रह सकता था, जिसने उसे मुफ़्त में ज़मीन दी थी, ज़मींदारों और पूंजीपतियों के उत्पीड़न से उसे मुक्त कराया था। लेकिन दूसरी ओर, छोटे मालिकों के रूप में मंझोला किसान अनाज के व्यापार में राजकीय इजारेदारी की स्थापना से, कृषि उपज के स्थिर दामों से संतुष्ट नहीं था। इसी वजह से

१९१८ की गर्मी में देश के कुछ क्षेत्रों में (उदाहरणार्थ वोल्गा, साइबेरिया, आदि क्षेत्रों में) मंझोले किसानों का एक भाग प्रतिक्रांति के पक्ष में चला गया।

फिर भी, १९१८ की शरत् में देहातों में मंझोले किसानों के प्रति सोवियत सरकार की सही नीति और कुलक तत्वों के विनाश के परिणामस्वरूप मंझोले किसान सोवियत सत्ता के पक्ष में मुड़ने लगे। कुछ क्षेत्रों में श्वेत रक्षकों के अधिनायकत्व का स्वाद चखने के बाद मंझोले किसान समझ गये कि प्रतिक्रांति की विजय पूंजीपतियों और ज़मींदारों की सत्ता बहाल करेगी। अपने अनुभव से मंझोले किसान जान गये कि सोवियत सत्ता उन्हें ज़मीन देने के बाद किसानों को ज़मीन से वंचित करने तथा पुरानी व्यवस्था क़ायम करने के प्रतिक्रांतिकारियों के प्रयासों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। अतः मंझोले किसान सोवियत सत्ता के सक्रिय समर्थक बन गये।

इस अवधि में इस मोड़ को मज़बूत करने और मंझोले किसानों को "तटस्थ करने" की नीति से उनके साथ सुदृढ़ सहबंध बनाने को लेनिन ने पार्टी और सोवियत सत्ता का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार माना। नवंबर १९१८ में उन्होंने 'पितिरीम सोरोकिन की मूल्यवान स्वीकारोक्तियां' शीर्षक लेख में लिखा: "मंझोले किसान के साथ समझौता कर पाना – परंतु एक क्षण के लिए भी कुलक के विरुद्ध संघर्ष का परित्याग न करना और केवल ग़रीब किसानों का ही मज़बूती से सहारा लेना – यह है मौजूदा घड़ी का कार्यभार, इसलिए कि ऊपर चर्चित कारणों से मंझोले किसानों का ठीक अब हमारी ओर पलटाव अवश्यंभावी है।"*

ग्रामीण आबादी का बड़ा भाग बनानेवाले मंझोले किसानों के साथ सुदृढ़ सहबंध क़ायम करने की नीति मार्च १९१९ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की आठवीं कांग्रेस के निर्णय में अंतिम रूप से पुष्ट की गयी। इस नीति को अमली जामा पहना करके कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार मंझोले किसानों के ढुलमुलपन पर क़ाबू पा सकीं तथा मज़दूर वर्ग और मेहनतकश किसानों का सुदृढ़ सैनिक-

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'पितिरीम सोरोकिन की मूल्यवान स्वीकारोक्तियां', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ८, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८४, पृ० ७२।

राजनीतिक सहबंध क़ायम कर सकीं, जो हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति के ख़िलाफ़ संघर्ष में एक प्रबल राजनीतिक शक्ति बन गया।

रूसी संघ और अन्य सोवियत जनतंत्रों के बीच सैनिक-राजनीतिक सहबंध की स्थापना देश की रक्षा-क्षमता को मज़बूत बनानेवाली एक महत्वपूर्ण घटना बन गयी।*

चूंकि सोवियत सत्ता पर क्रांतिकारी उपलब्धियों के खोने का ख़तरा मंडराने लगा था, इसलिए सोवियत जनतंत्रों में हस्तक्षेपकारियों और श्वेत रक्षकों के ख़िलाफ़ संघर्ष में अपनी शक्तियों को एकजुट करने की इच्छा सबल हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पहल का समर्थन किया और लेनिन के प्रस्ताव पर केंद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन ने ४ मई, १९१९ को "रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण समाजवादी जनतंत्रों की सशस्त्र सेनाओं की एक कमान संबंधी" प्रश्न पर विचार किया। स्वीकृत 'सैनिक सहबंध के निदेश के प्रारूप' में सशस्त्र सेनाओं की एक कमान क़ायम करने, सोवियत जनतंत्रों की सभी शक्तियों और संसाधनों के उपयोग में कड़ा से कड़ा केंद्रीयकरण करने, युद्ध के दौरान लाल सेना को साज़-सामान की सप्लाई और रेलमार्गों के जाल के संचालन को एकीकृत करने की व्यवस्था थी। सभी सोवियत जनतंत्रों के सर्वोच्च निकायों ने रूसी संघ की सरकार की आज्ञप्ति 'विश्व साम्राज्यवाद से संघर्ष के लिए रूस, उक्राइना, लाटविया, लिथुआनिया और बेलोरूस सोवियत जनतंत्रों के एकीकरण पर' का सर्वसम्मति से समर्थन किया।

अब तक सोवियत जनतंत्रों में स्वतंत्र रूप से गठित सशस्त्र सेनाओं

---

* उक्राइनी सोवियत समाजवादी जनतंत्र की घोषणा १२ दिसंबर, १९१७ को की गयी।

१७ दिसंबर, १९१८ को स्थापित लाटवियाई सोवियत समाजवादी जनतंत्र जनवरी १९२० तक बना रहा। सोवियत सत्ता वहां १९४० में जाकर ही बहाल की जा सकी।

१६ दिसंबर, १९१८ को घोषित लिथुआनियाई सोवियत समाजवादी जनतंत्र अगस्त १९१९ तक बना रहा। सोवियत सत्ता वहां १९४० में ही बहाल की जा सकी।

बेलोरूसी सोवियत समाजवादी जनतंत्र की स्थापना १ जनवरी, १९१९ को हुई। – सं०

को लाल सेना में एक कमान के अंतर्गत मिला दिया गया। इसी तरह भौतिक और श्रम संसाधनों का भी एकीकरण किया गया।

हस्तक्षेपकारियों और श्वेत रक्षकों के ख़िलाफ़ सशस्त्र संघर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए बनाये गये सोवियत जनतंत्रों के सैनिक सहबंध ने देश की सभी सैनिक-आर्थिक ताक़तों के संकेंद्रण को सुविधाजनक बनाया और युद्ध की अंतिम विजय का एक प्रमुख कारण बना। यह सहबंध जनगण का स्वैच्छिक और समानाधिकारपूर्ण सहबंध – सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ – क़ायम करने के मार्ग पर पहला क़दम भी था।

देश के एक सैनिक शिविर में रूपांतरण के आर्थिक क़दम

देश को एक सैनिक शिविर में बदलने के कार्यभार ने बोल्शेविक पार्टी को अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन लाने के लिए विवश कर दिया, जिसके मार्गदर्शक सिद्धांत लेनिन ने १९१८ के वसंत में ही अपने लेख 'सोवियत सत्ता के तात्कालिक कार्यभार' में निर्धारित कर दिये थे।

हस्तक्षेपकारियों के हमले और श्वेत रक्षकों के साथ मिलकर उनके द्वारा देश के खाद्य, ईंधन और कच्चे मालों के मुख्य क्षेत्रों पर क़ब्ज़े ने सोवियत जनतंत्र को अत्यंत कठिन आर्थिक स्थिति में डाल दिया था और वह विश्व पूंजी द्वारा घिरा हुआ एक दुर्ग बन गया था। अतः सोवियत सरकार के समक्ष यह सवाल पेश हुआ कि विद्यमान परिस्थितियों में सशस्त्र सेनाओं को अस्त्रों, गोले-बारूदों, वर्दियों और खाद्य-सामग्रियों की सप्लाई कैसे की जाये तथा हथियार बनानेवाले कारख़ानों, परिवहन और ईंधन उद्योग के अबाध काम को कैसे सुनिश्चित बनाया जाये।

लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी और सोवियत सरकार ने विभिन्न आर्थिक क़दम तैयार किये, जिन्होंने आगे चलकर "युद्धकालीन कम्युनिज़्म" का नाम पाया। ये क़दम १९१८ की गर्मी से १९१९ के वसंत तक लगभग एक साल की अवधि में शनैः शनैः लागू किये गये। "युद्धकालीन कम्युनिज़्म" नीति के निम्नांकित मुख्य अंग थे: १) बड़े और मध्यम उद्योगों तथा अधिकांश लघु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण; २) कृषि-उपजों की नियत वसूली की शुरूआत जिसने किसानों को

अपनी फ़ालतू कृषि-उपजों को राज्य को निर्धारित क़ीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। लेनिन द्वारा प्रतिपादित वर्ग सिद्धांत का पालन किया गया था : ग़रीब किसानों से कुछ नहीं लिया जाता था, मंझोले किसानों से मामूली राशियां और धनी किसानों से बड़ी राशियां ली जाती थीं ; ३) अनाज और अन्य अत्यावश्यक चीज़ों के व्यापार में राजकीय इजारेदारी का कड़ा पालन ; ४) "जो काम नहीं करेगा, वह खायेगा भी नहीं" नारे के अंतर्गत समूची वयस्क आबादी के लिए अनिवार्य श्रम का कार्यान्वयन।

"युद्धकालीन कम्युनिज़्म" नीति समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप से नहीं निकली थी। लेकिन विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध, आर्थिक तबाही और भुखमरी की परिस्थितियों में यही एकमात्र सही नीति थी, क्योंकि उसने देश में अत्यंत कम मात्रा में उपलब्ध भौतिक संसाधनों को जुटाना और युक्तिसंगत ढंग से इस्तेमाल करना तथा मोर्चे और चंदावल के बीच उन्हें सही ढंग से वितरित करना संभव बनाया।

लेनिन ने मेंशेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों का पर्दाफ़ाश किया, जो "युद्धकालीन कम्युनिज़्म" नीति लागू करने के लिए बोल्शेविकों की भर्त्सना कर रहे थे, और साबित किया कि बोल्शेविकों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही लेनिन ने उसके असाधारण और अस्थायी स्वरूप पर ज़ोर दिया।

पार्टी द्वारा उठाये गये क़दमों और मज़दूर वर्ग के असाधारण श्रम की वजह से शस्त्रास्त्रों, गोले-बारूदों और साज़-सामानों का उत्पादन बढ़ गया।

गृहयुद्ध, घेरेबंदी और हस्तक्षेप के दौरान खाद्य-समस्या एक ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या थी, जिस पर सैनिक, आर्थिक और अन्य समस्याओं का हल निर्भर करता था।

हस्तक्षेपकारियों के हमले और उनके द्वारा अनाज पैदा करनेवाले क्षेत्रों (उक्राइना, दोन, कुबान, साइबेरिया) पर क़ब्ज़े की वजह से असाधारण रूप से कठिन खाद्य-स्थिति उत्पन्न हो गयी। नगरों में रोटी की सप्लाई महीने प्रति महीने कम होती जा रही थी। देश में भयंकर भुखमरी व्याप्त हो गयी। १९१८ की गर्मी में खाद्य-स्थिति अत्यंत विकट बन गयी।

भुखमरी का सर्वप्रथम कारण यह था कि कुलक अनाज की जमाखो-

री कर रहे थे, पर सोवियत राज्य को निर्धारित क़ीमतों पर बेचने से इन्कार कर रहे थे। प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने भुखमरी पर सोवियत जनगण का मनोबल गिराने तथा क्रांति का गला घोंटने के एक साधन के रूप में बड़ी आशाएं लगा रखी थीं। अतः अनाज के लिए संघर्ष समाजवाद के लिए संघर्ष से जुड़ गया। लेनिन ने स्पष्ट किया कि यह "समाजवाद के लिए ऐसी लड़ाई है, जिसके लिए सारी शक्ति, सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है"।* इस लड़ाई को अनाज व्यापार में राजकीय इजारेदारी के कड़े पालन, हुक्मी वसूली के तहत किसानों से फ़ालतू अनाजों की ख़रीद के द्वारा ही जीता जा सकता था। और पार्टी ने बेहिचक इस मार्ग को चुना। मई १९१८ के प्रारंभ में 'खाद्य-सामग्रियों के जन कमिसार को अनाज की जमाख़ोरी और सट्टेबाज़ी करनेवाले ग्रामीण बुर्जुआ वर्ग से संघर्ष के लिए असाधारण अधिकार देने पर' आज्ञप्ति स्वीकार की गयी। इस आज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक अनाज मालिक को आगामी बुआई के लिए बीज-राशि और नयी फ़सल कटने तक परिवार के पोषण के लिए ज़रूरी राशि को छोड़कर सारा अनाज राज्य को दे देना था। फ़ालतू अनाज छिपानेवालों को जनता का दुश्मन घोषित किया गया और उन पर क्रांतिकारी अदालतों में मुक़दमे चलाये जाने थे।

पार्टी ने अग्रणी मज़दूरों को अनाज के सट्टेबाज़ों, कुलकों, तोड़-फोड़ करनेवालों, घूसख़ोरों, आबादी को अनाज की सप्लाई संबंधी कड़े राजकीय नियमों का उल्लंघन करनेवालों के ख़िलाफ़ विशाल जन-अभियान चलाने का आह्वान किया।

पार्टी के इस आह्वान पर मज़दूरों ने "अनाज दस्तों" का गठन किया। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में ये दस्ते अनाज सप्लाई में हाथ बंटाने और कुलकों के विरुद्ध संघर्ष में ग़रीब किसानों की सहायता करने हेतु देहातों में गये। इन दस्तों में पेत्रोग्राद, मास्को, इवानोवो-वोज़्नेसेन्स्क, निज़्नी नोवगोरोद, तूला और यारोस्लाव्ल जैसे औद्योगिक केंद्रों के

---

* व्ला० इ० लेनिन, अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, मज़दूरों, किसानों और लाल सेना के प्रतिनिधियों की मास्को सोवियत और ट्रेड-यूनियनों का संयुक्त अधिवेशन, ४ जून, १९१८।

तपे-तपाये, ईमानदार, राजनीतिक रूप से सचेत, संगठन के अनुभवी मज़दूर शामिल थे।

ग़रीब किसानों की समितियों ने भी अनाज और देहातों में सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए संघर्ष में बड़ी भूमिका अदा की। "अनाज दस्तों" के साथ उन्होंने कुलकों के मनमानेपन को दृढ़तापूर्वक रोक दिया, उनके विद्रोहों को दबाने में हिस्सा लिया, सत्ता के स्थानीय अवयवों से उन तत्वों का सफ़ाया कर दिया, जो उनमें धोखा-धड़ी से घुस आये थे, और औद्योगिक केंद्रों तथा लाल सेना को खाद्य-सप्लाई को सुनिश्चित बनाया।

खाद्य समस्या के हल में प्रस्तुत सभी कठिनाइयों के बावजूद पार्टी मज़दूरों, श्रमिक किसानों तथा खेतिहर मज़दूरों के समर्थन से फ़ालतू अनाज जमा करने और उसका ठीक वितरण करने में सफल रही।

अनाज के लिए, मेहनतकश किसानों के व्यापक संस्तरों के एकीकरण और प्रतिक्रांतिकारी कुलकों के दमन के लिए संघर्ष समाजवादी पितृभूमि की रक्षा संगठित करने हेतु पार्टी के कार्यकलाप का एक अविच्छेद्य अंग बन गया।

जनता की नैतिक-राजनीतिक शक्ति का प्रबलन

कम्युनिस्ट पार्टी ने देश को एक सैनिक शिविर में बदलने के लिए जनता के बीच एक व्यापक विचारधारात्मक और राजनीतिक अभियान शुरू किया। पार्टी ने नगरीय और ग्रामीण मेहनतकशों के व्यापक संस्तरों को युद्ध का न्यायसंगत स्वरूप समझाया, जिसे चलाने को सोवियत राज्य विवश था, उन्हें अपना कार्यक्रम और नीति स्पष्ट की, विदेशी हस्तक्षेपकारियों और श्वेत रक्षकों के उद्देश्यों का पर्दाफ़ाश किया और इस प्रकार शत्रु की पराजय के लिए जनगण और उनकी सेना के नैतिक बल को प्रोत्साहित किया।

पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इस प्रचार-अभियान में सक्रिय ढंग से भाग लिया, अपने उदाहरणों से उन्होंने कम्युनिस्टों को युद्धकालीन परिस्थितियों में प्रचार की कला सिखायी। स्वयं लेनिन अक्सर सभाओं, जुलूसों, कांग्रेसों और सम्मेलनों में बोलते थे। गृहयुद्ध की अत्यंत कठिन अवधि

में वह दिन में दो-तीन भाषण करते थे। १६१८-१६२० में, अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने जन-सभाओं में २१६ भाषण किये।

लेनिन ने बड़े ही विश्वासप्रद, सुस्पष्ट और बोधगम्य ढंग से कम्युनिस्टों, मज़दूरों, किसानों और लाल सैनिकों को आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय और सैनिक स्थितियां समझायीं, सोवियत सत्ता की शक्ति और अविजेयता के स्रोत प्रकट किये, देश और पार्टी के समक्ष प्रस्तुत कार्यभारों की तस्वीर पेश की तथा मोर्चे पर वीरतापूर्ण पराक्रम और चंदावल में आत्मत्यागपूर्ण श्रम के लिए जनता को प्रेरित किया।

अख़बारों ने श्रमिकों की राजनीतिक शिक्षा तथा समाजवादी पितृभूमि की रक्षा में समस्त जनगण को लामबंद करने में बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने मेहनतकशों को शत्रु से संघर्ष करने के लिए, आर्थिक और सैनिक कार्यभारों को हल करने के लिए प्रेरित करने में पार्टी की मदद की।

"प्रचार-ट्रेनें" व्यापक प्रचार अभियानों का, ख़ास तौर से मोर्चों पर, एक नया और कारगर रूप बन गयीं। इन "प्रचार-ट्रेनों" में, आम तौर से, राजनीतिक कर्मी, लेखक, कलाकार, शौक़िया कलाकार तथा अन्य सांस्कृतिक कर्मी शामिल होते थे, जो न केवल व्याख्यान देते और नाट्य प्रस्तुतियां पेश करते थे, बल्कि अपने श्रोताओं के ज्वलंत से ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर भी देते थे।

व्यापक प्रचार-अभियान ने, जो अपने उच्च विचारधारात्मक मानकों, ज्वलंत प्रासंगिकता, सच्चाई, सुस्पष्टता और सरलता के लिए विशिष्ट था, मज़दूरों और सभी मेहनतकशों को सोवियत जनतंत्र की रक्षा के लिए प्रेरित किया।

देश को एक सैनिक शिविर में बदलने के कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के कार्य के ये कुछ मूल पहलू थे।

३. सैनिक क्षेत्र में संगठनात्मक कार्य

समाजवादी राज्य की सशस्त्र सेनाओं का गठन

नये सैनिक संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद और आंतरिक प्रतिक्रांति की संयुक्त शक्तियों से सोवियत जनतंत्र की रक्षा करने की एक निर्णायक शर्त थी।

यदि मज़दूर वर्ग द्वारा सत्ता पर क़ब्ज़ा करने के लिए लाल रक्षकों, क्रांतिकारी सैनिकों और नाविकों की टुकड़ियां पर्याप्त थीं, तो वे बाहरी शत्रुओं से सर्वहारा राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थीं। दरअसल नये प्रकार के सैनिक संगठन की आवश्यकता थी और समाजवादी क्रांति का भाग्य इसकी स्थापना पर ही निर्भर करता था।

'सर्वहारा क्रांति और ग़द्दार काउत्स्की' लेख में लेनिन ने मार्क्स और एंगेल्स की अनेकानेक प्रस्थापनाओं का हवाला देते हुए लिखा कि सर्वहारा क्रांति का पहला काम पुरानी सशस्त्र सेनाओं को भंग करना और उनके स्थान पर नयी सेना क़ायम करना होना चाहिए। "प्रभुत्व-शाली होता जाता नया सामाजिक वर्ग पुरानी सेना को पूर्णतः विघटित करने के अलावा ..., किसी भी सेना के बिना सबसे ज़्यादा कठिन तथा पीड़ादायी अवधि से गुज़रने के अलावा ... कठोर गृहयुद्ध के दौरान धीरे-धीरे नयी सेना, नया अनुशासन, नये वर्ग का नया सैनिक संगठन निर्मित करने के अलावा और किसी भी तरह इस प्रभुत्व को न तो कभी हासिल और सुदृढ़ कर सकता था और न अब कर सकता है।"*

समाजवादी राज्य की सेना का गठन एक पेचीदा और कठिन काम था, सर्वोपरि इस वजह से कि व्यावहारिक रूप से इतिहास में पहली बार इसका निर्माण किया जा रहा था। ये कठिनाइयां इस वजह से और भी बढ़ गयीं कि सेना का गठन विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के दौरान किया जा रहा था। नवोदित सोवियत राज्य को आर्थिक बर्बादी, परिवहन दुर्व्यवस्था और घोर खाद्य-संकट की परिस्थि-तियों में अपनी सशस्त्र सेनाओं को गठित, सशस्त्र और प्रशिक्षित करने के लिए अपने सभी संसाधनों को लगा देना पड़ा।

लाल सेना का गठन तीव्र वर्ग संघर्ष के दौरान हुआ। साथ ही पार्टी को पार्टी-विरोधी तत्वों – "वामपंथी कम्युनिस्टों", "सैन्य विपक्ष" और त्रोत्स्कीवादियों – के प्रतिरोध पर भी क़ाबू पाना पड़ा, जो पार्टी की सैन्य नीति को तोड़ने-मरोड़ने और उसके कार्यान्वयन में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे। मज़दूरों और मेहनतकश किसानों के

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'सर्वहारा क्रांति और ग़द्दार काउत्स्की', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ८, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८४, पृ० १४६।

क्रांतिकारी उत्साह तथा पहल पर भरोसा करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने इन कठिनाइयों पर क़ाबू पा लिया। युद्ध की आग में उसने लाल सेना का गठन किया, उसे इस्पाती बनाया।

लेनिन ने अपने को नयी सेना के गठन के सैद्धांतिक पहलुओं के विशदीकरण तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसके संगठनात्मक कार्य में सक्रिय भाग भी लिया। लेनिन के तत्वावधान में सशस्त्र सेनाओं के निर्माण और केंद्रीय और स्थानीय कमान के अवयवों की संरचना की व्यावहारिक योजना तैयार की गयी।

१५ जनवरी, १६१८ को लेनिन की अध्यक्षता में जन कमिसार परिषद ने मज़दूरों और किसानों की लाल सेना के संगठन पर एक आज्ञप्ति स्वीकार की। २६ जनवरी, १६१८ को लेनिन ने लाल नौसेना के गठन पर आज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये।

लाल सेना और नौसेना के गठन में लेनिन द्वारा विशदीकृत सोवियत सशस्त्र सेनाओं के निर्माण के सिद्धांतों का बड़ा महत्व था। इन सिद्धांतों को सामाजिक, राजनीतिक, संगठनात्मक तथा शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है।

लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी केंद्रीय समिति के नेतृत्व को समाजवादी सशस्त्र सेनाओं के गठन के मुख्य और निर्णायक सामाजिक-राजनीतिक सिद्धांत के रूप में, उनके जीवन, सैन्य कार्यकलाप तथा उनकी अविजेयता के अनिवार्य तत्व के रूप में मानते थे। यह बात कि सशस्त्र सेनाएं कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में क्रियाशील हैं, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सोवियत समाज में अदा की गयी नेतृत्वकारी भूमिका की ही वस्तुगत नियमितता है। लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टी ने बुर्जुआ सिद्धांतकारों के सशस्त्र सेनाओं के वर्गहीन और वर्गेतर स्वरूप के बारे में झूठे दावों का अनम्य रूप से पर्दाफ़ाश किया और सर्वहारा राज्य की सशस्त्र सेनाओं पर पार्टी के नेतृत्व की खुली घोषणा की। सशस्त्र सेनाओं पर पार्टी के नियंत्रण में ढिलाई से वे दुस्साहसवादी और बोनापार्तवादी तत्वों का अस्त्र बन जा सकती हैं।

सोवियत सैनिक गठन के सामाजिक-राजनीतिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए लेनिन ने लाल सेना के वर्गगत स्वरूप तथा ऐतिहासिक मिशन का व्यापक विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि वह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का प्रमुखतम अवयव और समाजवादी पितृभूमि

की रक्षा का मुख्य अस्त्र है। उन्होंने लाल सेना के जन-स्वरूप पर ख़ास तौर से ज़ोर दिया, जो न केवल उसकी संरचना में, बल्कि उसके उद्देश्यों में, उसके जीवन की आंतरिक पद्धति में तथा समस्त मेहनतकशों के साथ उसके अटूट संबंध में व्यक्त होता है।

पार्टी और सोवियत सरकार ने लाल सेना के गठन के वर्गगत सिद्धांतों के उल्लंघन तथा उसकी पांतों में वर्ग शत्रुओं की घुसपैठ के प्रयासों का दृढ़तापूर्वक सामना किया।

लाल सेना के गठन का दूसरा सामाजिक-राजनीतिक सिद्धांत सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद था। लेनिन ने सिखाया कि रूस की परिस्थितियों में, जहां बहुत-सी जातियां और उपजातियां रहती हैं, लाल सेना का गठन बहुजातीय सेना के रूप में, जनगण के बीच बिरादराना दोस्ती की सेना, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना से ओत-प्रोत सेना के रूप में होना चाहिए। सोवियत रूस में बसनेवाली सभी जातियों और उपजातियों के लोग लाल सेना में भर्ती किये गये।

विदेशी हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति के ख़िलाफ़ संघर्ष में लाल सेना का अंतर्राष्ट्रीयतावादी स्वरूप इस चीज में भी प्रकट हुआ कि हंगरियाइयों, पोलों, चेकों, स्लोवाकों, सर्बियाइयों, बुल्गा-रियाइयों, कोरियाइयों, चीनियों, फ़िन्नों, जर्मनों, आदि से बनी बहुत-सी अंतर्राष्ट्रीय रेजिमेंटें और सैनिक टुकड़ियां भी उसकी पांतों में लड़ रही थीं।

लेनिन की ऐतिहासिक सेवा इस बात में है कि उन्होंने समाजवादी राज्य की सैनिक रक्षा के कार्यभारों के अनुरूप सशस्त्र सेनाओं के संगठ-नात्मक सिद्धांतों को तैयार किया। उन्होंने विश्वासप्रद ढंग से दिखाया कि स्थायी सेना के स्थान पर संपूर्ण जनता को सशस्त्र करने तथा जन मिलिशिया क़ायम करने संबंधी सामाजिक-जनवादियों की मांगों को ऐतिहासिक स्थिति की विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना अमूर्त ढंग से नहीं देखना चाहिए। बुर्जुआ समाज की परिस्थितियों में बुर्जुआ-जनवा-दी क्रांति के दौरान यह क़दम सेना का जनवादीकरण करने, सैनिकों को बैरकों के कठोर जीवन से मुक्त कराने और सेना को क्रांति के पक्ष में लाने में सहायता करता है।

उन परिस्थितियों में जब सोवियत राज्य के ख़िलाफ़ साम्राज्यवादी सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियां झोंक दी गयीं, मजदूरों और किसानों

की नियमित सेना की सुप्रशिक्षित टुकड़ियां ही क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा कर सकती थीं।

लेनिन पहले मार्क्सवादी थे, जिन्होंने मज़दूरों और किसानों की नियमित सेना की स्थापना की आवश्यकता सिद्ध की। उन्होंने सिद्ध किया कि एक केंद्रीयकृत कमान के अंतर्गत अनुशासनबद्ध, नियमित जन सेना ही सोवियत जनतंत्र की रक्षा कर सकती है। यह सशस्त्र सेनाओं पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विकास में एक साहसी क़दम था।

जहां तक लाल सेना की पांतों में शिक्षा और प्रशिक्षण का संबंध है, लेनिन ने माना कि मुख्य ज़ोर गहन विचारधारात्मक विश्वास, कम्युनिज़्म के ध्येय के प्रति निष्ठा, देश-प्रेम और उच्च नैतिक तथा जुझारू गुणों पर देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सैनिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रणाली सोवियत मातृभूमि के सुदक्ष और साहसी रक्षक, सोवियत जनगण की क्रांतिकारी और जुझारू परंपराओं के योग्य उत्तराधिकारी तैयार करने के लिए बनायी गयी है।

सैन्य गठन के लेनिनीय सिद्धांतों के आधार पर सोवियत राज्य ने सबल सेना का निर्माण किया, जिसने हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया।

शुरू में लाल सेना स्वयंसेवकों से बनी थी और १६१८ की गर्मी तक उसमें पांच लाख सैनिक थे। यह धनी ज़मींदारों और बुर्जुआ वर्ग के प्रतिरोध के दमन के लिए काफ़ी था। लेकिन विदेशी हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति की सुप्रशिक्षित बड़ी सेनाओं के ख़िलाफ़ लंबा युद्ध चलाने के लिए नियमित सेना की आवश्यकता थी। अतः १६१८ की गर्मी में सोवियत सरकार ने अनिवार्य भर्ती लागू करने का निर्णय स्वीकार किया। गृहयुद्ध (१६१८-१६२०) के अंत तक लाल सेना में ५० लाख सैनिक थे।

कमांडरों का प्रशिक्षण लाल सेना के निर्माण में एक जटिल समस्या थी। कम्युनिस्ट पार्टी की पांतों में बहुत थोड़े-से कम्युनिस्ट कमांडर थे और राजनीतिक रूप से विश्वसनीय तथा सुप्रशिक्षित कमांडरों के बिना एक नयी सेना का गठन करना असंभव था। इस पेचीदा कार्य को सोवियत राज्य ने निम्नांकित तीन विधियों से हल किया: पहले, कमांडर के पदों पर सैन्य अनुभव प्राप्त कम्युनिस्टों (सैनिकों और नौसैनिकों) को नियुक्त करके; दूसरे, मज़दूरों और किसानों को विशेष

कोर्सों और अफ़सर स्कूलों में प्रशिक्षित करके ; तीसरे, ज़ारशाही सेना के भूतपूर्व अफ़सरों और जनरलों को काम में ला करके।

गृहयुद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी की पांतों से, जनता से वसीली ब्लूख़ेर, सेम्योन बुदेन्नी, क्लिमेंत वोरोशीलोव, ओका गोरोदोविकोव, ग्रिगोरी कोतोव्स्की और वसीली चपायेव जैसे वीर कमांडर निकले।

अगर कमांडरों को प्रशिक्षित करने की उपर्युक्त दो विधियां स्वतः स्पष्ट थीं, तो तीसरी विधि सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों ही दृष्टियों से बड़ी दिलचस्पी की है, क्योंकि उसने नये समाज के निर्माण के प्रति लेनिन के साहसी रचनात्मक दृष्टिकोण को प्रकट किया। उन्होंने सिखाया कि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान रखनेवाले बुर्जुआ बुद्धिजीवियों, सैनिक विशेषज्ञों सहित, की सेवाओं का उपयोग किये बिना नये समाज और नयी सेना का निर्माण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा: "आप जानते हैं कि युद्ध-विज्ञान एकबारगी नहीं सीखा जा सकता। आप यह भी जानते हैं कि ज़ारशाही सेना से बचे अफ़सर – कर्नल और जनरल – ही युद्ध-विज्ञान जानते हैं... भूतपूर्व अफ़सरों से कमांडरों को चुनना आवश्यक हो गया था, ताकि मज़दूर और किसान उनसे सीख सकें, क्योंकि विज्ञान के बिना एक आधुनिक सेना का निर्माण नहीं किया जा सकता ..."* ज़ारशाही सेना के कोई ५० हज़ार सैन्य विशेषज्ञों को लाल सेना में भर्ती किया गया। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिक प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सकों और जूनियर चिकित्सीय कर्मियों से लगभग इतने ही विशेषज्ञों को लाल सेना में लामबंद किया गया। उन्होंने कमांडर के पदों पर, मुख्यालयों में और सैनिक अकादमियों में प्राध्यापकों के रूप में काम किया। उनमें से बहुतों ने ईमानदारी से लाल सेना को अपना ज्ञान दिया, जिसने सोवियत मातृभूमि और जनगण के हितों की रक्षा की। उनमें अलेक्सांद्र येगोरोव, सेर्गेई कामेनेव, दि्मत्री कार्बिशेव, पावेल लेबेदेव, अलेक्सांद्र सामोइलो, मिख़ाईल तुख़ाचेव्स्की और बोरीस शापोश्निकोव शामिल थे।

भूतपूर्व अफ़सरों को बड़े पैमाने पर लाल सेना में खींचने और उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध

---

* व्ला० इ० लेनिन, मेहनतकश कज़्ज़ाकों की पहली अखिल रूसी कांग्रेस को रिपोर्ट, १९२०।

में १९१८ के वसंत में केंद्रीय समिति और जन कमिसार परिषद ने सेना और नौसेना में सैनिक कमिसार नियुक्त करने शुरू किये।

सैनिक कमिसार सेना में पार्टी और सोवियत सत्ता के प्रतिनिधि होते थे। वे समाजवाद के लिए संघर्ष में पार्टी भावना, पार्टी अनुशासन और पार्टी दृढ़ता और साहस के वाहक थे।

सैनिक कमिसार लाल सेना में लाये गये ज़ारशाही के भूतपूर्व सैन्य विशेषज्ञों, अफ़सरों और जनरलों के कार्यकलापों पर राजनीतिक नियंत्रण रखते थे। उन्होंने सेना की पांतों में बड़ा संगठनात्मक और राजनीतिक-शैक्षिक कार्य चलाया, सेना के संचालन में क्रांतिकारी विधियां लागू कीं। वे हमेशा सैनिकों के साथ रहते और लड़ाई में पहली क़तारों में जाते थे। केवल निष्कलंक क्रांतिकारियों को ही सैनिक कमिसार के पद पर नियुक्त किया जाता था।

हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति के विरुद्ध जनगण का संघर्ष संगठित करने के अपने ऐतिहासिक उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पांतों का पुनर्निर्माण किया। उसने अपनी मूल शक्तियों को मोर्चे पर भेजा, राजकीय और आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपने प्रभाव को मज़बूत बनाया। विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के अंत तक लाल सेना में ३ लाख कम्युनिस्ट थे। इसका अर्थ यह था कि पार्टी के आधे से अधिक सदस्य हाथों में हथियार लेकर समाजवादी पितृभूमि की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने लाल सेना की पांतों को मज़बूती से जोड़ा, वे अत्यंत लगनशील तथा साहसी सैनिक थे और इस तरह उन्होंने महान लेनिनीय पार्टी के अविजेय विचारधारात्मक विश्वास और वीरता को साकार किया। ५० हज़ार से अधिक कम्युनिस्टों ने जनगण की स्वतंत्रता और ख़ुशहाली के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के वर्षों में युवा कम्युनिस्ट लीग (कोम्सोमोल) ने ७० हज़ार जवानों को लाल सेना में भेजा। युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने के लिए युवा कम्युनिस्ट लीग को 'लाल झंडे के पदक' से विभूषित किया गया।

लड़ाई में सेनाओं का नेतृत्व

विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के वर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार का एक मुख्य कार्य था सैनिक कार्रवाइयों का

नेतृत्व। कठोर संघर्ष की संपूर्ण अवधि में लेनिन के नेतृत्व में पार्टी की केंद्रीय समिति सच्चा सैनिक मुख्यालय थी, जिसने सभी महत्वपूर्ण युद्धकालीन प्रश्नों, सबसे पहले रणनीतिक नेतृत्व के प्रश्नों को हल किया जो निम्नलिखित थे: १) युद्ध के दौरान सैनिक कार्रवाइयों और उसके प्रत्येक अभियान की योजना बनाना; २) मुख्य प्रहार की दिशा निर्धारित करना; ३) शत्रु-शिविर में अंतर्विरोधों और टकरावों का उपयोग।

सोवियत जनतंत्र के एक सैनिक शिविर में रूपांतरण और शत्रु की पराजय के लिए देश की शक्तियों और संसाधनों की लामबंदी के परिणामस्वरूप १९१८ की गर्मी तक मुख्य क्षेत्रों में हस्तक्षेपकारियों और श्वेत रक्षकों के ख़िलाफ़ सबल प्रतिरोध संगठित करना संभव हो गया था और उसी वर्ष की शरत् तक वोल्गा क्षेत्र में प्रत्याक्रमण करके शत्रु की मुख्य शक्तियों का नष्ट कर दिया गया।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, १९१८ की गर्मी में पूर्वी मोर्चा सोवियत जनतंत्र का मुख्य रणक्षेत्र था। कोल्चाक* की कमान में हस्तक्षेपकारियों और प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों ने वोल्गा क्षेत्र, उराल और साइबेरिया के एक बड़े भाग पर क़ब्ज़ा कर लिया। वोल्गा क्षेत्र में कई नगरों पर क़ब्ज़ा करने के बाद हस्तक्षेपकारियों और श्वेत रक्षकों को हस्तक्षेपकारी सेनाओं से मिलने हेतु उत्तर और निज्नी नोवगोरोद की ओर बढ़ने का मौक़ा मिल गया, जहां से उनके लिए मास्को का रास्ता खुल जाता था। इन परिस्थितियों में वोल्गा क्षेत्र और उराल में लड़ाइयों का सोवियत देश के लिए निर्णायक महत्व था।

विद्यमान परिस्थितियों में पूर्वी मोर्चे को मज़बूत बनाना पार्टी का तात्कालिक कार्यभार बन गया। केंद्रीय समिति के प्रस्ताव के अनुसार सोवियत रूस के मध्य इलाक़ों के सभी बड़े पार्टी संगठनों ने अपने

---

*अ० व० कोल्चाक (१८७४–१९२०) – ज़ारशाही नौसेना के उप-एडमिरल, अक्तूबर १९१८ में साइबेरिया पहुंचे और विदेशी हस्तक्षेपकारियों के समर्थन से फ़ौजी तानाशाही क़ायम करके "रूसी राज्य के सर्वोच्च शासक" की उपाधि धारण की। उनकी सेना की पराजय के बाद इर्कूत्स्क क्रांतिकारी-सैनिक समिति के निर्णयानुसार उन्हें गोली मार दी गयी। – सं०

सदस्यों के २० प्रतिशत को पूर्वी मोर्चे पर भेजा जबकि वोल्गा क्षेत्र और उराल के पार्टी संगठनों ने अपने लगभग सभी सदस्यों को। प्रचार-कार्य चलाने और श्वेत रक्षकों के ख़िलाफ़ कड़े संघर्ष में सोवियत सेनाओं को एकजुट, अनुशासनबद्ध तथा प्रोत्साहित करने में समर्थ, अत्यंत सक्रिय और जुझारू पार्टी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले मोर्चे पर भेजा गया। अल्प अवधि में ही पूर्वी मोर्चे पर पांच आर्मियों और वोल्गा सैनिक बेड़े का निर्माण कर दिया गया, जिनमें १६१८ के अंत में लगभग २५ हज़ार कम्युनिस्ट थे।

सोवियत सेनाओं ने पूर्वी मोर्चे पर शत्रु के बढ़ाव को रोक दिया और सितम्बर में प्रत्याक्रमण शुरू करके कज़ान, लेनिन के जन्म-नगर सिम्बीर्स्क और समारा को हस्तक्षेपकारियों व श्वेत रक्षकों से मुक्त करा दिया। १६१८ के अंत तक सोवियत सेनाएं उराल की तलहटियों में पहुंच गयी थीं।

१६१८ की गर्मी और विशेष रूप से शरत् में सोवियत सेनाएं पूर्वी मोर्चे पर लड़ने के साथ-साथ रूस के दक्षिणी प्रदेशों – दोन नदी, निचली वोल्गा और उत्तरी काकेशिया के क्षेत्रों – में भी लड़ाई कर रही थीं। देनीकिन* के नेतृत्व में प्रतिक्रांतिकारियों ने जर्मनी तथा एंटेंट देशों के साम्राज्यवादियों के समर्थन से संपूर्ण वोल्गा क्षेत्र, उराल और दक्षिणी रूस पर क़ब्ज़ा करते हुए एक संयुक्त मोर्चा खोलने और देश के मध्यवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनायी। इस संबंध में दक्षिणी मोर्चे का महत्व और बढ़ गया।

केंद्रीय समिति के निर्देश पर मास्को, पेत्रोग्राद और कई मोर्चे के समीपवर्ती गुबेर्नियों के पार्टी संगठनों ने दक्षिणी मोर्चे के लिए, जो १६१८ के अंत में मुख्य मोर्चा बन गया था, कम्युनिस्टों की नयी व्यापक लामबंदी चलायी। इसके साथ ही उधर नयी सैनिक कुमकें

---

* आ० इ० देनीकिन (१८७२–१६४७) – ज़ारशाही फ़ौज के लेफ़्टिनेंट-जनरल, फ़रवरी क्रांति के बाद प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह में भाग लिया। अक्तूबर क्रांति के बाद प्रतिक्रांतिकारी सेना के एक संस्थापक। १६१८ की शरत् में एंटेंट के समर्थन से "दक्षिणी रूस की सशस्त्र सेनाओं" के प्रधान सेनाध्यक्ष बने। अपनी फ़ौजों की पराजय के बाद रूस से भाग गये। – सं०

भेजी गयीं। इसने दक्षिणी मोर्चे को काफ़ी मज़बूत बनाने और सेनाओं के बीच राजनीतिक तथा संगठनात्मक कार्य को बढ़ाने व सुधारने में सहायता की।

१६१६ के शुरू में सोवियत सेनाओं ने दक्षिणी मोर्चे पर प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिया, जो आगे चलकर सामान्य आक्रमण में विकसित हो गया और दोन क्षेत्र में समस्त श्वेत रक्षक सेना को पराजित कर दिया। दक्षिणी मोर्चे पर सोवियत सेनाओं की सफलता के कारणों का विश्लेषण करते हुए लेनिन ने लिखा:

"दोन क्षेत्र में हमारी विजयें मात्र लाल सेना की पांतों में पार्टी कार्यकलाप और सांस्कृतिक तथा शैक्षिक कार्य के तीव्रीकरण की बदौलत हुईं।—इसने एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ला दिया और फलस्वरूप हमारी लाल सेना ने हमारे लिए दोन क्षेत्र को जीत लिया।"* साथ ही लाल सेना ने दक्षिणी उक्राइना और वोल्गा क्षेत्र को भी मुक्त करा दिया।

१६१६ के वसंत तक सोवियत देश के भूभागों में हस्तक्षेपकारी और श्वेत रक्षक फ़ौजों में सैनिकों और अफ़सरों की संख्या दस लाख से अधिक हो गयी थी। मित्र-देशों की सेनाओं की सर्वोच्च कमान ने सभी सोवियत-विरोधी शक्तियों का समन्वित आक्रमण शुरू करके फ़ौजी हस्तक्षेप जारी रखने का निर्णय स्वीकार किया और सोवियत देश की सभी सीमाओं से मास्को की ओर सामान्य आक्रमण करने को आवश्यक माना।

इस निर्णय को अमल में लाते हुए मार्च १६१६ में अमरीका, ब्रिटेन, फ़्रांस और जापान के साम्राज्यवादियों द्वारा सुसज्जित चार लाख की सेना ने कोल्चाक की कमान में वोल्गा की ओर आगे बढ़ने और वहां मास्को पर संयुक्त प्रहार के लिए देनीकिन की फ़ौजों से मिलने के उद्देश्य से पूर्व से आक्रमण आरंभ कर दिया। उफ़ा के निकट सोवियत मोर्चे को भेदते हुए कोल्चाक की फ़ौज वोल्गा की ओर आगे बढ़ी और अप्रैल में वह कज़ान, सिम्बीर्स्क और समारा से केवल ८५–१०० किलोमीटर ही दूर रह गयी थी। १६१८ की गर्मी की भांति

---

* व्ला० इ० लेनिन, पेत्रोग्राद के लोक-भवन में एक सभा में दिया गया भाषण, १३ मार्च, १६१६।

ही पूर्वी मोर्चा पुनः मुख्य मोर्चा बन गया था, जहां क्रांति के भाग्य का फ़ैसला हो रहा था।

सोवियत जनतंत्र के लिए अग्नि-परीक्षा की इस घड़ी में लेनिन ने केंद्रीय समिति के आदेश पर 'पूर्वी मोर्चे की स्थिति पर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केंद्रीय समिति की थीसिसें' लिखीं, जिनमें सभी पार्टी संगठनों से कहा गया था:

११ अप्रैल, १९१९ को नौ केंद्रीय गुबेर्नियों में घोषित लामबंदी को चहुंमुखी और ज़ोरदार समर्थन प्रदान करने के लिए अपने समूचे प्रयास लगाना;

मोर्चे के समीपवर्ती क्षेत्रों में, ख़ास तौर से वोल्गा क्षेत्र में सभी ट्रेड-यूनियन सदस्यों के बीच हथियार बांटना;

लामबंद सैनिकों के बीच प्रचार को तेज़ करने के नये तरीक़ों का उपयोग करना;

नागरिक सेवाओं में मर्दों के स्थान पर स्त्रियों को रखना;

लामबंदी में मदद करने और सोवियत सेनाओं को शस्त्रास्त्रों, वस्त्रों, आदि की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय समितियां संगठित करना;

किसानों, ख़ास तौर से युवा किसानों को लाल सेना की पांतों में बड़े पैमाने पर खींचना।

केंद्रीय समिति ने सभी पार्टी, ट्रेड-यूनियन और सोवियत संगठनों का इन कार्यों को क्रांतिकारी उत्साह से अपने हाथ में लेने, अपनी सारी शक्ति लगाने, कोल्चाक की फ़ौज को हराने और वोल्गा, उराल तथा साइबेरिया की रक्षा करने और जीतने का आह्वान किया।

अप्रैल १९१९ में पार्टी की केंद्रीय समिति ने लाल सेना की संघर्षरत टुकड़ियों को सहायता प्रदान करने के लिए पार्टी सदस्यों को लामबंद करने का निर्णय लिया। अप्रैल-जून १९१९ की अवधि में एक लाख से अधिक योद्धाओं – कम्युनिस्टों, कोम्सोमोल सदस्यों और नियमित मज़दूरों – को पूर्वी मोर्चे पर भेजा गया। तब पार्टी ने अपने सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं को सशस्त्र सेनाओं में भेजा। नयी कुमकों, विशेषतः कम्युनिस्टों के आगमन ने मोर्चे की सेनाओं के स्वरूप को बदल दिया और उन्हें बड़ा मज़बूत बनाया। २८ अप्रैल, १९१९ को पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाओं ने छापामार टुकड़ियों के समर्थन से प्रत्याक्रमण

शुरू कर दिया और उसी वर्ष की शरत् तक उराल को मुक्त करा दिया तथा साइबेरिया के मैदानों में पहुंच गयीं।

२४ अगस्त, १९१९ को, जब कोल्चाक की "सिर पर पैर रखकर भागती फ़ौजों की कौंध ही" शेष रह गयी थी, लेनिन ने 'कोल्चाक पर विजय के विषय में मज़दूरों और किसानों को पत्र' लिखा। उसमें उन्होंने उन मूल सबक़ों को सूत्रित किया, जिन्हें कोल्चाक से संघर्ष के अनुभव से लिया जाना चाहिए था, ताकि देश के शत्रुओं को अंतिम रूप से पराजित किया जा सके और कोल्चाक की फ़ौजों द्वारा पैदा की गयी मुसीबतों की पुनरावृत्ति न होने दी जाये। सोवियत सैनिकों की बड़ी वीरता के बिना कोल्चाक की फ़ौजों को हराना असंभव होता।

मई १९१९ में, जब लाल सेना पूर्वी मोर्चे पर बड़ी सफलताएं हासिल कर रही थीं, जनरल युदेनिच* की कमान में प्रतिक्रांतिकारी फ़ौजों ने पेत्रोग्राद पर आक्रमण शुरू कर दिया। युदेनिच की स्थल सेनाओं को ब्रिटिश समुद्री बेड़े के ७० से अधिक युद्धपोतों ने समर्थन दिया। इस संबंध में केंद्रीय समिति ने 'पेत्रोग्राद की रक्षा पर' अपील जारी की, जिसमें कहा गया था कि सोवियत रूस अल्प से अल्प समय के लिए भी पेत्रोग्राद को शत्रु को नहीं दे सकता और कि उसकी किसी भी क़ीमत पर रक्षा की जानी चाहिए।

शत्रु पर तेज़ी से और मर्मांतक प्रहार करने के लिए पूरी शक्ति जुटा देने की आवश्यकता संबंधी लेनिन के निर्देश पर अमल करते हुए पेत्रोग्राद मोर्चे की सेनाओं ने अगस्त १९१९ के अंत तक युदेनिच की मुख्य शक्तियों को नष्ट कर दिया और अक्तूबर क्रांति के पालने – पेत्रोग्राद – को बचा लिया।

१९१९ की गर्मी में, जब सोवियत सेनाएं कोल्चाक के ख़िलाफ़ विजयी आक्रमण कर रही थीं, और युदेनिच की फ़ौजों को पेत्रोग्राद के निकट पराजित कर दिया गया था, हस्तक्षेपकारियों और श्वेत रक्षकों ने सोवियत देश पर एक नया आक्रमण शुरू कर दिया। सोवियत

---

* न० न० युदेनिच (१८६२–१९३३) – ज़ारशाही सेना के जनरल, १९१८ की शरत् में एंटेंट के समर्थन से एस्टोनिया में श्वेत रक्षक सेना का गठन किया। पेत्रोग्राद पर चढ़ाई में अपनी फ़ौजों की पराजय के बाद रूस से भाग गये। – सं०

रूस से बड़ी घृणा करनेवाले चर्चिल नें तब डींग मारते हुए कहा था कि सितम्बर में पेत्रोग्राद पर और दिसम्बर में मास्को पर क़ब्ज़ा कर लिया जायेगा।

देनीकिन पर मुख्य रूप से भरोसा करते हुए ब्रिटिश, फ़्रांसीसी और अमरीकी साम्राज्यवादियों ने उसकी सेना को बड़ी मात्रा में हथियार और गोले-बारूद सप्लाई किये, जो १९१९ की गर्मी में सोवियत देश के भूक्षेत्र पर कार्रवाई करनेवाली सभी श्वेत रक्षक फ़ौजों में अत्यधिक शक्तिशाली थी। देनीकिन की फ़ौजों ने अधिक से अधिक शरत् तक मास्को पर क़ब्ज़ा करने के उद्देश्य से वोल्गा से द्नेप्र तक व्यापक मोर्चे पर आक्रमण आरंभ किया। सोवियत रूस ने पुनः अपने को अत्यंत ख़तरनाक स्थिति में पाया।

१९१९ की जुलाई के प्रारंभ में पार्टी की केंद्रीय समिति ने सभी पार्टी संगठनों को संबोधित लेनिन के पत्र 'देनीकिन के खिलाफ़ लड़ाई में सारा ज़ोर लगा दो!' को अंगीकार किया। उसमें ज़ोर दिया गया था कि देनीकिन की फ़ौज के हमले की सहायता से सोवियत सत्ता का गला घोंटने के अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के नये प्रयास के कारण सोवियत राज्य अपने जीवन की एक अत्यंत संकटपूर्ण घड़ी में पहुंच गया है। इसलिए देनीकिन के हमले को रोकने और उस पर विजय पाने के लिए सोवियत जनतंत्र की सारी शक्तियों, मज़दूरों और किसानों की सारी शक्तियों को अनिवार्यतः लामबंद किया जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया था कि सोवियत जनतंत्र विश्व पूंजी द्वारा घिरा एक दुर्ग बन गया है और उसे कोल्चाक तथा देनीकिन से एक आश्रय के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार और उसमें रहने का अधिकार केवल वही लोग रख सकते हैं, जो हस्तक्षेपकारियों और श्वेत रक्षकों के ख़िलाफ़ संघर्ष में अपनी पूरी शक्ति से मदद कर रहे हैं। अतः युद्ध में भाग लेने के लिए समूची आबादी को खींचने – किसी को सीधे लड़ाई में, किसी को युद्ध से संबंधित विभिन्न सहायक कार्रवाइयों में – का कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सत्ता का अधिकार और कर्तव्य, दोनों ही था।*

यह पत्र शत्रु की पराजय के लिए पार्टी और जनता की लामबंदी

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'देनीकिन के खिलाफ़ लड़ाई में सारा ज़ोर लगा दो!' ९ जुलाई, १९१९।

में एक जुझारू दस्तावेज़ बना।

कुल मिलाकर ३० हज़ार कम्युनिस्ट, १० हज़ार कोम्सोमोल सदस्य और ३६ हज़ार ट्रेड-यूनियन सदस्य दक्षिणी मोर्चे पर भेजे गये।

पार्टी और सोवियत अवयवों के विराट सांगठनिक कार्य के कारण अक्तूबर के उत्तरार्ध में दक्षिण मोर्चे की सोवियत सेनाओं ने देनीकिन के गिरोहों के विरुद्ध आक्रमण करने की संभावना पायी। १६१६ के अंत तक उन्होंने खार्कोव, कीयेव और दोनेत्स कोयला क्षेत्र को मुक्त करा दिया था। जनवरी १६२० के प्रारंभ में तागान्रोग और रोस्तोव-ऑन-दोन को मुक्त करा दिया गया और मार्च के अंत में देनीकिन की फ़ौज के आख़िरी दुर्ग – नोवोरोस्सीइस्क – को ले लिया गया। देनीकिन देश छोड़कर भाग गये।

१६१६ में कोल्चाक, युदेनिच, देनीकिन और अन्य प्रतिक्रांतिकारी जनरलों की श्वेत रक्षक सेनाओं के ख़िलाफ़ घमासान लड़ाइयों में लाल सेना ने शत्रुओं की मुख्य शक्तियों को नष्ट कर दिया तथा उराल, साइबेरिया, उक्राइना, उत्तरी काकेशिया और तुर्किस्तान के एक बड़े भाग को मुक्त करा दिया। इस प्रकार सपूर्ण गृहयुद्ध में एक **मूल मोड़** आ गया। लेनिन ने लिखा कि सोवियत जनतंत्र ने "इतनी बड़ी विजय प्राप्त की कि हम अतिरंजना के बिना कह सकते हैं कि **सबसे बड़ी कठिनाइयां** पीछे छूट चुकी हैं"।*

पर १६२० के वसंत में साम्राज्यवादी शक्तियों (फ़्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका) ने अपनी पराजयों की परवाह न करते हुए सोवियत जनतंत्र के विरुद्ध नया आक्रमण संगठित किया और इस अपराधपूर्ण दुस्साहस में बुर्जुआ-ज़मींदार पोलैंड को खींच लिया। अप्रैल के अंत में पोलिश फ़ौजें उक्राइना में घुस आयीं और कीयेव पर क़ब्ज़ा कर लिया। इसके साथ ही जनरल व्रांगेल की कमान में फ़ौजों ने जून १६२० में क्रीमिया से आक्रमण शुरू करके दोनेत्स व कुबान क्षेत्रों के लिए ख़तरा प्रस्तुत कर दिया।

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने फिर सोवियत जनता का सामरिक कार्यभारों को पूरा करने में सारी शक्ति लगाने तथा साम्राज्यवादियों के नये आक्रमण से सोवियत जनतंत्र की रक्षा करने

* व्ला० इ० लेनिन, सोवियत की सातवीं अखिल रूसी कांग्रेस, ५–६, दिसम्बर, १६१६।

का आह्वान किया। सशस्त्र सेनाओं की सहायता करने के लिए २४ हज़ार कम्युनिस्टों, १२ हज़ार कोम्सोमोल सदस्यों और १४ हज़ार मज़दूरों – ट्रेड-यूनियन सदस्यों – को लामबंद किया गया।

अपने शासकों द्वारा सैनिक और आर्थिक विनाश के कगार पर लाये गये और आगे युद्ध जारी रखने की शक्ति से रहित बुर्जुआ पोलैंड ने अक्तूबर १९२० में सोवियत जनतंत्र के साथ शांति-संधि पर हस्ताक्षर कर दिये।

दक्षिणी रूस में जनरल व्रांगेल की प्रतिक्रांतिकारी फ़ौजें अब भी सक्रिय थीं। मिखाईल फ़्रूंज़े की कमान में दक्षिणी मोर्चे की सेनाओं ने क्रीमिया को जानेवाली भूसंधियों पेरेकोप और चोंगार पर बनी मोर्चेबंदियों पर हमला शुरू कर दिया। ये रक्षा-मोर्चेबंदियां वेर्देन की दुर्ग-मोर्चेबंदियों की तरह ही थीं। अक्तूबर क्रांति की तीसरी वर्षगांठ के दिनों में सोवियत सेनाओं ने असीम वीरता का प्रदर्शन करते हुए अभेद्य प्रतीत होनेवाली शत्रु की स्थितियों पर क़ब्ज़ा कर लिया और क्रीमिया में घुसकर उसे पूर्णतः मुक्त करा दिया। लेनिन के कथनानुसार, जनरल व्रांगेल की कमान में श्वेत रक्षक फ़ौजों की पराजय "लाल सेना के इतिहास में एक सबसे शानदार पृष्ठ है।"*

हस्तक्षेप और गृहयुद्ध की अवधि मूलतः समाप्त हो गयी। सुदूर पूर्व और मध्य एशिया में सोवियत सत्ता के कुछ शत्रु अब भी सक्रिय बने हुए थे, लेकिन हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति की मुख्य शक्तियों को कुचल दिया गया था। सोवियत देश के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद द्वारा शुरू किये गये पहले आक्रमण को विफल बना दिया गया था।

सोवियत जनता की विजय के कारण और महत्व

हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति की श्रेष्ठ शक्तियों पर विजय पाने में सोवियत राज्य कैसे सफल हुआ?

सोवियत देश ने पूंजीवादी दुनिया के विरुद्ध पहली निर्णायक लड़ाई इस वजह से जीती कि सोवियत जनता न्यायसंगत और मुक्तिकारी युद्ध चला रही थी। युद्ध के उद्देश्यों ने लोगों को महान देश-

* व्ला० इ० लेनिन, सोवियतों की सातवीं अखिल रूसी कांग्रेस, ५-९ दिसम्बर, १९१९।

भक्ति प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया। मज़दूरों, मेहनतकश किसानों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने अभूतपूर्व कठिनाइयों पर क़ाबू पाते हुए असीम वीरता प्रदर्शित की। मज़दूरों और किसानों की लाल सेना – क्रांति और मेहनतकशों की सेना – युद्ध की आग में जन्मी और मज़बूत बनी थी। जनता के बीच से बहुत से मेधावी सैनिक कमांडर और सुख्यात वीर निकले।

हस्तक्षेपकारियों और श्वेत रक्षकों के ख़िलाफ़ वीरतापूर्ण संघर्ष क्रांति द्वारा निर्मित नयी सामाजिक और राजकीय प्रणाली की जीवंत शक्तियों पर आश्रित था। समाजवाद के ऐतिहासिक लाभों ने देश की आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक शक्तियों को लामबंद करने तथा उसे एक सैनिक शिविर में रूपांतरित करने में सहायता की। मज़दूरों और किसानों का जुझारू सहबंध, क्रांति द्वारा मुक्त करायी गयी रूस की सभी जातियों का सहबंध गृहयुद्ध के दौरान मूर्तिमान हुआ और मज़बूत बना।

दुनिया की प्रगतिशील शक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति ने सोवियत जनतंत्र की विजय में योगदान किया। अनेक देशों में "सोवियत रूस से दूर रहो" समितियां बनायी गयीं। इसने सोवियत देश के मज़दूरों और किसानों को बड़ा नैतिक बल प्रदान किया तथा प्रतिक्रियावादी सरकारों की कार्रवाइयों को ठप कर दिया। लाल सेना की पांतों में दो लाख से ऊपर विदेशी स्वयंसेवक लड़े। इतिहास में मज़दूरों और किसानों की सत्ता के लिए संघर्ष में इतने राष्ट्रों के इतने लोग ऐसी सक्रियता से पहले कभी नहीं लड़े। दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय ध्येय बन गयी थी।

कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता को न्यायसंगत, मुक्ति युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा का कार्यक्रम तैयार किया और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाया। लेनिन ने विजय में कम्युनिस्ट पार्टी के योगदान का अत्युच्च मूल्यांकन किया: "जो चमत्कार वास्तव में घटित हुआ, उसका घटित होना केवल इसलिए संभव हुआ कि पार्टी सतर्क थी और उसमें कठोर अनुशासन था, कि पार्टी की प्रतिष्ठा ने सभी सरकारी विभागों तथा संस्थाओं को एकबद्ध कर दिया था, कि केंद्रीय समिति द्वारा दिये गये नारों का दसियों, सैकड़ों, हज़ारों और अंत में लाखों लोगों ने पूर्ण एकता के साथ अनुसरण किया

और इसलिए कि लोगों ने अविश्वसनीय क़ुर्बानियां दीं। केवल इन्हीं सब बातों की बदौलत हम एंटेंट तथा पूरी दुनिया के साम्राज्यवादियों द्वारा दो बार, तीन बार और यहां तक कि चार बार किये गये धावों के बावजूद विजय प्राप्त करने में सफल हुए।"*

सोवियत रूस में नयी, समाजवादी प्रणाली की स्थापना का ऐतिहासिक अनुभव इस बात का प्रमाण है कि अपदस्थ शोषक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के सक्रिय समर्थन से अपनी सत्ता पुनः क़ायम करने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखेंगे। विजयी जनता को हाथों में हथियार उठाकर अपनी क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेनिन के शब्दों में, "इतिहास में ऐसी क्रांति कभी नहीं हुई है, जिसमें विजय के बाद हथियार रख देना और निश्चेष्ट होना संभव हुआ हो।"** "कोई भी क्रांति तब कोई माने रखती जब वह अपनी रक्षा कर सके।"***

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस में चिली क्रांति के सबक़ों के संबंध में लेनिन की इस थीसिस की याद दिलायी गयी। इंगित किया गया कि चिली की त्रासदी हमें बरबस याद दिलाती है कि "क्रांति को अपनी रक्षा करने आना चाहिए। वह आधुनिक फ़ासिज़्म और विदेशी प्रतिक्रिया के षड्यंत्रों के खिलाफ़ सतर्कता का सबक़ देती है, स्वतंत्रता और प्रगति का मार्ग अपनानेवाले सभी लोगों के साथ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करती है।"****

हस्तक्षेपकारियों और आंतरिक प्रतिक्रांति की संयुक्त शक्तियों की पराजय का केवल सोवियत देश में समाजवाद की नियति के लिए ही

---

* व्ला० इ० लेनिन, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की नौवीं कांग्रेस में केंद्रीय समिति की रिपोर्ट, २९ मार्च, १९२०।

** व्ला० इ० लेनिन, 'सोवियत सत्ता की सफलताएं और कठिनाइयां', १७ अप्रैल, १९१९।

*** व्ला० इ० लेनिन, अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, मास्को सोवियत कारखाना समितियों और ट्रेड-यूनियनों के संयुक्त अधिवेशन में रिपोर्ट, २२ अक्तूबर, १९१८।

**** सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस की सामग्रियां, मास्को, पोलीतइज़्दात, १९७६, पृ० ३०।

नहीं, बल्कि विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया के विकास के लिए भी बड़ा महत्व था।

नवोदित समाजवादी जनतंत्र की ऐतिहासिक विजयों ने पूंजीवादी देशों के मेहनतकशों, उत्पीड़ित जातियों को दिखा दिया कि क्रांति आंतरिक प्रतिक्रांति और अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की शक्तियों पर क़ाबू पा सकती है, कि पूंजीवादी और औपनिवेशिक जुए को नष्ट किया जा सकता है, कि साम्राज्यवाद पर विजय एक वास्तविक और अमल में लाने लायक़ कार्य है। सोवियत जनतंत्र द्वारा अत्यधिक शक्तिशाली पूंजीवादी देशों की हस्तक्षेपकारी फ़ौजों के हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर देने और श्वेत रक्षकों की पराजय ने जनता को शोषकों और उत्पीड़कों के खिलाफ़ संघर्ष में प्रेरित किया। मज़दूर वर्ग का क्रांतिकारी संघर्ष और औपनिवेशिक तथा गुलाम देशों में जनगण का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तेज़ हो गये।

पूंजीवादी दुनिया के खिलाफ़ पहले निर्णायक संघर्ष में सोवियत जनतंत्र की विजय का अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस बात में है कि सोवियत देश – समाजवाद का निर्माण करनेवाला पहला देश – सुरक्षित और मज़बूत हो गया। लेनिन के शब्दों में, "सोवियत सत्ता को सुरक्षित करके हम सभी देशों के सर्वहाराओं को अपने बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ़ अविश्वसनीय रूप से कठिन संघर्ष में सबसे बढ़िया और शक्तिशाली सहायता प्रदान कर रहे हैं।"*

सोवियत जनगण के वीरतापूर्ण संघर्ष ने केवल क्रांतिकारी संघर्ष के राष्ट्रीय कार्यभारों को ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यभारों को भी व्यक्त किया। उसने साम्राज्यवाद की बड़ी शक्तियों को जकड़ दिया और उन्हें कमज़ोर बना दिया और इस तरह पूंजीपतियों के विरुद्ध मेहनतकशों के तथा उपनिवेशवादियों के विरुद्ध उत्पीड़ित जातियों के संघर्ष को आसान बनाया। समूची प्रगतिशील मानवजाति ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सोवियत जनगण के ऐतिहासिक पराक्रम का उच्च मूल्यांकन किया।

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'अलग और संयोजनकारी शांति-संधि के प्रश्न पर रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी (बोल्शेविक) की केंद्रीय समिति की स्थिति', १९१८।

अध्याय ३

आर्थिक स्वतंत्रता का आधार

१. पहले आर्थिक सुधार

मज़दूर वर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था पर अधिकार जमाना

सोवियत राज्य का उदय सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक विजय का द्योतक था। परंतु शब्द के पूर्ण अर्थ में शासक वर्ग बनने हेतु मज़दूर वर्ग के लिए बुर्जुआ वर्ग और ज़मींदारों के उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को ख़त्म करना और समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित बनाना आवश्यक था ताकि पूंजीवाद पर आर्थिक विजय के लिए आधार का निर्माण किया जा सके।

समाजवादी निर्माण की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि रूस साम्राज्यवादी बेड़ियों को तोड़ फेंकनेवाला और नये समाज के निर्माण की ओर आगे बढ़नेवाला पहला देश था। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी को समाजवाद की ओर ले जानेवाले मार्ग की सामान्य दिशा मालूम थी, फिर भी उसे इस मार्ग के प्रत्येक चरण में उठनेवाली सभी समस्याओं की जानकारी नहीं हो सकी थी। इससे बढ़कर, उसके पास इन समस्याओं के तैयार समाधान नहीं थे।

समाजवादी निर्माण के अज्ञात मार्ग और किसी भी अनुभव की अनुपस्थिति ने, बेशक, कठिनाइयों तथा विभिन्न ग़लतियों को पूर्वनिर्धारित किया। तो भी, नयी अर्थव्यवस्था के विकास में पहले क़दमों ने समाजवाद के सामान्य सिद्धांतों के परीक्षण, उनके और आगे रचनात्मक विकास के लिए आधार का काम किया।

नयी नीतियों के आधार पर राष्ट्र के आर्थिक जीवन का संगठन मुख्य कठिनाई था। इस समस्या के हल के बिना न तो समाजवादी समाज का निर्माण करना, न ही अक्तूबर क्रांति के फलस्वरूप प्राप्त राजनीतिक सत्ता को बनाये रखना संभव था।

राष्ट्रीयकरण एक कठिन और पेचीदा कार्य था। अर्थव्यवस्था में पहले समाजवादी सुधार कठोर वर्ग संघर्ष की परिस्थितियों में हुए। बुर्जुआ वर्ग ने देश में आर्थिक विनाश लाने के लिए कोई कोर-कसर न छोड़ी। चूंकि सोवियत सरकार के पास अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए तैयार संगठन और प्रशिक्षित, अनुभवी विशेषज्ञ नहीं थे, वह सभी पूंजीवादी उद्योगों का तुरंत राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकी, बल्कि उत्पादन पर मज़दूरों का नियंत्रण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, विदेश व्यापार की इजारेदारी, आदि जैसे अनेक संक्रमणकालीन प्रारंभिक क़दम उठाये।

उत्पादन पर मज़दूरों का नियंत्रण समाजवाद के मार्ग पर पहला क़दम, उद्योग पर स्वामित्व की पहली मंज़िल, उसके राष्ट्रीयकरण की शुरूआत था। उसने पूंजीपतियों के सारे आर्थिक कार्यों को मेहनतकश लोगों के निरीक्षण में रख दिया और इस तरह बुर्जुआ वर्ग और उसके गुर्गों द्वारा विनाश और ग़बन से उद्यमों तथा समूचे मूल्यवान मालों की रक्षा की। इसके साथ ही मज़दूरों का नियंत्रण सबके लिए खुला औद्योगिक प्रबंध का विद्यालय था। उसकी सहायता से सोवियत सरकार ने मज़दूरों को अर्थव्यवस्था के संचालन में खींचा, मालिकों की तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों को रोका और सभी उद्योगों तथा परिवहन को सोवियत राज्य के हाथ में हस्तांतरण के लिए तैयार किया।

मज़दूरों के नियंत्रण का रूप और व्यवस्था १४ नवम्बर, १९१७ को अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत एक विशेष आज्ञप्ति 'मज़दूरों के नियंत्रण के बारे में सिद्धांत' में निर्धारित किये गये थे।

राष्ट्रीयकृत उद्योग के संचालन के लिए जन अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च परिषद की स्थापना की गयी, जिसका कार्यभार नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। इस राजकीय संस्था के अलावा देश में जन अर्थव्यवस्था की स्थानीय परिषदें भी कायम की गयीं। इन परिषदों ने सोवियत राज्य के आर्थिक और सांगठनिक कार्यों को असली जामा पहनाया।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण बुर्जुआ वर्ग की आर्थिक शक्ति पर प्रबलतम प्रहार था। सोवियत सरकार ने सभी निजी बैंकों पर अपना नियंत्रण क़ायम कर लिया। लेकिन बैंकरों ने इस नियंत्रण को अकारगर बनाने

के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया: उन्होंने अपने बैंकों के पैसे विदेशी बैंकों और देश के दूर-दराज़ के उन क्षेत्रों में अपनी बैंक-शाखाओं में स्थानांतरित कर दिये, जहां प्रतिक्रांति के केंद्र बन रहे थे, उन उद्यमों की वित्तीय नाकेबंदी की, जिनमें मज़दूरों का नियंत्रण लागू किया गया था। तब सोवियत सरकार असाधारण क़दम उठाने के लिए विवश हो गयी। २७ दिसम्बर, १९१७ को तड़के सुबह लाल रक्षकों की सशस्त्र टुकड़ियों ने सभी निजी बैंकों पर क़ब्ज़ा कर लिया तथा उसी दिन शाम को सभी निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और उनके राजकीय बैंक में विलय पर एक आज्ञप्ति की घोषणा की गयी। निजी बैंकों का अधिग्रहण राष्ट्रीयकरण पर आज्ञप्ति की घोषणा के पहले ही, अप्रत्याशित रूप से किया गया, ताकि बुर्जुआ लोग अपनी जमा रकमें न निकाल सकें और बैंक खातों में गड़बड़ी न कर सकें।

सोवियत सत्ता के पहले महीनों में कार्यान्वित आर्थिक क़दम – ज़मींदारों की भूसंपत्तियों का अधिग्रहण, उत्पादन तथा वितरण पर राज्य के तत्वावधान में मज़दूरों के नियंत्रण की स्थापना, बैंकों, रेलवे, समुद्री और नदी परिवहन का राष्ट्रीयकरण, विदेश व्यापार की राजकीय इजारेदारी का समारंभ, ज़ारशाही और अस्थायी बुर्जुआ सरकार के विदेशी और घरेलू ऋणों की मंसूख़ी – देश को सभी बड़े औद्योगिक उद्यमों के राष्ट्रीयकरण के निकट ले गये। इसकी आवश्यकता अत्यंत वस्तुगत परिस्थितियों से उत्पन्न हुई थी। बात यह है कि रूस में साम्राज्यवाद के विकास के दौरान बैंकों और बड़े औद्योगिक तथा व्यापार प्रतिष्ठानों ने मिलकर एक प्रणाली का रूप ग्रहण कर लिया था। अत: व्यापार और औद्योगिक संघों पर राजकीय इजारेदारी क़ायम करने के लिए क़दम उठाये बिना केवल बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना कठिन था।

बड़े पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के बिना मुआवज़े के अधिग्रहण के ज़रिये महत्वपूर्ण औद्योगिक शाखाओं का राष्ट्रीयकरण करते हुए सोवियत राज्य ने पूंजीवादी आर्थिक संबंधों के तुरंत और पूर्ण विनाश के लिए आह्वान नहीं किया। उसने कुछ समय तक बुर्जुआ संपत्ति को सोवियत सत्ता के नियंत्रण में बने रहने दिया और वह मालिकों, ख़ास तौर से छोटे मालिकों और कुछ उन पूंजीपतियों को राष्ट्रीयकृत उद्योगों के लिए एक प्रकार का मुआवज़ा देने को भी तैयार था, जिन्होंने

उच्च कामकाजी और सांगठनिक गुण तथा बड़े पैमाने के उत्पादन को ठीक करने में नयी सत्ता की सहायता करने की तत्परता प्रकट करते हुए सोवियत राज्य के प्रति वफ़ादारी दिखायी थी। परंतु रूसी बुर्जुआ वर्ग ने सोवियत राज्य द्वारा दी गयी इस संभावना को ठुकरा दिया। बुर्जुआ वर्ग के ज़बर्दस्त प्रतिरोध ने सोवियत सरकार को शुरू में निर्धारित समय से पहले ही पुराने आर्थिक संबंधों को तेज़ी से नष्ट कर देने के लिए मजबूर कर दिया।

बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते हुए सोवियत सत्ता ने प्रत्येक उद्यम की अवस्था और प्रबंध की उसकी तैयारी को चहुंमुखी ढंग से ध्यान में रखा। उन कारखानों और फ़ैक्टरियों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनके मालिक या तो देश छोड़कर भाग गये थे या उत्पादन की तोड़-फोड़ की थी। आंकड़ों के अनुसार, जून १९१८ तक ५०० से कुछ अधिक उद्यमों और सितम्बर के शुरू तक ३,००० से ऊपर उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। १९१८ की गर्मी में सभी बड़े उद्योगों के बिना मुआवज़े के राष्ट्रीयकरण पर आज्ञप्ति जारी की गयी, जिसने बुर्जुआ वर्ग की आर्थिक स्थितियों पर मर्मांतक प्रहार किया।

इस तरह देश में नयी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी गयी।

पूंजीवादी संपत्ति के बड़े भाग के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका और आगे उन्मूलन निजी पूंजी को सीमित करके और उसके स्थान पर राजकीय आर्थिक समर्थन से सार्वजनिक संपत्ति क़ायम करके किया गया।

संक्रमण-काल में सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में पांच विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र थे:

१) पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था, जो बहुत हद तक नैसर्गिक कृषक अर्थव्यवस्था थी;

२) लघु माल उत्पादन, जिसमें ऐसे किसान और दस्तकार लगे हुए थे, जो उजरती श्रम का उपयोग किये बिना पण्य उत्पाद और माल पैदा करते थे;

३) पूंजीवादी क्षेत्र, जिसमें छोटे और मंझोले पूंजीपतियों के औद्योगिक और व्यापारिक उद्यम तथा देहात में कुलक अर्थव्यवस्था शामिल थी;

४) राज्य द्वारा नियंत्रित पूंजीवादी क्षेत्र, जिसमें पूंजीपतियों द्वारा चालू रियायत या पट्टे पर दिये गये उद्यम शामिल थे;

५) समाजवादी क्षेत्र, जिसमें राज्य द्वारा राष्ट्रीयकृत औद्योगिक उद्यम, परिवहन और बैंक तथा देहात में पहले राजकीय फ़ार्म आते थे।

निजी संपत्ति का उन्मूलन एक ही झटके में नहीं किया जा सकता। बड़े उद्योगों और निजी इजारेदारियों की परिसंपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके मज़दूर वर्ग छोटे उद्योगपतियों, व्यापारियों और दस्तकारों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह फ़ौरन उनके उत्पादन के स्थान पर समाजवादी उद्यम कायम नहीं कर सकता। कृषि-अर्थव्यवस्था में लघु उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और उसके स्थान पर समाजवादी उत्पादन क़ायम करना निश्चित समय की मांग करता है।

देश की अर्थव्यवस्था में विद्यमान बहुविध क्षेत्रों का उन्मूलन एक जटिल प्रक्रिया है। उसके कार्यान्वयन के ठोस मार्ग, दरें और अवधि वर्ग शक्तियों के संतुलन, उनके बीच संघर्ष की तीव्रता पर निर्भर करते हैं।

सोवियत राज्य के पहले क्रांतिकारी सुधारों के सामाजिक-आर्थिक परिणाम क्या थे?

समाजवादी राज्य द्वारा उत्पादन साधनों के समाजवादी समाजीकरण ने शोषण के पूंजीवादी संबंधों के भौतिक आधार को मूलत: नष्ट कर दिया। देहात में भूमि-सुधारों के फलस्वरूप अर्थतंत्र में शोषण के पूर्व-पूंजीवादी रूपों और इस शोषण के वाहक – ज़मींदार वर्ग – का पूर्णत: ख़ात्मा हो गया।

संक्रमण-काल के दौरान पूंजीवादी क्षेत्र, जिसका पूंजीवाद के तहत प्रभुत्व होता है, गौण स्थान पर आ जाता है और फिर धीरे-धीरे संकुचित होकर संक्रमणकालीन अवधि के अंत में समाप्त हो जाता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से रहित समाजवादी उत्पादन संबंधों को बनानेवाली समाजवादी आर्थिक प्रणाली क़ायम होती है।

समाजवाद के मार्ग पर क़दम रखनेवाले देश में आर्थिक परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप समाजवाद के आर्थिक नियम अस्तित्व में आते और काम शुरू करते हैं जो संक्रमणकालीन अवधि में समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना द्वारा निर्धारित होते हैं।

समाजवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला के निर्माण के लिए लेनिन की योजना

१९१८ के वसंत में ब्रेस्त शांति-संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सोवियत जनतंत्र ने शांतिपूर्ण निर्माण पर अपनी पूरी शक्ति संकेंद्रित की। लेनिन ने देश में मौलिक रूपांतरण की एक नयी मंज़िल के लिए, समाजवाद के निर्माण के लिए संक्रमण का एक ठोस कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने 'सोवियत सत्ता के तात्कालिक कार्यभार' में पेश की।

लेनिन ने पार्टी, सोवियतों और ट्रेड-यूनियनों द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों के केंद्र को राजनीतिक क्षेत्र से आर्थिक निर्माण के क्षेत्र में हटाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने ज़ोर दिया कि इतिहास में पहली बार क्रांतिकारी सर्वहारा की पार्टी को प्रशासनिक कार्यभारों – समाजवादी क्रांति के मूल कार्यभारों – को पूरा करने में तत्परतापूर्वक जुट जाना चाहिए। "हमने, बोल्शेविकों की पार्टी ने रूस को **क़ायल कर दिया है**। हमने ग़रीबों के लिए अमीरों से, मेहनतकशों के लिए शोषकों से रूस को **जीत लिया है**। अब हमें उसका **प्रशासन करना** होगा।"*

सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला के निर्माण ने हिसाब-किताब के संगठन और उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण तथा श्रम उत्पादकता में सुधार का कार्यभार प्रस्तुत किया। लेनिन ने लिखा कि सर्वहारा द्वारा सत्ता पर क़ब्ज़ा किये जाने के बाद बुर्जुआ वर्ग पर सैन्य विधि से नहीं, बल्कि उत्पादन के बेहतर संगठन, यानी आर्थिक प्रबंध की बेहतर विधियों से क़ाबू पाया जाना चाहिए। हिसाब-किताब और नियंत्रण टुटपुंजिया तत्वों, निठल्लों और परजीवियों से लड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन भी थे। हिसाब-किताब और नियंत्रण के कार्य सोवियतों, आर्थिक परिषदों, ट्रेड-यूनियनों, सहकारी समितियों और मज़दूर नियंत्रण निकायों को सौंपे गये।

श्रम उत्पादकता में वृद्धि को लेनिन ने समाजवाद में संक्रमण की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पूर्वशर्त माना। इसके लिए बड़े उद्योगों के

---

* व्ला० इ० लेनिन, संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ८, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८५, पृ० १६।

भौतिक आधार – ईंधन, लौह और इस्पात इंजीनियरी, मशीन-निर्माण, रासायनिक उद्योगों – के निर्माण, श्रमिकों के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक स्तरों में लगातार वृद्धि, उत्पादन के वैज्ञानिक संगठन, तकनीकी सज्जीकरण का अथक परिष्कार आवश्यक थे। अपनी अर्थव्यवस्था के विकास की प्रारंभिक अवधि में नवोदित समाजवादी जनतंत्र ने सुदक्ष कर्मियों के प्रशिक्षण की समस्या का सामना किया।

उस अवधि में बुर्जुआ विशेषज्ञों को मोटी तनख़्वाहों पर समाजवादी निर्माण में हिस्सा लेने के लिए खींचना आवश्यक था। फिर भी इस समस्या का मुख्य समाधान मज़दूरों और किसानों के बीच से नये, सच्चे जन बुद्धिजीवियों का निर्माण करना था।

लेनिन ने सचेत श्रम अनुशासन की शिक्षा-दीक्षा को बड़ा महत्व दिया: यह सबसे पहले था सबके लिए श्रम की अनिवार्यता; समाज के कल्याण के लिए श्रम के प्रति सचेत रुख़ की शिक्षा-दीक्षा; अनुशासन भंग करनेवालों के संबंध में सज़ा लागू करना; श्रम उत्पादकता और अनुशासन पर मेहनतकशों का नियंत्रण; पारिश्रमिक के समाजवादी सिद्धांत का कार्यान्वयन।

लेनिन ने समाजवादी स्पर्धा को श्रम उत्पादकता की बढ़ती, उसके संगठन में सुधार, नये, सचेत अनुशासन के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना, जिसके मुख्य सिद्धांत हैं परिणामों का प्रचार और तुलना, अनुभव और कार्य की बेहतर विधियों का व्यापक प्रसार, अग्रणी कर्मियों को भौतिक और नैतिक प्रोत्साहन। इन्हीं सिद्धांतों से पार्टी १६१६ में पहले कम्युनिस्ट "सुब्बोत्निकों"* से श्रम के प्रति कम्युनिस्ट रुख़ के विकास के वर्तमान व्यापक आंदोलन तक समाजवादी स्पर्धा के विकास में निदेशित हुई।

सोवियत देश सभी कठिनाइयों पर क़ाबू पाते हुए मज़बूत बनता गया, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में बड़े विश्वास के साथ

---

* पहला कम्युनिस्ट "सुब्बोत्निक" शनिवार, १२ अप्रैल, १६१६ को हुआ, जब मास्को के कम्युनिस्ट रेलवे-कर्मियों के एक ग्रुप ने स्वेच्छापूर्वक श्रमदान करते हुए १० घंटे काम किया और तीन इंजिनों की मरम्मत की। इस पहल का मास्को के अन्य उद्यमों के कम्युनिस्टों ने अनुकरण किया और फिर वह सारे देश में फैल गया। – सं०

मौलिक रूपांतरण पूरे किये। समाजवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला के निर्माण की अवधि में सोवियत राज्य के आर्थिक, सांगठनिक कार्य ने बड़ा महत्व ग्रहण कर लिया, क्योंकि सर्वहारा क्रांति का उद्देश्य पुरानी व्यवस्था को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि नये जीवन का निर्माण करना भी था।

इस प्रकार, सोवियत सत्ता की स्थापना, उत्पादन के मूल साधनों पर निजी पूंजीवादी स्वामित्व के उन्मूलन, बड़े उद्योग, परिवहन, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप दुनिया में पहली बार समाजवादी समाज का निर्माण आरंभ करने की संभावना प्रकट हुई।

२. समाजवाद का भौतिक और तकनीकी आधार

समाजवादी औद्योगीकरण
समाजवाद के निर्माण की लेनिनीय योजना की मुख्य कड़ी

प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से दुनिया का सबसे धनी देश, भूक्षेत्र के आकार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश होते हुए भी क्रांति के पहले रूस औद्योगिक उत्पादन की मात्रा और विकास के तकनीकी स्तर की दृष्टि से औद्योगीकृत पूंजीवादी देशों से ५०-१०० साल पीछे था। १९१३ में रूस का प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और फ़्रांस के प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का क्रमशः ४.८ प्रतिशत, ७.१ प्रतिशत, ७.७ प्रतिशत और लगभग १३ प्रतिशत था। ज़ारशाही रूस लगभग सभी धातुकर्तक औज़ारों, हार्वेस्टरों के एक बड़े भाग, हलों, हंसियों और कृषि के अन्य साधारण औज़ारों का आयात करता था।

समाजवाद के निर्माण के लिए सबसे पहले देश के तकनीकी-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना, समाजवाद के भौतिक-तकनीकी आधार – उत्पादन साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, टेक्नोलाजी के उच्च स्तर और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से मुक्त श्रम पर आधारित बड़े यंत्रीकृत उत्पादन – का निर्माण करना आवश्यक था।

इसलिए समाजवाद के निर्माण की लेनिनीय योजना में औद्योगीकरण को मुख्य स्थान प्राप्त था, जिसे समाजवाद के भौतिक और तकनीकी आधार के रूप में भारी उद्योग की स्थापना में, मेहनतकश लोगों के भौतिक कल्याण और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा सोवियत देश की तकनीकी और आर्थिक स्वतंत्रता तथा रक्षा क्षमता को सुनिश्चित बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करनी थी।

लेनिन के शब्दों में "कृषि को पुनर्गठित करने में समर्थ बड़े पैमाने का मशीन उद्योग ही समाजवाद का एकमात्र भौतिक आधार हो सकता है"।*

सोवियत सत्ता के पहले महीनों में ही लेनिन ने समाजवाद के निर्माण के एक संघटक अंग के रूप में देश के औद्योगीकरण की योजना तैयार की थी। मार्च १९१८ में लेनिन ने लिखा कि नये समाज का मार्ग ज्ञात है: "वह मशीन-उद्योग पर आधारित बड़े पैमाने की अर्थ-व्यवस्था में संक्रमण में, समाजवाद में संक्रमण में निहित है।"**

औद्योगीकरण की योजना में आधुनिक उद्योग के निर्माण की पहली शर्त – बिजलीकरण और टेक्नोलाजिकल प्रगति – को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। देश के औद्योगीकरण संबंधी लेनिन के विचार बिजलीकरण की राजकीय योजना में अत्यंत पूर्ण और ठोस रूप में व्यक्त हुए। गोएलरो योजना (रूस के बिजलीकरण का राजकीय आयोग) को सोवियतों की आठवीं कांग्रेस ने दिसम्बर १९२० में अनुमोदित कर दिया। लेनिन ने लिखा: "केवल तभी जब देश का बिजलीकरण हो जायेगा, जब उद्योग, कृषि और परिवहन बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग के टेक्नोलाजिकल आधार पर कायम हो जायेंगे, केवल तभी हम पूर्णतः विजयी होंगे।"***

---

* व्ला० इ० लेनिन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यनीति के बारे में रिपोर्ट की थीसिसें, १९२१।

** व्ला० इ० लेनिन, '"सोवियत सत्ता के तात्कालिक कार्यभार" शीर्षक लेख का मूलपाठ', १९१८।

*** व्ला० इ० लेनिन, सोवियतों की आठवीं अखिल रूसी कांग्रेस में भाषण, २२ दिसम्बर, १९२१।

१०-१५ साल के लिए निर्दिष्ट गोएलरो योजना में तत्कालीन मानकों के अनुसार १०,७५,००० किलोवाट की कुल क्षमता के ३० बड़े बिजलीघरों के निर्माण की व्यवस्था थी। द्नेप्र पनबिजलीघर भी इन में शामिल था। १६१३ में बिजली उत्पादन के मुक़ाबले में लगभग दसगुना अधिक बिजली पैदा करने की योजना थी। योजना में न केवल बिजलीघरों के निर्माण की, बल्कि जन-अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं के विकास की भी व्यवस्था थी। यह देश की समूची अर्थव्यवस्था के समाजवादी रूपांतरण की पहली वैज्ञानिक योजना थी। उस समय बहुतों को यह योजना अवास्तविक, अपूरणीय लगी थी। कई वैज्ञानिक गल्प-उपन्यासों के अंग्रेज़ लेखक एच० जी० वेल्स को यह सोवियत योजना दिवास्वप्न, यूटोपिया प्रतीत हुई थी। "क्या जंगलों और अनपढ़ किसानों के विस्तृत मैदानी देश में, जहां तकनीकी प्रगति का प्रायः अभाव है, और जहां व्यापार और उद्योग अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, एक अधिक साहसी परियोजना की कल्पना की जा सकती है?"* वेल्स ने लिखा कि रूस में बिजलीकरण के कार्यान्वयन की कल्पना "केवल अत्यंत अतिरंजित कल्पना के सहारे ही की जा सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता"।** "दस साल बाद फिर हमारे यहां आइये और देखिये कि रूस में इस अवधि में हमने क्या कर डाला है,"*** वेल्स के संदेहों के उत्तर में लेनिन ने कहा।

सोवियत सत्ता के पहले दिनों से ही सोवियत राज्य ने एक शक्तिशाली औद्योगिक राज्य में देश के रूपांतरण के बारे में लेनिनीय विचारों को अमली जामा पहनाया। लेकिन गृहयुद्ध के विजयी अंत और देश की अर्थव्यवस्था की बहाली के बाद जाकर ही बड़े पैमाने के औद्योगीकरण के विकास की आवश्यक परिस्थितियां बनीं।

---

* H. G. Wells, *Russia in the Shadows,* Hodder and Stonghton, London, S. A., p. 135.

** वही, पृ० १३७।

*** १६३४ में सोवियत संघ की यात्रा करने के बाद एच० जी० वेल्स ने बिजलीकरण की लेनिनीय योजना के सफल कार्यान्वयन को स्वीकार किया। –सं०

नयी आर्थिक नीति में संक्रमण

१५ दिसम्बर, १९२० को अख़बारों ने गृहयुद्ध के मोर्चों पर कार्रवाइयों का अंतिम संक्षिप्त विवरण छापा। चिरप्रतीक्षित शांति आरंभ हो गयी थी। किंतु शांतिपूर्ण जीवन अकल्पनीय रूप से कठिन परिस्थितियों में शुरू हुआ। देश को तहस-नहस कर दिया गया था। अधिकांश उद्यम ठप पड़ गये थे, धमन-भट्ठियां बुझ गयी थीं। १९२१ के प्रारंभ में बड़े प्रतिष्ठानों ने प्रथम युद्ध के पहले के मुक़ाबले में पांचगुना कम उत्पादन किया। धातु उत्पादन गिरकर १९वीं सदी के शुरू के वर्षों के उत्पादन के स्तर पर और कोयले तथा तेल का उत्पादन २०वीं सदी के आरंभिक वर्षों के उत्पादन के स्तर पर आ गया था। कृषि उत्पादन में क़रीब ५० प्रतिशत की गिरावट आयी थी। कुपोषण और भुखमरी के कारण महामारियां फैल गयी थीं। मसलन, १९२० में लाखों लोग टाइफ़स ज्वर के शिकार बने।

किसानों ने, जिन्होंने बड़ी कठिनाइयां और अभाव झेले थे, "युद्धकालीन कम्युनिज़्म" की प्रणाली से असंतोष व्यक्त किया। सोवियत सत्ता के शत्रुओं – समाजवादी-क्रांतिकारियों, मेंशेविकों और बुर्जुआ राष्ट्रवादियों – ने किसानों के असंतोष का इस्तेमाल करने की कोशिश की। कई क्षेत्रों में कुलक विद्रोह भड़क उठे, जिनमें अनाज की हुक्मी वसूली से असंतुष्ट मंझोले किसानों ने भी हिस्सा लिया। मार्च १९२१ में विदेशी साम्राज्यवादियों के समर्थन से समाजवादी-क्रांतिकारियों, मेंशेविकों, अराजकतावादियों और श्वेत रक्षकों ने पेत्रोग्राद के निकट क्रोंश्तादृत के दुर्ग में सोवियत-विरोधी विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह के नेताओं ने घोषणा की कि वे सोवियत सत्ता का नहीं, बल्कि अनाज की हुक्मी वसूली का विरोध करते हैं तथा "कम्युनिस्टों के बिना सोवियत सत्ता" की हिमायत करते हैं; वे नौसैनिकों के एक हिस्से को, जिनमें हाल ही में भरती हुए बहुत से किसान थे, अपनी तरफ़ करने में सफल हो गये। विद्रोह कुचल दिया गया। लेकिन ये सभी घटनाएं देश में गंभीर राजनीतिक संकट और आर्थिक नीति परिवर्तित करने की आवश्यकता को प्रमाणित करती थीं। "युद्धकालीन कम्युनिज़्म", जिसने गृहयुद्ध के दौरान, बेशक, सकारात्मक भूमिका अदा की थी, अब नये कार्यभारों को हल करने में बाधक हो गया था।

१९२१ के वसंत तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में संक्रमण और समाजवाद के और आगे निर्माण की एक ठोस योजना तैयार कर ली थी। मार्च १९२१ में हुई रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की दसवीं कांग्रेस ने नयी आर्थिक नीति (नेप) में संक्रमण के बारे में एक निर्णय स्वीकार किया। वह "युद्धकालीन कम्युनिज़्म" की विधियों की तुलना में नयी थी। वास्तव में, वह लेनिन द्वारा १९१८ के वसंत में ही प्रतिपादित आर्थिक नीति का तर्कसंगत सातत्य और विकास थी।

एक ऐसे देश में, जहां छोटे किसान आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं, समाजवादी क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक राज्य-सत्ता अपने हाथों में लेनेवाला सर्वहारा वर्ग अधिकांश किसानों के साथ समझौता नहीं करता। अतः पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि में मज़दूरों और मेहनतकश किसानों के बीच एक दृढ़ सहबंध की स्थापना आर्थिक नीति का मर्म तथा समाजवाद के सफल निर्माण की एक महत्वपूर्ण शर्त है।

लेनिन ने लिखा, "नयी आर्थिक नीति की समस्या, उसकी बुनियादी, निर्णायक और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने जिस नयी अर्थव्यवस्था का निर्माण शुरू किया है, उसके और उस कृषक अर्थव्यवस्था के बीच एक कड़ी स्थापित की जाये, जिसके द्वारा करोड़ों किसान अपनी जीविका कमाते हैं।"*

१९२१ के शुरू में सोवियत जनतंत्र की जन अर्थव्यवस्था में लघु माल कृषक अर्थव्यवस्था का हिस्सा ५१ प्रतिशत था, जबकि नैसर्गिक और लघु माल कृषक अर्थव्यवस्था और दस्तकारी उत्पादन में देश की कार्यक्षम आबादी का ८३ प्रतिशत लगा हुआ था। इसीलिए, लेनिन ने कहा, मुक्त व्यापार किसानों के बीच लंबे समय तक लोकप्रिय बना रहेगा, क्योंकि वह लघु माल उत्पादकों के नाते किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता था। इस तरह, अनाज की अनिवार्य वसूली के स्थान पर जिंसरूप कर लागू करने जैसी अपनी नीति के मूल प्रश्न में सोवियत सत्ता उस समय देश की अर्थव्यवस्था की विशिष्टताओं, उसके विभिन्न क्षेत्रों और उनके विकास के वस्तुगत नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ी।

---

* व्ला० इ० लेनिन, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की ग्यारहवीं कांग्रेस, २० मार्च – २ अप्रैल, १९२२।

नयी आर्थिक नीति में जिंसरूप कर और मुक्त व्यापार * के अलावा निम्नलिखित चीज़ें भी शामिल थीं : क) राज्य के स्वामित्व में छोटे उद्यमों को पट्टे पर निजी व्यक्तियों को दिया जाना ; ख) निजी दस्तकारी का विकास ; ग) विदेशी पूंजी को रियायतें दिया जाना ; घ) देहात में सीमित रूप में ज़मीन का पट्टे पर दिया जाना और उजरती श्रम का उपयोग।

परंतु जन अर्थव्यवस्था के समाजवादी क्षेत्र का विकास और सुदृढ़ीकरण नयी आर्थिक नीति का मर्म बने रहे।

बड़े राजकीय उद्योग की बहाली और विकास बड़ा महत्व रखते थे। उन उद्यमों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया, जिन पर मुख्य औद्योगिक शाखाओं का विकास निर्भर करता था। इन उद्यमों को प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल, खाद्य-सामग्रियां, सुदक्ष कर्मी, आदि दिये गये। अधिकांश उद्यमों में लागत-लेखाविधि लागू की गयी थी और मज़दूरी श्रम के गुण और मात्रा के अनुसार निर्धारित की गयी थी।

सोवियत राज्य ने इस बात को ध्यान में रखा था कि नयी आर्थिक नीति और जिंसरूप कर के समारंभ ने निजी व्यापार और बाज़ार संबंधों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान की थी, जो लघु माल कृषक अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में पूंजीवादी तत्वों के कुछ पुनर्जीवन, कुलकों की संख्या में वृद्धि, निजी उद्यमों के खड़े होने की ओर अवश्य ही ले जाती। दो शक्तियों और प्रवृत्तियों के बीच – पूंजीवाद और समाजवाद के बीच – निर्मम संघर्ष फैल गया। "कौन किस पर विजय पायेगा ?" – इस प्रश्न का निपटारा हो रहा था।

एक ओर, पूंजीवादी तत्व अपने अस्थायी आर्थिक विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए और बाज़ार पर तथा उसके ज़रिये उत्पादन पर प्रभुत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करते हुए फुटकर व्यापार में कूद पड़े। दूसरी ओर, समाजवादी राज्य जन अर्थव्यवस्था की निर्णायक अवस्थितियों (भारी उद्योग, बैंक, थोक व्यापार, विदेश व्यापार की

---

* मुक्त व्यापार केवल देश के भीतर ही लागू किया गया था – विदेश व्यापार की राजकीय इजारेदारी बनाये रखी गयी थी। – सं०

इजारेदारी, परिवहन, आदि) से अपना आर्थिक प्रभुत्व बहाल करने के पूंजीवादी तत्वों के प्रयासों को रोक रहा था।

आर्थिक विकास की इस जटिल अवस्था में पार्टी का मुख्य कार्यभार इसमें था कि वह सर्वहारा की क्रांतिकारी सत्ता और अर्थव्यवस्था में समाजवादी निर्णायक अवस्थितियों के सहारे आर्थिक, व्यापारिक, ऋण और सहकारी कार्यों की सभी विधियों को कम से कम समय में सीख ले और उन्हें निजी पूंजी के मुक़ाबले पर रखे। संक्षेप में, बुर्जुआ वर्ग से बेहतर ढंग से व्यापार-धंधा करना, आर्थिक प्रबंध करना सीखना एक मुख्य कार्यभार था।

इन परिस्थितियों में सोवियत राज्य ने औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन के लिए विदेशी पूंजीपतियों को रियायतें प्रदान करते हुए भी राजकीय नियंत्रण में पूंजीवादी क्षेत्र में निजी पूंजी लगाना आवश्यक माना। समाजवादी राज्य की परिस्थितियों में राजकीय पूंजीवाद का विशिष्ट स्वरूप संपत्ति संबंधों की विशिष्टताओं द्वारा निर्धारित होता है। राजकीय पूंजीवाद सार्वजनिक (राजकीय) संपत्ति और निजी पूंजीवादी संपत्ति के विलय के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आता है और वह सोवियत राज्य के संचालन में और उसकी भागीदारी से समाजवाद के निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह बुर्जुआ वर्ग की टेक्नोलाजिकल जानकारी, पूंजी और कामकाजी अनुभव को समाजवाद के हित में उपयोग करना संभव बनाता है, बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है, टुटपुंजिया तत्वों से संघर्ष चलाने तथा सार्वजनिक लेखा और नियंत्रण को ठीक करने में समाजवादी राज्य की सहायता करता है। सोवियत सत्ता ने पूंजीवाद के राजकीय नियमन की क्रियाविधि, राजकीय नियंत्रण में निजी पूंजी के विकास के विशिष्ट रूपों और सीमाओं तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास के हित में उसके इस्तेमाल को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया। जैसे-जैसे समाजवादी आर्थिक रूपों का सुदृढ़ीकरण होता गया, वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी तत्व विस्थापित होते गये। इस प्रकार, राजकीय पूंजीवाद वर्ग संघर्ष का एक नया रूप, विजयी सर्वहारा वर्ग और विजित बुर्जुआ वर्ग के बीच संबंध का एक विशिष्ट ऐतिहासिक रूप था।

रूस में राजकीय पूंजीवाद ने कोई ख़ास विकास नहीं पाया। इसका कारण यह है कि सोवियत सत्ता ने उन एकतरफ़ा शर्तों को नहीं स्वीकार

किया, जिन पर विदेशी पूंजीपति उससे रियायतें पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह संक्रमणकालीन अवधि में राजकीय पूंजीवाद के सार के निर्धारण में पार्टी के अनुभव के विशाल महत्व को तनिक भी कम नहीं करता।

पार्टी ने लेनिन द्वारा तैयार की गयी नयी आर्थिक नीति की पुष्टि की, जिसने समाजवादी समाज के निर्माण में मज़दूरों और किसानों के बीच स्थिर आर्थिक और राजनीतिक सहबंध को सुनिश्चित किया।

संक्रमणकालीन अवधि में समाजवादी आर्थिक प्रणाली के विशिष्ट स्वरूप से उत्पन्न नयी आर्थिक नीति पूंजीवाद पर समाजवाद के निर्णायक लाभों की वास्तविक पुष्टि थी। उसने माल-मुद्रा संबंधों, लागत-लेखा-विधि, भौतिक प्रोत्साहन के सिद्धांतों के व्यापक इस्तेमाल को सुनिश्चित किया। उसने देश की उत्पादक शक्तियों के सतत विकास, समाज के श्रम संसाधनों के पूर्णतम और युक्तिसंगत उपयोग की संभावना दी।

नयी आर्थिक नीति के कार्यान्वियन के ज़रिये और सोवियत राज्य तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े सांगठनिक और शैक्षिक कार्यों के फलस्वरूप देश ने आर्थिक विनाश पर क़ाबू पा लिया। १९२५ तक सोवियत संघ की जन अर्थव्यवस्था युद्ध-पूर्व स्तर पर पहुंच गयी।

बड़े उद्योग की बहाली सफलतापूर्वक पूरी हो गयी और १९२५ में उसका उत्पादन युद्ध-पूर्व उत्पादन का ७५ प्रतिशत था। हल्के और खाद्य उद्योग १९१३ के स्तर पर पहुंच रहे थे। नयी-नयी निर्माण परियोजनाएं आरंभ हो रही थीं। १९२५ में शतूरा और निज्नी नोवगोरोद (बलाख़्ना) बिजलीघर चालू किये गये। अगले साल विद्युत इंजीनियरी के दुनिया के नवीनतम मानकों के अनुसार बने वोल्खोव पनबिजलीघर के टर्बाइन अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगे। अज़रबैजान, बेलोरूस, तुर्किस्तान, जार्जिया और अन्य जनतंत्रों में बिजलीघर बन रहे थे। बिजली का उत्पादन युद्ध-पूर्व उत्पादन से ५० प्रतिशत बढ़ गया। इस तरह, देश की आर्थिक बहाली के दौरान उद्योग और बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में प्राप्त सफलताओं ने आर्थिक विकास में नयी मंज़िल में संक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। दिसम्बर १९२५ में हुई कम्युनिस्ट पार्टी की १४वीं कांग्रेस ने समाजवादी विधि से देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के एकमात्र आधार के रूप में समाजवादी औद्योगीकरण की नीति स्वीकार की। कांग्रेस के प्रस्तावों में कहा गया था कि आर्थिक

निर्माण को ऐसी दिशा में निर्दिष्ट करना आवश्यक है, जिससे कि सोवियत संघ को मशीनों और साज़-सामान के आयातक देश से मशीनों और उपकरणों के उत्पादक देश में, यानी एक आत्मनिर्भर समाजवादी आर्थिक शक्ति में बदला जा सके।

देश को कृषि-प्रधान देश से ऐसे औद्योगीकृत देश में बदलना, जो आवश्यक मशीनों का उत्पादन करने में समर्थ हो, – इसी में कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की १४वीं कांग्रेस द्वारा निर्धारित सामान्य नीति का सार निहित था।

अतः समाजवादी औद्योगीकरण का लेनिनीय विचार सोवियत राज्य का एक तात्कालिक व्यावहारिक कार्यभार बन गया।

समाजवादी औद्योगीकरण की विशिष्टताएं और स्रोत

औद्योगीकरण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए पुराने कारख़ानों और फ़ैक्टरियों का नयी टेक्नोलाजी के आधार पर पुनर्निर्माण करना और उद्योग की बहुत-सी नयी शाखाओं की स्थापना सहित विशाल पूंजी निर्माण आरंभ करना आवश्यक है।

औद्योगीकरण की समाजवादी विधि क्या है और वह पूंजीवादी विधि से किस चीज़ में मूलतः भिन्न है?

पूंजीवादी देशों में औद्योगीकरण आम तौर से हल्के उद्योग से शुरू हुआ, जिसके विकास के लिए भारी उद्योग की अपेक्षा कम पूंजी-निवेश की आवश्यकता थी, जबकि पूंजी-आवर्त काफ़ी तेज़ी से हुआ। लेकिन इस तरीक़े से भारी उद्योग के निर्माण में कई दशक लग गये।

सोवियत संघ में यह विधि अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि बाह्य और आंतरिक परिस्थितियों ने भारी उद्योग के तेज़ गति से विकास को आवश्यक बना दिया। केवल संक्षिप्त अवधि में भारी उद्योग का विकास और जन अर्थव्यवस्था की मुख्य शाखाओं का नवीनतम टेक्नोलाजी से सज्जीकरण ही समाजवाद के भौतिक और टेक्नोलाजिकल आधारों के निर्माण को, तब पूंजीवादी घेरे में बंद सोवियत राज्य की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित बना सकते थे।

इस वजह से पूंजीगत निर्माण के लिए साधनों की खोज के बारे में

प्रश्न बड़ी तीव्रतापूर्वक उठा। पूंजीवादी देशों ने मेहनतकशों के निर्मम शोषण तथा छोटे मालिकों, ख़ास तौर से किसानों के स्वत्वहरण की क़ीमत पर औद्योगीकरण को पूरा किया था। उपनिवेशों और पिछड़े हुए देशों की लूट-खसोट, पराजित देशों से युद्ध के हर्जाने, अत्यंत कठोर शर्तों पर लिये गये विदेशी ऋण भी पूंजीवादी औद्योगीकरण के तीव्र विकास के स्रोत थे।

किंतु सोवियत राज्य के लिए औद्योगीकरण के ये सभी जन-विरोधी, लुटेरे तरीक़े अस्वीकार्य थे। न ही सोवियत संघ विदेशी ऋणों पर भरोसा कर सकता था क्योंकि पूंजीवादी देशों ने स्वीकार करने लायक़ शर्तों पर ऋण देने से इन्कार कर दिया। सोवियत जनता केवल अपनी ही शक्तियों पर भरोसा कर सकती तथा देश में ही समाजवादी औद्योगीकरण के लिए आवश्यक साधन खोज सकती थी।

सोवियत राज्य ने समाजवादी औद्योगीकरण के लिए साधन-संचय की समस्या को आंतरिक कोषों को जुटाकर और समाजवादी व्यवस्था की संभावनाओं का उपयोग करके हल किया। सोवियत सत्ता ने बुर्जुआ वर्ग और ज़मींदारों की संपत्ति का स्वत्वहरण किया, जिन्होंने क्रांति से पहले राष्ट्रीय आय के ७५ प्रतिशत भाग को हथिया लिया था और इन साधनों को भारी उद्योग के विकास में लगा दिया; उसने विदेशी राज्यों द्वारा ज़ारशाही को दिये गये ऋणों को रद्द कर दिया। इसने उसे ज़ारशाही सरकार के ऋणों पर विदेशी ऋणदाताओं को उच्च दरों में ब्याज देने तथा विदेशी पूंजीपतियों को लाभांश देने के भारी बोझ से बचा दिया, जो सालाना ६० करोड़ रूबल स्वर्ण तक पहुंच गये थे।

विदेश व्यापार की इजारेदारी ने सोवियत राज्य को निर्यात से प्राप्त संपूर्ण आय को अपने हाथों में संकेंद्रित करने तथा देश के औद्योगिक विकास के हितों को ध्यान में रखते हुए माल-आयात योजनानुसार करने की संभावना दी। सोवियत किसानों ने भी औद्योगीकरण के लिए साधन जुटाने में बड़ा योगदान किया। क्रांति के बाद ज़मीन पर स्वतंत्रतापूर्वक श्रम करने का अधिकार पाकर और ज़मींदारों को लगान देने से मुक्त होकर किसानों ने अपनी भौतिक स्थिति को काफ़ी मज़बूत बना लिया था और वे कृषि-मशीनों और अन्य औद्योगिक मालों के उत्पादन में दिलचस्पी रखते थे।

इन सभी वित्तीय संसाधनों ने सोवियत राज्य को बाह्य सहायता के बिना अपनी ही शक्ति पर औद्योगीकरण को कार्यान्वित करने की संभावना प्रदान की। कार्यभार यह था कि इन सभी संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग किया जाये और कड़ी किफ़ायत, श्रम उत्पादकता में बढ़ती, उत्पादन का यौक्तिकीकरण, उत्पादन-लागत की कमी, विभिन्न ऋण और सहकारी संस्थाओं तथा बचत बैंकों में आबादी की स्वतंत्र बचतों की वृद्धि और घरेलू ऋणों को जारी करके संसाधनों की खोज की जाये।

समाजवादी औद्योगीकरण के कार्यान्वयन के मार्ग निर्धारित करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केंद्रीय समिति के अप्रैल पूर्णाधिवेशन (१९२६) ने राजकीय उद्योग और कृषि के बीच सही और परस्पर लाभप्रद संबंधों के आधार पर मज़दूर वर्ग और कृषक वर्ग के बीच सहबंध को और मज़बूत बनाने की तात्कालिक आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया। पूर्णाधिवेशन ने किसानों के हितों को हानि पहुंचाते हुए उद्योग को विकसित करने की त्रोत्स्कीपंथियों और अन्य पार्टी-विरोधी गुटों के लेनिनवाद-विरोधी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। ऐसी नीति मज़दूरों और मेहनतकश किसानों के बीच सुदृढ़ सहबंध पर क़ायम समाजवाद के आधार को क्षति पहुंचाती।

३. महती औद्योगिक शक्ति में सोवियत संघ का रूपांतरण

जनसाधारण का श्रम उत्साह

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य द्वारा तैयार समाजवादी औद्योगीकरण के कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिए बड़े व्यावहारिक काम किये गये। आर्थिक और प्रशासनिक तंत्र को सरल तथा किफ़ायती बनाने और आर्थिक प्रबंध प्रणाली में सुधार करने के लिए राष्ट्रव्यापी क़दम उठाये गये। अक्तूबर १९२७ में जारी किये गये २० करोड़ रूबल से ज्यादा के औद्योगीकरण के पहले राजकीय ऋण बांडों को ६० लाख से अधिक लोगों ने अत्यल्प समय में ही ख़रीद लिया।

सोवियत राज्य द्वारा अमल में लाये गये क़दमों ने १९२६-२७ में ही पूंजीगत निर्माण में लगभग एक अरब रूबल तथा १९२९-३० में ५ अरब रूबल से अधिक निवेश करना संभव बना दिया। इसने विराट आधुनिक औद्योगिक उद्यमों का निर्माण शुरू करने में सहायता की। १९२७ में द्नेप्र पनबिजलीघर, १,५०० किलोमीटर लंबी तुर्किस्तान-साइबेरियाई रेलवे का निर्माण शुरू हुआ, जो दक्षिणी कज़ाखस्तान और मध्य एशिया के कपास उत्पादक क्षेत्रों को अनाज, इमारती लकड़ी और कोयले में समृद्ध साइबेरिया से जोड़नेवाला सबसे छोटा मार्ग है। कुज़्नेत्स्क, मग्नितोगोर्स्क और क्रिवोई रोग में विशाल लौह और इस्पात समुच्चयों के निर्माण के लिए तैयारियां चल रही थीं।

मेहनतकशों के सभी सामाजिक संगठनों ने देश के औद्योगीकरण में सक्रिय हिस्सा लिया। इस कार्यभार को पूरा करने में मज़दूर वर्ग के सबसे बड़े संगठन – ट्रेड-यूनियनों – ने विशाल भूमिका अदा की। सो, उत्पादन सम्मेलन मज़दूरों को औद्योगिक उद्यमों के प्रबंध में खींचने का एक महत्वपूर्ण रूप बन गये, जिनमें उत्पादन की स्थिति; श्रम अनुशासन का सुदृढ़ीकरण, श्रम उत्पादकता की वृद्धि जैसे प्रश्नों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता था। इन सम्मेलनों में मज़दूर, इंजीनियर, तकनीशियन, प्रबंधक और ट्रेड-यूनियन नेता भाग लेते थे।

मज़दूरों के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए ब्रिगेडों और अलग-अलग व्यक्तियों के आधार पर अप्रेंटिस कोर्सों का व्यापक जाल बिछाया गया। नव-निर्माण स्थलों पर काम करने के लिए आनेवाले बहुत-से अनपढ़ किसानों ने पेशे पाये और सुदक्ष कर्मी बने। मज़दूर वर्ग की पांतों से उद्योग के प्रबंधक कर्मीवृंद का गठन हुआ। देश में तकनीशियनों और इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का जाल अधिकाधिक व्यापक होता गया।

उत्पादन के यौक्तिकीकरण और श्रम उत्पादकता की उच्च, "तूफ़ानी" दरें प्राप्त करने के लिए मज़दूरों का बढ़ता उत्साह जन आंदोलन में व्यक्त हुआ। १९२६ की गर्मी में मास्को-कज़ान रेलवे के मरम्मतखाने में, जहां गृहयुद्ध के वर्षों में पहले कम्युनिस्ट सुब्बोत्निक का आयोजन किया गया था, देश की पहली "तूफ़ानी उत्पादन टोली" प्रकट हुई। यह निकोलाई नेक्रासोव की टोली थी, जिसने श्रम उत्पादकता में बड़ी वृद्धि पायी थी। १९२६-२७ में लेनिनीय कोम्सोमोल की

पहल पर लेनिनग्राद और मास्को के उद्यमों और उक्राइना तथा उराल के औद्योगिक केंद्रों में ऐसी बहुत-सी "तूफ़ानी उत्पादन टोलियां" प्रकट हुईं। इन "तूफ़ानी उत्पादन टोलियों" के सदस्यों और श्रमिकों के पूरे के पूरे समूहों ने श्रम उत्पादकता और सुदक्षता बढ़ाने तथा उत्पादन सम्मेलनों में भाग लेने का दायित्व अपने ऊपर लिया। "तूफ़ानी उत्पादन टोलियों" ने नये, समाजवादी आधारों पर श्रम के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

औद्योगीकरण की प्रारंभिक अवधि में मज़दूरों के उत्पादन सम्मेलनों ने व्यापक प्रसार पाया। इन सम्मेलनों में केवल उद्यमों के आर्थिक जीवन से संबंधित प्रश्नों पर ही विचार-विमर्श नहीं होता था, बल्कि वे उत्पादन सम्मेलनों के निर्णयों के प्रबंधकों द्वारा कार्यान्वयन का निरीक्षण भी करते थे।

सोवियत और पार्टी प्रेस ने मज़दूरों के श्रम उत्साह के नये रूपों का व्यापक प्रचार किया। अख़बारों ने लेनिनग्राद और मास्को की उन फ़ैक्टरियों में मज़दूरों की पहलों के बारे में लेख और रिपोर्ताज प्रकाशित किये, जो उसी उद्योग में बेहतर श्रम उत्पादकता प्राप्त करने की प्रतियोगिता में लगी हुई थीं। ऐसे अभियानों ने न केवल अलग-अलग उद्यमों में, बल्कि समग्र उद्योग में भी कार्य के प्रति मज़दूरों की उत्तरदायित्व-भावना बढ़ा दी। देश के "सर्वोत्तम उद्यम" के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा की गयी। "सर्वोत्तम मज़दूर" उपाधि के लिए प्रतियोगिताएं शुरू की गयीं। ये उत्पादन योजनाओं को निर्धारित समय से पहले ही पूरा करने के लिए आम समाजवादी स्पर्धा के नये रूप थे। जनसाधारण की रचनात्मक सक्रियता देश के औद्योगीकरण के वास्ते संघर्ष में एक निर्णायक कारक थी।

सोवियत समाज के इतिहास के बुर्जुआ जालसाज़ों द्वारा फैलायी गयी बातें सरासर निरर्थक हैं कि सोवियत संघ में औद्योगीकरण की सफलताएं श्रमिकों के "शोषण" की क़ीमत पर प्राप्त की गयीं। वास्तव में, सोवियत लोगों को कोई कम कठिनाइयों पर क़ाबू नहीं पाना पड़ा। 'समाजवाद की महान विजयों के पचास वर्ष' लेख में इस संबंध में कहा गया: "अगर सोवियत लोगों ने महानतम राजनीतिक चेतना, संगठन और साहस प्रदर्शित न किया होता, तो हमारा देश एक समाजवादी और अग्रणी औद्योगिक देश कभी नहीं बन पाता। याद

करें, साथियो, कि उन वर्षों में लोग कैसे रहे: अनाज के लिए राशन-व्यवस्था लागू थी, कपड़ों और जूतों का अभाव था, आवास समस्या विकट थी और अन्य विभिन्न कठिनाइयां थीं। लेकिन इन सभी कठिनाइयों और अभाव के बावजूद देश जनसाधारण के श्रम उत्साह से अक्षरश: खदबदा रहा था और निर्माण-परियोजनाओं – द्नेप्र पनबिजलीघर, मग्नितोगोर्स्क परियोजना, तुर्किस्तान-साइबेरियाई रेलवे, कोम्सोमोल्स्क-आन-आमूर और बेरेज़्निकी, ख़ार्कोव, चेल्याबिन्स्क और स्तालिनग्राद के विशाल ट्रैक्टर कारख़ानों तथा गोर्की और मास्को के मोटर कारख़ानों – की ओर स्वयंसेवकों का तांता बंध गया था, जहां समाजवादी उद्योग की अग्रिम चौकियों का निर्माण किया जा रहा था।"

लेकिन पार्टी की पांतों में सोवियत सत्ता और लेनिनवाद के विरोधी तत्वों – त्रोत्स्कीपंथियों और अन्य अवसरवादियों – ने देश के औद्योगीकरण के सफल कार्यान्वयन में बाधा पहुंचायी। १९२६ की गर्मी में उन्होंने पराजित विरोधी गुटों के बचे-खुचे हिस्सों से एक संयुक्त पार्टी-विरोधी गुट बनाया और एक भूमिगत सोवियत-विरोधी राजनीतिक पार्टी की स्थापना में जुट गये। सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण की संभावना से इन्कार करते हुए त्रोत्स्कीपंथियों ने मज़दूर वर्ग के बीच उसकी अपनी शक्ति में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने औद्योगीकरण की पूंजीवादी विधि और किसानों पर कर बढ़ाने की हिमायत की।

१५वीं पार्टी कांग्रेस ने घोषणा की कि त्रोत्स्कीपंथी विपक्ष का अनुसरण और उसके विचारों का प्रचार कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता से मेल नहीं खाता और इस पार्टी-विरोधी गुट के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया।

समाजवादी औद्योगीकरण की पहली सफलताएं

सोवियत जनगण ने अपने मार्ग की सभी कठिनाइयों पर क़ाबू पा लिया। उन्होंने अपने बड़े श्रम उत्साह से औद्योगिक विकास की तेज़ गति को सुनिश्चित बनाया। केवल १९२७ में ही बड़े उद्योगों के उत्पादन में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह औद्योगिक विकास का ऐसा अभूतपूर्व सूचक था, जिसे कोई भी पूंजीवादी देश नहीं प्राप्त कर सकता था।

विशाल औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित समय से पहले ही पूरा हो गया। मसलन, मग्नितोगोर्स्क धातुकर्म समुच्चय के निर्माण को २ वर्ष ११ महीने, कुज्नेत्स्क कोयला-खनन के निर्माण को २ वर्ष ४ महीने, तुर्किस्तान-साइबेरियाई रेलवे के निर्माण को चार वर्ष से कम समय में और स्तालिनग्राद ट्रैक्टर कारखाने के निर्माण को ११ महीने में ही पूरा कर दिया गया।

मास्को में बॉल-बेयरिंग के पहले कारखाने का, जिसकी सोवियत इंजीनियरी उद्योगों को बड़ी आवश्यकता थी, निर्माण अभूतपूर्व कम समय – १२ महीने – में ही पूरा कर दिया गया। देश में ढले इस्पात का उपयोग करते हुए इस कारखाने ने १९३२ में १० लाख बॉल-बेयरिंगों को तैयार किया और इस तरह उद्योग को उनके आयात की आवश्यकता से मुक्त कर दिया।

समाजवादी क्षेत्र उद्योग में बढ़ती प्रभुत्वकारी भूमिका अदा करता जा रहा था। १९२७ के अंत में कुल औद्योगिक उत्पादन में उसका हिस्सा ८० प्रतिशत से ऊपर था। इसका अर्थ यह था कि यह प्रश्न कि औद्योगिक क्षेत्र में "कौन किस पर विजय प्राप्त करेगा", समाजवाद के पक्ष में तय हो गया था।

सोवियत जनतंत्रों में उद्योगों में पूंजी-निवेश राष्ट्र के पैमाने पर पूंजी-निवेश से अधिक तेज़ी से बढ़ रहा था। इसने क्रांति-पूर्व काल से विरासत में प्राप्त ग़ैर-रूसी जातियों के आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता की। यदि १९२६-२७ के आर्थिक वर्ष में देश में कुल पूंजी-निवेश में १९२५-२६ की तुलना में १७ प्रतिशत की बढ़ती हुई, तो तुर्कमान सोवियत जनतंत्र में पूंजी-निवेश में ३६ प्रतिशत, ट्रांसकाकेशियाई फ़ेडरेशन (अज़रबैजान, जार्जिया, आर्मेनिया) में ४७ प्रतिशत की और उज़्बेकिस्तान में दुगुनी वृद्धि हुई।

उक्राइना, बेलोरूस और अन्य सोवियत जनतंत्रों में नये औद्योगिक उद्यमों का निर्माण और पुराने कारखानों तथा फ़ैक्टरियों का आधुनिकीकरण किया गया।

देश के औद्योगीकरण की सफलताओं के फलस्वरूप मज़दूर वर्ग की पांतों में वृद्धि हुई और उसके भौतिक तथा सांस्कृतिक स्तर ऊंचे उठे। विशाल आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद सोवियत सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ने मेहनतकशों की भौतिक स्थिति में सुधार करने के

लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया। १९२७ में फुटकर क़ीमतें कम कर दी गयीं। उस काल में मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी युद्ध-पूर्व स्तर से ५.४ प्रतिशत और अगर सामाजिक बीमे और सामुदायिक सेवाओं के लिए निर्धारित राजकीय बजट को ध्यान में रखा जाये तो २८.४ प्रतिशत ज़्यादा बढ़ गयी थी। फिर भी देश में १० लाख से अधिक लोग बेरोज़गार थे। आगामी वर्षों में बेरोज़गारी के उन्मूलन, मज़दूरी में कटौती किये बिना आठ घंटे के कार्य-दिवस के बजाय सात घंटे का कार्य-दिवस लागू करने, आवास-निर्माण, स्कूलों और अन्य जन-कल्याण परियोजनाओं के निर्माण के लिए व्ययों में वृद्धि हेतु अर्थव्यवस्था के विकास की योजना बनायी गयी।

१९२७ में सोवियत लोगों ने महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की १०वीं वर्षगांठ मनायी। सारी दुनिया के मेहनतकशों ने सोवियत लोगों के साथ यह तिथि मनायी। अनेक देशों के मज़दूर प्रतिनिधिमंडल वर्षगांठ समारोहों में भाग लेने के लिए मास्को आये। वे सोवियत संघ में समाजवादी निर्माण की सफलताओं से परिचित हुए, कारख़ानों, फ़ैक्टरियों, खानों में गये, मज़दूरों से बातचीत की, कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोवियत राज्य के नेताओं से मिले।

'सोवियत संघ के मित्र' नामक समाज की पहली कांग्रेस मास्को में हुई, जिसमें ४५ देशों के कोई १,००० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के विश्व ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया और सारी दुनिया के मेहनतकशों का साम्राज्य-वादी युद्ध के खिलाफ़ दृढ़ संघर्ष करने, विश्व के पहले सर्वहारा राज्य की रक्षा करने का आह्वान किया।

पहली पंचवर्षीय योजना

जन अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्सज्जीकरण के कार्यभार के संबंध में और उसके योजनाबद्ध विनियमन के अनुभव के संचय के साथ अल्प और दीर्घकालीन योजनाओं को समन्वित करके राजकीय योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता और भी तीव्रता से महसूस की गयी। दिसम्बर १९२७ में कम्युनिस्ट पार्टी की १५वीं कांग्रेस ने आर्थिक

विकास की पहली पंचवर्षीय योजना की तैयारी के बारे में निर्देश स्वीकार किये। सोवियत राजकीय योजना आयोग (गोसप्लान) को भारी उद्योग, ख़ास तौर से इंजीनियरी, धातुकर्म, विद्युत उत्पादन और ईंधन तथा रासायनिक उद्योग जैसी मुख्य शाखाओं के तेज़ विकास की अपेक्षाकृत ऊंची दरें निर्धारित करने का कार्यभार सौंपा गया। देहात में बढ़ते सहकारी आंदोलन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टरों और अन्य कृषि मशीनों के उत्पादन के अति तीव्र विकास की योजना बनायी गयी। इन सभी क़दमों का उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था का रूपांतरण करना था।

मई १६२६ में सोवियतों की पांचवीं कांग्रेस ने सोवियत संघ के आर्थिक विकास की पहली पंचवर्षीय योजना (१६२८-१६३२) को पुष्ट कर दिया।

पहली पंचवर्षीय योजना के निम्न कार्यभार थे: सोवियत संघ को कृषि-प्रधान देश से एक औद्योगीकृत देश में बदलना, कृषि सहित जन अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं का पुनर्सज्जीकरण और पुनर्गठन करने में समर्थ उद्योग की स्थापना करना; लाखों छोटे-छोटे, छिटफुट खेतों को समाजवादी विकास के मार्ग पर लाना, अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं से पूंजीवादी तत्वों का सफ़ाया करना, समाजवादी समाज के निर्माण के आर्थिक आधार की स्थापना करना; देश की रक्षा-क्षमता और स्वतंत्रता को मज़बूत बनाना; सोवियत लोगों के भौतिक कल्याण तथा सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाना।

योजना में कुल औद्योगिक उत्पादन में युद्ध-पूर्व स्तर (१६१३) के मुक़ाबले में २०० प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था थी। पंचवार्षिकी में अर्थव्यवस्था में ६४.६ अरब रूबल के पूंजी-निवेश की व्यवस्था थी, जिनमें से १६.५ अरब औद्योगिक उद्यमों के निर्माण के लिए निर्धारित किये गये थे। इसे भारी उद्योग के विकास की तीव्र गति को सुनिश्चित करना था।

पहली पंचवर्षीय योजना में आबादी की ख़ुशहाली और सांस्कृतिक स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि की भी व्यवस्था थी। पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय में १०३ प्रतिशत, मज़दूरों की वास्तविक आय में ७१ प्रतिशत और किसानों की आय में ६७ प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गयी थी। योजना में आवास-निर्माण पर बड़ा ध्यान दिया गया था, अनिवार्य

प्रारंभिक शिक्षा में संक्रमण, स्कूलों, संस्कृति-प्रासादों और अन्य सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में बड़ी वृद्धि निर्धारित की गयी।

सोवियत लोग पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यभारों को पूरा करने में जुट गये। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तैयार की गयी विकास योजना के कार्यों को अपने ही कार्य माने, उन्हें योजना की यथार्थता पर विश्वास था और इसीलिए उन्होंने विकास की कठिनाइयों पर साहसपूर्वक क़ाबू पा लिया।

लाखों लोग विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए निर्जन इलाक़ों में गये। सारा देश एक विशाल निर्माण-स्थल में बदल गया था। सोवियत लेखक बोरिस गोर्बातोव ने उस काल के बारे में लिखा: "उन वर्षों में देश भर में पहियों की चरमराहट और घरघराहट लगातार हो रही थी – हर चीज़ और हर व्यक्ति ही रेल, सड़क और नाव से कहीं न कहीं आ-जा रहे थे, उजाड़ भूमि में खड़ा वैगन रेलवे स्टेशन में, तिरपाल का टेंट एक घर में और झोंपड़ियां नगर में बदल गयीं... वे महान, दूभर, आनंदभरे रोमांचों और उपलब्धियों के दिन थे। संसार ने निर्माण के ऐसे पैमाने को अभी नहीं देखा है।"*

समाजवादी प्रतियोगिता का व्यापक पैमाने पर संगठन

२० जनवरी, १६२६ को 'प्राव्दा' ने लेनिन का लेख 'प्रतियोगिता कैसे संगठित की जानी चाहिए?' छापा, जिसे उन्होंने अक्तूबर क्रांति के शीघ्र बाद ही लिखा था। लेख में ज़ोर दिया गया था कि "समाजवाद के अंतर्गत प्रतियोगिता का समाप्त होना तो दूर रहा, इसके विपरीत, वह पहली बार सचमुच **व्यापक** तथा सचमुच ही **जनव्यापी** पैमाने पर उसके उपयोग का... अवसर उत्पन्न करता है"।**

---

* बोरिस गोर्बातोव, संग्रहीत रचनाएं, खंड ३, मास्को, १६५५, पृ० १३ (रूसी में)।

** व्ला० इ० लेनिन, 'प्रतियोगिता कैसे संगठित की जानी चाहिए?', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ७, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १६८४, पृ० ४०४।

श्रमिकों ने लेनिन के लेख को आम समाजवादी प्रतियोगिता के और आगे विकास के लिए आह्वान के रूप में लिया। कम्युनिस्ट और कोम्सोमोल सदस्य समाजवादी प्रतियोगिता करनेवालों की पहली पांतों में थे। उन्होंने श्रम परिणामों के व्यापक प्रचार, तुलना, अग्रणी अनुभव के आदान-प्रदान, पिछड़े हुए मज़दूरों को साथीवत् सहायता, श्रम के भौतिक और नैतिक प्रोत्साहन के सामंजस्य जैसे समाजवादी प्रतियोगिता के महत्वपूर्ण तत्वों की व्यावहारिक पुष्टि की। समाजवादी प्रतियोगिता ने सर्वप्रथम कार्य-दिवस के युक्तियुक्त उपयोग, श्रम की नयी विधियों, श्रम अनुशासन के दृढ़ीकरण और साथीवत् पारस्परिक सहायता के ज़रिये उत्पादन वृद्धि में योगदान किया।

१६२६ के अंत तक समाजवादी प्रतियोगिता लगभग सभी बड़े उद्यमों में फैल गयी थी। परिणामस्वरूप, १६२६ में बहुत-से उद्योगों में श्रम उत्पादकता १०-२० प्रतिशत तक बढ़ गयी। प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में २५ प्रतिशत सालाना और भारी उद्योग के उत्पादन में ३१ प्रतिशत सालाना की वृद्धि हुई।

सोवियत संघ में पहली बार कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उद्योग का हिस्सा कृषि के हिस्से से बढ़ गया। अगर १६२७-२८ में उद्योग का हिस्सा ४५.२ प्रतिशत और कृषि का हिस्सा ५४.८ प्रतिशत था, तो १६२६-३० में उद्योग का हिस्सा ५३ प्रतिशत और कृषि का हिस्सा ४७ प्रतिशत था। इसने १६३० में हुई कम्युनिस्ट पार्टी की १६वीं कांग्रेस को यह निष्कर्ष निकालने का आधार प्रदान किया कि सोवियत संघ एक पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देश से एक विकसित औद्योगीकृत देश में अभूतपूर्व तेज़ गति से परिवर्तित हो रहा है।

उच्च विकास दरों के बावजूद सोवियत संघ औद्योगिक विकास के स्तर की दृष्टि से मुख्य पूंजीवादी देशों से अब भी पिछड़ा हुआ था। मिसाल के लिए, सोवियत संघ ने १६२६ में अमरीका के ४ करोड़ ३० लाख टन, जर्मनी के एक करोड़ ३२ लाख टन, फ़ांस के एक करोड़ ३ लाख टन, ब्रिटेन के ७७ लाख टन पिंड लोहे के उत्पादन के मुक़ाबले में ४० लाख टन पिंड लोहे का उत्पादन किया। इस्पात और वेल्लित लोहे तथा बिजली के उत्पादन में भी लगभग ऐसे ही अंतर बने हुए थे। स्थिति का तक़ाज़ा था कि पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये। अग्रणी उद्यमों के कर्मी-समूहों ने नारा

दिया: "पंचवर्षीय योजना को चार सालों में पूरा करो!" इस नारे को वर्कशॉप के प्रत्येक मज़दूर के तूफ़ानी श्रम से लेकर संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुधरे प्रबंध तक सभी उत्पादन कड़ियों के समन्वित कार्य के ज़रिये ही अमली जामा पहनाया जा सकता था। इसलिए पार्टी संगठनों, ट्रेड-यूनियनों ने श्रम उत्पादकता में लगातार वृद्धि करने, समाजवादी प्रतियोगिता और "तूफ़ानी उत्पादन श्रम" आंदोलन को संगठित करने, मज़दूरों, तकनीशियनों, इंजीनियरों की सुदक्षता बढ़ाने तथा उद्योग के प्रबंध की विधियों में सुधार करने के उद्देश्य से जन-साधारण के बीच व्यापक प्रचार-कार्य चलाया।

नयी टेक्नोलाजी के प्रयोग में पारंगति पाना

पहली पंचवर्षीय योजना की सफल पूर्ति के प्रयासों के दौरान निर्मित औद्योगिक उद्यमों को पूरी क्षमता से काम में लाने और टेक्नोलाजी के कारगर उपयोग का प्रश्न बड़े ज्वलंत ढंग से पेश हुआ। संजटिल, नयी सोवियत या विदेशी मशीनों ने, जिनसे इन कारख़ानों और फ़ैक्ट-रियों को सज्जित किया गया था, मज़दूरों से उच्च सुदक्षताओं की मांग की, जिनमें से अधिकांश अभी हाल ही में ख़रादी बने थे। उन्हें अभी नयी मशीनें चलाना, नयी टेक्नोलाजिकल विधियों से काम लेना नहीं आता था। इस संबंध में स्तालिनग्राद ट्रैक्टर कारख़ाने का उदाहरण प्रासंगिक है, जिसके निर्माण में ११ महीने ही लगे थे, लेकिन एक साल से भी अधिक समय तक वह अपनी निर्धारित क्षमता नहीं प्राप्त कर सका।

"हमने ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए नवीनतम मशीनें और उपकरण लिये," भारी उद्योग के जन कमिसार गेओर्गी ओर्जोनिकीद्ज़े ने कहा, "लेकिन अब हम ट्रैक्टर कैसे बनायें? हम लंबे समय तक इन मशीनों के इर्द-गिर्द चक्कर काटते रहे... हम बड़े कष्ट उठाते रहे, उठाते रहे, लेकिन इन मशीनों को ढंग से चलाना हमें आता ही न था।"

समाचारपत्र 'प्राव्दा' ने इस ट्रैक्टर कारख़ाने को चालू करने में प्रस्तुत कठिनाइयों के बारे में एक लेख छापा। इसके उत्तर में लेनिन-

ग्राद के 'क्रास्नी पुतीलोवेत्स' कारख़ाने* के पेशेवर मज़दूरों ने स्तालिनग्राद के ट्रैक्टर-निर्माताओं के नाम एक खुला पत्र प्रकाशित कराया। लेनिनग्राद के मज़दूरों ने, जो देश में ट्रैक्टर-निर्माण की टेक्नोलाजी में पारंगति प्राप्त करनेवाले पहले मज़दूर थे, स्तालिनग्राद के ट्रैक्टर-निर्माताओं को ठोस सहायता प्रदान की।

स्थिति इस वजह से भी और पेचीदा बन गयी कि कुछ प्रशासकों और प्रबंधकों ने नयी टेक्नोलाजी के प्रति उपेक्षापूर्ण रुख़ अपनाया। टेक्नोलाजी पर अधिकार पाने के लिए जन आंदोलन से ही स्थिति सुधर सकती थी। कारख़ानों, फ़ैक्टरियों और खानों में तथा नवनिर्माण स्थलों पर नयी टेक्नोलाजी में प्रवीणता पाने की प्रतियोगिताएं फैल गयीं। उद्यमों में सर्वत्र विभिन्न प्रशिक्षण मंडल, कोर्स और विद्यालय खोले गये, जहां मज़दूरों ने नयी मशीनों और युक्तियुक्त टेक्नोलाजिकल विधियों तथा श्रम के उत्कृष्ट उपायों के बारे में जानकारी पायी। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का जाल व्यापक होता गया। विभिन्न सम्मेलनों, व्याख्यानों, आदि के आयोजन और विशेष टेक्नोलाजिकल परीक्षा की व्यवस्था की बदौलत टेक्नोलाजिकल ज्ञान का व्यापक प्रचार फैल गया। नवनिर्मित उद्यमों के मज़दूर पहले ही से कार्यरत कारख़ानों और फ़ैक्टरियों में अध्ययन-यात्राओं पर गये। इस तरह से प्राप्त टेक्नोलाजिकल जानकारी ने मज़दूरों को अपने काम का उस्ताद बनने में सहायता की। शारीरिक श्रम करनेवाले कल के हज़ारों मज़दूरों और निर्माणकर्मियों ने नये पेशे पाये और सुयोग्य फ़िटर, ख़रादी, इस्पातकर्मी और कोयला काटने की मशीनों के चालक बने।

सोवियत राज्य ने प्रबंधकों की टेक्नोलाजिकल जानकारी बढ़ाने और उच्च योग्यताप्राप्त इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए क़दम उठाये। औद्योगिक अकादमियों और विशेष कोर्सों का जाल व्यापक बनाया गया, जहां औद्योगिक प्रबंधक अध्ययन करते थे। उच्च शिक्षा संस्थानों में मज़दूर संकाय खोले गये, जो युवा मेहनतकशों को इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए तैयार करते थे। तकनीकी इंस्टीट्यूटों और व्यावसायिक विद्यालयों में पढ़नेवाले कुल छात्रों में मज़दूरों

---

* अब 'कीरोव' कारख़ाना, अपनी समृद्ध क्रांतिकारी परंपराओं के लिए विख्यात एक सबसे पुराना औद्योगिक प्रतिष्ठान। – सं०

की संख्या लगभग ७५ प्रतिशत थी। पहली पंचवर्षीय योजनावधि में बड़े उद्योग ने लगभग एक लाख नये इंजीनियर और तकनीशियन पाये। यह सोवियत औद्योगिक बुद्धिजीवियों की नयी पीढ़ी थी, जिन्होंने रूस के पुराने बुद्धिजीवियों के सर्वोत्तम प्रतिनिधियों के साथ मिलकर देश के समाजवादी औद्योगीकरण की योजना को कार्यान्वित करने में मज़दूर वर्ग की सहायता करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।

देश के औद्योगीकरण में सोवियत मज़दूरों और इंजीनियरों की भूमिका को कम करने का प्रयास करते हुए कुछ बुर्जुआ इतिहासकार उस काल में सोवियत संघ में काम करने के लिए बुलाये गये विदेशी विशेषज्ञों के महत्व को स्पष्टतः बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। वास्तव में, सोवियत औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें चालू करने में केवल ४,५०० विदेशी मज़दूरों और विशेषज्ञों – सोवियत मज़दूरों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की कुल संख्या के एक प्रतिशत के चंद १०० वें भाग ही ने हिस्सा लिया।

अपनी औद्योगिक शक्ति का निर्माण करते हुए सोवियत संघ ने पूंजीवादी देशों की इंजीनियरी उपलब्धियों से अपने को पृथक् नहीं किया। सोवियत इंजीनियरों, तकनीशियनों और मज़दूरों ने विदेशी अनुभव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उनमें से बहुत-से अमरीका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ़्रांस, आदि देशों में कल-कारख़ानों में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गये। सोवियत संघ को मशीनों और उपकरणों का आयात भी करना पड़ा। १६३१ में सोवियत संघ विश्व बाज़ार में मशीनों का सबसे बड़ा ख़रीदार होता था: उसने जर्मन और ब्रिटिश लेथ मशीनों के निर्यात के आधे से अधिक भाग तथा अमरीकी निर्यात के तीसरे भाग का आयात किया। स्वयं विदेशी व्यापारियों ने स्वीकार किया कि बड़ी मंदी (१६२६-१६३२) के वर्षों में अनेक विदेशी फ़र्में सोवियत आर्डरों की बदौलत ही क़ायम रह सकीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सोवियत संघ अपने विदेश व्यापार के दायित्वों को निर्दोष ढंग से पूरा करता है और कि सोवियत संघ के साथ व्यापार का विस्तार लाभकारी कार्य है। लेकिन सोवियत आयात कभी भी घरेलू उत्पादन के १२-१३ प्रतिशत से ज़्यादा नहीं था और १६३२ में, जब सोवियत उद्योग कई क़िस्म के संयंत्रों, ट्रैक्टरों और बॉल-बेयरिंगों का उत्पादन करने लगा, तो आयात का हिस्सा गिरकर ४.६ प्रतिशत

तक हो गया। हालांकि सोवियत संघ विदेशी फ़र्मों से तकनीकी सहायता मांगने को विवश था, लेकिन सभी ही विदेशी फ़र्में सोवियत आर्डरों को पूरा न कर सकीं। अतः अमरीकी फ़र्म 'आर्थर जी० मैकी एंड कं०' के साथ हुए समझौते को, जिसने मग्नितोगोर्स्क धातुकर्म समुच्चय की डिज़ाइन तैयार करने का दायित्व लिया था, दो कारणों से रद्द करना पड़ा। पहले तो उसने परियोजना की डिज़ाइन बड़े विलंब से दी और दूसरे यह डिज़ाइन स्वीकार करने योग्य नहीं निकली। अंत में इस विशाल समुच्चय की डिज़ाइन तैयार करने का काम सोवियत विशेषज्ञों को सौंपा गया। १७ सोवियत डिज़ाइन संगठनों ने इस परियोजना की डिज़ाइन तैयार की और इस पेचीदे कार्यभार को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। कई विदेशी विशेषज्ञों ने दावा किया कि सोवियत रूस बड़ी क्षमता की ऐसी धमन और खुली भट्ठियों तथा रोलिंग मिलों का निर्माण शुरू करने के लिए पर्याप्ततः विकसित नहीं हुआ है, जो विकसित पूंजीवादी देशों तक में नहीं हैं। कुज़्नेत्स्क समुच्चय के प्रमुख इंजीनियर इवान बार्दिन (बाद में सुविख्यात अकादमीशियन) के साथ बातचीत करते हुए अमरीकी फ़र्म 'फ्रेन' के एक प्रतिनिधि ने कहा: "हम यहां १५० टन क्षमता की खुली भट्ठियों और बड़ी क्षमता की ऐसी धमन-भट्ठियों तथा रोलिंग मिलों के निर्माण को बिल्कुल असंभव मानते हैं, जैसी आपने सोची हैं। आपको समझना चाहिए कि अमरीका तक में हम अभी ऐसी परियोजनाओं का निर्माण शुरू ही कर रहे हैं। अनुभव के बिना, मशीनों के बिना और अपने अदक्ष मज़दूरों से आप यह कैसे करेंगे?" *

लेकिन इस परियोजना के अनोखेपन और जटिलता से सोवियत लोग नहीं डरे। निर्माताओं के निस्स्वार्थ प्रयासों ने काम के निर्धारित कोटों और अवधियों के बारे में आम धारणाओं को उलट-पुलट दिया। उदाहरणार्थ, जबकि विदेशी विशेषज्ञों ने कोक-ओवन बैटरी नं० ८ की भट्ठियों को पांच महीने में लगाने की योजना बनायी थी, मग्नितोगोर्स्क के मज़दूरों ने उन्हें ६७ दिनों में ही लगा दिया। उन्हीं विशेषज्ञों ने केंद्रीय विद्युत स्टेशन में टर्बाइन लगाने के लिए तीन महीने के समय की

---

* इ० प० बार्दिन, 'एक इंजीनियर का जीवन', मास्को, १९३८, पृ० १९६ (रूसी में)।

मांग की थी, लेकिन सोवियत निर्माताओं की एक टोली ने उसे २१ दिनों में ही पूरा कर दिया। मग्नितोगोर्स्क में काम करनेवाले अमरीकी इंजीनियर यह असंभव मानते थे कि जाड़े में धमन-भट्ठी चलायी जा सकेगी। परंतु सोवियत मज़दूरों और विशेषज्ञों ने इस कार्य को सफलता-पूर्वक पूरा कर दिया और १ फ़रवरी, १९३२ को यूरोप में सबसे बड़ी भट्ठी ने अपने पहले पिंड लौह का उत्पादन करके विशाल मग्नितोगोर्स्क धातुकर्म समुच्चय के चालू होने की घोषणा की। अगर तत्कालीन मानकों के अनुसार, पूंजीवादी दुनिया में सबसे बड़े धातुकर्म कारख़ाने, अमरीकी गैरी कारख़ाने के निर्माण में १०-१२ साल लगे, तो अपनी क्षमता में अमरीकी कारख़ाने के ही बराबर मग्नितोगोर्स्क समुच्चय का निर्माण लगभग उसके आधे समय में ही पूरा हो गया।

ऐसे ही उत्साह के साथ कुज़्नेत्स्क धातुकर्म समुच्चय का भी निर्माण किया गया। निर्माण-कार्य साइबेरिया के शून्य से ५०° सें० नीचे के तापमान में भी जारी रहा, जबकि ज़मीन डेढ़ मीटर तक जम जाती थी। १९३२ के अंत तक यह परियोजना अपनी पूर्ण क्षमता से काम करनेवाला उद्यम बन गयी थी।

देश को धातुओं, मशीनों, ईंधन और अन्य उत्पादों की सप्लाई करने के लिए दूसरे कारख़ाने, फ़ैक्टरियां और समुच्चय भी तेज़ी से बनाये जा रहे थे।

कई उद्योगों ने, जिनमें तेल, विद्युत इंजीनियरी, ट्रैक्टर निर्माण, सामान्य मशीन निर्माण उद्योग शामिल थे, १९३१ के अंत तक (अर्थात ढाई-तीन वर्षों में ही) अपनी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा कर दिया। इन सफलताओं ने दिखा दिया कि अग्रणी उद्यमों द्वारा पंचवर्षीय योजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य पूर्णत: अमल में लाने योग्य था। ये नयी टेक्नोलाजी के समारंभ और प्रयोग की पहली उप-लब्धियां थीं।

नये विशाल कारख़ानों, फ़ैक्टरियों, बिजलीघरों और खानों ने सोवियत अर्थव्यवस्था का कायापलट कर दिया और समूची अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्सज्जीकरण के लिए सुदृढ़ आधार की स्थापना की।

समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण : पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य परिणाम

कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सोवियत जनता ने पहली पंचवर्षीय योजना को निर्धारित समय से पूर्व ही – चार वर्ष तीन महीने में, यानी १ जनवरी, १९३३ तक पूरा कर दिया। यह एक बड़ी विजय थी। पंचवार्षिकी के कार्यान्वयन के दौरान पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि को पूरा करने के ऐसे मौलिक कार्यभार संपन्न किये गये, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधारों का निर्माण, बहुपद्धति वाली आर्थिक प्रणाली का उन्मूलन, सोवियत संघ की आर्थिक स्वतंत्रता और रक्षा-क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

पंचवर्षीय योजना अवधि में सोवियत संघ का एकदम कायापलट हो गया। औद्योगिक उत्पादन की मात्रा काफ़ी बढ़ गयी, भारी उद्योग और उसकी मुख्य शाखा मशीन-निर्माण बड़ी ही तेज़ गति से विकसित हुए। पंचवार्षिकी के अंत तक मशीन-निर्माण उद्योग के उत्पादन में ३०० प्रतिशत की तथा कृषि-मशीनों के उत्पादन में ४५० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। अल्प काल में ट्रैक्टर, विमान, मोटर, बॉल-बेयरिंग निर्माण, रासायनिक, संश्लिष्ट रबड़ और मशीनी औज़ार निर्माण जैसी आधुनिक भारी उद्योग की नयी शाखाएं प्रकट हो गयीं, जिनका पहले रूस में कोई अस्तित्व नहीं था।

इन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की सालाना औसत विकास-दर २२ प्रतिशत थी। इतनी तेज़ विकास-दर किसी भी पूंजीवादी देश में अपने विकास के चरमोत्कर्ष काल तक में नहीं पायी गयी।

पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में १,५०० नयी औद्योगिक परियोजनाएं चालू की गयीं। परिणामस्वरूप, १९३२ के अंत तक सोवियत संघ ने तेल, पिंड लौह और मशीनों के उत्पादन में विश्व में दूसरा तथा बिजली उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया।

तीव्र औद्योगिक विकास ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के सहसंबंध में परिवर्तन सुनिश्चित किये। १९३२ में सोवियत संघ के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा १९२८ के ४८ प्रतिशत के मुक़ाबले में ७० प्रतिशत था। इसका अर्थ यह था कि पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्यभार – देश का कृषि-प्रधान देश से औद्योगिक देश में

रूपांतरण – सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था।

योजना की पूर्ति के फलस्वरूप केवल सोवियत अर्थव्यवस्था का बड़ा परिमाणात्मक विकास ही नहीं हुआ, बल्कि उसके गुणात्मक सूचकों में सुधार करना, सबसे पहले, श्रम उत्पादकता में तेज़ वृद्धि प्राप्त करना भी संभव हो गया। मिसाल के लिए, टेक्नोलाजिकल पुनर्सज्जीकरण और उत्पादन के बेहतर संगठन के कारण श्रम का स्वरूप बदल गया और पहली पंचवार्षिकी में उद्योग और भारी उद्योग में श्रम उत्पादकता में क्रमशः ४१ और ५० प्रतिशत की बढ़ती हुई।

उत्पादक शक्तियों के विनियोग में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। विशाल प्राकृतिक संसाधनों को, जिनका पहले दोहन नहीं हुआ था, आर्थिक परिसंचरण में खींच लाया गया। उराल, साइबेरिया, सुदूर पूर्व, कज़ाख़स्तान, मध्य एशियाई जनतंत्रों और ट्रांसकाकेशिया में नये औद्योगिक केंद्र प्रकट हुए। पहली पंचवार्षिकी में सोवियत जातीय जनतंत्रों के अधिक तेज़ आर्थिक विकास की व्यवस्था की गयी थी, ताकि विगत से उन्हें विरासत में प्राप्त पिछड़ेपन को पहले कम और फिर एकदम दूर किया जा सके। इस सबने न केवल आर्थिक आधार और उत्पादन तथा आर्थिक संबंधों को बड़ा व्यापक बनाया, बल्कि इन क्षेत्रों में घट रही अनुकूल सामाजिक प्रक्रियाओं को भी जबर्दस्त प्रेरणा प्रदान की।

ऐतिहासिक रूप से बहुत थोड़ी अवधि में कार्यान्वित उत्पादन के सुसंगत समाजीकरण के फलस्वरूप देश में समाजवादी प्रणाली की विजय हुई। यदि १९२९ में राष्ट्रीय आय में उसका हिस्सा मात्र ५९ प्रतिशत था, तो १९३२ में वह ९३ प्रतिशत हो गया। उद्योग और कृषि में समाजवादी पद्धति प्रभुत्वशाली हो गयी। पहली पंचवार्षिकी के अंत तक अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीवादी क्षेत्र का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया था। नयी आर्थिक नीति के ज़माने के शहरी बुर्जुआ संस्तर का व्यापार तथा उद्योग से सफ़ाया कर दिया गया।

सोवियत समाज की उत्पादक शक्तियों में ये सभी परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन उत्पादन संबंधों में गहन परिवर्तनों के साथ-साथ हुए। यह, सर्वप्रथम, उत्पादन साधनों पर सार्वजनिक, समाजवादी स्वामित्व की बढ़ती भूमिका, सोवियत अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर नियोजित संगठन, श्रम के सामाजिक वितरण के गहनीकरण और समाजवादी

अनुशासन के सुदृढ़ीकरण में प्रकट हुआ।

इन प्रक्रियाओं ने अपनी बारी में विभिन्न बड़ी सामाजिक समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया। १९३० के अंत तक सोवियत संघ में बेरोज़गारी का जड़ से उन्मूलन किया जा चुका था। रोज़गार दफ़्तर बंद कर दिये गये। अख़बारों में और फ़ैक्टरियों के फाटकों पर "आवश्यकता है..." के विज्ञापन लगाये जाने लगे। श्रमिकों को व्यवस्थित ढंग से भरती किया जाने लगा और औद्योगिक उद्यमों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामूहिक समझौतों का प्रचलन हुआ। पहली पंचवर्षीय योजनावधि में मज़दूरों और कर्मचारियों की संख्या में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई। १९३२ तक लगभग सभी औद्योगिक उद्यमों में सात घंटे का कार्य-दिवस लागू किया जा चुका था, जबकि हानिकर परिस्थितियों वाले उद्योगों ने छः घंटे का कार्य-दिवस लागू किया। उद्योग और निर्माण में लगे कर्मियों की वास्तविक आय में बड़ी वृद्धि हुई। जन शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और कला के विकास के कार्यक्रम की अतिपूर्ति की गयी। इन उद्देश्यों के लिए व्यय में योजना में निर्धारित १६० प्रतिशत के मुक़ाबले में ३०० प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह सोवियत अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी रूपांतरणों के साथ सांस्कृतिक क्रांति घटी, जिसने सार्वजनिक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा लागू की, निरक्षरता का उन्मूलन किया और बड़ी संख्या में सुयोग्य कर्मी प्रशिक्षित किये।

सोवियत जनगण ठीक ही अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की ऐतिहासिक भूमिका का उच्च मूल्यांकन करते हैं, जो दुनिया के पहले समाजवादी राज्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण मंज़िल थी और जिसने समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा सभी भावी योजनाओं की आधारशिला रखी।

जन अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण की पूर्ति

पहली पंचवर्षीय योजना की सफल पूर्ति ने देश के और आगे सुसंगत समाजवादी औद्योगीकरण, जनगण की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति हेतु उसकी उत्पादक और टेक्नोलाजिकल क्षमता में वृद्धि के लिए एक मज़बूत आधार का काम किया।

अतः समाजवाद के भौतिक और टेक्नोलाजिकल आधार के निर्माण की पूर्ति और सोवियत संघ में समाजवादी समाज का निर्माण निकट के आगामी वर्षों के मुख्य उद्देश्य बन गये। व्यापक सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद १७वीं पार्टी कांग्रेस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना (१६३३-१६३७) के प्रारूप को पुष्ट कर दिया। नवम्बर १६३४ में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और जन कमिसार परिषद ने योजना की वैधानिक रूप से पुष्टि की। आगामी पांच वर्षों में मूल राजनीतिक कार्य थे अर्थव्यवस्था से बचे-खुचे पूंजीवादी तत्वों और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण पैदा करनेवाले कारणों का उन्मूलन तथा समाजवादी उत्पादन संबंधों का सुदृढ़ीकरण और विकास। अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण की पूर्ति मुख्य आर्थिक कार्यभार थी और नयी टेक्नोलाजी पर अमल करना इस पूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी। योजना में पांच वर्ष में औद्योगिक उत्पादन को दुगुना करने की व्यवस्था थी। लौह और इस्पात उद्योग तथा अलौह धातु उद्योगों के लिए उच्च उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये। तेल निष्कर्षण, कोयला खनन और रेल इंजिनों तथा वैगनों के उत्पादन में बड़ी वृद्धि करने की भी व्यवस्था की गयी थी। रासायनिक उत्पादन में बड़ा विकास पाया जाना था, जबकि बिजली उत्पादन में १८० प्रतिशत की बढ़ती होनी थी। नये और पुनर्निर्मित उद्यमों में कुल निवेश पहली पंचवार्षिकी के कुल निवेश से तिगुना अधिक था।

नियोजित नव-निर्माण की दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश की उत्पादक शक्तियों के बेहतर वितरण और सोवियत जनतंत्रों के त्वरित आर्थिक विकास की व्यवस्था थी। देश के पूर्वी प्रदेशों (उराल, पश्चिमी और पूर्वी साइबेरिया, बश्कीरिया, कज़ाख़स्तान और मध्य एशिया) में नये औद्योगिक केंद्र बनाये जाने थे। योजना में हल्के और खाद्य उद्योगों को कच्चे मालों के स्रोतों के निकट स्थापित करने की भी व्यवस्था थी। सूती मिलों के एक बड़े भाग की स्थापना मध्य एशियाई और ट्रांसकाकेशियाई जनतंत्रों और साइबेरिया में की जानेवाली थी। अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण की पूर्ति ने सर्वप्रथम मशीन-निर्माण के तीव्र विकास का तक़ाज़ा किया।

१६३३-३४ में नोवो-क्रामातोर्स्क मशीन-निर्माण संयंत्र, उराल भारी मशीन-निर्माण संयंत्र और चेल्याबिन्स्क ट्रैक्टर कारखाना चालू

किये गये। लुगान्स्क में रेल इंजिन निर्माण कारख़ाने का निर्माण पूरा किया गया और उराल वैगन निर्माण संयंत्र, नोवोचेर्कास्क रेल इंजिन निर्माण संयंत्र तथा अन्य बहुत से औद्योगिक उद्यम चालू किये गये। मोटरगाड़ियों, मशीनी औज़ारों, कम्बाइन हार्वेस्टरों और दूसरी मशीनों के उत्पादन में बड़ी वृद्धि प्राप्त की गयी। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मोटर संयंत्र आधुनिक लारियों और कारों का उत्पादन करने लगे। ट्रैक्टर कारख़ाने कैटरपिलर ट्रैक्टर बनाने लगे और सोवियत संघ कम्बाइन हार्वेस्टरों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। देश की आर्थिक स्वतंत्रता सुदृढ़ हुई। सोवियत संघ बहुविध उत्पादों का उत्पादन करने लगा, जिसने विदेश व्यापार के स्वरूप को आमूलतः बदल दिया; वास्तव में विभिन्न माल आयात की सूची से हटकर निर्यात की सूची में आ गये। हालांकि देश को अब भी कुछ संजटिल मशीनों, उच्च कोटि के इस्पात, अलौह और दुर्लभ धातुओं का आयात करना पड़ रहा था, फिर भी विश्व बाज़ार में सोवियत इंजीनियरी उद्योग के माल अधिकाधिक प्रकट होने लगे।

संपूर्ण अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण की पूर्ति ने धातुकर्म उद्योग के तीव्र विकास की मांग की। इस कार्यभार को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में क्रिवोई रोग, नोवोलीपेत्स्क और नोवोतूल्स्की धातुकर्म संयंत्रों जैसे नये विशाल लौह और इस्पात संयंत्र और अन्य धातुकर्म उद्यम चालू किये गये। देश के दूसरे, "पूर्वी" कोयला और धातु उत्पादक क्षेत्र में मुख्य समुच्चयों– मग्नितोगोर्स्क और कुज़्नेत्स्क धातुकर्म समुच्चयों–का उत्पादन बढ़ता गया। नये प्रतिष्ठानों को सोवियत मशीनों से लैस किया जा रहा था। १९३४ में मग्नितोगोर्स्क, कुज़्नेत्स्क और मकेयेव्का संयंत्रों ने क्रांति-पूर्व रूस में उत्पादित समस्त कच्चा लोहा उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन किया।

अलौह धातु उद्योग ने भी, जिसके समक्ष देश की अलौह धातुओं की मांग को पूरा करने का कार्यभार प्रस्तुत था, इन वर्षों में कोई कम सफलताएं नहीं प्राप्त कीं। द्नेप्र अल्युमिनियम संयंत्र और चेल्याबिन्स्क जस्ता संयंत्र जैसे बड़े उद्यमों का निर्माण पूरा किया गया; बाल्क़श और मध्य उराल तांबा संगलन संयंत्रों और उराल अल्युमिनियम संयंत्र का निर्माण ज़ोरों से चल रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान

अलौह धातुओं के उत्पादन में ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१९३५ में गोएलरो योजना के १५ साल पूरे हो गये। उस समय तक रूस के बिजलीकरण की लेनिनीय योजना की तिगुनी से अधिक पूर्ति की जा चुकी थी: १७ बड़े ताप और ११ पनबिजलीघर चालू हो चुके थे। १९३०-१९३५ की अवधि में सोवियत संघ ने बिजली उत्पादन में ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, जापान, फ़्रांस, इटली और नार्वे को पीछे छोड़ दिया और अमरीका तथा जर्मनी के बाद तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया।

रासायनिक उद्योग का विकास अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण की पूर्ति का एक निर्णायक कारक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका उत्पादन तिगुने से अधिक बढ़ गया। रासायनिक उद्योग की नयी शाखाएं – नाइट्रोजन उत्पादन, संश्लिष्ट धागे, प्लास्टिक और संश्लिष्ट रबड़ – बड़ी तेज़ी से विकसित हुईं। सोवियत वैज्ञानिकों ने दुनिया में सबसे पहले संश्लिष्ट रबड़ का विकास किया। दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में अत्याधुनिक मशीनों से सज्जित हल्के और खाद्य उद्योगों के सैकड़ों उद्यम चालू किये गये, जिसके परिणामस्वरूप उनका उत्पादन दुगुना बढ़ गया।

सभी परिवहन प्रणालियों का टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण बड़ी ही तेज़ गति से किया गया। माल ढुलाई परिवहन के लक्ष्यों की दुगुनी से अधिक पूर्ति की गयी थी। नयी रेललाइनें बिछायी गयीं, जल-मार्ग बनाये गये। लगभग १,००० किलोमीटर रेललाइनों का बिजलीकरण किया गया। श्वेत सागर – बाल्टिक नहर और मास्को-वोल्गा नहर की खुदाई तथा उत्तरी समुद्री मार्ग के समारंभ का बड़ा महत्व था। मास्को की पहली भूमिगत रेलों (मेट्रो) ने काम करना शुरू किया।

इसी काल में अंग्रेज़ उपन्यासकार एच० जी० वेल्स, जिन्हें "क्रेमलिन के स्वप्नदर्शी" की, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक *Russia in the Shadows* में लेनिन को कहा था, भविष्यवाणियों पर कम विश्वास था, दूसरी बार सोवियत संघ आये। मास्को की सड़कों पर घूमते-फिरते एच० जी० वेल्स को सोवियत निर्मित कारें, बसें, ट्रॉलीबसें और ट्रामें दौड़ती दिखायी दीं। एक सड़क परिवहन के लिए बंद थी, क्योंकि उसके आर-पार गड्ढा बना था। "यहां मास्को मेट्रो का खुली विधि से निर्माण किया जा रहा है," लेखक को बताया गया। वह मुस्कराये।

अंग्रेज़ विज्ञान गल्प-साहित्य लेखक ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया कि लेनिन कितने सही थे और उनका वह "विद्युत यूटोपिया" कितना सही उतरा था, जिसपर वेल्स ने १६२० में संदेह व्यक्त किया था।

सभी सोवियत जनतंत्रों में औद्योगीकरण की अनवरत प्रक्रिया जारी रही। अग्रणी औद्योगिक केंद्रों के मज़दूरों, इंजीनियरों और तकनीशियनों ने देश के दूर-दराज़ के प्रदेशों में नये उद्योग क़ायम करने और जातीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने में अति सक्रिय भाग लिया। हज़ारों उज़्बेक, कज़ाख, ताजिक, अज़रबैजानी, तातार, बश्कीर, तुर्कमान और अन्य बिरादराना जातियों के कर्मियों ने अग्रणी उद्यमों में कार्य का अनुभव प्राप्त किया, देश के प्रमुख इंस्टीट्यूटों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। सोवियत जनतंत्रों में समाजवादी उद्योगों के विकास के साथ मज़दूर वर्ग के जातीय कर्मियों, अपने बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। सुविकसित जनतंत्रों के स्तर तक पहले के पिछड़े हुए जनतंत्रों का आर्थिक उत्थान समाजवाद में सभी सोवियत जातियों के एकसाथ संक्रमण का एक वास्तविक आधार था।

दूसरी पंचवार्षिकी ने सोवियत संघ की रक्षा क्षमता के सुदृढ़ीकरण में बड़ा योगदान किया। इस योजनावधि में रक्षा उद्योग का उत्पादन लगभग तिगुना बढ़ा था, आधुनिक विमानों, तोपखाने, टैंकों, युद्ध जलपोतों के निर्माण के बड़े कार्यक्रम को अमल में लाया गया। बढ़ते फ़ासिस्ट आक्रमण और विश्वयुद्ध के खतरे की परिस्थितियों में इस सबका भारी महत्व था।

साथ ही जन उपभोग में १०० प्रतिशत से अधिक और राजकीय तथा सहकारी व्यापार में २०० प्रतिशत से अधिक की बढ़ती हुई। १६३५-३६ की अवधि में न केवल रोटी, बल्कि सभी खाद्य-पदार्थों और औद्योगिक वस्तुओं की राशनिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। खुदरा क़ीमतें धीरे-धीरे कम की गयीं। १६३७ में ग्रामीण और शहरी मेहनतकशों की सांस्कृतिक-सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक बीमा) के लिए राजकीय व्यय में १६३२ की तुलना में २७० प्रतिशत की वृद्धि की गयी। आबादी की आवासीय परिस्थितियों में सुधार और सामुदायिक सेवाओं पर राजकीय व्यय में लगातार बढ़ोत्तरी हुई। नये-नये नगर प्रकट हुए, आवासीय गृहों, स्कूलों, अस्प-तालों, थियेटरों, सांस्कृतिक प्रासादों, पुस्तकालयों का निर्माण किया

गया।

सोवियत संघ में विशाल पैमाने पर निर्माण ने पूंजीवादी दुनिया को अचरज में डाल दिया, जबकि मित्रों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

सुप्रसिद्ध डेनिश लेखक मार्टिन एंडर्सन नेक्से ने १९३४ में सोवियत संघ की यात्रा करने के बाद लिखा कि सोवियत संघ में सर्वत्र निर्माण हो रहा है, न केवल हज़ारों फ़ैक्टरियां और कल-कारख़ाने, बल्कि शिक्षा संस्थान, आवासीय गृह, सांस्कृतिक प्रासाद और पुस्तकालय भी बनाये जा रहे हैं। "सुदूर उत्तर, तुंद्रा और उराल में तीन-चार सालों में नये बड़े नगर बनाये जा रहे हैं। जहां कुछ साल पहले तक ताइगा या रेगिस्तान फैले हुए थे, वहां आज कुज़्नेत्स्क, मग्नितोगोर्स्क जैसे बड़े नगर क़ायम हो गये हैं।"*

" टेक्नोलाजी में पारंगत कर्मी सब कुछ तय करते हैं! "

समाजवादी पुनर्निर्माण के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र नयी टेक्नोलाजी से लैस होते जा रहे थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के केवल दो वर्षों में ही उद्योग, परिवहन और कृषि को उतने मशीन-औज़ार, मशीनें और अन्य उपकरण मिले जितने संपूर्ण पहले पंचवर्षीय योज-ना-काल में। इस टेक्नोलाजी के कुशल उपयोग पर देश की उत्पादक शक्तियों का आगे विकास निर्भर था। अतः नयी टेक्नोलाजी में पारंगति तथा उसका पूर्ण प्रयोग करने में समर्थ कर्मियों के प्रशिक्षण ने निर्णायक महत्व प्राप्त कर लिया। इस कार्यभार की पूर्ति की सभी पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा पेश किया कि "टेक्नो-लाजी में पारंगत कर्मी सब कुछ तय करते हैं!", जो "पुनर्निर्माण की अवधि में टेक्नोलाजी सब कुछ तय करती है!" नारे का पूरक था, जिसने पुनर्निर्माण की अवधि के प्रारंभ में मुख्य कार्यभारों को निर्धारित किया। अब चर्चा नयी टेक्नोलाजी चलाने और उद्योग, परिवहन, कृषि, रक्षा, आदि क्षेत्रों में सर्वत्र उसका पूर्णतम उपयोग

---

* मार्टिन एंडर्सन नेक्से, 'दो संसार। सोवियत संघ की यात्रा से अनुप्राणित विचार एवं अनुभूतियां', लेनिनग्राद, १९३५, पृ० २१।

करने में समर्थ सैकड़ों या हज़ारों नहीं, वरन लाखों जनों की थी। सोवियत लोगों ने पार्टी के इस आह्वान का बड़े उत्साहपूर्वक समर्थन किया। मज़दूरों ने सीधे अपने कार्य-स्थलों पर अपनी सुदक्षताएं बढ़ायीं। विभिन्न कोर्सों में आवश्यक न्यूनतम टेक्नोलाजिकल जानकारी प्राप्त करनेवाले सभी मज़दूरों के लिए अनिवार्य राजकीय परीक्षा लागू करने के बाद इस कार्य ने बड़ी व्यापकता प्राप्त कर ली। प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं की निर्माण-परियोजनाओं में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेनेवाले कर्मियों में से एक, अकादमीशियन इवान बार्दिन ने लिखा: "दसियों हज़ार लोग एक चमत्कारिक खोज की भांति ज्ञान को आत्मसात कर रहे थे, जिसने उनकी आंखों के सामने दुनिया अचानक खोल दी थी। वे बड़ी ललक के साथ किताबें पढ़ रहे थे, ऐसे साधन के रूप में फ़ार्मूलों और समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे, जो उन्हें शक्ति देता, उन्हें विजय-मार्ग दिखाता, वह विजय-मार्ग जो उन्हें खुशियों और आनंद से भरे जीवन, एक अर्थपूर्ण, संघर्ष और दिलचस्पी से भरे जीवन की ओर ले जाता।"*

नयी टेक्नोलाजी में पारंगत होने के जन अभियान ने समाजवादी प्रतियोगिता को ज़बर्दस्त प्रेरणा प्रदान की। दूसरी पंचवार्षिकी के मध्य तक अधिकांश मज़दूर समाजवादी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। मज़दूर वर्ग के उच्च सांस्कृतिक और टेक्नोलाजिकल स्तर ने प्रतियोगिता के नये, उच्च रूपों को जन्म दिया। इस वातावरण में दोनेत्स्क के कोयला खनक अलेक्सेई स्ताखानोव के नाम पर उत्पादन के प्रवर्तकों का स्ताखानोव आंदोलन शुरू हुआ। उक्राइना में 'सेन्त्राल्नाया-इर्मिनो' कोयला खान के मज़दूरों ने नयी टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करते हुए खानों में श्रम के बेहतर संगठन के लिए अनेक क़दम उठाये। ३० अगस्त, १९३५ की रात की पाली में खान में थूनियां लगानेवालों के साथ जैक हैमर से काम करते हुए युवा खनिक स्ताखानोव ने १०२ टन कोयला, यानी निर्धारित कोटे से १४ गुना अधिक कोयला निकाला। स्ताखानोव के कार्य का यह मानक न केवल सोवियत संघ के लिए, बल्कि औद्योगीकृत पूंजीवादी देशों के लिए भी अभूतपूर्व था। मसलन,

---

* इ० प० बार्दिन, 'एक इंजीनियर का जीवन', पृ० १९३ (रूसी में)।

एक पाली में एक कोयला खनक द्वारा कोयला काटने का निर्धारित कोटा ब्रिटेन में ११ टन और जर्मनी (रूर प्रदेश) में १४ टन था। लेकिन स्ताखानोव का रिकार्ड तीन दिन तक ही बना रहा और ३ सितम्बर को उसी खान के एक दूसरे खनक, पार्टी सेल के सचिव मिरोन द्युकानोव ने उसके रिकार्ड को तोड़कर ११५ टन कोयला निकाला। दो दिन बाद ही कोम्सोमोल सदस्य द्मित्री कोन्त्सेदालोव ने १२५ टन कोयला निकाला। कुछ दिनों के बाद अलेक्सेई स्ताखानोव ने एक पाली में १७५ टन और फिर २२७ टन कोयला निकालकर अपने पहले के रिकार्ड को तोड़ दिया।

सोवियत संघ के सभी जनतंत्रों में बहुत-से खानों, फ़ैक्टरियों, कारखानों, रेलवे और नव निर्माण-स्थलों में मज़दूरों ने इन अग्रणी कोयला खनकों की पहल का अनुकरण किया। उदाहरणार्थ, गोर्की मोटर कारखाने के लोहार अलेक्सांद्र बुसीगिन और उनकी टोली ने क्रैंकशैफ़्टों और अन्य पुर्ज़ों की स्टाम्पिंग करके अमरीकी कारखानों के अच्छे से अच्छे लोहारों को बहुत पीछे छोड़ दिया। उस समय जबकि अमरीकी लोहार ३६ सेकंड में एक क्रैंकशैफ़्ट बनाते थे–तकनीकी दृष्टि से ५० सेकंड निर्धारित समय था,–तो बुसीगिन ने फ़ी क्रैंकशैफ़्ट की गढ़ाई में ३२-३०.८ सेकंड का ही समय लिया।

मशीन-औज़ार निर्माण में कटर इवान गूदोव, सूती बुनकरिन येवदोकीया विनोग्रादोवा और मारिया विनोग्रादोवा, मोची निकोलाई स्मेतानिन और लकड़ी चीरने की मशीन के चालक व० मुसीन्स्की अपने उद्योग-धंधों में स्ताखानोव आंदोलन के नव-प्रवर्तक थे। २३ किलोमीटर प्रति घंटा के मुक़ाबले में ४७-५० किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से मालगाड़ियां चलानेवाले इंजिन ड्राइवर प्योत्र क्रिवोनोस परिवहन में इस आंदोलन के अगुआ थे।

स्ताखानोव आंदोलन उत्कृष्ट श्रम का सर्वोच्च रूप था। उसने समाजवादी प्रतियोगिता में मेहनतकश जनसाधारण को खींचने में समर्थ बनाया और मेहनतकशों की रचनात्मक पहल के नये रूपों को जन्म दिया।

उद्योग का अनुसरण करते हुए उत्पादन के प्रवर्तकों का आंदोलन कृषि में भी फैल गया। चुकंदर की खेती में विशिष्टता प्राप्त मारिया देमचेन्को, ट्रैक्टर चालकों की टोली की नेता प्रास्कोव्य अंगेलिना,

कम्बाइन हार्वेस्टर चालक कोन्स्तान्तीन बोरिन, आदि इस क्षेत्र के अगुआ थे।

कहने की आवश्यकता नहीं कि अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने, अपने काम का सच्चा माहिर बनने की प्रत्येक कर्मी की अपनी ही विधि थी, जिसके माध्यम से वह श्रम उत्पादकता के विद्यमान मानकों से बारंबार आगे बढ़ जाता था। अब अलग-अलग व्यक्तियों, टोलियों और खातों के श्रम उत्पादकता के कीर्तिमानों ने पुराने उत्पादन मानकों की आमूलतः समीक्षा करने तथा श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए ज़ोरदार ढंग से प्रेरित किया।

नव-प्रवर्तकों का यह उल्लेखनीय आंदोलन "इस्पात की मांस-पेशियों वाले", जैसा कि विदेशी पूंजीवादी प्रेस ने दावा किया, अलग-अलग कर्मियों के असाधारण कीर्तिमानों के कारण नहीं उत्पन्न हुआ था, बल्कि इसकी जड़ें सोवियत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास, उत्पादन के बढ़े हुए स्वचालीकरण, पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के "तूफ़ानी कर्मियों" की उपलब्धियों तथा समाजवादी प्रतियोगिता में भाग लेनेवाले असंख्य मज़दूरों की वाहिनी के कारनामों में निहित थीं। अपनी ओर लाखों मेहनतकशों को खींचनेवाले इस आंदोलन की जीवंतता और लोकप्रियता के यही कारण थे। श्रम उत्पादकता के उच्च सूचकों की प्राप्ति और सोवियत जनगण के कल्याण में वृद्धि इस आंदोलन का मुख्य प्रेरक थीं। इस आंदोलन ने मज़दूरों के उच्चतर सांस्कृतिक और टेक्नोलाजिकल स्तरों को प्रतिबिंबित किया तथा समाजवादी उद्योग के प्रबंधकों और संगठनकर्ताओं की नयी पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में सहायता की।

व्यापक जनसाधारण को अपनी परिधि में लेनेवाले नव-प्रवर्तन आंदोलन का सबल विकास सोवियत जनता की उच्च राजनीतिक और श्रमिक सक्रियता का प्रमाण था। मशीन-निर्माण में स्ताख़ानोव आंदोलन के एक अगुआ अलेक्सांद्र बुसीगिन अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब वह १९३६ की गर्मी में काले सागर के स्वास्थ्य-केंद्र में अपनी छुट्टियां मना रहे थे, तो उनके पास अमरीकी मोटर उद्योग के "सम्राट" फ़ोर्ड का एक प्रतिनिधि आया। बातचीत के अंत में फ़ोर्ड के प्रतिनिधि ने उनसे कहा: "श्री बुसीगिन, डेट्रायट में हेनरी फ़ोर्ड के कारखाने में आने और वहां काम करने के लिए उनका निमंत्रण आपको देते

हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको वहां सर्वोत्तम परिस्थितियां मिलेंगी और आप ढेर सारा सोना कमायेंगे।"

"श्री फ़ोर्ड को बता दें", बुसीगिन ने उत्तर दिया, "कि सोवियत मज़दूर अपने को सोने के लिए नहीं बेचता। मैं अपनी सोवियत मातृभूमि के लिए काम करता हूं और सारा जीवन उसकी सेवा करता रहूंगा। मैं पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए काम नहीं करूंगा और जहां तक सर्वोत्तम परिस्थितियों का सवाल है, तो वे मुझे अपने देश में उपलब्ध हैं।"

इस पर फ़ोर्ड के प्रतिनिधि ने कटु मुस्कराहट से कहा, "लगता है, लोहार दृढ़ लोग होते हैं।"

बुसीगिन ने कहा, "आप मेरे स्थान पर यही चीज़ किसी भी सोवियत मज़दूर, लोहार, खरादी या मोची से सुनेंगे। हम सभी अपने सुख के निर्माता हैं।"*

कम्युनिस्ट स्ताखानोव आंदोलन के प्रवर्तक और संगठनकर्ता थे और उन्होंने अपने उदाहरण से दूसरे मज़दूरों को प्रेरित किया। १९३५ में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और सोवियत सरकार ने अग्रणी मज़दूरों के अनुभव के सामान्यीकरण तथा प्रसार के उद्देश्य से स्ताखानोव आंदोलन के सहभागियों का पहला अखिल संघीय सम्मेलन बुलाया। क्रेमलिन में तीन हज़ार सर्वोत्तम मज़दूरों का यह सम्मेलन चार दिन चला। सम्मेलन के मंच से इस आंदोलन के प्रवर्तकों और सरकारी तथा पार्टी नेताओं ने भाषण किये। कामकाजी विचार-विनिमय हुआ, अर्थव्यवस्था के आगे विकास के मार्ग और कार्यभार स्पष्ट किये गये, नव-प्रवर्तकों के आंदोलन का आर्थिक और राजनीतिक महत्व, उसके स्रोत निर्धारित किये गये।

स्ताखानोव आंदोलन मज़दूरों और किसानों की शोषण से मुक्ति, सोवियत लोगों के उच्चतर भौतिक और सांस्कृतिक स्तर और नयी टेक्नोलाजी तथा ऐसे विशेषज्ञों की उपलब्धता का परिणाम था, जो उसके प्रयोग में पारंगत हो गये थे। वह श्रम के प्रति नये, समाजवादी दृष्टिकोण के उदय का भी द्योतक था। सोवियत संघ में श्रम सम्मान,

---

* 'समाजवाद के निर्माताओं के संस्मरण', गोस्पोलितइज़्दात, मास्को, १९५९, पृ० २७५ (रूसी में)।

गौरव और शौर्य का मामला बन गया था।

स्ताखानोव आंदोलन एक अस्थायी आंदोलन नहीं था; उसने देश की अर्थव्यवस्था के आगे टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कार्य की गुणात्मक रूप से नयी अवस्था को प्रकट किया। कोटा-निर्धारण की पुरानी प्रणाली एक अवरोध बन गयी थी जो श्रम उत्पादकता और मज़दूरी की वृद्धि को रोके हुए था। नयी, उच्च उत्पादक टेक्नोलाजी लागू किये जाने के बाद पुराने पड़ चुके कोटों की समीक्षा करने संबंधी आंदोलनकर्ताओं के प्रस्तावों ने, जिन्हें योजना तैयार करते समय ध्यान में रखा गया था, मज़दूरी और श्रमिकों की खुशहाली के आगे विकास को सुनिश्चित बनाया।

बुर्जुआ प्रेस ने स्ताखानोव आंदोलन के सार को तोड़ने-मरोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश की। उसने इस आंदोलन के बारे में ऐसे लांछनपूर्ण प्रपंच फैलाये जैसे कि वह "मज़दूरों की शारीरिक शक्ति", "शारीरिक अतिश्रम", "बेगार", आदि पर आधारित हो। लेकिन सोवियत संघ की यात्रा पर आनेवाले विदेशी मज़दूरों के प्रतिनिधिमंडलों ने एक दूसरी ही तस्वीर देखी और इन प्रपंचों का खंडन किया। उन्होंने समाजवादी समाज में मानव गरिमा की विशाल जाग्रति देखी, जहां मज़दूर अपने देश का मालिक बन गया था।

उत्पादन प्रवर्तकों का आंदोलन पूरे देश में बड़ी तेज़ी से अभूतपूर्व पैमाने पर फैल गया। साल भर बाद ही उसमें हर तीसरा मज़दूर भाग ले रहा था।

सर्वोत्तम मज़दूरों के अनुभव के व्यापक प्रसार ने श्रम उत्पादकता को काफ़ी ऊंचा उठाने में सहायता की। दूसरी पंचवार्षिकी के दौरान वह उद्योग में निर्धारित ६३ प्रतिशत से बढ़कर ८२ प्रतिशत हो गयी।

स्ताखानोव आंदोलन की शानदार परंपराओं ने श्रम के प्रति कम्युनिस्ट रुख के लिए वर्तमान राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आगे विकास पाया।

८. समाजवादी औद्योगीकरण की विजय का महत्व

सोवियत जनगण की निस्स्वार्थ और असाधारण श्रम और कम्युनिस्ट पार्टी के विशाल संगठनात्मक और राजनीतिक कार्य के फलस्वरूप पहली पंचवर्षीय योजना की भांति दूसरी पंचवर्षीय योजना भी निर्धारित

समय से पहले १ अप्रैल, १९३७ को, यानी चार वर्ष तीन महीने में ही पूरी हो गयी। १९३७ में सोवियत संघ का औद्योगिक उत्पादन १९३२ के औद्योगिक उत्पादन से दुगुना और १९१३ के औद्योगिक उत्पादन से आठगुना बढ़ गया तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उसका हिस्सा बढ़कर ७८.६ प्रतिशत हो गया। सोवियत संघ एक विश्व औद्योगिक शक्ति बन गया। १९३३-३७ की अवधि में कोई ४,५०० नये औद्योगिक उद्यम – प्रथम पंचवार्षिकी से तिगुना अधिक – चालू किये गये। इसका अर्थ यह था कि हर रोज़ दो-तीन नये कारखाने या फ़ैक्टरियां चालू की जा रही थीं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य और निर्णायक कार्यभार – अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण की पूर्ति – को मूलतः पूरा कर लिया गया था। उद्योग और परिवहन का नये टेक्नोलाजिकल आधार पर पुनर्निर्माण हो गया था।

तकनीकी पुनर्निर्माण ने देश का कायापलट कर दिया। जातीय जनतंत्रों की सफलताएं सचमुच विलक्षण थीं। रूसी संघात्मक जनतंत्र और उक्राइनी जनतंत्र के औद्योगिक और वैज्ञानिक केंद्र जातीय जनतंत्रों की अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण के आधार थे, जिन्होंने उन्हें उपकरणों की सप्लाई की, सुयोग्य कर्मी भेजे। इस सहायता ने पहले की पिछड़ी जातियों के समाजवाद में संक्रमण को तेज़ कर दिया।

१९३७ में दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान नवनिर्मित या पुनर्निर्मित उद्यमों का उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन का ८० प्रतिशत था। काफ़ी उत्पादक शक्तियों का देश के पूर्वी प्रदेशों में स्थानांतरण आर्थिक नीति में एक नया क़दम था। कुज़्नेत्स्क और करागांदा कोयला खानों का महत्व अधिकाधिक बढ़ गया, उराल और साइबेरिया की औद्योगिक शक्ति सुदृढ़ हुई। सोवियत राज्य ने परस्पर जुड़े निम्न कार्यभारों को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया था: संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का चहुंमुखी विकास; पूर्वी औद्योगिक केंद्रों का निर्माण; देश के केंद्रीय और सीमांत प्रदेशों के बीच आर्थिक खाई का उन्मूलन; सोवियत जातियों और नृजातीय समूहों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास-स्तरों में असमानता की समाप्ति।

दूसरी पंचवर्षीय योजना टेक्नोलाजिकल और आर्थिक रूप से

अत्यधिक विकसित पूंजीवादी देशों की बराबरी में आने और फिर उनसे आगे बढ़ने के कार्यभारों की पूर्ति में महत्वपूर्ण मंज़िल थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफल पूर्ति के फलस्वरूप सोवियत संघ कुल औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में अमरीका के बाद दूसरे स्थान पर तथा जर्मनी, इंगलैंड और फ़्रांस को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में पहले स्थान पर आ गया। विकास-दर की दृष्टि से सोवियत संघ दुनिया में पहले स्थान पर था। उद्योग और परिवहन के यंत्रीकरण की दृष्टि से सोवियत संघ दुनिया का एक अग्रणी राष्ट्र बन गया। ये नयी समाजवादी प्रणाली की असाधारण उपलब्धियां थीं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के वर्ष सोवियत लोगों की अनेकानेक सच्ची वीरतापूर्ण सिद्धियों के वर्ष थे।

जुलाई १६३६ में सोवियत पाइलटों वालेरी च्कालोव, गेओर्गी बाइदुकोव और अलेक्सांद्र बेल्याकोव ने अ न त-२५ बिमान में मास्को – आर्कटिक सागर – लेना नदी का मुहाना – ओखोत्स्क सागर – कमचात्का – ओखोत्स्क सागर – आमूर का मुहाना – मास्को के ६३७४ किलोमीटर लंबे वायुमार्ग पर बिना उतरे उड़ान भरी और आकाश में ५६ घंटे २० मिनट बिताये। १६३७ में विख्यात सोवियत हवाबाज़ वालेरी च्कालोव, गेओर्गी बाइदुकोव, अलेक्सांद्र बेल्याकोव, मिखाईल ग्रोमोव, अंद्रेई युमाशेव और स० दनीलिन ने मास्को – संयुक्त राज्य अमरीका तक बिना उतरे उड़ानें भरी थीं।

१६३७ की गर्मी में एक और सोवियत उपलब्धि दुनिया के अख़बारों की सुर्ख़ियां बनी। इवान पापानिन, प्योत्र शिर्शोव, येव्गेनी फ़्योदोरोव और एर्न्स्ट क्रेन्केल के आर्कटिक अभियान-दल 'उत्तर ध्रुव १' ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया, जो फ़रवरी १६३८ में सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

साफ़ है कि सोवियत लोगों की इन असाधारण उपलब्धियों ने उन वर्षों में सोवियत उद्योग के विकास के उच्च सामान्य स्तर और देश की आर्थिक शक्ति को प्रतिबिंबित किया।

* * *

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद की इस प्रस्थापना का अनुसरण करते हुए देश का औद्योगीकरण आरंभ

किया कि भारी मशीनी उद्योग समाजवाद का भौतिक आधार है। इस संबंध में देश के बिजलीकरण पर लेनिन के आदेशों को पूरा करने पर बड़ा ध्यान दिया गया। केवल अपना भारी उद्योग ही पूंजीवादी घेरे की स्थितियों में अर्थव्यवस्था के टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण को सुनिश्चित बना सकता, मेहनतकशों के भौतिक और सांस्कृतिक स्तरों को ऊंचा उठा सकता, सोवियत संघ की आर्थिक स्वतंत्रता और रक्षा क्षमता को मज़बूत बना सकता था।

जहां समाजवादी आर्थिक प्रणाली के लाभों ने समाजवादी औद्योगीकरण के कार्यक्रम को अल्प काल में अमल में लाना और लेनिनीय गोएलरो योजेना को कार्यान्वित करना संभव बनाया, वहीं पहली पंचवर्षीय योजनाओं ने अर्थव्यवस्था के अति तीव्र विकास को सुनिश्चित बनाया। यदि पहली पंचवर्षीय योजना की पूर्ति ने दुनिया में समाजवाद की स्थिति को सुदृढ़ किया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने पूंजीवाद पर समाजवाद की श्रेष्ठता को और भी ज्वलंत ढंग से प्रदर्शित कर दिया।

समाजवादी औद्योगीकरण की नीति का सफल कार्यान्वयन सोवियत राज्य के ऐतिहासिक भाग्य के लिए सर्वतोमुखी महत्व रखता था। उसने देश की आर्थिक स्वतंत्रता को मज़बूत बनाने, अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं का टेक्नोलाजिकल पुनर्निर्माण करने के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था का नये समाजवादी आधार पर रूपांतरण करने के लिए आवश्यक भौतिक बुनियाद रखी। समाजवादी समाज के भौतिक और तकनीकी आधार का निर्माण अभूतपूर्व अल्प अवधि में किया गया था, जबकि पूंजीवादी देशों में औद्योगीकरण में सदियां लग गयी थीं। सोवियत संघ में ऐतिहासिक प्रगति की अभूतपूर्व तीव्र दरों ने समाजवादी समाज की विलक्षण श्रेष्ठताओं, उसकी जीवंत शक्ति को प्रदर्शित कर दिया, जिसमें मेहनतकश जनसाधारण अपने भाग्य के मालिक और सृजनकार होते हैं।

सोवियत संघ में समाजवादी औद्योगीकरण का अनुभव, बेशक अपनी कुछ विशिष्टताओं के साथ, दुनिया के दूसरे देशों में समाजवादी विकास के वस्तुगत नियमों को प्रतिबिंबित करता है।

अधिकांश वर्तमान समाजवादी देशों के लिए औद्योगीकरण समाजवाद की विजय के लिए एक निर्णायक शर्त थी। साथ ही, आधुनिक

परिस्थितियों में, जबकि विश्व समाजवादी राष्ट्रमंडल क़ायम है और वैज्ञानिक-टेक्नोलाजिकल क्रांति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, समाज-वादी औद्योगीकरण कुछ अपनी ही विशिष्टताएं रखता है।

आजकल समाजवाद का निर्माण उन परिस्थितियों से कहीं बहुत अधिक अनुकूल परिस्थितियों में हो रहा है, जो सोवियत संघ में तीसरे और चौथे दशकों में क़ायम थीं। इसका कारण यह है कि समाजवादी देशों को औद्योगीकरण के सोवियत अनुभव का सुदक्षतापूर्वक उपयोग करने, शुरू से ही सोवियत संघ के सबल समर्थन पर भरोसा करने, बिरादराना समाजवादी राष्ट्रमंडल की उस प्रणाली में विकास करने की संभावना प्राप्त है, जो देश-विशेष की घरेलू क्षमताओं का अधिक युक्तियुक्त ढंग से और कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करना संभव बनाती है। पारस्परिक सहायता कम विकसित समाजवादी देशों को अधिक विकसित समाजवादी देशों के स्तर पर उठाने में मदद करती है।

उदाहरणार्थ, अब प्रत्येक देश में उस तरह उद्योग की सभी शाखाएं क़ायम करने के लिए अत्यधिक ज़ोर लगाने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह सोवियत संघ शुरू में लगाने के लिए विवश हुआ था। श्रम का अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी विभाजन अलग-अलग देशों को उद्योग की केवल वही शाखाएं विकसित करने की संभावना देता है, जिनके लिए उनके पास अत्यधिक आर्थिक और प्राकृतिक परिस्थितियां तथा टेक्नोलाजिकल अनुभव (कच्चे माल की उपलब्धता, पर्याप्त उपकरण, उत्पादन अनुभव, श्रमशक्ति, आदि) हैं।

सोवियत संघ और समाजवादी राष्ट्रमंडल के दूसरे देशों में समाज-वादी निर्माण के अनुभव ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को पूंजीवाद से समाज-वाद में संक्रमण की अवधि में समाज के विकास के बारे में नये विचारों से समृद्ध बनाया, बिरादराना कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों को दुनिया के क्रांतिकारी रूपांतरण के आधारभूत नियमों की स्पष्ट समझ से लैस किया और आधुनिक युग में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के महान अंत-र्राष्ट्रीय महत्व को व्यवहार में सिद्ध कर दिया।

सोवियत जनता ने मानवजाति को बिल्कुल नये, अद्वितीय रचनात्मक अनुभव से समृद्ध बनाया है। उसका आत्मसात्करण और प्रयोग आज दुनिया की आबादी के एक बहुत बड़े भाग को समाजवाद की ओर सफलतापूर्वक और तेज़ी से आगे बढ़ने में सहायता करते हैं।

अध्याय ४

सहकारिता का मार्ग – जीवन की समृद्धि का मार्ग

रूस में, जहां आबादी में किसानों का बड़ा हिस्सा था, समाजवादी समाज का निर्माण बहुत-कुछ छोटे, बिखरे खेतों को बड़े सामूहिक फ़ार्मों में बदलने पर निर्भर करता था। यह अक्तूबर क्रांति की विजय के बाद अत्यंत जटिल समस्या थी और उसके समाधान का अर्थ था आर्थिक संबंधों, संपूर्ण ग्रामीण जीवन-पद्धति में क्रांति।

कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों के बड़े महत्व को समझने के लिए समस्त आर्थिक विकासक्रम पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

१. किसानों का सोवियत सत्ता का समर्थन

क्रांतिपूर्व रूस में भू-संबंध

ज़ारशाही में किसानों का जीवन कैसा था? क्रांतिपूर्व रूस में कैसे भू-संबंध क़ायम थे?

ज़ारशाही रूस एक पिछड़ा, कृषि-प्रधान देश था, जहां ८० प्रतिशत आबादी खेती में लगी हुई थी। किसान भूमिहीनता, कंगाली, भुखमरी और शोषण से पीड़ित थे। १९वीं सदी के सातवें दशक तक सामंती संबंध रूसी कृषि पर हावी रहे। करोड़ों किसान, मर्द और औरतें ज़मींदारों की निजी संपत्ति थे। ज़मींदार किसानों का क्रय-विक्रय कर सकते थे, कुत्तों से उनकी अदला-बदली कर सकते थे, जुए में उन्हें दांव पर रख सकते या उपहारस्वरूप दे सकते थे।

राष्ट्रव्यापी किसान विद्रोह के भय से ज़ारशाही सरकार १८६१

में भूदास-प्रथा समाप्त करने के लिए विवश हो गयी। यह सुधार "ऊपर से", ज़मींदारों के हित में किया गया। किसानों की यह कुख्यात "मुक्ति" निर्लज्ज लूट-खसोट, उन पर ज़ोर-ज़बर्दस्ती और अत्याचार बन गयी। ज़मींदारों ने किसानों को भूदास-प्रथा से मुक्त करते हुए बढ़िया ज़मीनें अपने पास ही रख लीं। उन भू-खंडों के लिए, जिन पर किसानों के पूर्वज सदियों से काम करते आ रहे थे, उन्हें लगभग ५० साल तक भूमि विमोचन कर देना था। ज़मीन के घोर अभाव से पीड़ित किसान ज़मींदारों से एकतरफ़ा शर्तों पर लगान पर ज़मीन लेने के लिए मजबूर थे। बहुधा लगान किसानों की आय से बहुत ज़्यादा होते थे। किसानों ने अपने को एक ऐसी स्थिति में पाया, जो भू-दास प्रथा की प्रणाली से ज़रा भी भिन्न नहीं थी।

किसानों के पास ज़मीनें बहुत कम थीं। जबकि किसानों के पास औसतन सात देस्यातिना ज़मीन थी, लाखों ग़रीब किसानों के पास औसतन दो देस्यातिना से भी कम ज़मीन थी। लेकिन प्रत्येक ज़मींदार के पास औसतन २००० देस्यातिना से अधिक ज़मीन थी। ज़ारशाही के ऊंचे ओहदेदारों और अभिजातों के हाथों में विशाल मात्रा में ज़मीनें थीं। ज़मींदारों में स्वयं ज़ार का पहला स्थान था, जो ७० लाख देस्यातिना ज़मीन (अर्थात दस लाख किसान परिवारों की ज़मीनों के बराबर) के साथ अपने को "रूसी ज़मीन का मालिक" मानता था।

ज़ारशाही रूस में किसान घोर कंगाली का जीवन जी रहे थे। लगभग ३० प्रतिशत किसानों के पास घोड़े-बैल तक नहीं थे, ३४ प्रतिशत कृषि के सामान्य उपकरण नहीं ख़रीद सकते थे और १५ प्रतिशत के पास खेतीयोग्य ज़मीन नहीं थी। किसान अक्सर सूखों और ख़राब फ़सलों से प्रभावित होते रहते थे। लगभग ६५ प्रतिशत किसानों के पास इतना अनाज कभी नहीं होता था कि वह अगली फ़सल तक चल सके। भुखमरी और कंगाली किसानों को अपने गांव छोड़ने के लिए विवश कर देती थी। वे देश के मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों को चले जाते थे और दिहाड़ी पर काम पर लग जाते थे। वे नगरों में कारख़ानों और फ़ैक्टरियों, पीट खानों और कोयला खानों, बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों, लकड़ी काटने के स्थलों, आदि पर शारीरिक श्रम करने के लिए चले जाते थे।

लेनिन ने १९१२ में लिखा : "ज़मींदारों द्वारा लूटे गये, अफ़सरों की स्वेच्छाचारिता द्वारा कुचले हुए, पुलिस के प्रतिबंधों, छिद्रान्वेषणों और हिंसा के मकड़े के जाल में फंसे हुए, पहरेदारों, पादरियों तथा ज़ेम्स्त्वो के अधिकारियों की निगरानी में रखे किसान प्राकृतिक विपदाओं तथा पूंजी के विरुद्ध उतने ही अरक्षित हैं, जितने कि अफ़्रीका के वहशी। आजकल केवल वहशी देशों में ही इतनी व्यापक भुखमरी देखने को मिल सकती है, जितनी कि बीसवीं सदी के रूस में।"*

ज़ारशाही राजतंत्र, ज़मींदारों और पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ क्रांतिकारी संघर्ष, शोषक व्यवस्था का उन्मूलन ही एकमात्र समाधान था।

रूस के किसानों ने अपने अधिकारों, ज़मीन और स्वतंत्रता के लिए किसान विद्रोहों के सुप्रसिद्ध नेताओं – इवान बोलोत्निकोव (१७वीं सदी के प्रारंभ में), स्तेपान राज़िन (१७वीं सदी के आठवें दशक में), येमेल्यान पुगाचोव (१८वीं सदी के नौवें दशक में) – के नेतृत्व में लंबा संघर्ष किया। इन और बाद के विद्रोहों ने ज़ारशाही निरंकुशता की जड़ें हिला दीं। विद्रोही किसानों ने अभिजातों की ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर लिया, भूसंपत्तियां जला दीं और ज़मींदारों तथा उनके नौकरों से निपटने के लिए कानून अपने हाथों में ले लिये। लेकिन ज़ारशाही सरकार ने सेनाएं और पुलिस-दल भेजकर इन विद्रोहों का हमेशा दमन कर दिया। हज़ारों विद्रोहियों को गोलियों से उड़ा दिया गया, कठोर कारावास की सज़ा दी गयी, खुलेआम बेंतों से पिटाई की गयी।

मात्र ज़मींदारों की भूसंपत्तियां जलाकर किसान स्वतंत्रता और ज़मीन नहीं प्राप्त कर सकते थे। शोषण की समूची प्रणाली को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ज़ारशाही सरकार का तख़्ता उलटना आवश्यक था। लेकिन इसके लिए किसानों के पास सबसे बड़ी चीज़ – संगठन – का अभाव था।

स्वतंत्रता प्राप्त करने और ज़मीन का सच्चा मालिक बनने में सहायता करने के लिए किसानों के क्रांतिकारी उत्साह और शोषकों के प्रति उनकी घृणा को सही दिशा में लगाना आवश्यक था। यह क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग ही कर सकता था।

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'अकाल', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ४, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८२, पृ० १४०।

मज़दूरों और किसानों के दो मेहनतकश वर्गों का सहबंध वह शक्ति थी, जिसने ज़ारशाही निरंकुशता का तख़्ता उलट दिया और बुर्जुआ वर्ग के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया।

मज़दूरों और किसानों का यह सहबंध कैसे मूर्तिमान हुआ?

मज़दूरों और किसानों का सहबंध – भूमि प्रश्न के सफल समाधान की मुख्य शर्त

मज़दूरों और किसानों के बीच सहबंध रूस में १९०५-१९०७ की क्रांतिकारी लड़ाइयों की आग में बनना शुरू हुआ। बोल्शेविक पार्टी ने मज़दूर वर्ग का नेतृत्व करते हुए ज़ारशाही के ख़िलाफ़, लेनिन द्वारा प्रस्तुत और पुष्ट सर्वहाराओं और संपूर्ण किसानों के सहबंध के नारे के तहत एक जनवादी जनतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने दिखाया कि किसान केवल मज़दूरों के साथ सहबंध करके ही अपनी ज़मीन और आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। इस सहबंध के बिना किसान हमेशा अपने ज़मींदारों के भूदास ही बने रहेंगे। लेकिन अकेले सर्वहारा वर्ग देश का जनवादीकरण और अपनी सत्ता की स्थापना नहीं कर सकता। फलतः वर्ग सहयोग के एक विशेष रूप के तौर पर मज़दूरों और किसानों के सहबंध की आवश्यकता सर्वहाराओं और किसानों, दोनों को ही है। ज़ारशाही निरंकुशता, पूंजीवादी शासन पर हमले का ज़ोर तथा क्रांति की सफलता इस सहबंध की शक्ति पर निर्भर था।

मज़दूरों और किसानों के संयुक्त संघर्ष ने पहली रूसी क्रांति को सच्चा जनवादी स्वरूप प्रदान किया। हालांकि क्रांति ने ज़ारशाही निरंकुशता की जड़ें हिला दीं, किंतु वह उस पर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर सकी। १९०५-१९०७ की क्रांति की पराजय का एक कारण मज़दूरों और किसानों के बीच सुदृढ़ सहबंध का अभाव था। बहुत अर्थों में यह सहबंध स्वतःस्फूर्त था, अक्सर अचेत ढंग से बन जाता था, सर्वहाराओं और किसानों की शक्तियां पर्याप्त ढंग से संगठित नहीं थीं, वे बिखरी थीं, उनके पास कोई केंद्रीकृत नेतृत्व नहीं था।

संयुक्त क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान प्राप्त मज़दूरों और किसानों

का अनुभव सुदृढ़ और व्यापक बना। मज़दूरों और किसानों के क्रांतिकारी सहबंध को मज़बूत बनाने के लिए बोल्शेविक पार्टी द्वारा वर्षों से चलाये जा रहे संघर्ष की बदौलत अधिकांश किसान तथा सैनिक सर्वहारा वर्ग के पक्ष में खिंच आये और फ़रवरी १९१७ में ज़ारशाही पर तथा अक्तूबर १९१७ में बुर्जुआ वर्ग पर विजय संपन्न हुई।

समाजवादी क्रांति ने किसानों को क्या दिया ?

अक्तूबर क्रांति की विजय और मज़दूरों तथा ग़रीब किसानों की सत्ता की स्थापना ने देहातों में समाजवादी विकास का मार्ग खोल दिया।

देश की कृषि व्यवस्था में जनवादी सुधार, ज़मींदारों के स्वामित्व और भूदास-प्रथा के अवशेषों का उन्मूलन इस मार्ग की अनिवार्य मंज़िलें थे। समाजवादी क्रांति ने इन कार्यभारों को चलते-चलते, किसानों के जीवन में गहन समाजवादी रूपांतरणों को निकट लाते और सुगम बनाते हुए पूरा किया।

मज़दूरों, सैनिकों और किसानों ने समाजवादी क्रांति से जिन चीज़ों की आशा की थी, वे सभी चीज़ें सोवियत सत्ता की पहली आज्ञप्तियों में पेश की गयी थीं, जिन्होंने 'जातियों को शांति, किसानों को ज़मीन, भूखों को रोटी और मज़दूरों को फ़ैक्टरियां' की घोषणा की थी। शांति और भूमि संबंधी आज्ञप्तियों ने लाखों किसानों को विश्वास दिला दिया कि बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में केवल सर्वहारा वर्ग ही उनकी आशाओं को पूरा कर सकता है।

भूमि संबंधी लेनिन की आज्ञप्ति ने भूमि पर और उत्पादन के अन्य साधनों पर ज़मींदारों के स्वामित्व को बिना मुआवज़ा दिये समाप्त कर दिया तथा ज़मींदारों, मठों और चर्च की ज़मीनों, और सभी औज़ारों तथा बखारों के साथ संपूर्ण भूसंपत्तियों को सार्वजनिक संपत्ति में बदल दिया। आज्ञप्ति ने इस बात की कड़ी चेतावनी दी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने या उसे लूटने-पाटने के अपराधियों को कड़ी सज़ा दी जायेगी।

२७ अक्तूबर, १९१७ को स्वीकृत भूमि संबंधी आज्ञप्ति ने भूमि प्रश्न को उसी रूप में हल कर दिया, जिस रूप में स्वयं किसानों ने

प्रस्ताव किया था। उनकी इच्छाओं के अनुसार आज्ञप्ति ने ज़मींदारों और किसानों, दोनों ही की ज़मीनों पर निजी स्वामित्व का अधिकार समाप्त कर दिया। सभी ज़मीनें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी गयीं। ज़मीन का क्रय-विक्रय करने, उसे लगान पर देने पर पाबंदी लगा दी गयी। भाड़े के श्रम पर पाबंदी लगा दी गयी : ज़मीन केवल उन लोगों को उपयोग करने के लिए दी गयी, जो उस पर या तो अपने श्रम से या अपने परिवार की सहायता से या सहकारिता में खेती कर सकते थे।

अत: सोवियत राज्य के सभी लोगों को भूमि का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। भूमि के बड़े भाग का वितरण ज़मीन की मात्रा और गुण, ग्रामीण आबादी के घनत्व और अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक इलाक़े के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना था। आज्ञप्ति में समय-समय पर भूमि के पुनर्वितरण तथा कम उपजाऊ क्षेत्रों से किसानों को राजकीय सहायता से अधिक उपजाऊ ज़मीनों पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था थी।

ज़मींदारों और चर्च की भूसंपत्तियों से खेती के सभी औज़ारों को बिना मुआवज़ा दिये राज्य या समुदायों को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक उद्यानों, बागानों, नर्सरियों, नस्ली अश्व फ़ार्मों, पशु पालन फ़ार्मों, पोल्ट्री फ़ार्मों जैसी सुविकसित भूसंपत्तियों का सवाल था, तो उनका वितरण नहीं किया गया, बल्कि उनके आकार और महत्व के अनुसार उन्हें आदर्श कृषि उद्यमों के रूप में राज्य या समुदायों के उपयोग के लिए दिया गया।

शेष ज़मीनों का "अलग-अलग गांवों या बस्तियों के निर्णय के अनुसार" स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग (पारिवारिक, सामुदायिक या सहकारी उपयोग) किया जा सकता था।

भूमि संबंधी आज्ञप्ति में भूमि के समतावादी उपयोग की प्रस्थापना सहित किसानों की इच्छाओं के समावेश ने किसानों के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने की मज़दूरों की इच्छा प्रदर्शित की।

भूमि पर ज़मींदारों के स्वामित्व के उन्मूलन के परिणामस्वरूप किसानों को क्या मिला?

भूमि संबंधी आज्ञप्ति के कार्यान्वयन के दौरान किसानों ने १५

करोड़ देस्यातिना से अधिक ज़ब्त ज़मीनें और ३०-३५ करोड़ रूबल मूल्य के कृषि उपकरण निःशुल्क पाये। उसने किसानों को कृषक भूमि बैंक के डेढ़ अरब रूबल के ऋणों के भुगतान, ज़मींदारों के सालाना भू-लगानों के भुगतानों और भूमि-क्रय से मुक्त करा दिया जिनका कुल योग ७० करोड़ रूबल स्वर्ण से अधिक था। इसके अलावा, ज़मींदारों से ज़ब्त किये गये पशुओं का कोई ६० प्रतिशत किसानों को दे दिया गया। भूमि के राष्ट्रीयकरण ने मेहनतकश किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया।

भूमि संबंधी आज्ञप्ति और दूसरे सोवियत क़ानूनों के अनुसार स्वयं किसानों ने ज़मींदारों से ज़मीन, पशु, कृषि औज़ार, इमारतें, अनाज भंडार, बीज, आदि संपत्तियां छीन लीं। देहातों में किसानों की सभाओं में भूमि-वितरण के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया और किसानों के बीच ज़मीन के वितरण के लिए गांव-गांव में विशेष आयोग क़ायम किये गये।

ग़रीब किसानों को ज़ब्त ज़मीनों के हस्तांतरण ने, जिनके हिस्से में कोई ६६ प्रतिशत खेत थे, दो मेहनतकश वर्गों के, जो महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की मुख्य प्रेरक शक्ति थे, राजनीतिक सहबंध को आर्थिक रूप से मज़बूत बना दिया। ज़मीन और ज़मींदारों की कृषि मशीनों और उपकरणों का ग़रीब और मंझोले किसानों के बीच वितरण (मंझोले किसान देहाती आबादी का एक पांचवां भाग थे) ने मंझोले किसानों को पूंजीवादी तत्वों से पृथक करने और आगे चलकर मज़दूरों के साथ उनके सहबंध को सुदृढ़ बनाने में सोवियत राज्य को समर्थ बनाया।

कुलकों को भी ज़मीन और ज़मींदारों की कृषि मशीनों और उपकरणों का एक हिस्सा दिया गया। किंतु भूमि आज्ञप्ति ने कुलक फ़ार्मों के आकार की सीमा को बड़ी कड़ाई से सीमित कर दिया था और कुलकों ने यह शीघ्र ही महसूस भी कर लिया। ज़मींदारों की ज़मीनों और कृषि उपकरणों के वितरण के दौरान ही गांव के ग़रीबों और कुलकों के परस्पर विरोधी हित खुलकर सामने आ गये। कुलकों ने ज़मीन के वितरण का विरोध किया, राज्य को निर्धारित क़ीमतों पर अनाज बेचने से इन्कार किया और नवोदित सोवियत जनतंत्र को भूखों मारने की धमकी दी। अपने अनाज के गोदामों और कालेबाज़ारी से

संचित पूंजी की रक्षा में कुलक सोवियत राज्य के ख़िलाफ़ हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए। १९१८ के उत्तरार्ध में उन्होंने रूस के यूरोपीय भाग में २४० सोवियत-विरोधी विद्रोह संगठित किये, अनाज की वसूली करनेवाले दस्तों* के ४,५०० मज़दूरों, ४,००० से अधिक पार्टी और सोवियत कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण कर्मियों एवं असाधारण आयोग के ५,००० कर्मियों की हत्या कर दी। अनाज के लिए संघर्ष क्रांति की रक्षा, समाजवाद के लिए संघर्ष बन गया।

१९१८ की गर्मी में ग़रीब किसानों की समितियों की स्थापना और उनके द्वारा उठाये क़दमों ने ज़मींदारों से ज़ब्त ज़मीनों और कृषि उपकरणों के वितरण में सुधार करना, कुलकों से अतिरिक्त खाद्य-पदार्थों को छीन लेना, मज़दूरों और लाल सेना को खाद्य-पदार्थों की सप्लाई करना संभव बनाया। कुलकों से छीनी गयी लगभग ५ करोड़ हेक्टर ज़मीन और पशुओं और कृषि उपकरणों का एक भाग ग़रीब तथा मंझोले किसानों को हस्तांतरित कर दिये गये।

१९१८ के अंत तक अपना काम पूरा करने के बाद ग़रीब किसानों की समितियां ग्रामीण सोवियतों में मिल गयीं।

सोवियत सत्ता द्वारा किये गये भूमि सुधारों से मेहनतकश किसानों को बड़े लाभ मिले। जबकि कुलक उस ज़मीन का ६२.५ प्रतिशत खो चुके थे, जो क्रांति से पहले उनके हाथों में थी, ग़रीब और मंझोले किसानों की ज़मीन में १५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। ज़मीन और उत्पादन के दूसरे साधन पाकर ग़रीब किसानों के काफ़ी बड़े हिस्से ने अपनी आय बढ़ा ली और वे मंझोले किसानों के स्तर पर पहुंच गये। परंतु जब तक गांवों में कुलक विद्यमान थे, तब तक शोषण और अत्याचार को समाप्त नहीं किया जा सकता था। अलग-अलग परिवारों की छोटी खेती किसानों को ग़रीबी से मुक्त नहीं करा सकी, उन्हें कुलकों के शोषण से नहीं बचा सकी। कृषि का समाजवादी सामूहिकीकरण ही इस समस्या का एकमात्र समाधान था।

---

* १९१७-२१ के खाद्य-संकट के दौरान औद्योगिक केंद्रों और सेना को अनाज तथा अन्य खाद्य-पदार्थों की सप्लाई करने के लिए अनाज वसूली के विशेष मज़दूर दस्ते बनाये गये। – सं०

२. मेहनतकशों की क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा में किसानों का योगदान

१९१८ के वसंत में शुरू किये गये और घरेलू प्रतिक्रांति को सैनिक तथा भौतिक सहायता देनेवाले सोवियत रूस के ख़िलाफ़ साम्राज्यवादी राज्यों के हस्तक्षेप ने देश में सैनिक और राजनीतिक स्थिति को तेज़ी से बदल दिया।

ऐसी परिस्थितियों में, जब शहरी सर्वहारा और ग़रीब किसान प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, मंझोले किसानों की स्थिति ने निर्णायक महत्व प्राप्त कर लिया, जो देहातों में पण्य अनाज के मुख्य उत्पादक बन गये थे।

ज़मींदारों से ज़ब्त की गयी ज़मीनों के एक बड़े भाग का वास्तविक स्वामी बनकर मंझोले किसानों ने बड़े लाभ पाये। उन्होंने अक्तूबर क्रांति और उसकी आज्ञप्तियों का समर्थन किया। फिर भी, १९१८ के वसंत और गर्मी में अनाज की राजकीय इजारेदारी से, जो भूखों मर रही शहरी आबादी को ऊंची क़ीमतों पर अनाज बेचने की अनुमति नहीं देती थी, असंतुष्ट मंझोले किसानों ने बड़ा ढुलमुलपन दिखाया। कुछ स्थानों में, ख़ास तौर से अनाज पैदा करनेवाले क्षेत्रों में, मंझोले किसान कुलकों के बहकावे में आ गये और अनाज के मुक्त व्यापार का समर्थन किया।

इन परिस्थितियों में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग ने मंझोले किसानों को तटस्थ करने की नीति का अनुसरण किया और उसे अपने एक सबल मित्र को अपने पक्ष में लाने के लिए वर्ग संघर्ष का एक रूप माना। व्ला० इ० लेनिन ने लिखा कि तटस्थीकरण की नीति "समझाने-बुझाने, उदाहरणों, अनुभव से शिक्षा, ढुलमुलपन को बलप्रयोग से दबाने, आदि से बनी है"।* इस नीति की सहायता से मज़दूर वर्ग ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना और सुदृढ़ी-

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'सर्वहारा अधिनायकत्व के बारे में पुस्तिका के आरंभिक मसविदे और ख़ाका', १९१९।

करण के लिए संघर्ष की अवधि में टुटपुंजिया वर्ग के एक बड़े भाग की तटस्थता को सुनिश्चित किया और सोवियत सत्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण तटस्थता से मैत्रीपूर्ण तटस्थता में उसके नये-नये संस्तरों का संक्रमण प्राप्त किया।

उग्र वर्ग संघर्ष के प्रभाव से सोवियत सत्ता के सक्रिय समर्थन के लिए मंझोले किसानों के राजनीतिक रुझानों में परिवर्तन परिपक्व हो रहा था। वह उन सरकारों की किसान-विरोधी नीति से और भी तेज़ हो गया, जिन्हें घरेलू प्रतिक्रांतिकारियों और विदेशी हस्तक्षेप-कारियों ने अस्थायी रूप से अधिकृत सोवियत भूक्षेत्रों पर क़ायम की थीं। इसे अपनी क्रांतिकारी उपलब्धियों के प्रति ख़तरा मानते हुए पहले ग़रीब किसानों और फिर १६१८ की पतझड़ से मंझोले किसान भी मज़दूर वर्ग के साथ सैनिक और राजनीतिक सहबंध में एकजुट होने लगे। मंझोले किसानों के अपने अनुभव ने ऐसे सहबंध की आवश्यकता का क़ायल कर दिया था।

मंझोले किसानों के सोवियत सत्ता के पक्ष में आ जाने से उनके और मज़दूरों के बीच एक सुदृढ़ सहबंध क़ायम करने की संभावना पेश हो गयी। कुलकों से संघर्ष को क्षण भर के लिए रोके बिना और ग़रीब किसानों पर ही भरोसा रखते हुए मंझोले किसानों से समझौते कर पाना – किसानों के सवाल पर ऐसे ही नारे को लेनिन ने नवम्बर १६१८ में सूत्रित किया था।

मार्च १६१६ में आठवीं पार्टी कांग्रेस ने, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस नीति को स्वीकार किया और आगे विकसित किया। कांग्रेस में बोलते हुए लेनिन ने कहा कि "**एक सुदृढ़ सहबंध के आधार पर**"* मंझोले किसानों से संबंध बनाना आवश्यक है। कांग्रेस ने मंझोले किसानों के प्रति पार्टी और सोवियत राज्य की नीति इस रूप में निर्धारित किया कि उन्हें समाजवाद के निर्माण में धीरे-धीरे और योजनाबद्ध ढंग से खींचना चाहिए।

इस नीति के कार्यान्वियन के लिए तत्काल उठाये जानेवाले निम्न व्यावहारिक क़दमों की एक राजकीय योजना तैयार की गयी: मंझोले

---

* व्ला० इ० लेनिन, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की आठवीं कांग्रेस।- उद्घाटन भाषण, १८ मार्च, १६१६।

किसानों पर करों में कमी; कृषि कम्यूनों में मंझोले किसानों को शामिल करने के संबंध में स्वेच्छा के सिद्धांत का पालन; राज्य द्वारा मंझोले किसानों से वसूल किये जानेवाले खाद्य-पदार्थों की मात्रा में कमी; राजनीतिक विद्रोहों में भाग लेनेवाले मंझोले किसानों को राजक्षमा, आदि।

इस तरह, विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंझोले किसानों के साथ सहबंध सबसे पहले सैनिक-राजनीतिक स्वरूप का था जिसका आर्थिक आधार इस चीज़ में प्रकट हुआ कि सोवियत राज्य मंझोले किसानों और उनको दी गयी ज़मीनों की रक्षा करेगा और वे नगरों तथा सेना को कच्चे मालों और खाद्य-पदार्थों की सप्लाई करने के लिए अपनी सभी अतिरिक्त उपज को राज्य को सौंप देंगे।

मंझोले किसान सारे देश में एकसाथ ही सोवियत सत्ता के पक्ष में नहीं आ गये। रूस के केंद्रीय क्षेत्रों में, जहां किसानों पर मज़दूर वर्ग के प्रभाव की बेहतर संभावनाएं थीं, मज़दूरों और किसानों के बीच यह सैनिक-राजनीतिक सहबंध अपेक्षाकृत पहले मज़बूत बन गया। साइबेरिया और सुदूर पूर्व में परिस्थितियां भिन्न थीं। वहां के किसानों को भूदास-प्रथा की बिल्कुल जानकारी नहीं थी और उन पर बुर्जुआ वर्ग, मेंशेविकों तथा समाजवादी-क्रांतिकारियों का बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। अतः साइबेरिया और सुदूर पूर्व के किसान अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही जान सकते थे कि कोल्चाक का शासन बुर्जुआ लोगों, ज़मींदारों और राजतंत्र की बहाली की ओर ले जायेगा। १९१९ के अंत में लेनिन ने लिखा: "...वास्तव में साइबेरिया और उराल के किसानों ने अपने भाग्य का निर्धारण किया। १९१८ की गर्मी में वे बोल्शेविकों से असंतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि बोल्शेविकों ने उन्हें अपने अतिरिक्त अनाज अलाभकर क़ीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया और वे कोल्चाक की तरफ़ हो गये। अब किसान ने देख लिया है, तुलना की है और एक भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचा है... कि दो अधिनायकत्व ही हो सकते हैं, कि या तो उसे मज़दूरों का अधिनायकत्व चुनना चाहिए – और इसका अर्थ है शोषकों का जुआ उतार फेंकने में मेहनतकशों की सहायता करना – या शोषकों का। ...दोनों ही अधिनायकत्वों का अनुभव पाने के बाद किसान ने मज़दूर वर्ग का अधिनायकत्व चुना

और पूर्ण विजय तक उसके साथ आगे जायेगा।"*

इन क्षेत्रों में मज़दूरों और मंझोले किसानों के बीच सैनिक और राजनीतिक सहबंध कोल्चाक की सेनाओं के चंदावल में ज़बर्दस्त किसान विद्रोहों में प्रकट हुआ, जिनमें धनी किसानों तक ने भाग लिया। साइबेरिया को कोल्चाक की फ़ौजों से मुक्त कराने के बाद मंझोले किसानों ने अनाज के अपने अनिवार्य कोटे बेच दिये और देश के केंद्रीय क्षेत्रों को अनाज तथा अन्य खाद्य-पदार्थों की सप्लाई की।

राज्य और मज़दूरों द्वारा किसानों को दी गयी सहायता ने इस सहबंध को मज़बूत बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। मिसाल के लिए, १९१८-२० की अवधि में २,२८,००० हल, २७,३०० पटेले, ३,६०० थ्रैशर, ३,६०० बुआई की मशीनें और २१,८०,००० हंसिये गांवों में भेजे गये।

दो मेहनतकश वर्गों के सहबंध की शक्ति और जीवंतता गृहयुद्ध के वर्षों की अग्निपरीक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरीं।

३. मज़दूरों और किसानों का सहबंध – समाजवाद के निर्माण का आधार

सात साल से लगभग लगातार चल रहे युद्ध ने किसानों की खेती पर विनाशकारी प्रभाव डाला था। बुआई का क्षेत्र २५ प्रतिशत घट गया था। किसानों को कृषि-मशीनों की बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन युद्ध में तहस-नहस हो चुका उद्योग उनका न के बराबर उत्पादन कर रहा था। किसान अनाज तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें संपूर्ण अतिरिक्त अनाज राज्य को दे देना पड़ता था। युद्धकालीन परिस्थितियों की कठिनाइयों से अनिवार्य बनी "युद्धकालीन कम्युनिज़्म" की नीति गृहयुद्ध के बाद किसानों को संतुष्ट नहीं कर सकी।

किसानों के साथ नये आर्थिक संबंधों की स्थापना में मज़दूर वर्ग

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'सोवियतों की सातवीं अखिल रूसी कांग्रेस में दिया गया भाषण', ५ दिसम्बर, १९१९।

भी दिलचस्पी रखता था, क्योंकि अनिवार्य वसूली न तो उद्योग न ही मेहनतकशों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा कर सकी। कृषि उत्पादन में वृद्धि पूरे समाज के हित में थी।

हाल ही में बने मज़दूरों और किसानों के सैनिक और राजनीतिक सहबंध को एक सुदृढ़ आर्थिक आधार की ज़रूरत थी और "किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए क़दम उठाना, उनकी आर्थिक स्थिति को हल्का बनाने के लिए अधिकतम करना"* आवश्यक था। इन क़दमों को पैदावार बढ़ाने में किसानों की व्यक्तिगत दिलचस्पी पैदा करनी थी। इसी तरीक़े से ही कृषि अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया, बड़े उद्योग के लिए साधन जुटाया, मज़दूरों और किसानों के सहबंध को मज़बूत बनाया तथा उद्योग और कृषि को समाजवादी आधारों पर रूपांतरित किया जा सकता था।

कृषि पैदावार की अनिवार्य वसूली से जिंसरूप कर में बदलाव ने किसानों को अपनी उपज बढ़ाने के लिए भौतिक प्रोत्साहन प्रदान किया। इस सुधार का प्रगतिशील स्वरूप इसमें था कि उसने कुलकों को काफ़ी सीमित करते हुए और ग्रामीण आबादी के घोर ग़रीब हिस्सों को सहायता देते हुए न केवल कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, वरन उसका विस्तार भी किया। नगर और देहात के बीच एक आर्थिक कड़ी के रूप में, मज़दूरों और किसानों के बीच आर्थिक सहबंध के सुदृढ़ीकरण के एकमात्र संभव मार्ग के रूप में और समाजवादी आर्थिक प्रबंध के एक साधन के रूप में व्यापार राजकीय कार्य का मामला बन गया।

लेनिनीय सहकारिता योजना

अक्तूबर क्रांति की विजय के बाद देहातों का समाजवादी रूपांतरण मज़दूर वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टी के समक्ष प्रस्तुत एक अत्यंत जटिल कार्यभार बन गया। लेनिन के शब्दों में, "यह समाजवादी निर्माण का एक सबसे कठिन कार्यभार है, जो सभी पूंजीवादी देशों

---

* व्ला० इ० लेनिन, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की दसवीं कांग्रेस, ८-१६ मार्च, १९२१।

के समक्ष प्रस्तुत होगा।"*

लेनिन की सहकारिता योजना, जिसने इस रूपांतरण का मार्ग, रूप और विधियां निर्दिष्ट कीं, कृषि अर्थव्यवस्था के समाजवादी रूपांतरण की योजना बन गयी। लेनिन ने जनवरी १९२३ में लिखे लेख 'सहकारिता के बारे में' में इस योजना की विस्तृत रूपरेखा पेश की। यह योजना रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशिष्टताओं के लंबे और गहन अध्ययन, समाजवाद के निर्माण में पहले अनुभव के सामान्यीकरण, पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि में किसानों की सहकारिता पर मार्क्स और एंगेल्स के विचारों के विकास का परिणाम थी।

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के संस्थापकों ने पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि में सहकारिता के स्थान, भूमिका और महत्व के बारे में निम्नलिखित विचार पेश किये:

१) किसानों की सहकारिता लघु उत्पादन से बड़े यंत्रीकृत उत्पादन में संक्रमण का एक वस्तुगत नियम है। मार्क्स के शब्दों में, "छोटा भू-स्वामित्व अपनी प्रकृति से ही श्रम की सामाजिक उत्पादक शक्तियों, श्रम के सामाजिक रूपों, पूंजी के सामाजिक संकेन्द्रण, बड़े पैमाने पर पशुपालन के विकास और विज्ञान के वर्धमान प्रयोग को अपवर्जित करता है।"**

२) किसान की द्वैध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लघु किसानी खेती का बड़ी समाजवादी खेती में रूपांतरण सर्वोत्तम मार्ग है। एंगेल्स ने इस संबंध में लिखा कि सहकारी उत्पादन का पूर्ण कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था में संक्रमण-अवस्था के रूप में व्यापकतः इस्तेमाल करना पड़ेगा।***

३) सहकारिता की समाजवादी भूमिका और महत्व सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद ही प्रकट हो सकते हैं। मार्क्स ने लिखा: "सहकारी प्रणाली कभी पूंजीवादी समाज का रूपांतरण नहीं

---

* व्ला० इ० लेनिन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस में भाषण की थीसिसें, १९२१।

** कार्ल मार्क्स, 'पूजी', खंड ३, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८३, पृ० ७१२।

*** अगस्त बेबेल को एंगेल्स का पत्र, २०-२३ जनवरी, १८८६।

कर सकती। सामाजिक उत्पादन को मुक्त और सहकारी श्रम की एक बड़ी तथा सामंजस्यपूर्ण प्रणाली में बदलने के लिए **आम सामाजिक परिवर्तनों की, समाज के मूलाधार में परिवर्तनों की ज़रूरत पड़ती है।"***

४) सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की परिस्थितियों में किसानों का सहकारी उत्पादन किसानों और मज़दूरों के सहबंध को सुदृढ़ करना तथा वर्गहीन समाज के निर्माण के लिए परिस्थितियां तैयार करना संभव बनाता है।

देहात में समाजवाद के निर्माण की विधियां निर्धारित करने में राज्य राजनीतिक कारकों को भी ध्यान में रखता है। किसानों के उत्पादन साधनों के समाजीकरण को पूंजी के ख़िलाफ़, समाजवाद की विजय के लिए मज़दूरों और मेहनतकश किसानों के वर्ग सहबंध के एक विशेष रूप के तौर पर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को सुनिश्चित बनाना चाहिए।

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व व्यक्तिगत श्रम पर आधारित किसानों की छोटी निजी संपत्ति के प्रति पूंजीवादी संपत्ति से भिन्न रुख़ अपनाता है। यह सुस्पष्ट है कि देहात में उत्पादन साधनों का समाजीकरण उद्योग में अपनायी गयी विधि से भिन्न विधि से किया जाना चाहिए। यह विधि किसानों और मज़दूरों, दोनों ही को स्वीकार्य होनी चाहिए। इसे किसानों के वर्ग स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए तथा खेतिहर मज़दूरों और मज़दूरों के सहबंध को मज़बूत बनाना चाहिए। इसके साथ ही उत्पादन साधनों के समाजीकरण की विधि को किसानों को समाजवाद के निर्माण में धीरे-धीरे खींचने में सहायता देना है।

जब समाज में राजनीतिक सत्ता और अर्थव्यवस्था में निर्णायक स्थितियां मज़दूर वर्ग के हाथों में हों, तो छोटे मालिकों का आर्थिक समुदाय या सहकारिताओं में एकीकरण छोटी किसानी खेती को बड़े पैमाने की खेती में रूपांतरण की समाजवादी विधि है।

* का० मार्क्स, 'अस्थायी जनरल कौंसिल के डेलीगेटों के लिए निर्देश', का० मार्क्स और फ़्रे० एंगेल्स, संकलित रचनाएं, तीन खंडों में, खंड २, भाग १, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९७७, पृ० ९८।

पुरानी बुर्जुआ सहकारिता का समाजवादी सहकारिता में रूपांतरण कृषि के समाजवादी पुनर्निर्माण की लेनिनीय योजना के कार्यान्वयन की पहली आवश्यक शर्त थी।

लेनिन ने बारंबार कहा कि किसानों को समाजवाद के निर्माण में सहकारिता के ज़रिये खींचा जाना चाहिए।

पूंजीवाद के तहत सहकारिता उत्पादन के पूंजीवादी संगठन के रूप में सामने आती है, जबकि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व और उत्पादन के मूल साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की परिस्थितियों में उसके स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आते हैं।

रूस में सहकारिता १९वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रकट हुई और उत्पादक आर्तेलों (सहकारिताओं), उपभोक्ता समाजों, उधार और बचत समाजों, आदि संगठनों के रूप में क़ायम थी। उसने मज़दूरों, दस्तकारों, छोटे सफ़ेदपोश कर्मचारियों को एकजुट किया, लेकिन उसका स्वरूप मुख्यत: ग्रामीण था।

पूंजीवाद, ग़रीबी, ज़मींदारों, साहूकारों और बिचौलियों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ संघर्ष के एक साधन के रूप में उभरी सहकारिता धीरे-धीरे पूंजीवादी संबंधों की प्रणाली में खिंचने लगी और स्वयं ही उजरती श्रम का शोषक बन गयी।

अक्तूबर क्रांति की विजय ने बुर्जुआ सहकारिता को समाजवादी सहकारिता में, पूंजीवाद के एक दुमछल्ले से समाज के समाजवादी रूपांतरण के एक साधन में बदलने की परिस्थितियां निर्मित कीं। लेनिन ने ज़ोर देते हुए कहा, "बुर्जुआ सहकारिताओं से समझौते से डरना हमारे लिए हास्यास्पद होगा, क्योंकि हम अब शासक सत्ता हैं। हमें ऐसे समझौते की ज़रूरत है, जो आंशिक, बिखरी सहकारिताओं से एक अखिल राष्ट्रीय सहकारिता में संक्रमण के व्यावहारिक रूप से संभव, सुविधाजनक और उपयुक्त रूप पाने में हमें समर्थ बना सके। राजकीय सत्ता के रूप में हमें बुर्जुआ सहकारिताओं से समझौता करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ऐसे समझौते का अर्थ हमारे अधीन उनकी अनिवार्य मातहती होगा।"*

खाद्य-पदार्थों के क्रय, संचय और आबादी के बीच उनके वितरण

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'सोवियत सत्ता के तात्कालिक कार्यभार' लेख की मूल रूप, १९१८।

में सहकारिताओं को खींचना, उनके प्रबंधक निकायों से बुर्जुआ तत्वों को बहिष्कृत करना, विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन और क्रय में विशेषज्ञताप्राप्त सहकारिताओं की संख्या में वृद्धि करना इस दिशा में पहले क़दम थे। इन्हीं दिनों पहली उत्पादक सहकारिताएं (कम्यून), आर्तेल और साझी जुताई समाज संगठित किये गये।

अखिल रूसी कृषि सहकारिता संघ ने, जिसमें विभिन्न कृषि सहकारिताओं में शामिल ७५ प्रतिशत परिवार एकजुट थे, कृषि सहकारिता प्रणाली में मुख्य भूमिका अदा की। कम्यूनों, आर्तेलों और साझी जुताई समाजों ने, जो संघ में सभी सहकारिताओं का ५० प्रतिशत बनाते थे, सहकारिताओं के कार्यकलाप पर निरंतर समाजवादी प्रभाव डाला।

१६२२ में बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति के तहत व० कूइबिशेव के नेतृत्व में संगठित सहकारी आयोग ने सहकारिताओं और उनके निकायों के कार्यकलाप का अध्ययन किया, उनके कार्यों के अनुभव का सामान्यीकरण किया तथा सहकारी आंदोलन के सभी निकायों में कर्मियों के प्रशिक्षण, चुनाव, पदोन्नति और नियुक्ति का विवेचन किया।

राजकीय ऋण देने सहित सहकारी आंदोलन को निरंतर सहायता प्रदान करते हुए सोवियत सरकार ने उसके उत्पादन कार्य का नियमन और छोटे उत्पादकों को समाजवाद की ओर उन्मुख करके सहकारिता पर उत्तरोत्तर बढ़ता प्रभाव डाला।

उत्पादन सहकारिताओं सहित कृषि सहकारिताओं की लगातार बढ़ती संख्या उनके प्रति मेहनतकश किसानों के सकारात्मक रुख का प्रमाण थी।

सहकारिता में किसानों को खींचने में पार्टी द्वारा संचित अनुभव का विश्लेषण करते हुए लेनिन ने उसके समाजवादी विकास की पूर्ण संभावना प्रकट की।

सोवियत सत्ता के अंतर्गत सहकारिता ने देहात में समाजवाद की स्थापना के लिए "सब कुछ आवश्यक" प्रदान किया, क्योंकि उसने "अत्यधिक सरल, आसान और किसान के लिए सुलभ्य मार्ग से नयी व्यवस्था में संक्रमण"* की संभावना दी। सहकारिता संगठन

* व्ला० इ० लेनिन, 'सहकारिता के बारे में', १९२३।

के एक रूप के तौर पर किसानों के लिए सुविदित थी, व्यवहार की कसौटी पर खरी उतर चुकी थी। अभी उसकी समाजवादी संभावनाओं को न देख पाते हुए, लेकिन संयुक्त प्रयासों के आर्थिक लाभों को समझते हुए किसानों ने सहकारिता में ग़रीबी और अज्ञान से मुक्ति देखी। किसानों को सामूहिक श्रम के लाभों को अपनी आंखों से देखने की संभावना प्रदान करते हुए सहकारिता समाजवाद की ओर छोटे किसानों के आगे बढ़ने का न केवल सरल, सुलभ्य, बल्कि अत्यधिक दृढ़ और विश्वसनीय मार्ग भी थी।

सहकारिता किसानों के व्यक्तिगत हितों और समाज के हितों में ताल-मेल बैठाती है। सहकारिता के सरल से सरल रूप भी (विपणन, सप्लाई और वितरण) समाजवादी तत्वों के विकास, उस सामूहिकतावाद के विकास को सर्वतोमुखी बढ़ावा देते हैं, जो नये समाजवादी संबंधों के स्वरूप से पूर्णतः मेल खाता है या जैसा कि लेनिन ने लिखा, "समाजवाद से लगभग हमेशा पूर्णतः मेल खाता है।"* उत्पादन में सहकारिता का उच्चतम रूप वस्तुतः उत्पादन का समाजवादी संगठन है।

लेनिन ने ज़ोर दिया कि लघु किसानी खेती ग़रीबी से नहीं बच सकती, कि सहकारी उद्यम और सामूहिक खेती शुरू करने में किसानों की सहायता की जानी चाहिए। केवल कृषि का सामूहिकीकरण ही देश को समाजवादी विकास के मार्ग पर ले जा सकता था और लाखों किसानों को कुलकों के जुए, ग़रीबी तथा अज्ञान से मुक्ति दिला सकता था।

समाजवादी सहकारिता के सिद्धांत

लेनिनीय सहकारी योजना में कृषक परिवारों के सहकारीकरण के सिद्धांतों और विधियों का भी प्रतिपादन किया गया था। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था **क्रमिक और स्वैच्छिक रुख।** "आदेश जारी करके या बाहर से दबाव डालकर इन खेतों को तेज़ी से कोई नया

* वही।

रूप देने की कोशिश करना सरासर बेतुकी बात होगी। हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि हम केवल धीरे-धीरे और सतर्क रहकर और केवल सफल व्यावहारिक उदाहरण द्वारा ही अलग-अलग किसानों के छोटे-छोटे करोड़ों खेतों पर कोई असर डाल सकते हैं, क्योंकि किसान इतने व्यवहार-कुशल होते हैं और खेती के पुराने तरीक़ों से इतनी बुरी तरह चिपके होते हैं कि वे केवल सलाह के आधार पर या हिदायतों के आधार पर किसी गंभीर परिवर्तन के लिए राज़ी नहीं होंगे।"* लेकिन स्वैच्छिकता के सिद्धांत का यह अर्थ नहीं था कि किसान स्वतः-स्फूर्त ढंग से समाजवाद के मार्ग पर मज़दूर वर्ग का अनुसरण करेंगे। मज़दूरों और किसानों के बीच सहबंध को सुदृढ़ करके कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने कृषि के सामूहिक रूपों के संक्रमण में किसानों की सहायता करते हुए उन्हें सक्रियतः प्रभावित किया। लेनिन ने इंगित किया कि किसानों को सामूहिक उत्पादन के लाभों के प्रति उनके अपने ही अनुभव से क़ायल करना आवश्यक है।

किसान अपने जीवन में परिवर्तन को केवल तभी स्वीकार करता है जब उसमें वह आर्थिक लाभ देखता है। अतः स्वैच्छिकता का सिद्धांत सहकारिता में किसानों को मिलनेवाले **भौतिक लाभों** पर निर्भर है।

व्यक्तिगत दिलचस्पी के इस सिद्धांत को सहकारीकरण की **क्रमिकता** के दृष्टिकोण के साथ मेल बैठाया जाना चाहिए, जो प्रारंभिक अवस्थाओं में सामूहिकीकरण (सप्लाई, विपणन और ऋण सहकारिता) में किसानों को खींचने के सबसे सरल और स्वीकार्य रूपों के प्रयोग की पूर्वकल्पना करता है। देश के औद्योगीकरण और सहकारिता के इन प्रकारों के लाभों में किसानों के बढ़ते विश्वास के साथ समाजवाद में सामूहिक कृषि उत्पादन संगठन के मुख्य रूप के तौर पर उत्पादक सहकारिताओं में संक्रमण नियमसंगत और उचित होगा। लेनिन ने कहा: "बहुसंख्य छोटे किसानी खेतों को बड़े फ़ार्मों में तुरंत ही नहीं बदला जा सकता। कृषि, जो अब तक असंगठित रूप से की जाती रही है, तुरंत या अल्प काल में समाजीकृत और बडे राजकीय उद्यम में परिवर्तित नहीं

---

* व्ला० इ० लेनिन, कृषि-कम्यूनों और कृषि आर्तेलों की पहली कांग्रेस में दिया गया भाषण, ४ दिसम्बर, १९१९।

की जा सकती।"*

इस पूर्वाधार से आगे बढ़ते हुए कि किसी भी सामाजिक प्रणाली को भौतिक समर्थन की आवश्यकता होती है, लेनिन ने ज़ोर देते हुए लिखा कि "वर्तमान समय में सहकारी प्रणाली वह सामाजिक प्रणाली है, जिसे हमें अब साधारण सहायता से अधिक सहायता देनी चाहिए"।**

लेनिन ने सहकारी योजना को "पूरी सांस्कृतिक क्रांति",*** किसानों के सांस्कृतिक स्तरों में वृद्धि से अविच्छिन्न रूप से जोड़ा "ताकि वे सहकारिताओं के कार्य में हरेक की सहभागिता के सभी लाभों को समझें और इस सहभागिता को संगठित करें"।****

लेनिन ने कृषि को रूपांतरित करने में समर्थ बड़े उद्योग के निर्माण को समाजवादी आधार पर कृषि के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक माना। देश के औद्योगीकरण के कार्यान्वयन ने कृषि मशीनों का उत्पादन शुरू करना और कृषि के विकास के लिए आवश्यक भौतिक-तकनीकी आधार निर्मित करना संभव बना दिया।

सहकारिता आंदोलन के दौरान पार्टी और सोवियत निकायों ने स्थानीय आर्थिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टताओं, स्थानीय आबादी की जीवन पद्धति और परंपराओं को उचित रूप से ध्यान में रखा।

लेनिनीय सहकारिता योजना समाजवादी आधार पर कृषि के समाजवादी रूपांतरण संबंधी सभी व्यावहारिक कार्यों की सुदृढ़ बुनियाद बनी।

आम सामूहिकीकरण के लिए तैयारी

चूंकि रूस जैसे देश में, जहां छोटे-छोटे खेतों की प्रधानता थी, कृषि विकास की विधि संबंधी प्रश्न समग्रतः समाजवाद के भाग्य को निर्धारित करनेवाला एक मूल प्रश्न था, इसलिए लेनिनीय सहकारी

---

* व्ला० इ० लेनिन, केंद्रीय गुबेर्नियों की ग़रीब किसान समितियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में किया गया भाषण, ८ नवम्बर, १९१८।

** व्ला० इ० लेनिन, 'सहकारिता के बारे में', १९२३।

*** वही।

**** वही।

योजना के विचारों को सिद्धांत और व्यवहार, दोनों में अमली जामा पहनाने के तरीक़ों पर ज़बर्दस्त विचारधारात्मक संघर्ष छिड़ गया।

पार्टी ने त्रोत्स्कीपंथियों के विरुद्ध तीव्र राजनीतिक संघर्ष चलाया, जो पूंजीवादी राज्यों द्वारा घिरे एक देश में समाजवाद की विजय की संभावना से इन्कार करते थे, किसानों को प्रतिक्रियावादी मानते थे और उनके समाजवादी कायापलट की संभावना में विश्वास नहीं करते थे।

पार्टी ने त्रोत्स्की-ज़िनोव्येव विरोधपक्ष के ख़िलाफ़ संघर्ष किया, जो सहकारिता को पूंजीवादी प्रवृत्तियों का वाहक मानता था, उसे सामूहिकीकरण के मुक़ाबले में रखता था और सामूहिकीकरण को गांव के निर्धनतम हिस्सों के लिए ही उपयुक्त मानता था।

विरोधियों के कठोर प्रतिरोध पर क़ाबू पाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने लाखों किसानों के अनुभव का अध्ययन और सैद्धांतिक सामान्यीकरण किया, देहात में समाजवादी कायापलट के विशिष्ट रूप तैयार किये तथा उसकी अवधि निर्धारित की।

सामूहिक फ़ार्म संगठित करने का काम व्यवहारतः सोवियत सत्ता की स्थापना के शीघ्र बाद ही शुरू हो गया। भूतपूर्व ज़मींदारियों पर पहली उत्पादक सहकारिताएं – कृषि संघ, आर्तेल और कम्यून – क़ायम की गयीं, जिनके उदाहरण से किसान बड़ी खेती के लाभों के प्रति विश्वस्त हुए। ये सामूहिक खेती के पहले केंद्र थे। पार्टी और सोवियत राज्य ने सामूहिक फ़ार्मों को टेक्नोलाजिकल, आर्थिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके विकास और सुदृढ़ीकरण में चहुंमुखी हाथ बंटाया।

कृषि आर्तेल उत्पादक सहकारिता के सर्वाधिक उपयुक्त रूप निकले। १९२७ के मध्य तक देश में लगभग १५,००० ऐसे आर्तेल थे, जिनमें एक प्रतिशत से कम कृषक फ़ार्म संयुक्त हुए थे।

कुछ सफलताओं के बावजूद सोवियत सत्ता के प्रारंभिक वर्षों में कृषि बड़ी धीमी गति से विकसित हुई। वह खाद्य-पदार्थों और कच्चे मालों की बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी। कृषि का पिछड़ेपन देश के आगे विकास में बाधक बन गया था।

वस्तुगत आवश्यकता के साथ समाजवादी निर्माण के कार्यभारों ने कृषि के समाजवादी रूपांतरण की मांग की। मुख्यतः छोटी निजी

संपत्ति और शारीरिक श्रम पर आधारित कृषि उद्योग से पिछड़ी हुई थी और शहरी आबादी की खाद्य-पदार्थों तथा उद्योग की कच्चे मालों की बढ़ती मांगों को नहीं पूरा कर सकती थी। केवल बड़ी यंत्रीकृत कृषि ही समाजवादी निर्माण के कार्यभारों को पूरा कर सकती थी।

बड़े कृषि उत्पादन में संक्रमण स्वयं किसानों के मौलिक हितों को देखते हुए आवश्यक था, क्योंकि वे छोटी कृषि में समाजवादी राज्य द्वारा कृषि मशीनों के रूप में दी गयी सहायता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे, न ही खेती के काम को आसान बना तथा अपनी भौतिक स्थिति को ऊंचा उठा सकते थे। स्वयं जीवन ने लेनिन के उन शब्दों की सत्यता को पुष्ट कर दिया, जो उन्होंने १९१७ में कहे थे: "यदि हम पहले की भांति ही अपने छोटे, बिखरे हुए खेतों को जारी रखेंगे, चाहे यह स्वतंत्र ज़मीन पर स्वतंत्र नागरिकों के रूप में ही क्यों न हो, तो हमारे सामने अब भी अनिवार्य विनाश का ख़तरा प्रस्तुत होगा..."*

आर्थिक आवश्यकताओं ने अनुत्पादक छोटे किसानी खेतों को बड़े सामूहिक फ़ार्मों में बदलना अनिवार्य बना दिया। समग्र रूप में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद क्रांत्योत्तर काल में पण्य अनाज की मात्रा में काफ़ी गिरावट आयी थी। इसका मुख्य कारण कृषि का बिखरा हुआ स्वरूप था। क्रांति-पूर्व रूस में ज़मींदारों और कुलकों के फ़ार्म पण्य अनाज का एक बड़ा हिस्सा देते थे। अक्तूबर क्रांति के फल-स्वरूप ज़मींदारों की भूसंपत्तियों का उन्मूलन हो गया और कुलकों के फ़ार्मों की संख्या काफ़ी घट गयी। १९२७ में छोटे और मंझोले किसानी फ़ार्मों की संख्या १९१३ में १५०-१६० लाख के मुक़ाबले में २४०-२५० लाख हो गयी थी। वे पण्य अनाज के मुख्य उत्पादक और सप्लायर बन गये थे। क्रांति के पहले छोटे किसानी फ़ार्मों द्वारा उत्पादित पण्य अनाज की मात्रा बहुत कम (१४.७ प्रतिशत) थी, लेकिन क्रांति के बाद किसानों के उपभोग में वृद्धि के कारण वह गिरकर नीचे (११.२ प्रतिशत) आ गयी। अनाज की वसूली में बड़ी कमी आ गयी: १९२७-

---

* व्ला० इ० लेनिन, किसानों के प्रतिनिधियों की पहली अखिल रूसी कांग्रेस, १९१७।

१६२८ में किसानों ने १६१३ में १३० करोड़ पूड* की तुलना में ६२ करोड़ ७० लाख पूड अनाज बेचे।

कुल पण्य अनाज में राजकीय और सामूहिक फ़ार्मों का हिस्सा मात्र ६ प्रतिशत था। कुलकों ने पण्य अनाज की मात्रा को कृत्रिम ढंग से कम कर दिया और अनाज की वसूली की तोड़-फोड़ करने और पूंजीवाद को बहाल करने का प्रयास करते हुए सोवियत राज्य को अनाज बेचने से इन्कार कर दिया।

इस तरह, बड़ी समाजवादी कृषि में संक्रमण की आवश्यकता वस्तुगत आंतरिक कारणों से पैदा हुई थी। कृषि का पूर्ण सामूहिकीकरण देहात में पूंजीवादी तत्वों को जन्म देनेवाले कारणों का अनिवार्यतः उन्मूलन कर देता। अनाज समस्या का समाधान करने, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से देश की रक्षा को मज़बूत बनाने का यही एकमात्र तरीक़ा था। बाह्य कारकों ने भी सामूहिकीकरण के कार्यान्वयन को आवश्यक बना दिया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद सोवियत संघ में समाजवादी निर्माण को क्षति पहुंचाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहा था। रूस में पूंजीवाद को बहाल करने का षड्यंत्र करते हुए बुर्जुआ वर्ग ने आशा की थी कि देश में बचे-खुचे पूंजीवादी तत्व – मिसाल के लिए देहात में कुलक – उनकी योजनाओं का समर्थन करेंगे।

दिसम्बर १६२७ में कम्युनिस्ट पार्टी की १५वीं कांग्रेस में सामूहिकीकरण की नीति की घोषणा की गयी। कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया था: "वर्तमान समय में छोटे, बिखरे किसानी फ़ार्मों का बड़े सामूहिक फ़ार्मों में एकीकरण और रूपांतरण देहात में पार्टी का **मुख्य कार्य** बन जाना चाहिए।"**

कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीति को उस काल के विभिन्न पार्टी दस्तावेज़ों में ठोस रूप दिया और विकसित किया गया। उनमें १६वें पार्टी सम्मेलन (अप्रैल १६२६) के प्रस्तावों का बड़ा महत्व था,

* पुराना रूसी तोल, जो १६.३८ किलोग्राम या ३६ पौंड के बराबर होता है। – सं०

** सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेसों, सम्मेलनों और केंद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशनों के निर्णय, खंड ४, मास्को, १६७०, पृ० ५७ (रूसी में)।

जिन्होंने आर्थिक विकास की पहली पंचवर्षीय योजना को पुष्ट किया, जिसमें सामूहिकीकरण पर विशेष क़दमों की व्यवस्था थी।

सामूहिकीकरण की नीति ने पार्टी और सोवियत निकायों से जनता में सामूहिकीकरण के विचारों के प्रचार को तेज़ करने और देश में अंतिम शोषक वर्ग – कुलक वर्ग – पर हमला शुरू करने की मांग की।

१६२७-२६ में संपूर्ण सामूहिकीकरण के लिए भौतिक तथा टेक्नोलाजिकल पूर्वाधार क़ायम करने हेतु विराट काम किया गया। सामूहिक फ़ार्मों को दिये जानेवाले धन और कृषि-मशीनों में वृद्धि की गयी। ट्रैक्टरों की संख्या में बढ़ती की गयी और उनके अधिक सुदक्ष उपयोग के लिए "ट्रैक्टर दस्ते" तथा आगे चलकर मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन बनाये गये, जिन्होंने कृषि के समाजवादी पुनर्निर्माण के शक्तिशाली उत्तोलक का काम किया।

संपूर्ण सामूहिकीकरण की नीति के कार्यान्वयन में राजकीय फ़ार्मों द्वारा दी गयी बड़ी संगठनात्मक और टेक्नोलाजिकल सहायता, सांस्कृतिक और प्रचार कार्य का असाधारण महत्व था। बड़ी यंत्रीकृत कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हज़ारों किसान राजकीय फ़ार्मों में गये।

संपूर्ण सामूहिकीकरण ने सभी ग़रीब किसानों, खेत मज़दूरों और सभी ग्रामीण कार्यकर्ताओं की एकजुटता की मांग की। ग़रीब किसानों के हितों की रक्षा और कुलकों से संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाले निर्धन किसानों के ग्रुप ग्रामीण सोवियतों, सामूहिक फ़ार्मों और कृषि सहकारिताओं में संगठित हो रहे थे।

सामूहिक फ़ार्म आंदोलन के संगठनकर्ताओं और कृषि विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए अखिल संघीय सामूहिक फ़ार्म केंद्र के तहत केंद्रीय स्कूल और कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के तहत विशेष कोर्स खोले गये तथा उच्च और माध्यमिक कृषि शिक्षा संस्थानों का जाल बिछाया गया।

शहरी पार्टी और ट्रेड-यूनियन संगठनों ने गांवों पर अपने संरक्षण*

* संरक्षण – सोवियत संघ में सार्वजनिक कार्य का एक रूप, एक उद्यम के कर्मियों द्वारा दूसरे उद्यम के कर्मियों को दी जानेवाली विधिवत् साथीवत् सहायता। यहां चर्चा मज़दूरों द्वारा किसानों को दी गयी सहायता के बारे में है। – सं०

को पहले से काफ़ी व्यापक बना दिया। सामूहिकीकरण को अमली जामा पहनाने में व्यावहारिक सहायता प्रदान करने के लिए पार्टी ने मज़दूर वर्ग से देहात में जाने और नव-स्थापित सामूहिक फ़ार्मों का प्रबंध करने के लिए अपने २५ हज़ार अत्यंत वर्गचेतन और बड़े अनुभवी कर्मी देने की अपील की। मज़दूर वर्ग ने इस अपील के उत्तर में अपने कोई ३५ हज़ार कर्मी देहात भेजे। राजकीय फ़ार्मों के खेतिहर मज़दूरों ने भी सक्रिय प्रचारकों और सामूहिक फ़ार्म संगठनकर्ताओं के रूप में अपना योगदान किया। इसके अलावा, बुआई, कटाई, कृषि मशीनों की मरम्मत और सांस्कृतिक तथा प्रचार कार्य में सहायता करने के लिए दसियों हज़ार मज़दूर देहात भेजे गये।

१६३० के वसंत में १,१३,००० कम्युनिस्टों और ५,५३,००० कोम्सोमोल सदस्यों ने सामूहिक फ़ार्मों में काम किया। वे सामूहिक फ़ार्म आंदोलन के संगठित हरावल थे।

सहकारी फ़ार्मों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। १६२६ के उत्तरार्ध में ६७,४०० सामूहिक फ़ार्म थे। उनके पास कुल खेतीयोग्य ज़मीन का ३.६ प्रतिशत था, जिस पर उन्होंने कुल पण्य उपज के ४.६ प्रतिशत का उत्पादन किया। उस समय तक मंझोले किसान भी सामूहिक फ़ार्मों में बड़ी संख्या में शामिल होने लगे थे।

यह सब इस बात का प्रमाण था कि कृषि के संपूर्ण सामूहिकीकरण के लिए आवश्यक भौतिक, टेक्नोलाजिकल और राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित हो चुकी थीं। १६२६ के अंत में सामूहिक फ़ार्म आंदोलन के विकास और सामूहिक फ़ार्मों के प्रति अधिकांश किसानों के रुख़ में हुए मौलिक परिवर्तनों का मूल्यांकन करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन (नवम्बर १६२६) ने उल्लेख किया कि सामूहिक फ़ार्म आंदोलन ने **समस्त क्षेत्रों के संपूर्ण सामूहिकीकरण** में विकसित होना शुरू कर दिया है। लेनिनीय सहकारी योजना के कार्यान्वयन में निर्णायक और अत्यंत जटिल अवस्था शुरू हुई।

कृषि के समाजवादी रूपों में विकास, पूंजीवादी तत्वों के सफ़ाये और इसके कारण कुलकों के प्रतिरोध में वृद्धि के फलस्वरूप देश में वर्ग संघर्ष अधिक तेज़ हो गया।

व्यापक पैमाने पर सामूहिकीकरण और कुलकों पर हमले के दौरान पार्टी में दक्षिणपंथी भटकाव ने बड़ा ख़तरा प्रस्तुत किया। उसके नेताओं –

बुखारिन, रीकोव और तोम्स्की – ने पार्टी की कृषि नीति का खुल्लम-खुल्ला विरोध किया और कुलकों की पैरवी की। उनके विचारों ने लेनिनीय सहकारी योजना और पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि में वर्गों और वर्ग संघर्ष के उनके सिद्धांत को सरासर तोड़ा-मरोड़ा। उन्होंने उत्पादक सहकारिता की भूमिका से इन्कार किया और माना कि संभरण और विक्रय सहकारिता के ज़रिये समाजवाद पर पहुंचा जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी निर्माण केवल तभी सफल हो सकता है जब मज़दूर वर्ग और कुलकों सहित समस्त कृषक वर्ग के बीच सहबंध क़ायम हो, कि सोवियत संघ में समाजवाद के पिछड़े रूप का ही निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि उसके निर्माण की अवधि लंबी और गति बहुत ही धीमी होगी। वर्ग संघर्ष को धीरे-धीरे मिटाने और समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तत्वों के "शांतिपूर्ण विलय" की अवधारणा पेश करते हुए दक्षिणपंथियों ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के मुख्य कार्यभार को मानो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रखनेवाले विभिन्न वर्गों और समाजवाद के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख़ से भरे ग्रुपों सहित सामाजिक ग्रुपों के बीच संबंधों को विनियमित करने तक ही सीमित कर दिया। उन्होंने कुलक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए संभावनाएं बढ़ाने की मांग की।

दक्षिणपंथियों के विचार सरासर टुटपुंजिया थे, मार्क्सवाद-लेनिनवाद से तनिक भी मेल नहीं खाते थे तथा उनका उद्देश्य देहात में समाजवादी परिवर्तनों को क्षति पहुंचाना, मज़दूरों और मेहनतकश किसानों के बीच सहबंध को कमज़ोर करना एवं किसानों के बीच पूंजीवादी तत्वों को मज़बूत बनाना था। दक्षिणपंथियों की स्थिति की स्वीकृति वस्तुगत रूप से पूंजीवाद की बहाली की ओर ले जाती।

दक्षिणपंथियों के विरुद्ध पार्टी के दृढ़ संघर्ष और उनकी विचारधारात्मक तथा सांगठनिक पराजय ने कृषि में आगे समाजवादी परिवर्तन लाना, समाजवाद का सफलतापूर्वक निर्माण करना संभव बना दिया।

कम्युनिस्ट पार्टी – जन सामूहिक फ़ार्म आंदोलन की संगठनकर्ता। सामूहिकीकरण की विजय

५ जनवरी, १९३० को स्वीकृत पार्टी की केंद्रीय समिति का निर्णय 'सामूहिकीकरण की गति और राज्य द्वारा सामूहिक फ़ार्म आंदोलन को सहायता की कार्रवाइयों के बारे में' लेनिनीय सहकारी योजना के कार्यान्वयन का नीति निर्देशक दस्तावेज़ था।

पार्टी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की विविध आर्थिक और जातीय विशिष्टताओं तथा किसानों की तैयारी के स्तर को ध्यान में रखा और इसके आधार पर सामूहिकीकरण के कार्यान्वयन की निश्चित अवधियां तय कीं। सबसे पहले सामूहिकीकरण को देश के प्रमुख अनाज पैदा करनेवाले इलाक़ों में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

सामूहिकीकरण के सफल कार्यान्वयन ने शोषकों के अंतिम वर्ग – कुलक वर्ग – की स्थिति को एकदम कमज़ोर बना दिया। १ फ़रवरी, १९३० को केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और जन कमिसार परिषद ने 'संपूर्ण सामूहिकीकरण के क्षेत्रों में कृषि के समाजवादी पुनर्निर्माण के सुदृढ़ीकरण और कुलकों से संघर्ष संबंधी कार्रवाइयों के बारे में' फ़ैसला लिया। इस फ़ैसले ने संपूर्ण सामूहिकीकरण के क्षेत्रों में अलग-अलग किसानों द्वारा ज़मीन लगान पर लेने और भाड़े के श्रम का इस्तेमाल करने की अनुमति संबंधी क़ानून को समाप्त कर दिया तथा सोवियत सत्ता निकायों को कुलकों की संपत्ति ज़ब्त करने और उन्हें इन क्षेत्रों से निर्वासित करने की अनुमति प्रदान की। ग़रीब किसानों के शोषण से प्राप्त कुलकों की संपत्ति का एक बड़ा भाग ग़रीब किसानों और खेतिहर मज़दूरों के प्रवेश-योगदान के रूप में सामूहिक फ़ार्मों की अविभाज्य परिसंपत्तियों में मिला दिया गया।

स्वयं किसानों ने देहात में पूंजीवादी तत्वों का उन्मूलन करने संबंधी वर्ग नीति को अमल में लाने में सक्रिय भाग लिया। यह देहात में समाजवादी पुनर्निर्माण के लिए मेहनतकश किसानों का सच्चा क्रांतिकारी आंदोलन था। कुलक-विरोधी आयोग ग़रीब किसानों, वर्गचेतन मंझोले किसानों, सामूहिकीकरण के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए भेजे गये मज़दूरों और सोवियतों के प्रतिनिधियों से बने थे।

कुलकों के शारीरिक उन्मूलन के बारे में बुर्जुआ प्रचार का प्रपंच

सरासर झूठ है। वास्तव में बात उनकी शोषणकारी प्रवृत्तियों को जड़ से समाप्त करने और श्रम से उनकी पुनर्शिक्षा की थी। एक वर्ग के रूप में कुलकों के उन्मूलन की नीति में विभेदीकृत दृष्टिकोण की व्यवस्था थी: अधिकांश कुलकों को सामाजिक रूप से उपयोगी श्रम में लगने की संभावना दी गयी और उनके पास उत्पादन के न्यूनतम साधन और औज़ार छोड़े गये। सोवियत-विरोधी तत्वों के प्रति ही, जिन्होंने नयी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का हथियार उठाकर मुक़ाबला किया, दमनकारी कार्रवाइयां की गयीं। १९३० के शुरू से १९३२ की पतझड़ तक २,४०,००० से अधिक कुलक परिवारों को संपूर्ण सामूहिकीकरण के क्षेत्रों से निर्वासित किया गया। निर्वासन के क्षेत्रों में कुलकों को काम देने और उनके लिए जीवन की सामान्य परिस्थितियां बनाने हेतु क़दम उठाये गये। उन्हें पुनर्शिक्षित करने और पूर्ण अधिकारप्राप्त नागरिक बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी गयी। अधिकांश निर्वासित कुलक पश्चिम साइबेरिया और कज़ाख़स्तान में स्थित काष्ठ, निर्माण और खनन उद्योगों और राजकीय फ़ार्मों में काम कर रहे थे। संपूर्ण सामूहिकीकरण के कार्यान्वयन ने पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ दिया और देहात में समाजवाद की विजय को सुनिश्चित बनाया।

संपूर्ण सामूहिकीकरण की पहली अवस्था के परिणामों का निष्कर्ष निकालते हुए कम्युनिस्ट पार्टी की १६वीं कांग्रेस ने उल्लेख किया: "अगर ज़मींदारों की ज़मीन की ज़ब्ती अक्तूबर क्रांति द्वारा देहात में उठाया गया **पहला** पग थी, तो सामूहिक फ़ार्मों में संक्रमण **दूसरा** और, इससे बढ़कर, निर्णायक पग था जो सोवियत संघ में समाजवादी समाज की बुनियाद के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है।"*

लेकिन ऐसी बात नहीं कि कृषि के समाजवादी पुनर्निर्माण के कार्य की पूर्ति में, जो सर्वहारा द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद सबसे पेचीदा और कठिन कार्य था, भूलें और कमियां नहीं हुईं। ज़बर्दस्त सामूहिक फ़ार्म आंदोलन में बड़ी सफलताओं के साथ-साथ पार्टी नीति से कुछ विचलन भी हुए। ऐसी घटनाएं विरल नहीं थीं, जब सामूहिक फ़ार्मों के संगठन में स्वैच्छिकता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया

---

* 'सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय...', खंड ४, पृ० ४५८ (रूसी में)।

और देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया। पार्टी ने इंगित किया कि कृषि आर्तेल सामूहिक फ़ार्मों के निर्माण का मुख्य रूप है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में कृषि आर्तेलों के बजाय कम्यून भी क़ायम किये गये, जिनमें सभी कृषि मशीनों, पशुओं और पोल्ट्री तक का समाजीकरण कर दिया गया। इन ग़लतियों की वजह से किसानों में असंतोष पैदा हो गया, जिसका कुलकों और अन्य सोवियत-विरोधी तत्वों ने सामूहिकीकरण को विफल बनाने में इस्तेमाल किया।

सामूहिकीकरण की प्रारंभिक अवधि में इन गंभीर ग़लतियों के क्या कारण थे? बेशक, इन ग़लतियों का दोष सामूहिकीकरण पर, पार्टी और सोवियत राज्य की नीति पर नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि सोवियत-विरोधी जालसाज़ दावा करते हैं। इन ग़लतियों के कारण थे कृषि में समाजवादी रूपांतरणों की जटिलता और अभिनवता, आवश्यक अनुभव का अभाव, वास्तविक संभावनाओं और स्वयं किसानों की तैयारी के स्तर को ध्यान में रखे बिना प्रशासनिक विधियों से सामूहिकीकरण को तेज़ करने की विभिन्न प्रबंधकों की इच्छा।

पार्टी की केंद्रीय समिति ने इन नकारात्मक प्रवृत्तियों का ठीक समय पर पर्दाफ़ाश किया। १४ मार्च, १६३० को 'सामूहिक फ़ार्म आंदोलन संबंधी पार्टी नीति में भटकावों के विरुद्ध' प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उसमें ग़लतियों का आलोचनात्मक और गहन विश्लेषण किया गया, सामूहिक फ़ार्म आंदोलन के लिए उनके ख़तरे और नुक़्सान दिखाये गये तथा उन्हें ठीक और दूर करने के तरीक़े निर्धारित किये गये।

केंद्रीय समिति के प्रस्ताव और उसे कार्यान्वित करने के उद्देश्य से संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यों ने ग़लतियों को अल्प समय में ठीक करना, देहात में स्थिति, ख़ास तौर से मंझोले किसानों के साथ संबंधों को सुधारना संभव बना दिया। इसने बनाये जा चुके सामूहिक फ़ार्मों को मज़बूत करने और उनमें किसानों के प्रवेश को सुनिश्चित करने में सहायता की।

पहली पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग १५ लाख खेतों अथवा उनकी कुल संख्या के ६१.५ प्रतिशत का सामूहिकीकरण किया जा चुका था। बड़े पैमाने की समाजवादी कृषि सोवियत संघ में कृषि

का मुख्य रूप बन गयी।

सामूहिक फ़ार्मों का संगठनात्मक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण मुख्य कार्य बना। उसकी पूर्ति के लिए कृषि मशीनों के कारगर प्रयोग, श्रम उत्पादकता और सार्वजनिक कोषों में वृद्धि, श्रम के संगठन और वेतन-दरों की सुव्यवस्था, सामूहिक फ़ार्मों के कर्मियों के प्रशिक्षण, किसानों के निजी स्वामित्व वाले टुटपुंजिया विचारों और बचे-खुचे कुलकों के प्रभाव से संघर्ष की आवश्यकता थी।

१९३३ में मशीन और ट्रैक्टर स्टेशनों तथा राजकीय फ़ार्मों में बनाये गये राजनीतिक विभागों ने सामूहिक फ़ार्मों के संगठनात्मक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने सामूहिक फ़ार्मों में उत्पादन के लिए पार्टी और प्रबंधक कर्मियों, सभी कम्युनिस्टों में ज़िम्मेदारी की भावना बढ़ाने में सहायता की। राजनीतिक विभागों ने किसानों के बीच व्यापक राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य चलाया, सामूहिक फ़ार्मों में घुस आये विरोधी तत्वों से संघर्ष किया और सामूहिक किसानों को सार्वजनिक स्वामित्व तथा श्रम के प्रति समाजवादी रुख़ की भावना में प्रशिक्षित किया। अपने कार्य के दो वर्ष के दौरान राजनीतिक विभागों ने सामूहिक फ़ार्मों के संपूर्ण जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। अपना उद्देश्य पूरा कर लेने के बाद वे सामूहिक फ़ार्मों और मशीन और ट्रैक्टर स्टेशनों में पार्टी सेलों में मिल गये।

१९३३ और १९३५ में हुई अग्रणी सामूहिक किसानों की अखिल संघीय कांग्रेसों ने सामूहिक फ़ार्मों के संगठनात्मक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण में बड़ा योगदान किया। अग्रणी सामूहिक किसानों की दूसरी कांग्रेस ने कृषि आर्तेल की आदर्श नियमावली स्वीकार की, जिसने सामूहिक फ़ार्म निर्माण के अनुभव को वैधानिक रूप से मज़बूत बनाया।

जैसे-जैसे सामूहिक फ़ार्म सुदृढ़ होते गये, वैसे-वैसे पृथक खेती करनेवाले किसानों के निजी खेतों का सामूहिकीकरण होता गया। दूसरी पंचवार्षिकी के अंत तक यह काम लगभग पूरा हो गया था और सामूहिक फ़ार्मों में किसानों के ९३ प्रतिशत खेत एकजुट हो गये थे तथा उनके तहत देश के बुआई क्षेत्र का ९९.१ प्रतिशत आ गया था। कुल मिलाकर २,४३,७०० सामूहिक फ़ार्म और ३,९९२ राजकीय फ़ार्म बने थे। संपूर्ण सामूहिकीकरण और राजकीय फ़ार्मों के व्यापक विकास के फलस्वरूप देहात में लघु माल और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की

जगह समाजवादी आर्थिक प्रणाली क़ायम हो गयी।

सामूहिक फ़ार्मों का निर्माण इस बात का प्रमाण था कि समाजवाद ने जन अर्थव्यवस्था की सबसे पिछड़ी शाखा में विजय प्राप्त कर ली थी। यह आर्थिक संबंधों, किसानों की जीवन पद्धति में बड़ी क्रांति का द्योतक था।

राजनीतिक दृष्टि से सामूहिक फ़ार्म प्रणाली ने सोवियत राज्य और इसके मुख्य आधार – मज़दूरों और किसानों के सहबंध को मज़बूत बनाया।

आर्थिक दृष्टि से सामूहिक फ़ार्म प्रणाली ने बड़े कृषि उत्पादन के लाभों को समाजवाद की सेवा में उपलब्ध कराया और कृषि को आधुनिक औद्योगिक आधार पर विकसित करने की संभावना दी।

सामाजिक दृष्टि से सामूहिक फ़ार्म प्रणाली ने मेहनतकश किसानों को शोषण और ग़रीबी से मुक्त ही नहीं कराया, वरन देहात में सामाजिक संबंधों की एक नयी प्रणाली क़ायम करने में भी सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप सोवियत समाज में वर्ग विभेदों पर पूर्णतः क़ाबू पा लिया गया।

* * *

सोवियत संघ में कृषि के समाजवादी रूपांतरण ने आबादी के सबसे बड़े और सबसे पिछड़े हिस्से – किसानों – को समाजवाद के निर्माण में खींचने की संभावना के बारे में वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत की सत्यता सिद्ध कर दी।

बाद में समाजवादी विकास का मार्ग अपनानेवाले जनगण ने लेनिनीय सहकारी योजना के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को पुष्ट कर दिया। उन्होंने सोवियत संघ में सामूहिकीकरण के अनुभव का अपने देशों में कृषि के समाजवादी रूपांतरण में उपयोग किया। स्वभावतः ही, देश-विशेष में विभिन्न परिस्थितियों, परंपराओं, भौतिक और सांस्कृतिक स्तरों ने सहकारिता के रूपों और विधियों को प्रभावित किया। साथ ही, सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों में कृषि के समाजवादी रूपांतरण के अनुभव ने दिखा दिया कि किसानी फ़ार्मों के उत्पादन सहकारीकरण का आधार सामान्य नियमों और सिद्धांतों में निहित है।

ये नियम हैं:

–लघु माल कृषक अर्थव्यवस्था से बड़े सहकारी उत्पादन में **क्रमिक संक्रमण** ;

–सामूहिक खेती के **बहुविध रूप**, निम्नतम से उच्चतम रूपों में **क्रमिक संक्रमण** ;

–सहकारिताओं के निर्माण में भी और सामूहिक खेती के रूपों के चुनाव में भी भौतिक दिलचस्पी पर आधारित **स्वैच्छिकता** ;

–बड़े उत्पादन सहकारीकरण के आधार पर एक **वर्ग के रूप में कुलकों का उन्मूलन** (देहात में वर्ग संघर्ष की विशिष्ट परिस्थितियों और समाजवादी राष्ट्रमंडल की उपस्थिति ने कुछ समाजवादी देशों को कुलकों के प्रति उन क़दमों से कुछ भिन्न क़दम उठाने की संभावना दी, जो सोवियत संघ में लागू किये गये थे; बलप्रयोग से कुलकों का संपत्तिहरण सभी ही परिस्थितियों में अनिवार्य नहीं है)।

नवम्बर १९६९ में सामूहिक किसानों की तीसरी अखिल संघीय कांग्रेस में कहा गया कि सहकारिता पर लेनिन के महान विचार, किसानों के सवाल को सुलझाने में पार्टी की नीति समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों का अनुभव अत्यंत स्पष्टता से दिखाता है कि देहात में समाजवाद का निर्माण–किसानों के लिए खुशहाली का एकमात्र रास्ता है, समूचे मेहनतकशों के कल्याण का आधार है।

अध्याय ५

युगों पुराने पिछड़ेपन से संस्कृति की ऊंचाइयों तक

१. विचारधारात्मक और सांस्कृतिक क्रांति – पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की नियमसंगत प्रक्रिया

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय – सांस्कृतिक क्रांति का समारंभ

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति ने, जिसने पूंजीवाद से समाजवाद और कम्युनिज़्म में मानवजाति के संक्रमण की आधारशिला रखी, समाज के आत्मिक जीवन के नवीकरण के युग – सांस्कृतिक क्रांति के युग – का सूत्रपात किया।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण की लेनिनीय योजना में सांस्कृतिक क्रांति को बड़ा स्थान प्राप्त था। इसका कारण यह था कि समाजवाद न केवल एक नयी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली की, बल्कि गुणात्मक रूप से एक नयी उच्च क़िस्म की संस्कृति, वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा कलात्मक विकास के उच्च स्तर की भी पूर्वकल्पता करता है।

लेनिन ने कहा कि मेहनतकश जनसाधारण के सांस्कृतिक स्तर में सुधार के बिना, अर्थव्यवस्था के लिए उच्च योग्यताप्राप्त विशेषज्ञों और नये जन बुद्धिजीवियों के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि केवल शिक्षित लोग ही जटिल टेक्नोलाजी में पारंगत हो तथा उसका अत्यंत कारगर उपयोग कर सकते हैं, उत्पादन के अत्याधुनिक औज़ारों और साधनों पर आधारित केवल उच्च उत्पादक श्रम ही समाजवादी आर्थिक प्रणाली के सभी लाभों को प्रकट कर सकता और पूंजीवादी प्रणाली पर उसकी श्रेष्ठता दिखा सकता है।

सांस्कृतिक क्रांति क्या है?

सांस्कृतिक क्रांति समाज के चहुंमुखी आत्मिक नवीकरण की क्रांतिकारी प्रक्रिया है जिसमें निम्न बातें शामिल हैं: श्रमिकों के बीच पहले

पूरी साक्षरता और फिर वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार ; मानवजाति द्वारा संचित सांस्कृतिक विरासत का आलोचनात्मक आत्मसात्करण ; रूप में जातीय, अंतर्वस्तु में समाजवादी और अपने स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीयतावादी अधिक विकसित संस्कृति का सृजन ; समाजवाद के ध्येय के प्रति समर्पित नये बुद्धिजीवियों का अभ्युदय ; लोगों के आत्मिक स्वरूप में परिवर्तन ; जन चेतना में समाजवादी विचारधारा का उन्नयन।

सांस्कृतिक क्रांति संपूर्ण जनगण के सांस्कृतिक विकास में, विज्ञान, साहित्य और कलाओं के विकास में संपूर्ण दौर की परिचायक है। यह श्रमिकों की चेतना, विचारधारा और आत्मिक जीवन में गहनतम परिवर्तन और समाजवादी भावना में उनकी पुनर्शिक्षा की द्योतक है। अगर मज़दूर वर्ग के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण सांस्कृतिक क्रांति की एक निर्णायक पूर्वापेक्षा है, तो अपनी बारी में, जनगण के सांस्कृतिक स्तर में सुधार समाज का समाजवादी रूपांतरण करने, पूंजीवाद से उच्चतर श्रम उत्पादकता प्राप्त करने, राजकीय प्रशासन में व्यापक जनगण को खींचने की आवश्यक शर्त है।

सांस्कृतिक क्रांति स्वत:स्फूर्त नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य द्वारा निदेशित एक रचनात्मक, संगठनात्मक प्रक्रिया है। वे कार्यभारों की योजना बनाते, सांस्कृतिक क्षेत्रों में रूपांतरण की अंतर्वस्तु निर्धारित करते और उनके कार्यान्वयन के लिए जन-प्रयास संगठित करते हैं।

समाजवादी संस्कृति किसी रिक्त स्थान से नहीं पैदा होती, बल्कि वह सभी प्रगतिशील, आत्मिक, बौद्धिक सम्पदाओं, मानवजाति द्वारा निर्मित और संचित ज्ञान की समस्त निधियों का नियमसंगत विकास है। लेनिन ने तथाकथित 'सर्वहारा संस्कृतिपंथ'* के पक्षधरों के ग़लत

* 'सर्वहारा संस्कृतिपंथ' की स्थापना १९१७ में पेत्रोग्राद में हुई थी। सर्वहारा क्रांति के बाद उसमें मुख्यत: मज़दूर वर्ग के बीच से आये लेखकों का एक बड़ा ग्रुप शामिल हो गया था। उन दिनों वह क्रांतिकारी कार्यभारों से जुड़ा सबसे बड़ा रचनात्मक संगठन था। फिर भी 'सर्वहारा संस्कृतिपंथ' क्रांतिकारी साहित्य का सच्चा प्रवक्ता और संगठनकर्ता नहीं बन सका। इसका एक मुख्य कारण उसका ग़लत सैद्धांतिक विचार था – सर्वहारा संस्कृति को सभी अन्य संस्कृतियों के मुक़ाबले में रखा गया था। —सं०

विचारों की आलोचना की, जिन्होंने विगत की प्रगतिशील सांस्कृतिक उपलब्धियों से पूर्णतः पृथक् "नयी", "शुद्धतः सर्वहारा" संस्कृति के निर्माण की हिमायत की।

विगत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति लेनिनीय रुख ऐतिहासिक प्रक्रिया की मार्क्सवादी अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी संस्कृति और विगत युगों की संस्कृति में निरंतरता सहित सांस्कृतिक विकास में निरंतरता की अस्वीकृति सभ्यता के क्रमिक विकास में विराम की ओर ले जाती है। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की आठवीं कांग्रेस (१९१९) में स्वीकृत कार्यक्रम में लिखा गया है कि मेहनतकशों के श्रम के शोषण के आधार पर निर्मित और अब तक शोषकों को अनन्य रूप से उपलब्ध संपूर्ण कला निधियों के द्वार श्रमजीवी लोगों के लिए खोल दिये जाने चाहिए।

इसके साथ ही लेनिन ने सर्वहारा द्वारा विगत की संस्कृति के आत्मसात्करण की समस्या को वर्गगत विचारधारात्मक स्थिति से देखा। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक विरोधी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली में दो संस्कृतियां – शोषकों की मूलतः जन-विरोधी संस्कृति तथा जनसाधारण की इच्छाओं और आशाओं को व्यक्त करनेवाली जनवादी संस्कृति – होती हैं। विजयी सर्वहारा उस सब कुछ का उपयोग करता है, जो प्रगतिशील और जनवादी है और उस सब कुछ को अस्वीकार कर देता है, जो प्रतिक्रियावादी और वर्गीय रूप से उसके लिए पराया है। लेनिन ने समाजवादी समाज द्वारा विगत की संचित सांस्कृतिक निधियों के आलोचनात्मक आत्मसात्करण का समर्थन किया ताकि वे नयी समाजवादी संस्कृति का अभिन्न अंग बन सकें।

समाजवादी संस्कृति और बुर्जुआ संस्कृति में मौलिक अंतर क्या है? सर्वप्रथम यह कि समाजवादी संस्कृति सच्चे अर्थ में जन स्वरूप की होती है, जबकि बुर्जुआ संस्कृति अपने सार और प्रवृत्ति में जन-विरोधी होती है। अतः सांस्कृतिक क्रांति का मुख्य कार्यभार संस्कृति को सच्चे माने में जन संस्कृति बनाना है। इसके लिए शोषणकारी समाज में जनगण और संस्कृति के बीच खाई को पाटना, संपूर्ण आत्मिक संपदा को जनसाधारण की निर्विवाद संपत्ति बनाना, जनगण के बीच प्रचुर रूप से विद्यमान प्रतिभाओं के सच्चे विकास के लिए व्यापक संभावना प्रदान करना आवश्यक है।

समाजवादी संस्कृति कम्युनिस्ट आदर्शों और वैज्ञानिक विश्व-दृष्टिकोण पर आधारित है। सांस्कृतिक क्रांति मेहनतकश जनसाधारण को प्रतिक्रियावादी विचारों, विज्ञान-विरोधी विश्वदृष्टिकोण से मुक्त कराती है। लोगों की चेतना में पूंजीवाद के अवशेषों का उन्मूलन सांस्कृतिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

अपनी अंतर्वस्तु और सामाजिक कार्यों की दृष्टि से समाजवादी संस्कृति मानवीय और गहनतः नैतिक होती है। वह पूंजीवादी समाज में वर्ग-विरोधी संबंधों द्वारा जनित लोगों के बीच सांस्कृतिक असमानता– नारियों की असमानता, नगर से देहात के पिछड़ेपन, बौद्धिक और शारीरिक श्रम के बीच विरोध–पर क़ाबू पाने में समर्थ बनाती है।

समाजवादी संस्कृति व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास, व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं के प्रयोग और सभी नागरिकों के मन में श्रम के प्रति नये समाजवादी दृष्टिकोण के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है। सब कुछ श्रमजीवी व्यक्ति के लिए– यह समाजवादी संस्कृति का मर्म है।

सांस्कृतिक क्रांति के कार्यभार हैं जातियों की सांस्कृतिक असमानता का उन्मूलन, पहले की पिछड़ी जातियों का तेज़ गति से सांस्कृतिक विकास, रूप में जातीय और अंतर्वस्तु में समाजवादी संस्कृति का निर्माण। समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद की विचारधारा व्यक्ति की सांस्कृतिक और आत्मिक दुनिया को समृद्ध और विस्तृत बनाती है। संस्कृति का समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयकरण, यानी विविध राष्ट्रीय रूपों, उनके परस्पर समृद्धिकरण और अन्योन्य प्रभाव के आधार पर राष्ट्रीय संस्कृतियों की बढ़ती सन्निकटता सांस्कृतिक क्रांति की विधिसंगत प्रक्रिया है।

सांस्कृतिक क्रांति के सिद्धांत को तैयार करते हुए लेनिन ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि सांस्कृतिक निर्माण के कार्यभार सफलतापूर्वक पूरे कर लिये जायेंगे, क्योंकि जनसाधारण सच्ची संस्कृति के निर्माण में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के दौरान ज्ञान के प्रति, संस्कृति के स्वांगीकरण के प्रति उनकी इच्छा अभूतपूर्व थी। लेनिन ने हर्षपूर्वक लिखा: "नीचे, अर्थात उन मेहनतकश जनसाधारण के बीच प्रकाश और ज्ञान के लिए शक्तिशाली इच्छा

जाग्रत हो गयी है, जिन्हें पूंजीवाद... शिक्षा से अलग रख रहा था। हम उचित ही गर्व कर सकते हैं कि हम इस इच्छा को बढ़ा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं।"*

जनता की सांस्कृतिक-राजनीतिक शिक्षा

जनता की सांस्कृतिक-राजनीतिक शिक्षा, मेहनतकशों के बीच सांस्कृतिक-शैक्षिक और वैचारिक-राजनीतिक कार्य ने सांस्कृतिक क्रांति में बड़ी भूमिका अदा की।

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के १६१६ के कार्यक्रम में "स्वशिक्षा और स्वविकास में मज़दूरों और किसानों के लिए व्यापक राजकीय सहायता (बहिस्कूली शिक्षा संस्थाओं–पुस्तकालयों, वयस्क स्कूलों, सांस्कृतिक प्रासादों और विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण कोर्सों, व्याख्यानों, सिनेमाघरों, स्टुडियों, आदि–के जाल का निर्माण)"** की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम में देश की संपूर्ण आबादी के लिए बहिस्कूली शिक्षा की मुख्य कड़ियां निर्धारित की गयी थीं। कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं कांग्रेस को संबोधित करते हुए लेनिन ने कहा: "इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने की लोगों में बेहद प्यास है और शिक्षा के क्षेत्र में बेहद प्रगति हुई है–अधिकांशतः स्कूलों के अलावा दूसरे तरीक़ों से–मेहनतकश जनसाधारण को शिक्षा देने के मामले में काफ़ी प्रगति हुई है। इस प्रगति को किसी स्कूली ढांचे में सीमित करके नहीं रखा जा सकता, लेकिन वह विशाल है।"***

अपेक्षाकृत अल्प समय में ही देश में जन शिक्षा की पूरी प्रणाली क़ायम कर ली गयी। इसमें पुस्तकालय, किसान वाचनालय, मज़दूर क्लब, सांस्कृतिक प्रासाद, संग्रहालय, थियेटर, सिनेमा, रेडियो, अख़बार, साहित्य और कला जैसे जनगण के सांस्कृतिक विकास के

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'जन शिक्षा कमिसारियत का कार्य', १६२१।

** 'सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय...'

*** व्ला० इ० लेनिन, संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ८, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १६८५, पृ० २६१।

साधन शामिल थे। सोवियत राज्य ने न केवल भौतिक और आत्मिक संस्कृति की संपूर्ण निधियां मेहनतकशों को उपलब्ध करायीं, बल्कि अपने सांस्कृतिक-शैक्षिक कार्यों को पूरा करते हुए उसने सभी साधनों से संस्कृति के इन वरदानों का लाभ उठाने में उनकी सहायता भी की।

सोवियत सत्ता के आरंभिक वर्षों में राजनीतिक और शैक्षिक कार्य का मुख्य उद्देश्य जनता को विजयी क्रांति के महत्व तथा शांति और भूमि संबंधी पहली आज्ञप्तियों, रूस की जातियों के अधिकारों की घोषणा, मेहनतकश और शोषित जनता के अधिकारों की घोषणा की अंतर्वस्तु को समझाना था। कम्युनिस्ट पार्टी ने हज़ारों कम्युनिस्टों को प्रचारकों के रूप में काम करने के लिए नगरों और गांवों में भेजा। इस काल में सभाएं जनगण की राजनीतिक शिक्षा का अत्यंत व्यापक रूप थीं। सही और सुचारु ढंग से व्यवस्थित प्रचार देश के दूर-दराज़ के क्षेत्रों में पहुंचा, जो मेहनतकशों की राजनीतिक शिक्षा में सहायता करता तथा सोवियत सत्ता में उनके विश्वास को मज़बूत बनाता था।

पुस्तकालय, किसान वाचनालय, सांस्कृतिक प्रासाद किसानों के बीच सांस्कृतिक-शैक्षिक कार्य के केंद्र थे। सांस्कृतिक प्रासादों के कर्मियों – प्रचारकों – ने समाजवादी देशभक्ति और अंतर्राष्ट्रीयतावाद, क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा हेतु संघर्ष में दृढ़ता और आत्मत्याग की भावना विकसित करने में सहायता की। सांस्कृतिक प्रासादों में स्वशिक्षा ग्रुप और शौक़िया नाट्य मंडलियां क़ायम की गयीं। सोवियत समाज में शौक़िया कला कार्यकलापों ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। सामूहिक और राजकीय फ़ार्मों के सांस्कृतिक प्रासादों में हज़ारों नाट्य, नृत्य, गान, आदि मंडलियां काम कर रही थीं। चौथे दशक के मध्य में उनकी सदस्य-संख्या ३० लाख से अधिक हो गयी थी।

१९३७ में मास्को में शौक़िया कलाकारों का पहला अखिल संघीय प्रदर्शन हुआ। व्यापक जन कला का प्रदर्शन समाजवादी समाज में व्यक्ति की आत्मिक प्रतिभाओं के सर्वतोमुखी विकास का ज्वलंत प्रमाण था। इसके साथ उसने नयी समाजवादी संस्कृति के सृजन में जनगण की सक्रिय भूमिका भी दिखा दी। इस सबने मज़दूरों और किसानों के बीच सहबंध को और मज़बूत बनाया। मज़दूर वर्ग की सहायता ने किसानों की राजनीतिक शिक्षा में विशाल भूमिका अदा की। कारख़ानों और फ़ैक्टरियों के मज़दूरों ने अध्ययन मंडलियां संगठित कीं, ग्रामीण पुस्त-

कालयों, वाचनालयों और स्कूलों के लिए पुस्तकें भेजीं, वार्ताएं और व्याख्यान दिये। इस तरह, जनता के मन में श्रम और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति समाजवादी रुख, वैयक्तिक हितों पर सामाजिक हितों की वरीयता की समझ और सोवियत देशभक्ति और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विचार विकसित किये गये।

जनगण की राजनीतिक शिक्षा के कार्य में प्रेस ने बहुत बड़ी और दायित्वपूर्ण भूमिका अदा की। कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य ने सोवियत सत्ता की स्थापना के पहले दिनों से ही मज़दूरों और किसानों के लिए प्रेस के विकास के बारे में चिंता प्रदर्शित की और प्रतिक्रांतिकारी बुर्जुआ अखबारों के कार्यकलाप को दृढ़तापूर्वक बंद कर दिया।

सोवियत और पार्टी प्रेस सोवियत राज्य की नीति का वाहक, जनगण को वैचारिक और राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में सहायक है। उसने समाजवादी निर्माण में सफलताओं और त्रुटियों को दिखाया, समाजवादी प्रतियोगिता के परिणामों पर प्रकाश डाला, मार्क्सवाद-लेनिनवाद का व्यापक प्रचार किया। व्यापक जनसाधारण के बीच मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विचारों के प्रचार को मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट तथा मज़दूर आंदोलन के अन्य असाधारण कार्यकर्ताओं की कृतियों के बड़ी संख्या में प्रकाशन से योग मिलता था। प्रसिद्ध पार्टी पत्रकारों ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत, साहित्य और कला के विभिन्न प्रश्नों पर लेख लिखे। उन्होंने बड़े ही कुशल और स्पष्ट ढंग से वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों का विवेचन और बुर्जुआ विचारधारा का पर्दाफ़ाश किया। लेनिन ने बारंबार ज़ोर दिया कि सर्वहारा कम्युनिस्ट प्रेस को संपूर्ण जनता की राय प्रकट करनी चाहिए। यही वजह है कि पाठकों के साथ रोज़मर्रा का संपर्क प्रेस के सफल कार्य, जनसाधारण में उसकी व्यापक लोकप्रियता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। सोवियत संघ में प्रेस और जनता के बीच निकट संपर्क मज़दूर और ग्रामीण संवाददाताओं के शक्तिशाली आंदोलन में प्रकट हुआ। हरेक दिन सोवियत अखबारों में पेशेवर पत्रकारों के अलावा मज़दूरों, सामूहिक किसानों, वैज्ञानिकों, संस्कृतिकर्मियों के भी लेख छपते थे।

रेडियो जनसाधारण को शिक्षित करने का एक अन्य कारगर साधन था। सोवियत संघ में रेडियो-प्रसारण १९२२ में शुरू हुए, जब उन दिनों का दुनिया का अत्यधिक शक्तिशाली मास्को रेडियो प्रसारण

स्टेशन चालू किया गया। तब से रेडियो शहरी और देहाती जीवन में सतत पदार्पण करने लगा और जनसाधारण को संस्कृति तथा राजनीति से जोड़ने का एक बड़ा साधन बन गया।

व्यक्ति की वैचारिक शिक्षा के सभी साधनों के सुसंगत विकास के फलस्वरूप समाजवाद के निर्माण के दौरान नये सोवियत मानव का निर्माण हुआ। उसकी मुख्य विशेषताएं हैं: उच्च आदर्श और समाजवादी मातृभूमि के प्रति निस्स्वार्थ प्रेम; श्रम से लगाव और सभी कठिनाइयों पर क़ाबू पाने की क्षमता, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रति निष्ठा; सच्ची मानवतावादी नैतिकता और समृद्ध आत्मिक संस्कृति।

सोवियत जनता और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारात्मक और राजनीतिक एकता, कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द-गिर्द उसकी अखंड एकजुटता समाजवादी समाज में व्यक्ति के उच्च नैतिक मानकों की सामान्य अभिव्यक्ति है।

२. जनगण की साक्षरता और शिक्षा

मेहनतकशों की सार्विक शिक्षा के कार्यान्वयन में सोवियत राज्य की भूमिका

आबादी की व्यापक निरक्षरता ज़ारशाही की एक सबसे कठिन विरासत थी। रूस में ७५ प्रतिशत आबादी पढ़-लिख नहीं सकती थी और यह एक ऐसे देश में, जिसने अपने इतिहास में मानवजाति को बहुत से महान वैज्ञानिक और साहित्यकार तथा कलाकार दिये, जहां अक्तूबर क्रांति के २०० साल पहले विज्ञान अकादमी क़ायम की जा चुकी थी और जहां मास्को विश्वविद्यालय था जो उचित ही विश्व में विज्ञान और संस्कृति के प्रमुख केंद्र होने का दावा कर सकते थे। देहात में निरक्षरता का प्रतिशत और भी ऊंचा था। १८९७ की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी की निरक्षरता मर्दों में ८०.४ प्रतिशत और स्त्रियों में ९३ प्रतिशत थी।

रूसी साम्राज्य के दूर-दराज़ के जातीय प्रदेशों में तस्वीर और भी दु:खद थी। मसलन, किर्गीज़ों में साक्षरता ०.६ प्रतिशत, ताजिकों में

०.५ प्रतिशत, तुर्कमानों और याकूतों में ०.७ प्रतिशत तथा उज़्बेकों में १.६ प्रतिशत थी। ४८ जातियों के पास कोई लिपि नहीं थी। सुदूर उत्तर, पूर्व, उत्तरी काकेशिया में रहनेवाली बहुत सी जातियों और नृजातीय समूहों को शिक्षा प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं थी और वे लगभग निरक्षर थे। लेनिन के शब्दों में, "निरक्षर आदमी राजनीति के बाहर खड़ा होता है, उसे सबसे पहले क ख ग सिखना चाहिए"।*

२६ दिसम्बर, १६१६ को रूसी संघीय जनतंत्र की जन कमिसार परिषद ने 'रूसी संघीय जनतंत्र की आबादी में निरक्षरता के उन्मूलन के बारे में' आज्ञप्ति स्वीकार की, जिसने निरक्षरता उन्मूलन आंदोलन का सूत्रपात किया। आज्ञप्ति में कहा गया था: "जन कमिसार परिषद ने निर्णय किया है: १) जनतंत्र के ८ से ५० साल की उम्र के सभी लोगों को, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते, अपनी इच्छानुसार रूसी में या अपनी मातृभाषा में पढ़ना-लिखना सीखना चाहिए।" आज्ञप्ति में बच्चों के लिए सामान्य स्कूलों के साथ-साथ अनपढ़ वयस्कों के लिए विशेष स्कूल खोलने की व्यवस्था थी। इस आज्ञप्ति ने सारे देश को आंदोलित कर दिया। मज़दूर और किसान, मर्द और औरतें, जवान और बूढ़े काम के बाद अपनी मेज़ों पर आ बैठे और पहली सोवियत वर्णमाला के पृष्ठों पर अंगुलियां फेरते हुए हिज्जे के साथ पढ़ा: "हम गुलाम नहीं हैं। गुलाम नहीं हैं हम"।

अमरीकी लेखक अल्बर्ट रीस विलियम्स ने, जो रूस में अक्तूबर क्रांति की घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे, लिखा कि सोवियत सत्ता के पहले महीनों में "सर्वत्र स्कूल खोले गये – महलों में, बारिकों में, कारखानों और फ़ैक्टरियों में... इन स्कूलों में लाखों बच्चे, चालीस या साठ साल के लोग तक पढ़ने गये। सारा देश पढ़ना-लिखना सीख रहा था।"**

पूरे देश में निरक्षरता उन्मूलन केंद्र क़ायम किये गये, जिनमें तीन महीने के कोर्स चलाये जाते थे। आगे चलकर दस महीने के कोर्स संगठित किये गये। इसके अलावा, अर्धसाक्षरों के लिए स्कूल खोले गये,

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'नयी आर्थिक नीति और राजनीतिक शिक्षा विभागों के कार्यभार', १६२१।

** अल्बर्ट रीस विलियम्स, 'लेनिन और अक्तूबर क्रांति के बारे में', प्रगति प्रकाशन, मास्को, १६७३, पृ० १८६।

जो चारवर्षीय प्रारंभिक स्कूली शिक्षा देते थे। जब गृहयुद्ध ज़ोरों पर चल रहा था, क्रांतिकारी सैनिक परिषद ने "प्रत्येक कंपनी, बैटरी, स्क्वाड्रन और दस्ते में" लाल सेना के अनपढ़ सैनिकों के लिए कोर्स संगठित किये। इन कोर्सों में पढ़ना उतना ही ज़रूरी था जितना कि सैनिक कवायदें करना।

विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध से जनित कठिनाइयों के बावजूद, स्कूलों में आवश्यक शिक्षा-साधनों के बड़े अभाव के बावजूद (स्कूलों में अक्सर काग़ज़ की जगह चूना लेपित पट्टों, पेंसिल की जगह कोयले, इस्पात की क़लम की जगह पर की क़लम और स्याही की जगह चुकंदर के रस का उपयोग किया गया) निरक्षरता उन्मूलन आंदोलन उन दिनों भी व्यापक रूप से फैल गया था। इसका कारण, सर्वप्रथम, मज़दूरों और किसानों की ज्ञान की अबूझ प्यास, जन-शिक्षा के प्रति राज्य की चिंता और इस अति महत्वपूर्ण कार्यभार को पूरा करने के लिए उसके द्वारा उठाये गये क़दम था।

निरक्षरता उन्मूलन के देशव्यापी जन आंदोलन के सकारात्मक नतीजे गृहयुद्ध के अंत तक प्राप्त भी हो चुके थे। लड़ाई के तीन वर्षों में लाखों लोग पढ़ना-लिखना सीख गये थे। आगे चलकर निरक्षरता उन्मूलन आंदोलन और भी तेज़ हो गया। निरक्षरता उन्मूलन के लिए संघर्ष व्यापक सामाजिक आंदोलन में बदल गया, जिसने ज्ञान और समाजवादी विचारों के प्रति जनगण के आकर्षण के ऐसे नये रूप पेश किये, जो नये जीवन के निर्माण में सक्रिय सहभागिता के लिए आवश्यक होते हैं। १९२३ में स्थापित स्वैच्छिक समाज 'निरक्षरता मुर्दाबाद!' ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके १,६०० सदस्यों में लेनिन, मिख़ाईल कलीनिन, मक्सिम गोर्की, अनातोली लुनाचार्स्की, व्लादीमिर मयाकोव्स्की और अन्य प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक कर्मी शामिल थे।

इस राजकीय कार्यभार को पूरा करने में कम्युनिस्टों ने अग्रणी भूमिका अदा की। कोम्सोमोल सदस्यों, ट्रेड-यूनियनों, लाल सेना के राजकीय विभाग और दूसरे संगठनों ने निरक्षरता उन्मूलन आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। १९२८ की पतझड़ में कोम्सोमोल ने सार्विक साक्षरता अभियान शुरू किया। इस अभियान में दस लाख से अधिक लोगों ने बिना पारिश्रमिक के काम किया और निरक्षरता उन्मूलन मंडलों

में वयस्कों को पढ़ना-लिखना सिखाया। १६२३ और १६३६ के बीच पांच करोड़ से अधिक निरक्षरों और लगभग चार करोड़ अर्ध-निरक्षरों को प्रारंभिक शिक्षा दी गयी। यह देश में निरक्षरता के उन्मूलन पर लेनिन के आदेशों को अमली जामा पहनाने हेतु सोवियत राज्य की नीति की विजय का प्रमाण था।

सोवियत स्कूलों का निर्माण

क्रांतिपूर्व रूस में स्कूल बहुत कम थे और स्कूली शिक्षा बच्चों तथा किशोरों की एक बड़ी संख्या की पहुंच से बाहर थी। लेनिन ने ज़ारशाही रूस में सार्वजनिक शिक्षा की प्रणाली का विश्लेषण किया और लिखा : "इस प्रकार स्कूली आयु के बच्चे २२ प्रतिशत हैं जबकि ४.७ प्रतिशत, अर्थात **एक पांचवां भाग ही** स्कूल जा रहा है! इसका अर्थ यह है कि बच्चों और किशोरों का लगभग **चार-पांचवां भाग** सार्वजनिक शिक्षा से **वंचित है**!!"* स्कूल मज़दूरों और किसानों के बच्चों की पहुंच के बाहर थे। ग़ैर-रूसी जातीय क्षेत्रों में स्थिति इससे भी बदतर थी। उदाहरण के लिए, संपूर्ण मध्य एशिया में प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल मध्य रूस के मुक़ाबले में दसगुना कम थे, उच्च शिक्षा संस्थानों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। ज़ारशाही मेहनतकश लोगों, ख़ास तौर से "विजातीय लोगों" को, जैसा कि जातीय इलाक़ों के निवासियों को कहा जाता था, शिक्षित करना ख़तरनाक मानती थी। इस वजह से अक्तूबर क्रांति के पहले उन जातीय इलाक़ों में क़ायम दो-चार स्कूलों में सामान्यत: रूसी में ही शिक्षा दी जाती थी।

अक्तूबर क्रांति की विजय के बाद तुरंत सोवियत राज्य ने स्कूली प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य स्कूल को जनगण को आत्मिक रूप से ग़ुलाम बनाने के एक साधन से प्रतिक्रियावादी विचारधारा से उन्हें मुक्त कराने के एक साधन के रूप में बदलना था, ताकि स्कूल को जन शिक्षा का एक सच्चा केंद्र बनाया जा सके।

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'जनशिक्षा मंत्रालय की नीति के बारे में'. १६१३।

१६ अक्तूबर, १६१८ को घोषित अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित 'रूसी संघीय जनतंत्र के एकीकृत श्रम स्कूल के बारे में नियमन' और 'एकीकृत श्रम स्कूल के बारे में घोषणा' में स्कूली सुधारों और शिक्षा के जनवादीकरण की मुख्य दिशाएं निर्धारित की गयीं। इन दस्तावेज़ों ने एकीकृत श्रम स्कूली प्रणाली लागू की: पहला वर्ग (पंचवर्षीय) ८ से १२ साल तक के बच्चों के लिए, दूसरा वर्ग (चारवर्षीय) १३ साल से १७ साल तक के बच्चों के लिए। शिक्षा निःशुल्क हो गयी, लड़के-लड़कियां साथ-साथ पढ़ने लगे। सभी छोटी-बड़ी जातियों ने अपनी मातृभाषाओं में स्कूली शिक्षा संगठित करने का समान अधिकार पाया।

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की आठवीं कांग्रेस में स्वीकृत कार्य-क्रम में जन शिक्षा के विकास के मूल सिद्धांत निर्धारित किये गये। कार्यक्रम में ज़ोर दिया गया था कि स्कूली शिक्षा मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत पर आधारित तथा पार्टी की नीति और समाजवादी निर्माण के कार्यभारों से जुड़ी होनी चाहिए। सोवियत सत्ता की पहली आज्ञप्तियों में एक आज्ञप्ति 'चर्च के राज्य से और स्कूल के चर्च से पृथक्करण के बारे में' थी। इसने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सुसंगत कार्यान्वयन की आधारशिला रखी (सोवियत संघ में धार्मिक अनुष्ठान करानेवालों के प्रशिक्षण के लिए आत्मिक शिक्षा राजकीय शिक्षा प्रणाली में नहीं आती, उसका संचालन धार्मिक संगठनों द्वारा ही किया जाता है)।

संस्कृति को रूस की ग़ैर-रूसी जातियों की पहुंच में लाना विशेष महत्व रखता था। यहां जातीय अध्यापकों के लगभग पूर्ण अभाव, पितृसत्तात्मक-सामंती अवशेषों के दुराग्रह ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया। साक्षरता अभियान ने पूर्व की नारियों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

कई जातीय जनतंत्रों में लड़के-लड़कियों की सहशिक्षा शुरू करने में तुरंत सफलता नहीं मिली। नयी स्कूली प्रणाली क़ायम करने में कुछ समझौते भी करने पड़े। मिसाल के लिए, चर्च को राज्य से और स्कूल को चर्च से पृथक करने संबंधी क़ानून कुछ मध्य एशियाई जनतंत्रों में सर्वत्र ही नहीं लागू किया गया। उदाहरणार्थ, तुर्कमानिस्तान में पुरानी स्कूली प्रणाली, जिसमें शिक्षा धार्मिक आधार पर दी जाती थी, १६२८ में जाकर ही समाप्त हो पायी। कुछ क्षेत्रों में स्कूली उम्र की लड़कियों

को नये स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनके परिवारों को भूमि पाने में विशेषाधिकार तथा कृषि-मशीनें ख़रीदने के लिए ऋण दिये गये। सोवियत क़ानून ने उन लोगों को कड़ी सज़ा दी, जो औरतों को पढ़ने जाने और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने से रोकते थे।

सोवियत और सार्वजनिक संगठनों ने पुरानी परंपराओं में जमायी जड़ता और नारियों की चहारदीवारी पर क़ाबू पाने के लिए जातीय जनतंत्रों की आबादी के बीच धैर्यपूर्वक समझाने-बुझाने का तथा शैक्षिक कार्य चलाया। उन्हें वर्ग शत्रु तत्वों के प्रचंड प्रतिरोध से संघर्ष करना पड़ा, जिन्होंने शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आबादी के पिछड़े हिस्से पर अपने प्रभाव पर नया प्रहार देखा। निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा की असीमित स्वतंत्रता, सोवियत स्कूल की वैज्ञानिक और सर्वहारा वर्गीय प्रवृत्ति ने शीघ्र ही उसे सभी जनतंत्रों में समरूप बना दिया।

नये जन स्कूल का निर्माण करते हुए सोवियत राज्य ने रूसी और विश्व शिक्षाशास्त्र की सर्वोत्तम परंपराओं और उपलब्धियों को आलोचनात्मक ढंग से आत्मसात और विकसित किया। लेनिन ने सोवियत समाज के समक्ष अध्यापक की स्थिति को बेहतर बनाने, उसकी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के बारे में प्रश्न पेश किये। उन्होंने कहा: "हमारे अध्यापक को उस स्तर पर उठाया जाना चाहिए, जिस पर वह कभी नहीं पहुंचा, न ही वह बुर्जुआ समाज में पहुंच सकता है।"* सोवियत सत्ता ने अध्यापकों के प्रति निरंतर हितचिंता प्रदर्शित की। अपनी बारी में अध्यापकों ने, जिनके समक्ष समाजवादी समाज के युवा निर्माताओं को शिक्षित करने का कार्यभार प्रस्तुत था, सोवियत एकीकृत श्रम स्कूल के निर्माण और विकास के लिए निस्स्वार्थ ढंग से परिश्रम किया। लेकिन उपलब्ध अध्यापक कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पेश किये गये कार्यभारों की पूर्ति को पूर्णतः सुनिश्चित नहीं कर सकते थे। लाखों अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, उनकी योग्यताओं में वृद्धि करना आवश्यक था। सोवियत जन शिक्षा संगठनों ने अध्यापकों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के लिए विभिन्न रूपों और विधियों का उपयोग किया: अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का जाल बढ़ाया और पुनर्गठित किया गया, विविध अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स और

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'डायरी के पन्ने', १९२३।

अध्यापकों के प्रशिक्षण वाले सामान्य शिक्षा स्कूल खोले गये। अध्यापकों के तीव्र प्रशिक्षण के लिए असाधारण क़दम – अध्यापक प्रशिक्षण इंस्टीट्यूटों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की कम अवधि, विषयो का त्वरित अध्ययन – उठाये जाने की आवश्यकता थी। अध्यापकों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण की अल्पकालीन प्रणाली ने स्कूलों में अध्यापकों की आवश्यक संख्या की भरती करना संभव बना दिया।

उद्योग और परिवहन में सुयोग्य कर्मियों के अभाव को ध्यान में रखते हुए जन शिक्षा निकायों ने कारखाना और फ़ैक्टरी स्कूलों के जाल को व्यापक बनाने पर बड़ा ध्यान दिया। ये स्कूल १९२०-२१ में प्रकट हुए, वे नये प्रकार के विद्यालय थे, जो जन अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने में सक्षम थे। इन स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ फ़ैक्टरियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। तीन-चार सालों में वे अपने चुने हुए व्यवसाय में पारंगत हो जाते थे और सुयोग्य कर्मी, टोली नायक, सहायक फ़ोरमैन या फ़ोरमैन बन जाते थे।

निरक्षरता का उन्मूलन सांस्कृतिक क्षेत्र में सोवियत जनगण की महती उपलब्धि थी। लेकिन यह आबादी की सार्विक शिक्षा के लिए काफ़ी नहीं था। अतः १९३० में सोवियत सरकार ने सार्विक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पर क़ानून स्वीकार किया, जिसके अनुसार ८ साल के बच्चों के लिए चारवर्षीय प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने जाना अनिवार्य हो गया।

सार्विक प्रारंभिक शिक्षा को लागू करना कोई आसान काम नहीं था। हज़ारों स्कूल बनाने और सुसज्जित करने थे, देहात में, ख़ास तौर से जातीय जनतंत्रों और कम आबादी वाले उत्तरी क्षेत्रों में, बोर्डिंग स्कूल बनाये जाने थे तथा विद्यार्थियों को कपड़े, जूतों और भोजन की व्यवस्था करनी थी।

फिर भी, दो-तीन साल की अवधि में ही सोवियत संघ में सार्विक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अमल में लायी जा चुकी थी। १९३२ के अंत तक प्रारंभिक स्कूलों में ८-११ साल के ९३ प्रतिशत बच्चे जा रहे थे। इसके अलावा, १९३३ के अंत तक बड़े नगरों में ७-वर्षीय सार्विक पोलीतकनीकी शिक्षा भी लागू कर दी गयी थी। इसके साथ-साथ पूर्ण माध्यमिक शिक्षा भी प्रगति कर रही थी।

इस तरह, सोवियत जनगण ऐतिहासिक रूप से अत्यल्प काल में ही व्यापक निरक्षरता के उन्मूलन से सार्विक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ७-वर्षीय अनिवार्य शिक्षा में संक्रमण तक पहुंच गये।

३. मेहनतकश जनगण के बुद्धिजीवी

मेहनतकश बुद्धिजीवियों का निर्माण

नये सोवियत बुद्धिजीवियों का निर्माण सांस्कृतिक क्रांति का एक और भी पेचीदा कार्य था।

अपनी स्थापना के पहले वर्षों में सोवियत सत्ता के पास मज़दूरों और किसानों के बीच से आनेवाले विशेषज्ञों की आवश्यक संख्या नहीं थी। लेकिन जीवन ने बहुत-सी तात्कालिक आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यभारों की पूर्ति की मांग की। समाजवादी निर्माण में बुर्जुआ विशेषज्ञों को खींचना और क्रांति के पहले के बुद्धिजीवियों को समाजवाद की भावना में पुनर्शिक्षित करने की आवश्यकता पैदा हुई।

रूस के प्रगतिशील बुद्धिजीवी गौरवशाली क्रांतिकारी-जनवादी परंपराओं में पले थे, वे देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से ओत-प्रोत थे। इस चीज़ ने अनेक बुर्जुआ विशेषज्ञों को सोवियत सत्ता के पक्ष में पीड़ारहित ढंग से आने में सहायता की। सुप्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक क्लिमेंत तिमिर्याज़ेव सोवियत सत्ता के पहले समर्थकों में से एक थे। कवि ब्लोक और मयाकोव्स्की ने क्रांति का उमंगपूर्वक स्वागत किया। कई असाधारण वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान, बहुधा सोवियत जनतंत्र की रक्षा से जुड़े अनुसंधान जारी रखे। उनमें इवान पाव्लोव, निकोलाई जुकोव्स्की, कोंस्तांतीन त्सिओल्कोव्स्की, अलेक्सांद्र फ़ेर्समान, अलेक्सेई बाख़, इवान गुब्किन, अलेक्सेई क्रिलोव, निकोलाई ज़ेलीन्स्की, अलेक्सांद्र कर्पीन्स्की, द्मित्री प्र्यानिश्निकोव और दनील ज़ाबोलोत्नी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि बहुत-से बुद्धिजीवी अपने वर्ग पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मज़दूरों की पांतों में शामिल हो सके। अतः तथ्य बुर्जुआ इतिहासकारों और पत्रकारों के इस दावे का दो-टूक खंडन करता है कि रूसी बुद्धिजीवियों ने सोवियत सत्ता को स्वीकार नहीं किया और उसके ख़िलाफ़ संघर्ष किया।

लेकिन यह बात सही है कि कुछ पुराने बुद्धिजीवी अक्तूबर क्रांति की विजय के बाद के पहले वर्षों में सोवियत-विरोधी प्रचार के बहकावे और बुर्जुआ प्रभाव में आ गये तथा सोवियत-विरोधी तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया या विदेश चले गये।

सोवियत सत्ता के शत्रुओं ने यह सिद्ध करने के प्रयास में मोटी-मोटी किताबें लिख डाली हैं कि बोल्शेविकों ने बुद्धिजीवियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया और देश में रह जानेवाले विशेषज्ञों को डराया-धमकाया। यह सब झूठ है। कम्युनिस्ट पार्टी ने बलप्रयोग को सोवियत सत्ता से पुराने बुद्धिजीवियों का सहयोग सुनिश्चित करने की एक विधि के रूप में कभी नहीं देखा। सोवियत सत्ता निकायों ने नयी परिस्थितियों में ईमानदारी से काम करने को सहमत होनेवाले पुराने बुद्धिजीवियों के कल्याण के प्रति बड़ी हितचिंता प्रदर्शित की। आर्थिक विनाश और भुखमरी के उन कठिन वर्षों में उनके लिए अच्छी जीवन-परिस्थितियां और उच्च वेतन सुनिश्चित किये गये। लेकिन समाजवादी पुनर्शिक्षा बुर्जुआ बुद्धिजीवियों को आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप में खींचने की मुख्य विधि थी: यह लक्ष्य उत्पादन और सामाजिक कार्यकलाप में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करके और सोवियत नीतियों के उद्देश्यों को उन्हें समझाकर प्राप्त किया गया। समाजवादी भावना में पुराने बुद्धिजीवियों की पुनर्शिक्षा के साधन थे राजनीतिक शिक्षा, सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्रवाइयां, प्रेस, सार्वजनिक संगठनों, सर्वप्रथम, ट्रेड-यूनियनों के कार्यकलाप में सहभागिता। पुराने बुद्धिजीवियों की पुनर्शिक्षा का कार्य विश्वास और समझाने-बुझाने की विधि पर आधारित था। बेशक, सोवियत सत्ता ने तोड़-फोड़ और सोवियत-विरोधी कार्रवाइयों में लगे मुट्ठीभर पुराने बद्धिजीवियों के प्रतिरोध पर दृढ़तापूर्वक क़ाबू पा लिया।*

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य के इन सब कार्यों के फलस्वरूप अधिकांश बुद्धिजीवी सोवियत सत्ता के पक्ष में आ गये। यह सोवियत घरेलू और विदेशनीति के प्रति मेहनतकश बुद्धिजीवियों के समर्थन में,

---

* १९२८-३१ में देश में तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों में हिस्सा लेनेवाले बुर्जुआ विशेषज्ञों पर मुक़दमे ("शाख़्ती मुक़दमा", "औद्योगिक पार्टी का मुक़दमा", आदि) चलाये गये। इन मुक़दमों के परिणामस्वरूप पुराने बुद्धिजीवियों की पांतों में अंतिम रूप से फूट पड़ गयी। –सं०

सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय सहभागिता में, मज़दूरों और किसानों के उनके निकट आने में, समाजवादी निर्माण के ध्येय में अपना ज्ञान और योग्यता लगाने की उनकी तत्परता में प्रकट हुआ।

लेकिन समाजवादी राज्य की सेवा में पुराने बुद्धिजीवियों की भरती तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था, विज्ञान और संस्कृति के लिए आवश्यक विशेषज्ञों की समस्या को हल नहीं कर सकी। सोवियत सत्ता के पहले वर्षों में लेनिन ने "अल्प से अल्प समय में किसानों और मज़दूरों के बीच से सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों"* को प्रशिक्षित करने का कार्यभार पेश किया।

नये, समाजवादी बुद्धिजीवियों के प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा का बड़ा स्थान था।

उच्चतर स्कूल का पुनर्निर्माण

लेनिन ने उच्चतर स्कूल को नयी संस्कृति के विकास सहित समाजवादी निर्माण के कार्यभारों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना।

सोवियत सरकार ने उच्चतर स्कूल को मेहनतकशों की सेवा में रखा। कम्युनिस्ट पार्टी ने उच्चतर स्कूल के मूलगामी पुनर्निर्माण की मुख्य दिशाएं तैयार कीं। पार्टी कार्यक्रम में इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यभार निर्धारित किये गये थे: "पढ़ने के इच्छुक सभी लोगों और सर्वप्रथम मज़दूरों के लिए उच्चतर स्कूलों के द्वार को व्यापक रूप से खोलना; उच्चतर स्कूलों में पढ़ाने की योग्यता रखनेवाले सभी लोगों को अध्यापन-कार्य में खींचना; नये प्राध्यापकों और पुराने प्राध्यापकों के बीच सभी कृत्रिम बाधाओं को हटाना; सर्वहाराओं और किसानों को उच्चतर स्कूलों के उपयोग की वास्तविक संभावना प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को भौतिक सहायता प्रदान करना।"**

सोवियत राज्य ने तुरंत उन्हें अमली जामा पहनाना आरंभ कर

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'आर्थिक सरगर्मी के सवालों पर सोवियतों की नौवीं अखिल रूसी कांग्रेस का आदेश', २८ दिसम्बर, १९२१।

** 'सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय ...'

दिया। पहले २ अगस्त, १९१८ को जन कमिसार परिषद ने लेनिन द्वारा हस्ताक्षरित एक आज्ञप्ति जारी की। सोवियत सरकार ने खुले रूप से घोषणा की कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिला वर्ग सिद्धांत के आधार पर होगा, जिसके अनुसार मज़दूरों और किसानों के बच्चों को वरीयता प्रदान करने के साथ-साथ राजकीय वज़ीफ़े भी दिये जायेंगे। शिक्षा शुल्क सहित उच्चतर स्कूल में प्रवेश की सभी बाधाएं हटा दी गयीं।

उच्चतर शिक्षा के जनवादीकरण के लिए विभिन्न क़दम उठाये गये। इतिहास में पहली बार एक विशेष इंस्टीट्यूट – उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में मज़दूर संकायों की प्रणाली – क़ायम किया गया। मज़दूर संकायों का काम युवा मेहनतकशों के सामान्य शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें उच्चतर स्कूलों में पढ़ाई के लिए तैयार करना था। पहला मज़दूर संकाय १९१९ में मास्को में स्थापित किया गया। सरकार के समर्थन से मज़दूर संकाय तेज़ी से बढ़े और विकसित हुए। १९२३ में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का पहला ग्रुप उनसे निकला। १९२३-२८ की अवधि में मज़दूर संकायों ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए ३५,००० लोगों को प्रशिक्षित किया। १९३४ में संस्थाओं के परीक्षार्थियों में उनका भाग ४५ प्रतिशत था।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों के अनुभव में वृद्धि और अध्यापन विधियों में सुधार ने सोवियत विशेषज्ञों के सामान्य वैज्ञानिक और टेक्नोलाजिकल स्तर को ऊंचा उठाया, उत्पादन से शिक्षा के संबंध को अधिक सघन बनाया और विद्यार्थियों को मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण से सज्जित किया। व्याख्यानों, सेमिनारों और विद्यार्थियों के स्वतंत्र अध्ययनों को वैज्ञानिक-शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्राप्त था।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के दाखिले में वर्ग सिद्धांत के कार्यान्वयन और विद्यार्थियों के बीच मज़दूर संकायों के छात्रों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप विद्यार्थी समुदाय के गठन में आमूल परिवर्तन हुए। १९२८ में, अर्थात पहली पंचवार्षिकी के आरंभ तक रूसी जनतंत्र संघ के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों में सर्वहारा युवाजनों का हिस्सा ५३ प्रतिशत था।

जातीय जनतंत्रों में पुराने बुद्धिजीवियों की पुनर्शिक्षा तथा नये

बुद्धिजीवियों की तैयारी समाजवादी बुद्धिजीवियों के निर्माण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्य का एक संघटक अंग थीं। अधिकांश जातीय जनतंत्रों और प्रदेशों में औद्योगिक सर्वहारा का कोई अस्तित्व नहीं था, जबकि आबादी लगभग शत-प्रतिशत निरक्षर थी। अत: इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने स्थानीय बुद्धिजीवियों के प्रति सतर्कतापूर्ण तथा सुचिंतापूर्ण रुख़ अपनाया और सभी वफ़ादार तत्वों को सोवियत तंत्र के कार्यकलाप में खींचा।

सीमांत जातीय प्रदेशों में असमानता के उन्मूलन की सुसंगत नीति को अमल में लाते हुए सोवियत राज्य ने नये बुद्धिजीवियों की तैयारी में उन्हें व्यावहारिक सहायता प्रदान करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी। जातीय प्रदेशों के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण को तेज़ करने के लिए पार्टी और सोवियत सरकार ने कुछ क़दम उठाये: वहां उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा संस्थान खोले गये, रूसी जनतंत्र संघ के केंद्रीय प्रदेशों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जातीय जनतंत्रों और इलाक़ों के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या दाख़िल की गयी।

लेनिन द्वारा हस्ताक्षरित रूसी जनतंत्र संघ की जन कमिसार परिषद की ७ सितम्बर, १९२० की आज्ञप्ति के अनुसार ताशकंद में मध्य एशिया का पहला राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। लेनिन की पहल पर मास्को ने नव-स्थापित विश्वविद्यालय के सहायतार्थ ८६ उच्च योग्यताप्राप्त प्रोफ़ेसर, प्रयोगशाला उपकरणों से भरे ६६ वैगन और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए २०,००० पुस्तकें भेजी थीं।

आगे चलकर मध्य एशिया के राजकीय विश्वविद्यालय में बहुत-से अनुसंधान इंस्टीट्यूट – रासायनिक, वनस्पतिवैज्ञानिक, भौगोलिक, प्राणि-वैज्ञानिक, भौतिक-वैज्ञानिक और गणितशास्त्रीय इंस्टीट्यूट – खोले गये। तीसरे दशक में मध्य एशिया के जनतंत्रों में भूमि और जल सुधारों तथा कृषि के तीव्र विकास को देखते हुए मध्य एशियाई सिंचाई अनुसंधान संस्थान खोला गया था।

समाजवाद के निर्माण की आवश्यकताओं को देखते हुए पार्टी और सोवियत कर्मीवृंद तथा प्रशासनिक कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था के प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए नये शिक्षा संस्थान खोले गये। ये थे कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय, सोवियत और पार्टी स्कूल, लाल निदेशक कोर्स, औद्योगिक अकादमियां, लाल प्रोफ़ेसर इंस्टीट्यूट, कारखाना

और फ़ैक्टरी तकनीकी कोर्स तथा कर्मीवृंद के तीव्र प्रशिक्षण के लिए अन्य सुविधाएं।

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने पार्टी और राजकीय कार्य के लिए जातीय कर्मीवृंद के प्रशिक्षण के लिए बड़े प्रयास किये। सोवियत सत्ता के पहले वर्षों में ही जातीय प्रदेशों में विभिन्न पार्टी कोर्स संगठित किये गये। १९२२ में ताशकंद में मज़दूर और दहक़ान कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय क़ायम किया गया, जो बाद में लेनिन नामक मध्य एशियाई कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय हो गया। सभी जातीय जनतंत्रों में वैज्ञानिक संस्थानों का जाल फैल गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए छात्रों का मुख्य स्रोत मज़दूर संकाय नहीं, बल्कि सामान्य माध्यमिक स्कूल बन गये थे। चौथे दशक के मध्य में पुराने और नये बुद्धिजीवियों के बीच अंतर मिटने लगा। ईमानदारी से काम करनेवाले बुर्जुआ विशेषज्ञ सोवियत बुद्धिजीवियों का अभिन्न अंग बन गये।

सोवियत उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने अर्थव्यवस्था और संस्कृति की सभी शाखाओं के लिए उच्च योग्यताप्राप्त विशेषज्ञ तैयार किये। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में ८,६८,००० विशेषज्ञ प्रशिक्षित किये गये। १९३८-३९ में ही सोवियत संघ में छात्रों की संख्या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित २२ यूरोपीय देशों में छात्रों की संख्या से अधिक हो गयी थी। १ जनवरी, १९४१ को सोवियत अर्थव्यवस्था में लगे उच्च या माध्यमिक शिक्षाप्राप्त विशेषज्ञों की संख्या २४,०१,००० थी। विभिन्न विशेषज्ञों की देश की मांग अधिकांशतः पूरी हो गयी थी। इस तरह, सोवियत उच्चतर शिक्षा ने समाजवाद की विजय और सांस्कृतिक क्रांति को संपन्न करने में बड़ा योगदान किया।

४. समाजवाद की सेवा में विज्ञान का उपयोग

सोवियत संघ में सांस्कृतिक क्रांति विज्ञान के विकास से, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उसके बढ़ते प्रभाव से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। यह स्वाभाविक है, क्योंकि समाजवादी समाज विज्ञान की उच्चतम उपलब्धियों पर आधारित होना चाहिए। १९१८ में ही लेनिन

की पहल पर सोवियत विज्ञान के आगे विकास तथा उसे उत्पादन की आवश्यकताओं से और निकटता से जोड़ने के लिए विभिन्न क़दम उठाये गये। इसके साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में सर्वोत्तम विदेशी अनुभवों का उपयोग करने का भी आह्वान किया।

देश में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों का व्यापक जाल क़ायम किया जाने लगा। १९१८-२१ में देश में ५० से अधिक ऐसे संस्थान काम कर रहे थे। उनमें से बहुतों ने समाजवादी उद्योग की स्थापना और विकास में सर्वांगीण योगदान किया और सोवियत विज्ञान को असाधारण उप-लब्धियों से गौरवान्वित किया।

विज्ञान का विकास पहली बार राजकीय काम बना। सोवियत सरकार ने विज्ञान अकादमी और तीव्र आर्थिक विकास से जुड़ी समस्याओं के हल में उसकी सक्रिय भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया।

लेनिन की रचना 'वैज्ञानिक और तकनीकी काम की योजना का मसविदा'• ने, जिसमें देश के आर्थिक विकास के विशाल कार्यभार निर्धारित किये गये थे, सोवियत विज्ञान के योजनाबद्ध संगठन की आधारशिला रखी। उन्होंने लिखा: "सर्वोच्च आर्थिक परिषद... को रूस के औद्योगिक पुनर्गठन और आर्थिक प्रगति के लिए योजना की यथासंभव तीव्र तैयारी हेतु विभिन्न विशेषज्ञ आयोग संगठित करने के लिए विज्ञान अकादमी को तुरंत अपने आदेश देने चाहिए।"*

मौलिक वैज्ञानिक अध्ययनों को जारी रखते हुए ही वैज्ञानिकों ने अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर सक्रिय अनुसंधान करना आरंभ किया। १९१८ में वोल्गा और उराल के बीच के क्षेत्र में तेल पूर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ। १९१९ में कुर्स्क चुम्बकीय विसंगति में चहुंमुखी शोधकार्य आरंभ किये गये, जिनके फलस्वरूप वहां विशाल लौह अयस्क भंडारों का दोहन होने लगा। सोवियत वैज्ञानिकों ने गोएलरो योजना की तैयारी और कार्यान्वयन में, देश के औद्योगीकरण तथा कृषि के सामूहिकीकरण संबंधी बड़े कार्यों में सक्रिय हिस्सा लिया।

समाजवादी अर्थव्यवस्था के नियोजन के वैज्ञानिक सिद्धांत ने अनुसंधान कार्य को उत्पादन की आवश्यकताओं से अधिक सघन रूप से जोड़ दिया। तीसरे दशक में ही विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञताप्राप्त

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'वैज्ञानिक और तकनीकी काम की योजना का मसविदा', १९१८।

इस घटना ने लोगों का कोई विशेष ध्यान नहीं खींचा, पर आज उसका महत्व स्पष्ट दिखायी देता है। इस राकेट की डिज़ाइन अंतरिक्ष अनुसंधान युग का सूत्रपात करनेवाले, पहले सोवियत अंतरिक्षयानों के प्रमुख डिज़ाइनर सेर्गेई कोरोलेव ने अपने सहयोगियों के साथ बनायी थी।

सोवियत वैज्ञानिकों और विदेशी वैज्ञानिकों के बीच संपर्क मज़बूत बने। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कांग्रेसों और सम्मेलनों में सोवियत वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

इस प्रकार, राजकीय कार्य के नाते सोवियत विज्ञान ने सर्वतोमुखी विकास पाया। अनुसंधान की मार्क्सवादी-लेनिनवादी विधि, उत्पादन, समाजवादी निर्माण के ठोस कार्यभारों से गहन संबंध और सामूहिक वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्य सोवियत विज्ञान के मूल लक्षण बने।

नये, जन बुद्धिजीवियों की तैयारी, उच्च योग्यताप्राप्त विशेषज्ञों का प्रशिक्षण और समाजवादी निर्माण के उद्देश्यों के अनुरूप वैज्ञानिक कार्य का व्यापक क्षेत्र सोवियत संघ में सांस्कृतिक क्रांति की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं।

५. समाजवादी साहित्य और कला का प्रस्फुटन

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार की सांस्कृतिक नीति में साहित्य और कला को प्रमुख स्थान प्राप्त था। उन्होंने साहित्य और कला के निरंतर विकास और परिष्कार को चहुंमुखी रूप से सुविधाजनक बनाया तथा उन्हें जनगण और कम्युनिज़्म के आदर्शों की सेवा में लगाया।

क्लासिकीय विरासत – महान रूसी साहित्य, विदेशी लेखकों की असाधारण साहित्यिक कृतियों, विगत से विरासत में मिली कला-निधियों – के प्रति हितचिंता सोवियत साहित्य की एक ख़ास विशेषता है। सांस्कृतिक क्रांति ने, जो अभाव और आर्थिक विनाश, गृहयुद्ध और विदेशी हस्तक्षेप की कठिन परिस्थितियों में शुरू हुई थी, रूसी और विश्व साहित्य की सर्वोत्तम मानवतावादी परंपराओं को नूतनता प्रदान करते हुए जारी रखा, उन्हें रचनात्मक और आलोचनात्मक ढंग से विकसित किया।

सोवियत सरकार के आदेश को अमल में लाते हुए शिक्षा जन कमिसारियत ने मई १९१८ से मई १९१९ तक (यानी जब गृहयुद्ध अपने ज़ोरों पर चल रहा था और कागज़ का घोर अभाव था) क्लासिकीय रूसी लेखकों की ११५ कृतियों की ६० लाख प्रतियां छापीं। अकेले पुश्किन की कृतियां ही ७,५०,००० प्रतियों में छपीं।

समाजवादी क्रांति की विजय के शीघ्र बाद ही मक्सिम गोर्की, देम्यान बेद्नी, अलेक्सांद्र सेराफ़िमोविच, आदि लेखकों ने उदीयमान सोवियत साहित्य को बहुत बढ़िया ढंग से परिभाषित किया। क्रांतिपूर्व रूसी जनवादी साहित्य के सर्वोत्तम प्रतिनिधि – अलेक्सांद्र ब्लोक, वालेरी ब्र्यूसोव, व्लादीमिर मयाकोव्स्की, सेर्गेई येसेनिन, विक्तोर वेरेसायेव, अलेक्सेई नोविकोव-प्रिबोई, सेर्गेई सेर्गेयेव-त्सेन्स्की, आदि – सोवियत सत्ता के पक्षधर थे।

इस काल के साहित्य में मज़दूरों के बीच से आनेवाले कवियों फ़्योदोर श्कूलेव, व्लादीमिर किरील्लोव, निकोलाई पोलेतायेव, वसीली काज़िन, आदि को उल्लेखनीय स्थान प्राप्त था। उनमें से कई गृहयुद्ध में लड़े थे। श्रम के विषय की ओर सर्वहारा कविता की अभिमुखता, क्रांति, नव-जीवन का गुणगान करने की उसकी अभिलाषा ने संपूर्ण साहित्य के विकास पर बड़ा प्रभाव डाला।

लेकिन क्रांति के इन प्रथम वर्षों में सोवियत साहित्य और कला के विकास के प्रति "अति-क्रांतिकारी", वामपंथी विचार रखनेवाले लोगों ने भी कोई कम प्रभाव नहीं डाला। नयी, समाजवादी संस्कृति से क्लासिकीय साहित्यकारों को "विमुख करने" के प्रयास किये गये। कुछ लोगों ने समस्त पूर्ववर्ती रूसी और विश्व साहित्य तथा कला के वैचारिक और कलात्मक मूल्यों से इन्कार किया। लेकिन लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मसले पर सटीक स्थिति अपनायी, जिसने नवोदित सोवियत साहित्य को ऐसे वामपंथी विरूपणों और भ्रमों पर तेज़ी से क़ाबू पाने में सहायता की तथा सोवियत साहित्य को वैचारिक आधार प्रदान करने के संघर्ष में बड़ी भूमिका अदा की। अक्तूबर १९२० में तीसरी कोम्सोमोल कांग्रेस को संबोधित करते हुए लेनिन ने ज़ोर दिया कि "सर्वहारा संस्कृति कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आसमान से टपक पड़ी हो। वह उन लोगों का आविष्कार नहीं है, जो अपने को सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ कहते हैं। यह सब बेकार की बातें हैं। सर्वहारा

संस्कृति को उन ज्ञान निधियों का विधिसंगत विकास होना चाहिए, जिसे मानवजाति ने पूंजीवाद, सामंतवादी और नौकरशाही समाज के जुए के नीचे अर्जित किया है।"*

व्सेवोलोद इवानोव, निकोलाई असेयेव, निकोलाई तीखोनोव, द्मित्री फ़ूर्मानोव, कोंस्तांतीन फ़ेदिन, व्सेवोलोद विश्नेव्स्की, आदि बहुत से लेखकों ने अपने कलात्मक जीवन का आरंभ करते हुए गृहयुद्ध के वर्षों में अपनी पहली रचनाएं लिखीं। लेओनीद लेओनोव ने लिखा, "क्रांति और गृहयुद्ध ने मुझे एक लेखक का जीवन दिया।" अनेक लेखकों, कवियों और कलाकर्मियों ने क्रांति तथा नव-जीवन के निर्माण के विषय की ओर अभिमुख होकर यथार्थवादी स्थितियों से सच्चाई का चित्रण किया। सोवियत सत्ता के मंच पर लेखकों की एकजुटता की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ी। उस काल में द्मित्री फ़ूर्मानोव की कृति 'चपायेव', अलेक्सांद्र सेराफ़िमोविच की 'लौह धारा' और व्सेवोलोद इवानोव की 'छापामार कहानियां' जैसी असाधारण कृतियां प्रकट हुईं। उन्होंने इतिहास में जनता के निर्णायक महत्व और कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका को प्रकाश में लाया। महान सर्वहारा लेखक मक्सिम गोर्की ने रूसी जनगण के जीवन पर आधारित असाधारण कृतियां लिखीं। व्लादीमिर मयाकोव्स्की ने अपनी रचनाओं में पार्टी प्रतिबद्धता का भव्य उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कविता 'व्लादीमिर इल्यीच लेनिन' सच्चे समाजवादी साहित्य की अनुपम कृति है। गोर्की, मयाकोव्स्की, आदि सोवियत लेखकों और कवियों की कृतियों का सोवियत संघ की जातीय भाषाओं में ही नहीं, बल्कि अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया।

सोवियत लेखकों, कलाकारों और अन्य कलाकर्मियों की रचनात्मक कृतियों में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक नयी विधि – समाजवादी यथार्थवाद – विकसित हुई। विगत की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात करते हुए उसने सोवियत साहित्य और कला की नूतनकारी भावना और विचारधारात्मक प्रतिबद्धता निर्धारित की।

वास्तविकता का सच्चा और ऐतिहासिक रूप से सटीक प्रतिबिंबन समाजवादी यथार्थवाद का सार है। जीवन को उसकी विविधता और

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'युवक संघों के कार्यभार', १९२०।

अविराम विकास में देखना, जीवन में जो कुछ भी नया और प्रगतिशील है, उसका सक्रिय समर्थन करना, जो कुछ भी पुराना, जड़ और मरणासन्न है, उस सबके खिलाफ़ निर्मम संघर्ष करना, मेहनतकश जनसाधारण के हितों की दृढ़ और सुसंगत रक्षा करना – ये मूलसिद्धांत समाजवादी यथार्थवाद की विधि का आधार बनाते हैं।

समाजवादी यथार्थवाद की विधि बुद्धिजीवियों से समाज की प्रगति को शासित करनेवाले नियमों की गहन समझ तथा पार्टी पक्षधरता की स्थिति से, यानी मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक परिघटनाओं के विवरण की मांग करती है। यथार्थवादी कला और साहित्य के विकास में सर्वोच्च अवस्था के नाते समाजवादी यथार्थवाद समकालीन जीवन से, नये समाज के व्यावहारिक निर्माण से लेखकों, कलाकारों के गहन संबंध की पूर्वकल्पना करता है। सोवियत लेखकों द्वारा अंगीकार की गयी समाजवादी यथार्थवाद की विधि ने उन्हें ऐसी कृतियां रचने में समर्थ बनाया जैसी कि मिखाईल शोलोखोव की 'धीरे बहे दोन रे', फ्योदोर ग्लाद्कोव की 'सीमेंट' और 'ऊर्जा', लीदिया सेइफ़ुलिना की 'विरिनेया', निकोलाई ओस्त्रोव्स्की की 'अग्निदीक्षा', अलेक्सेई तोलस्तोय के उपन्यासत्रय 'सत्यपरीक्षा', मारियेत्ता शागिन्यान की 'पनबिजलीघर परियोजना', इल्या एरेन्बुर्ग की 'दूसरा दिन', कोंस्तांतीन फ़ेदिन की 'यूरोप का अपहरण', म० कोल्त्सोव की 'स्पेनी डायरी', वालेंतिन कतायेव की 'समय, आगे बढ़ो!', इल्फ़ और पेत्रोव की 'एकमंज़िला अमरीका', कोंस्तांतीन पाउस्तोव्स्की की 'कोल्खिदा', आदि। गोर्की के शब्दों में, ये लेखक जीवन की वास्तविकताओं से "कला की सत्यता को ढालने और पाने में सफल हुए"।

सोवियत साहित्य और कला के विकास की एक विशिष्ट बात यह थी कि ऐतिहासिक रूप से अल्प अवधि में ही सोवियत संघ की सभी जातियों के साहित्य और कलाएं अपने विविध रूपों और शैलियों में विकसित हो गये। जातीय लेखकों और कवियों की कृतियां देश-विदेश में मशहूर हो गयीं। वे थे: मिकोला बाजान और मक्सिम रील्स्की (उक्राइना), यान्का कुपाला और याकूब कोलास (बेलोरूस), गेओर्गी लेओनीद्ज़े और गलाक्तिओन ताबीद्ज़े (जार्जिया), अवेतिक इसाक्यान और आकोप आकोप्यान (आर्मेनिया), सामेद वुर्गुन और जफ़र जबर्ली (अज़रबैजान), मुख़्तार औयेज़ोव और साबिद मुकानोव

(कज़ाख़स्तान), साद्रिद्दीन आईनी और अबुलकासिम अहमेदज़ादे लाहुती (ताजिकिस्तान), तुगेलबाई सदीकबेकोव (किर्गीज़िया) और बेर्दी केर्बाबायेव (तुर्कमानिस्तान)। सोवियत लोगों ने कज़ाख़ लोक कवि जाम्बुल जबायेव, सुलेमान स्ताल्स्की और दाघिस्तानी कवि हमज़ात त्सादासा की कविताएं बहुत पसंद कीं।

सोवियत काल में सुदूर उत्तर की जातियों के भी अपने लेखक और कवि प्रकट होने लगे, जिनकी कृतियां बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी हैं।

१९३४ में मास्को में लेखकों की पहली अखिल संघीय कांग्रेस हुई, जिसमें सोवियत संघ की ५२ जातियों के लेखकों और ४० देशों के मेहमानों ने भाग लिया। मक्सिम गोर्की ने अपने भाषण में समाजवादी समाज के साहित्य के मुख्य लक्षणों पर प्रकाश डाला तथा उसके विकास का गहन विश्लेषण दिया। सभी जनतंत्रों के लेखक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने जातीय साहित्यों की शानदार प्रगति का वर्णन किया। कांग्रेस ने देश के सभी लेखकों को एक संगठन – सोवियत लेखक संघ – में एकजुट किया तथा लेखकों का ऐसी कृतियों की रचना करने का आह्वान किया, जो सोवियत लोगों को मानवतावाद और समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना में शिक्षित करने में सहायता करें।

कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे तले सोवियत लेखकों की एकजुटता ने बहुजातीय सोवियत साहित्य को एक सबल वैचारिक और शैक्षिक शक्ति में बदल दिया।

सोवियत थियेटर का उदय और विकास भी कम्युनिस्ट पार्टी से प्रतिबद्धता, जनगण से संपर्क और बहुविध जातीय रूपों के माध्यम से समाजवादी अंतर्वस्तु के प्रकटीकरण के लिए अभिलाक्षणिक था। क्रांति के विचार, गृहयुद्ध में मेहनतकश जनगण का वीरतापूर्ण संघर्ष और समाजवादी निर्माण का ऊंचा मनोभाव कई नाटकों में प्रकट हुए: कोंस्तांतीन त्रेन्योव का 'लुबोव यारोवाया', व्सेवोलोद इवानोव का 'बख़्तरबंद ट्रेन १४-६९' और बोरिस लाव्रेन्योव का 'टूट-फूट'। मयाकोव्स्की ने 'खटमल' और 'ग़ुसलख़ाना' जैसी व्यंग्यात्मक कृतियां रचीं, जिन्होंने नौकरशाही, कूपमंडूकतावादी और संस्कृतिविहीनता का मज़ाक़ उड़ाया। क्रांतिकारी विषयवस्तु ने नये दर्शक पाये, मज़दूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों ने उसका जीवंत समर्थन किया, जिनमें से बहुतों ने

उन घटनाओं में प्रत्यक्षतः भाग लिया था, जिनका इन नाटकों में इतनी कुशलतापूर्वक वर्णन हुआ था।

चौथे दशक में सोवियत थियेटरों में रूसी और विश्व क्लासिकीय लेखकों के नाटक मंचित किये गये। मक्सिम गोर्की ने सोवियत नाट्यकला के विकास पर बड़ा प्रभाव डाला जिन्होंने उन वर्षों में अपना सर्वोत्तम नाटक 'येगोर बुलिचोव और अन्य' लिखा। निकोलाई पोगोदिन के नाटक 'राइफ़लधारी आदमी' में लेनिन को पहली बार चित्रित किया गया। व्सेवोलोद विश्नेव्स्की के 'आशावादी त्रासदी', बोरिस रोमाशोव के 'अग्नि पुल', अलेक्सांद्र कोर्नेइचुक के 'प्लातोन क्रेचेत', अलेक्सांद्र अफ़िनोगेनोव के 'सलाम, स्पेन', इसाक बाबेल के 'घुड़सवार सेना' और व्लादीमिर किर्शोन के 'रोटी' जैसे नाटकों को उल्लेखनीय कलात्मक सफलता मिली। १६३६ में सोवियत सरकार ने सोवियत संघ के जन कलाकार की माननीय उपाधि जारी की। सोवियत कला के असाधारण सोवियत कलाकार और मास्को कला थियेटर के संस्थापक कोंस्तांतीन स्तानिस्लाव्स्की और व्लादीमिर नेमिरोविच-दान्चेन्को इस उपाधि से विभूषित पहले कुछ लोगों में थे।

सोवियत सिनेमा भी यथार्थता के चित्रण में पक्षधरता और जनगण के साथ अपने अटूट संबंध के आधार पर विकसित हुआ। सिनेमा व्यापक मेहनतकश जनसाधारण के प्रबोधन और कम्युनिस्ट शिक्षा का एक सबल साधन बन गया। दस्तावेज़ी, वैज्ञानिक और कलात्मक फ़िल्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाले बहुत से पार्टी और सरकारी निर्णयों में फ़िल्म उद्योग के विकास की समस्याओं तथा सिनेमा संगठनों के कार्यकलाप का सविस्तार विवेचन किया गया।

सेर्गेई आइज़ेन्श्तेइन द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'युद्धपोत पोतेम्किन' (१६२५) ने सोवियत और विश्व यथार्थवादी सिनेमा के विकास में एक नये युग का सूत्रपात किया और लाखों सिनेमा दर्शकों पर ज़बर्दस्त प्रभाव डाला था। १६२६ में फ़िल्म निर्देशक व्सेवोलोद पुदोव्किन ने गोर्की के उपन्यास 'मां' पर आधारित फ़िल्म बनायी, जिसने भी विश्व स्वीकृति पायी। 'अक्तूबर में लेनिन', '१६१८ में लेनिन' (निर्देशक म० रोम्म) और 'राइफ़लधारी आदमी' (निर्देशक सेर्गेई युत्केविच) जैसी लेनिन के बारे में फ़िल्मों का बड़ा शैक्षिक महत्व था। सेर्गेई वसील्येव और गेओर्गी वसील्येव बंधुओं द्वारा निर्मित फ़िल्म 'चपायेव'

ने सोवियत सिनेमा को विश्वव्यापी प्रसिद्धि दिलायी। उक्राइनी निर्देशक अलेक्सांद्र दोव्जेन्को ने १९२९-३० में श्रेष्ठ फ़िल्में 'शस्त्रागार' और 'ज़मीन' बनायीं। ग्रिगोरी कोज़िन्त्सेव और लेओनीद त्राउबेर्ग द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'मक्सिम के बारे में त्रयी' ने युवा पीढ़ी पर अमिट छाप छोड़ी। पेत्रोग्राद के मज़दूर-बहुल उपनगर का एक युवा मज़दूर (बोरिस चिर्कोव ने उसकी भूमिका अदा की थी) उस समस्त पीढ़ी का प्रतीक बन गया, जिसने क्रांति के लिए कम्युनिज़्म के विचारों की चरितार्थता के लिए संघर्ष किया था।

उन वर्षों में फ़िल्म स्टुडियों के भौतिक और तकनीकी आधार को मज़बूत बनाने और उनके लिए कला कर्मियों तथा तक्नीशियनों की व्यवस्था करने में बड़ी सफलताएं प्राप्त की गयीं। जातीय जनतंत्रों में भी फ़िल्म स्टुडियो क़ायम किये गये। फ़िल्म-प्रोजेक्टरों की संख्या में बड़ी तेज़ी से बढ़ाव आया। देश में १९२७ में उनकी संख्या ७,३०० थी, जो १९३७ में बढ़कर २८,००० हो गयी थी।

चौथे दशक में ध्वनि फ़िल्मों के समारंभ ने फ़िल्मों की विचार-धारात्मक और भावात्मक छाप को बढ़ा दिया। पहली ध्वनि फ़िल्मों — निकोलाई एक्क की 'जीवन में पदार्पण', फ़्रेडरिक एर्मलेर और सेर्गेई युत्केविच की 'जवाबी योजना', सेर्गेई गेरासिमोव की 'सात साहसी' — ने नये सामाजिक संबंधों के निर्माण, उस उग्र वर्ग संघर्ष को दिखाया, जिसमें समाजवाद के विचारधारात्मक और नैतिक सिद्धांत सुदृढ़ बनें।

विगत की संस्कृति के प्रति सोवियत सरकार के रवैये और उसे समाजवाद की सेवा में लगाने की इच्छा ने स्मारक निर्माण में अपनी ज्वलंत अभिव्यक्ति पायी। लेनिन के इरादे के अनुसार मास्को और अन्य नगरों में विगत के महान चिंतकों और मानवतावादियों, क्रांतिकारियों, लेखकों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, संगीतकारों और अभिनेताओं के स्मारक बनाने की योजना बनायी गयी। तय किया गया कि महानतम क्रांतिकारियों कार्ल मार्क्स और फ़्रेडरिक एंगेल्स के स्मारक सबसे पहले बनाये जायें।

सेर्गेई मेर्कूरोव, मात्वेई मानिज़ेर और वेरा मूख़िना जैसे अनेक असाधारण वास्तुकारों ने इस विचार को अमली जामा पहनाया। इवान शाद्र (जार्जिया में ज़ेमो-अव्चाल्स्काया पनबिजलीघर पर लेनिन की मूर्ति), वेरा मूख़िना (गोर्की नगर में मक्सिम गोर्की की मूर्ति) और

मात्वेई मानिज़ेर ('९ जनवरी, १९०५ के शहीदों को' स्मारक) ने बड़े भव्य स्मारक बनाये। उस काल में सोवियत कलाकारों द्वारा बनाये गये अनेकानेक स्मारकों और चित्रों ने मेहनतकश जनगण के वीरतापूर्ण और निस्स्वार्थ संघर्ष तथा नये समाजवादी समाज के निर्माण के मनोभाव को प्रतिबिंबित किया। कलाकार सेर्गेई गेरासिमोव, बोरिस इओगान्सोन, अलेक्सांद्र देइनेका, यूरी पीमेनोव और गेओर्गी र्याज्स्की ने अपने चित्रों में सोवियत मानव – योद्धा और नये समाज का निर्माता – के लक्षण प्रकट किये। सुप्रसिद्ध युद्ध-चित्रकार मित्रोफ़ान ग्रेकोव के चित्रों ने लाल सेना के वीरतापूर्ण पराक्रमों को चित्रित किया। इसाक ब्रोद्स्की, अलेक्सांद्र गेरासिमोव, आदि चित्रकारों ने लेनिन के चित्र बनाये।

उन वर्षों में राजनीतिक रेखाचित्रों, पोस्टरों, अख़बारी व्यंग्यचित्रों जैसी विविध विधाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। ये सभी समाजवादी राज्य के शत्रुओं के ख़िलाफ़ कारगर साधन थे। द्मित्री मोर और विक्तोर देनी, बोरिस येफ़ीमोव और कुक्रिनिक्सी (मिख़ाईल कुप्रियानोव, पोर्फ़िरी क्रिलोव और निकोलाई सोकोलोव) इन विधाओं के सफल व्याख्याता थे।

ललित कला में भी समाजवादी यथार्थवाद सृजनशील श्रम की मूल विधि था जिसने उन सभी रूपवादी और प्रकृतिवादी प्रवृत्तियों पर विजय पा ली थी जो उस काल के कुछ कलाकारों और वास्तुकारों की कृतियों में मौजूद थीं।

समाजवादी निर्माण के वर्षों में सोवियत संघ की सभी जातियों की संगीत कला ने बड़ा विकास पाया। क्रांतिकारी विषयों और क्लासिकीय साहित्यिक कृतियों की विषयवस्तुओं के आधार पर क्रांतिकारी गीत रचे गये, ऑपेरा और बैले प्रस्तुत किये गये, जिनमें रेइनहोल्ड ग्लिएर का 'लाल पोस्त का फूल', अलेक्सांद्र स्पेन्दिआरोव का 'अल्मास्त', इवाल द्ज़ेर्जीन्स्की का 'धीरे बहे दोन रे', तीख़ोन ख्रेन्निकोव का 'तूफ़ान में', सेर्गेई प्रोकोफ़ियेव का 'सेम्योन कोत्को' और बोरिस असाफ़ियेव का 'बाख़चिसराय का फ़ौवारा' शामिल थे। द्मित्री शोस्ताकोविच की 'पांचवीं सिम्फ़नी', संगीतकार द्मित्री कबालेव्स्की का 'लेनिन की स्मृति में शोकगीत', सेर्गेई वसिलेन्को की वाद्य-संगीत रचना 'सोवियत पूर्व', यूरी शापोरिन का सिम्फ़नी-कैन्टटा 'कुलिकोवो

रणक्षेत्र पर' और अराम खचातुर्यान के पियानो और वायलिन कंसर्ट असाधारण संगीत रचनाएं थीं।

उन जातीय जनतंत्रों में, जहां क्रांति के पहले पेशेवर कला का कोई अस्तित्व नहीं था, जहां कोई स्वरचिह्न नहीं था, संगीत कला के जटिल रूप विकसित हो गये। अज़रबैजान के संगीतकार उजेइर गाजिबेकोव ने वीरगाथा ऑपेरा 'केर-ओग्ली' की रचना की, येव्गेनी तिकोत्स्की और अनातोली बोगातिरेव ने पहले बेलोरूसी ऑपेरे लिखे, नाजिब जिगानोव ने पहले तातार ऑपेरों की रचना की। कज़ाखस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गीज़िया के संगीतकारों ने भी अपने जातीय ऑपेरों और बैलों की रचना की।

अनातोली अलेक्सांद्रोव, इसाक दुनायेव्स्की, व्लादीमिर जखारोव, अनातोली नोविकोव, मात्वेई ब्लांतेर और पोक्रास बंधुओं के गीत बड़े ही लोकप्रिय हुए। सभी जनतंत्रों में लोक संगीतकारों, गायकों, लोककथाकारों और वाद्य-संगीत मंडलियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। सोवियत संगीत विद्यालय के प्रतिनिधियों – पियानो और वायलिन वादक लेव ओबोरिन, दविद ओइस्त्राख, एमिल गिलेल्स और याकोव ज़ाक तथा संगीत कंडक्टर येव्गेनी म्रवीन्स्की एवं नातन राखलिन – ने वारसा, ब्रसेल्स, पेरिस और वियेना में अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिताओं में विजयें प्राप्त कीं।

सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जातीय संस्कृतियों का अभूतपूर्व विकास हुआ। सांस्कृतिक क्रांति प्रत्येक जाति की प्राचीन संस्कृति के प्रगतिशील पहलुओं के पुनर्जागरण और सर्वतोमुखी विकास की पूर्वकल्पना करती है। लेकिन उस समय जातीय जनतंत्रों में कुछ सांस्कृतिक कर्मियों ने कला में जातीय को निरपेक्ष बना दिया और उसे जड़ीभूत तथा अन्य जातियों से पृथक्कृत रूप में समझा। उदाहरणार्थ, उन्होंने सोवियत पूर्वी जनतंत्रों में पेशेवर कला का घोर विरोध किया। उनके विचार में, ऑपेरा, सहगान और सिम्फ़नी संगीत, पेशेवर थियेटर और सिनेमा के विकास ने "कलात्मक चिंतन की जातीय विशेषताओं" को अपूरणीय क्षति पहुंचायी।

मेहनतकशों की जातीय एकजुटता के लिए पराये ऐसे विचारों पर क़ाबू पाया गया। मास्को में होनेवाले सोवियत जातीय जनतंत्रों के कला समारोह सोवियत संस्कृति के सच्चे उत्सव, लेनिनीय जातीय

नीति की विजय और सांस्कृतिक क्रांति की सफलता थे।

यह सब इस बात का प्रमाण था कि सोवियत संघ की बहुत-सी जातियां, जो पहले अपनी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने की संभावनाओं से वंचित थीं, महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय के बाद संस्कृति और कला के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ चलीं।

सोवियत संघ के चहुंमुखी विकास ने वास्तुकारों और नगरनिर्माताओं के समक्ष नये कार्यभार पेश किये। इस समस्या का समाधान पाने की खोज में बहुत विचार-विमर्श हुए कि समाजवादी नगर और गांव, फ़ैक्टरियां, रिहायशी मकान, स्कूल, सांस्कृतिक प्रासाद, क्लब, किंडर-गार्टन कैसे होने चाहिए? १६३१-३५ में तैयार की गयी मास्को के पुनर्निर्माण की महायोजना ने समाजवादी नगर नियोजन के मौलिक, वैज्ञानिक सिद्धांतों को बढ़िया ढंग से निर्धारित किया। इस योजना के अनुसार, क्रांति-पूर्व काल के अवशेषों के रूप में बचे जर्जर मकानों और संकरी गलियों वाले छोटे मुहल्लों की जगह बड़े वास्तुशिल्पीय समुच्चय, नये चौक, बुलवार और पार्क बनाये जानेवाले थे। यह योजना बड़े ही सुसंगत ढंग से बनायी गयी थी: रिहायशी मकानों के मुहल्ले, सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रतिष्ठानों के निकट हरियाली के बीच बनाये जाने थे।

पुनर्निर्माण के मास्को के अनुभव का अन्य सोवियत नगरों के निर्माण में उपयोग किया गया। एकीकृत योजना के अनुसार अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर नये नगर बनाये गये। नगर-निर्माण के इन सभी महत्वपूर्ण कार्यभारों को पूरा करने में सोवियत वास्तुकारों ने सोवियत कला के अन्य सभी कर्मियों की भांति समाजवादी यथार्थवाद की विधि का अनुसरण किया।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, प्रगतिशील राष्ट्रीय परंपराओं और विश्व कला की उपलब्धियों के सुदृढ़ आधार पर सोवियत संघ में हुए महान क्रांतिकारी रूपांतरणों ने सोवियत संघ की जातियों को ऐतिहासिक रूप से अल्प अवधि में ही इतना लंबा रास्ता तय करने और समाजवादी संस्कृति तथा कला के विकास में असाधारण सफलताएं पाने में समर्थ बनाया, जिसे पूंजीवाद के तहत तय करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते। बुर्जुआ विचारकों की यह "भविष्यवाणी" ग़लत सिद्ध हुई कि सर्वहारा

वर्ग संस्कृति को नष्ट कर देगा। उनकी यह आशंका भी बिल्कुल निराधार निकली कि सृजनात्मक कार्यकलाप में जनगण को खींचने और संस्कृति का व्यापक प्रसार करने से उसका पतन होगा। न केवल साहित्य और कला की श्रेष्ठ कृतियों के लिए, बल्कि सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रचनात्मक प्रयास के लिए भी सोवियत लोगों की सच्ची अदम्य प्यास उनके आत्मिक विकास का ज्वलंत सूचक थी। समाजवादी व्यवस्था, जीवन के सोवियत रूप ने जनगण के बीच प्रतिभाओं के व्यापक विकास के लिए फलप्रद ज़मीन तैयार की। १६३३ में मक्सिम गोर्की ने लिखा: "विगत में कहीं भी, पुनर्जागरण काल जैसे महान प्रयासों के काल में भी प्रतिभाओं की संख्या इतनी तेज़ी और प्रचुरता से नहीं बढ़ी, जितनी कि वह यहां अक्तूबर के बाद बढ़ रही है।"*

* * *

नयी, समाजवादी, सच्ची जन-संस्कृति का निर्माण सोवियत संघ में सांस्कृतिक क्रांति का मुख्य परिणाम था। इस संस्कृति की महानतम उपलब्धि करोड़ों मेहनतकशों के मन में समाजवादी चेतना का विकास थी।

सांस्कृतिक क्रांति समाजवादी निर्माण की अवधि में सामाजिक विकास का सामान्य नियम है। यह समाजवादी विकास का मार्ग अपनानेवाले सभी देशों और जातियों के लिए आवश्यक है, चाहे विगत से विरासत में मिली संस्कृति के स्तर समेत उनकी ऐतिहासिक राष्ट्रीय विशेषताएं कुछ भी क्यों न हों।

आज भी बुर्जुआ सिद्धांतकार अक्सर यह दावा करते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति एक "शुद्धतः राष्ट्रीय परिघटना" है, जो केवल सांस्कृतिक रूप से पिछड़े देशों की अभिलाक्षणिकता है। वे इस आधार पर तथाकथित "सभ्य देशों" में सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता से इन्कार करते हैं कि उनमें जन-संपर्क साधनों (प्रेस, टेलीविजन, रेडियो, आदि) का तेज़ी से विकास हो रहा है जो "संस्कृति को सबके लिए सजातीय" बनाते हैं।

---

* मक्सिम गोर्की, संग्रहीत रचनाएं, मास्को, १६४६-१६५५, खंड २७, पृ० ४५ (रूसी में)।

यह बिल्कुल साफ़ है कि कोई भी जन संपर्क साधन स्वयं ही उस संस्कृति की वैचारिक अंतर्वस्तु और राजनीतिक दिशावृत्ति को नहीं बदल सकता और न बदलेगा, जिसका वह प्रचार कर रहा होता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जन सूचना साधन किस वर्ग के हाथों में हैं और वे किनके हितों की सेवा करते हैं।

सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि सांस्कृतिक क्रांति को संपन्न करने के लिए निम्न चीज़ें आवश्यक हैं: प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की एक ऐसी सुनिर्मित प्रणाली क़ायम करना, जो सभी जनसाधारण की पहुंच में हो; विगत की प्रगतिशील सांस्कृतिक संपदा के द्वार मेहनतकशों के लिए खोल देना; पुराने बुद्धिजीवियों को पुनर्शिक्षित करने और उनकी सेवाओं का समाजवादी निर्माण में उपयोग करने के साथ-साथ मेहनतकशों की पांतों से नये बुद्धिजीवियों को तैयार करना; और संपूर्ण आबादी को मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर शिक्षित करना।

अध्याय ६

समाजवादी जनवाद का विकास

१. समाजवादी राज्य की स्थापना और समाजवाद के निर्माण में उसकी भूमिका

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय के बाद मज़दूर वर्ग, सभी मेहनतकशों के समक्ष सोवियत राज्य के निर्माण, विकास और सुदृढ़ीकरण, मज़दूरों और ग़रीब किसानों के बीच सहबंध को मज़बूत बनाने, क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा करने, जातीय असमानता को दूर करने और समाजवादी उत्पादन संबंधों की स्थापना करने के कठिन कार्यभार प्रस्तुत हुए।

जनवरी १९१८ में सोवियतों की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 'श्रमजीवी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा' ने अक्तूबर क्रांति की उपलब्धियों और नयी राज्य-सत्ता की स्थापना को और मज़बूत बनाया। इस दस्तावेज़ ने रूस को मज़दूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों का जनतंत्र घोषित किया। केंद्रीय और स्थानीय समूची सत्ता सोवियतों के हाथों में थी। सोवियत जातीय जनतंत्रों के संघ के रूप में स्वतंत्र जातियों के स्वतंत्र संघ के आधार पर सोवियत रूसी जनतंत्र की घोषणा की गयी।

घोषणा ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का उन्मूलन करने, समाज में वर्ग-विभेद को समाप्त करने, शोषकों के सभी प्रतिरोधों को निर्मम-तापूर्वक दबाने और समाजवादी आधार पर समाज का संगठन करने के कार्यभारों का ऐलान किया। बाद में यह घोषणा सोवियतों की पांचवीं अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा १० जुलाई, १९१८ को स्वीकृत पहले सोवियत संविधान का अभिन्न अंग बन गयी।

रूस के मज़दूरों और किसानों के सामने नया राज्य और सामाजिक जीवन के नये रूप क़ायम करने की अविश्वसनीय कठिनाइयां थीं। दुनिया के पहले समाजवादी राज्य का निर्माण करना जन-क्रांति की विजय से कोई कम कठिन कार्यभार नहीं था। देश में तीव्र वर्ग संघर्ष चल रहा था। सत्ताच्युत वर्गों ने सोवियत राज्य द्वारा उठाये गये सभी क़दमों का अड़ियल ढंग से विरोध किया। क्रांति की कुछ बाद की मंज़िलों में मज़दूरों और किसानों के बीच अंतर्विरोध पैदा हो गये। मेंशेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों की टुटपुंजिया पार्टियों ने नये समाज के निर्माण का विरोध किया। लेकिन मुख्य कठिनाई यह थी कि समाजवाद का मार्ग अभी अज्ञात था। मज़दूरों और किसानों के राज्य में प्रशासनिक, आर्थिक, फ़ौजी, आदि निकायों को संगठित करने का कोई अनुभव नहीं उपलब्ध था। यह कठिनाई इसलिए और भी बढ़ गयी कि सोवियत राज्य शत्रुतापूर्ण पूंजीवादी दुनिया के घेरे में अकेले समाजवाद का निर्माण कर रहा था।

अक्तूबर क्रांति ने व्यापक जनसाधारण को जाग्रत कर दिया और उन्हें राजनीतिक कार्यकलाप में खींच लिया। विभिन्न कांग्रेसों, सम्मेलनों, सभाओं में उनकी बड़ी संख्या में भागीदारी ने उनकी क्रांतिकारी सक्रियता प्रकट की। लेनिन ने इस "सभाई जनवाद" को जनसाधारण द्वारा जीवन की नयी परिस्थितियों पर विचार-विमर्श का प्रारंभिक रूप, मज़दूरों और किसानों के राज्य के निर्माण तथा प्रशासन में पहला पग कहा।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि अपने हाथ में सत्ता लेनेवाला सर्वहारा वर्ग समाज के राजनीतिक आधार को आमूलचूल बदलने में समर्थ है।

पुरानी राजकीय मशीनरी का विनाश

पुरानी राजकीय मशीनरी को नष्ट करना तथा नये, सर्वहारा राजकीय तंत्र की स्थापना सोवियत सत्ता को मज़बूत बनाने की एक महत्वपूर्ण शर्त थी। लेनिन ने लिखा: "आज तक जितनी क्रांतियां हुई हैं उन्होंने राज्य की मशीनरी को सर्वांगपूर्ण बनाया है, जबकि ज़रूरत

है उसे नष्ट करने की, चकनाचूर करने की। यह निष्कर्ष राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत की मुख्य और बुनियादी चीज़ है।"* स्पष्ट है कि यहां चर्चा शोषक राज्य की सेना, पुलिस, अदालतों, जेलों और अन्य दंडात्मक तथा दमनात्मक संस्थाओं सहित बलप्रयोग की मशीनरी की है। लेनिन ने ज़ोर दिया कि क्रांति इस बात में नहीं है कि नया वर्ग **पुरानी** राजकीय मशीनरी के द्वारा कमान, संचालन करे, बल्कि इस बात में है कि वह इस मशीनरी को तोड़ दे और **नयी** मशीनरी के द्वारा कमान, संचालन करे।**

उत्पीड़नकारी बुर्जुआ राजकीय मशीनरी को नष्ट करना इसलिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम मेहनतकशों को पददलित तथा उनका दमन करने की साधन होती है और कि बुर्जुआ वर्ग उसका इस्तेमाल हमेशा जनगण की क्रांतिकारी कार्रवाई के खिलाफ़ करता है। पूंजीवादी राज्य के बलप्रयोग के निकायों का उपयोग नयी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में समाजवादी कार्यभागों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन्हें नष्ट कर देना चाहिए।

लेनिन ने ज़ोर दिया कि बलप्रयोग की बुर्जुआ राजकीय मशीनरी, पूंजीवाद की संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के विनाश का अर्थ बुर्जुआ समाज द्वारा स्थापित सभी राजकीय संस्थाओं से इन्कार नहीं है। बलप्रयोग की मशीनरी के साथ-साथ, जिसे बेशक नष्ट कर दिया जाना चाहिए, बुर्जुआ राज्य में आर्थिक प्रबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लेखा और सांख्यिकी (बैंक, सिंडीकेट, डाकखाने, रेलवे, आदि) से संबंधित संस्थाएं भी होती हैं। इन सभी संस्थाओं से शत्रुतापूर्ण तत्वों का सफ़ाया कर देना चाहिए, उन्हें पूंजीपतियों के नियंत्रण से हटाकर सोवियतों के नियंत्रण में रखना और समाजवादी सुधारों के हित में इस्तेमाल करना चाहिए।

बुर्जुआ राजकीय मशीनरी को नष्ट करने का अर्थ पुराने अधिकारियों को दंडित करना नहीं है। नयी सत्ता बुर्जुआ सरकार के केवल उन नौकरशाहों से पूछताछ करती, जिन्होंने जनगण के विरुद्ध अपराध किया

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'राज्य और क्रांति', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ७, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८४, पृ० ४४।

** वही, पृ० १३७।

था या उनके प्रति अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था। जब तक अधिकांश कर्मचारी क्रांतिकारी सरकार के प्रति वफ़ादार रहते हैं, तब तक वे पुनर्शिक्षा की अवधि से गुज़रते हुए नयी राजकीय सत्ता की मशीनरी में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं।

अक्तूबर १९१७ से १९१८ के वसंत तक रूस में बलप्रयोग की पुरानी राजकीय मशीनरी को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय और स्थानीय सोवियत सत्ता निकाय क़ायम किये जा रहे थे।

लेनिन ने इस संबंध में कहा : "संसार में पहली बार हमारे यहां, रूस में राजकीय सत्ता का इस तरह निर्माण हुआ है कि केवल मज़दूरों को लेकर, केवल मेहनतकश किसानों को लेकर – शोषकों को बाहर रखते हुए – जन-संगठन, सोवियतें बनी हैं और इन सोवियतों को सारी राजकीय सत्ता सौंपी गयी है।"*

सोवियतों और अन्य राजकीय निकायों की मशीनरी जनवादी सिद्धांतों के आधार पर क़ायम की गयी और उसने मेहनतकशों की इच्छा और हितों को व्यक्त किया। विख्यात क्रांतिकारियों, सुशिक्षित और अनुभवी लोगों को राजकीय सत्ता के प्रशासनिक कार्यों में लगाया गया। नयी, समाजवादी राजकीय मशीनरी के निर्माण और उसके रोज़मर्रा के कार्यकलाप में व्यापक जनसाधारण तथा सोवियत सत्ता के प्रति वफ़ादार पुराने कर्मचारियों को खींचा गया।

नयी राजकीय प्रणाली के निर्माण के लिए बहुविधि कार्यकलाप मज़दूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका को सुनिश्चित करने और कृषक वर्ग के साथ उसके सहबंध को सुदृढ़ करने के हित में चलाये गये।

समाजवादी रूपांतरणों के दौरान श्रमिक जनों की चेतना में मौलिक परिवर्तन आया, सामाजिक मामलों के निदेशन में अपनी क्षमता में विश्वास पैदा होकर दृढ़ होता गया। मज़दूरों और किसानों का राजकीय संचालन का कौशल बढ़ रहा था। ऐसे क्रांतिकारी स्कूल के बिना, राजकीय प्रशासन में मेहनतकशों द्वारा अनुभव प्राप्ति के बिना मज़दूरों और किसानों के राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती, उसे मज़बूत नहीं बनाया जा सकता।

---

* वही, खंड ८, पृ० ३१९।

अध्याय ६

समाजवादी जनवाद का विकास

१. समाजवादी राज्य की स्थापना और समाजवाद के निर्माण में उसकी भूमिका

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय के बाद मज़दूर वर्ग, सभी मेहनतकशों के समक्ष सोवियत राज्य के निर्माण, विकास और सुदृढ़ीकरण, मज़दूरों और ग़रीब किसानों के बीच सहबंध को मज़बूत बनाने, क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा करने, जातीय असमानता को दूर करने और समाजवादी उत्पादन संबंधों की स्थापना करने के कठिन कार्यभार प्रस्तुत हुए।

जनवरी १९१८ में सोवियतों की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 'श्रमजीवी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा' ने अक्तूबर क्रांति की उपलब्धियों और नयी राज्य-सत्ता की स्थापना को और मज़बूत बनाया। इस दस्तावेज़ ने रूस को मज़दूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों का जनतंत्र घोषित किया। केंद्रीय और स्थानीय समूची सत्ता सोवियतों के हाथों में थी। सोवियत जातीय जनतंत्रों के संघ के रूप में स्वतंत्र जातियों के स्वतंत्र संघ के आधार पर सोवियत रूसी जनतंत्र की घोषणा की गयी।

घोषणा ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का उन्मूलन करने, समाज में वर्ग-विभेद को समाप्त करने, शोषकों के सभी प्रतिरोधों को निर्मम-तापूर्वक दबाने और समाजवादी आधार पर समाज का संगठन करने के कार्यभारों का ऐलान किया। बाद में यह घोषणा सोवियतों की पांचवीं अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा १० जुलाई, १९१८ को स्वीकृत पहले सोवियत संविधान का अभिन्न अंग बन गयी।

रूस के मज़दूरों और किसानों के सामने नया राज्य और सामाजिक जीवन के नये रूप क़ायम करने की अविश्वसनीय कठिनाइयां थीं। दुनिया के पहले समाजवादी राज्य का निर्माण करना जन-क्रांति की विजय से कोई कम कठिन कार्यभार नहीं था। देश में तीव्र वर्ग संघर्ष चल रहा था। सत्ताच्युत वर्गों ने सोवियत राज्य द्वारा उठाये गये सभी क़दमों का अड़ियल ढंग से विरोध किया। क्रांति की कुछ बाद की मंज़िलों में मज़दूरों और किसानों के बीच अंतर्विरोध पैदा हो गये। मेंशेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों की टुटपुंजिया पार्टियों ने नये समाज के निर्माण का विरोध किया। लेकिन मुख्य कठिनाई यह थी कि समाजवाद का मार्ग अभी अज्ञात था। मज़दूरों और किसानों के राज्य में प्रशासनिक, आर्थिक, फ़ौजी, आदि निकायों को संगठित करने का कोई अनुभव नहीं उपलब्ध था। यह कठिनाई इसलिए और भी बढ़ गयी कि सोवियत राज्य शत्रुतापूर्ण पूंजीवादी दुनिया के घेरे में अकेले समाजवाद का निर्माण कर रहा था।

अक्तूबर क्रांति ने व्यापक जनसाधारण को जाग्रत कर दिया और उन्हें राजनीतिक कार्यकलाप में खींच लिया। विभिन्न कांग्रेसों, सम्मेलनों, सभाओं में उनकी बड़ी संख्या में भागीदारी ने उनकी क्रांतिकारी सक्रियता प्रकट की। लेनिन ने इस "सभाई जनवाद" को जनसाधारण द्वारा जीवन की नयी परिस्थितियों पर विचार-विमर्श का प्रारंभिक रूप, मज़दूरों और किसानों के राज्य के निर्माण तथा प्रशासन में पहला पग कहा।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि अपने हाथ में सत्ता लेनेवाला सर्वहारा वर्ग समाज के राजनीतिक आधार को आमूलचूल बदलने में समर्थ है।

पुरानी राजकीय मशीनरी का विनाश

पुरानी राजकीय मशीनरी को नष्ट करना तथा नये, सर्वहारा राजकीय तंत्र की स्थापना सोवियत सत्ता को मज़बूत बनाने की एक महत्वपूर्ण शर्त थी। लेनिन ने लिखा: "आज तक जितनी क्रांतियां हुई हैं उन्होंने राज्य की मशीनरी को सर्वांगपूर्ण बनाया है, जबकि ज़रूरत

है उसे नष्ट करने की, चकनाचूर करने की। यह निष्कर्ष राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत की मुख्य और बुनियादी चीज़ है।"* स्पष्ट है कि यहां चर्चा शोषक राज्य की सेना, पुलिस, अदालतों, जेलों और अन्य दंडात्मक तथा दमनात्मक संस्थाओं सहित बलप्रयोग की मशीनरी की है। लेनिन ने ज़ोर दिया कि क्रांति इस बात में नहीं है कि नया वर्ग **पुरानी** राजकीय मशीनरी के द्वारा कमान, संचालन करे, बल्कि इस बात में है कि वह इस मशीनरी को तोड़ दे और **नयी** मशीनरी के द्वारा कमान, संचालन करे।**

उत्पीड़नकारी बुर्जुआ राजकीय मशीनरी को नष्ट करना इसलिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम मेहनतकशों को पददलित तथा उनका दमन करने की साधन होती है और कि बुर्जुआ वर्ग उसका इस्तेमाल हमेशा जनगण की क्रांतिकारी कार्रवाई के खिलाफ़ करता है। पूंजीवादी राज्य के बलप्रयोग के निकायों का उपयोग नयी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में समाजवादी कार्यभागों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन्हें नष्ट कर देना चाहिए।

लेनिन ने ज़ोर दिया कि बलप्रयोग की बुर्जुआ राजकीय मशीनरी, पूंजीवाद की संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के विनाश का अर्थ बुर्जुआ समाज द्वारा स्थापित सभी राजकीय संस्थाओं से इन्कार नहीं है। बलप्रयोग की मशीनरी के साथ-साथ, जिसे बेशक नष्ट कर दिया जाना चाहिए, बुर्जुआ राज्य में आर्थिक प्रबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लेखा और सांख्यिकी (बैंक, सिंडीकेट, डाकखाने, रेलवे, आदि) से संबंधित संस्थाएं भी होती हैं। इन सभी संस्थाओं से शत्रुतापूर्ण तत्वों का सफ़ाया कर देना चाहिए, उन्हें पूंजीपतियों के नियंत्रण से हटाकर सोवियतों के नियंत्रण में रखना और समाजवादी सुधारों के हित में इस्तेमाल करना चाहिए।

बुर्जुआ राजकीय मशीनरी को नष्ट करने का अर्थ पुराने अधिकारियों को दंडित करना नहीं है। नयी सत्ता बुर्जुआ सरकार के केवल उन नौकरशाहों से पूछताछ करती, जिन्होंने जनगण के विरुद्ध अपराध किया

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'राज्य और क्रांति', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ७, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८४, पृ० ४४।

** वही, पृ० १३७।

था या उनके प्रति अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था। जब तक अधिकांश कर्मचारी क्रांतिकारी सरकार के प्रति वफ़ादार रहते हैं, तब तक वे पुनर्शिक्षा की अवधि से गुज़रते हुए नयी राजकीय सत्ता की मशीनरी में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं।

अक्तूबर १९१७ से १९१८ के वसंत तक रूस में बलप्रयोग की पुरानी राजकीय मशीनरी को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय और स्थानीय सोवियत सत्ता निकाय क़ायम किये जा रहे थे।

लेनिन ने इस संबंध में कहा: "संसार में पहली बार हमारे यहां, रूस में राजकीय सत्ता का इस तरह निर्माण हुआ है कि केवल मज़दूरों को लेकर, केवल मेहनतकश किसानों को लेकर – शोषकों को बाहर रखते हुए – जन-संगठन, सोवियतें बनी हैं और इन सोवियतों को सारी राजकीय सत्ता सौंपी गयी है।"*

सोवियतों और अन्य राजकीय निकायों की मशीनरी जनवादी सिद्धांतों के आधार पर क़ायम की गयी और उसने मेहनतकशों की इच्छा और हितों को व्यक्त किया। विख्यात क्रांतिकारियों, सुशिक्षित और अनुभवी लोगों को राजकीय सत्ता के प्रशासनिक कार्यों में लगाया गया। नयी, समाजवादी राजकीय मशीनरी के निर्माण और उसके रोज़मर्रा के कार्यकलाप में व्यापक जनसाधारण तथा सोवियत सत्ता के प्रति वफ़ादार पुराने कर्मचारियों को खींचा गया।

नयी राजकीय प्रणाली के निर्माण के लिए बहुविधि कार्यकलाप मज़दूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका को सुनिश्चित करने और कृषक वर्ग के साथ उसके सहबंध को सुदृढ़ करने के हित में चलाये गये।

समाजवादी रूपांतरणों के दौरान श्रमिक जनों की चेतना में मौलिक परिवर्तन आया, सामाजिक मामलों के निदेशन में अपनी क्षमता में विश्वास पैदा होकर दृढ़ होता गया। मज़दूरों और किसानों का राजकीय संचालन का कौशल बढ़ रहा था। ऐसे क्रांतिकारी स्कूल के बिना, राजकीय प्रशासन में मेहनतकशों द्वारा अनुभव प्राप्ति के बिना मज़दूरों और किसानों के राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती, उसे मज़बूत नहीं बनाया जा सकता।

---

* वही, खंड ८, पृ० ३१९।

नये राज्य का निर्माण। राजनीतिक और सामाजिक रूपांतरण

अक्तूबर क्रांति की विजय के शीघ्र बाद सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस ने सोवियत राजकीय सत्ता के सर्वोच्च निकाय – अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और जन कमिसार परिषद – क़ायम किये।

कार्यकारिणी समिति सोवियतों की कांग्रेसों के बीच राजकीय सत्ता का सर्वोच्च निकाय थी। वह सोवियत सरकार के आदेशों पर विचार और उनकी पुष्टि करती थी, सरकार और जन कमिसारों की रिपोर्टें सुनती थी। कई प्रश्नों पर उसने जन कमिसार परिषद के साथ संयुक्त आज्ञप्तियां जारी कीं।

जन कमिसार परिषद राजकीय सत्ता का सर्वोच्च कार्यकारी और प्रशासनिक निकाय थी। उसने जन कमिसारियतों और अन्य केंद्रीय निकायों के कार्यकलाप का निदेशन किया तथा स्थानीय निकायों के कार्यकलाप का मार्गदर्शन और नियंत्रण किया। कार्यकारिणी समिति के साथ उसे आज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार भी था।

इसके साथ ही सोवियत सत्ता के स्थानीय निकाय भी क़ायम किये गये। जब तक स्थानीय सत्ता की नयी प्रणाली क़ायम नहीं हो गयी, तब तक सोवियतों के साथ-साथ पुराने सत्ता निकाय भी बने रहे। ये निकाय दूमा और ज़ेम्स्त्वो (नगरपालिका) थे, जो अधिकांशतः बुर्जुआ अस्थायी सरकार के तहत चुने गये थे तथा धनी वर्गों के प्रतिनिधियों से बने थे। लेकिन सोवियतें उनके कामों पर नियंत्रण रखती थीं। जनवरी १९१८ तक मज़दूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतें देश में राजकीय सत्ता के पूर्ण अधिकारप्राप्त निकाय बन गयीं। सरकार ने निर्वाचकों को उनके विश्वास को सही सिद्ध न करनेवाले प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करते हुए एक आज्ञप्ति स्वीकृत की, जिसने सोवियतों में घुस आये शत्रुतापूर्ण लोगों का सफ़ाया करना संभव बनाया।

बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में सोवियतों ने नयी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा काम किया और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी। उन्होंने प्रतिक्रांतिकारियों से संघर्ष किया, स्थानीय अर्थव्यवस्था संगठित की, उद्योग का

राष्ट्रीयकरण किया, ट्रेड-यूनियनों के साथ मिलकर मेहनतकशों की जीवन परिस्थितियां सुधारीं, खाद्य-पदार्थों के वितरण का विनियमन किया और स्वास्थ्य तथा शिक्षा संस्थानों के कार्य का निदेशन किया।

सोवियतों के काम में भाग लेते हुए लाखों मेहनतकशों ने सोवियत राज्य का निर्माण किया और अभूतपूर्व पहल तथा क्रांतिकारी सृजनशीलता प्रदर्शित करते हुए उसका प्रशासन करना सीखा। इसी में सोवियतों – विश्व इतिहास में मज़दूरों और किसानों की पहली सत्ता – की शक्ति निहित थी।

क्रांति के शत्रुओं ने आशा लगा रखी थी कि बोल्शेविकों को जटिल राजकीय मशीनरी को चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मी नहीं मिलेंगे। इस क्षेत्र में कठिनाइयां वास्तव में बड़ी थीं, लेकिन पार्टी और लेनिन को मालूम था, उन्हें विश्वास था कि मेहनतकशों के बीच से ऐसे संगठनकर्ता आयेंगे, जो राजकीय प्रशासन के मामलों में पारंगत होने में समर्थ होंगे।

लेनिन ने लिखा: "हमारे पास राजकीय मशीनरी को एक कलम में **दसगुना बढ़ा लेने** का एक जादुई ज़रिया भी है, जैसा किसी पूंजीवादी राज्य के पास न कभी था और न कभी हो सकता है। यह जादुई ज़रिया है राज्य के दिन प्रतिदिन के शासन-कार्य में मेहनतकशों को, ग़रीबों को शरीक करना।"*

राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में पहले समाजवादी रूपांतरण करने के साथ-साथ सोवियत सत्ता ने ऐसे जनवादी रूपांतरण भी पूरे किये, जो फ़रवरी बुर्जुआ-जनवादी क्रांति द्वारा किये जाने थे, लेकिन जिन्हें उसने नहीं किया। ख़ास तौर से अभिजात वर्ग, पादरी वर्ग, व्यापारी, टुटपुंजिया वर्ग में श्रेणीगत विभाजन जैसे सामंती अवशेषों का उन्मूलन कर दिया गया। संपूर्ण आबादी के लिए एक सामान्य नाम – रूसी सोवियत जनतंत्र के नागरिक – दिया गया। सिविल विवाह लागू किया गया। चर्च में विवाह नागरिकों का निजी मामला घोषित किया गया। चर्च को राज्य से और स्कूल को चर्च से पृथक् कर दिया गया। सभी जातीय असमानताएं समाप्त कर दी गयीं।

नारियों की असमानता की सभी अभिव्यक्तियों को पूरी तरह दूर

---

* वही, पृ० २७३।

करना और उन्हें सक्रिय सामाजिक कार्यों में खींचना नये समाजवादी समाज के निर्माण की पेचीदा सामाजिक समस्या थी।

नारियों को मुक्त किये बिना और उत्पादन तथा सामाजिक कार्य-कलापों में उनकी समान भागीदारी के बिना समाजवादी जनवाद पर अमल करना, बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करना असंभव था।

सोवियत सत्ता की स्थापना के बाद नारियों की असमानता के सभी चिह्न धीरे-धीरे मिटा दिये गये। राजकीय सत्ता के सभी निकायों के लिए चुनने और चुने जाने तथा प्रशासनिक और आर्थिक निकायों में कोई भी पद प्राप्त करने के लिए स्त्री-पुरुषों के समान अधिकार के बारे में क़ानून स्वीकार किया गया। समान श्रम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को सुसंगत रूप से कार्यान्वित किया गया। सोवियत राज्य ने उत्पादन में लगी स्त्रियों की स्वास्थ्य रक्षा और जच्चा-बच्चों की राज-कीय रक्षा की व्यवस्था करते हुए क़ानून स्वीकृत किये। उसने न केवल जच्चा-बच्चों की क़ानूनी रक्षा को सुनिश्चित किया, बल्कि उनके हितों की रक्षा के लिए भौतिक ज़मानतें भी दीं। उसने जच्चा-बच्चा केंद्र, प्रसूति परामर्श केंद्र क़ायम किये, विभिन्न भत्ते प्रदान किये तथा सार्व-जनिक खान-पान सेवाएं संगठित कीं, जिन्होंने स्त्रियों के जीवन को अधिक आसान बना दिया।

सरकार और सार्वजनिक संगठनों ने स्त्रियों को उद्योग में खींचा और सुदक्षताएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। १९२९ में औद्योगिक श्रमिकों की कुल संख्या में स्त्रियों का हिस्सा ३४.२ प्रतिशत था। १९२८ में स्थानीय सोवियतों के लिए चुने गये प्रतिनिधियों की कुल संख्या में महिला प्रतिनिधियों का हिस्सा २६ प्रतिशत था।

सोवियत पूर्व की नारियों को मुक्त कराने के लिए बड़ा कार्य किया गया, जहां औरतें अधिकारविहीन, क्रय-विक्रय की वस्तु थीं।

सोवियत सत्ता के निकायों और सार्वजनिक संगठनों ने स्त्रियों के बीच व्यापक राजनीतिक और शैक्षिक कार्य चलाये। नवम्बर १९१८ में महिला मज़दूरों और महिला किसानों की पहली अखिल रूसी कांग्रेस का आयोजन हुआ। उसने नारियों की वास्तविक मुक्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबद्ध महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श किया। कांग्रेस में लेनिन ने भाषण किया, जिसमें उन्होंने ज़ोर दिया कि "तब तक

कोई समाजवादी कायापलट् नहीं हो सकता जब तक कि मेहनतकश औरतों का एक बड़ा भाग उसमें हिस्सा न ले"*। क्रांति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें महिलाएं कितनी सक्रियता से भाग लेती हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय संगठनों में क़ायम विशेष विभागों ने मेहनतकश औरतों को बड़ी व्यावहारिक सहायता प्रदान की। इन विभागों के तहत कार्यरत महिला प्रतिनिधियों ने बड़े संगठनात्मक, राजनीतिक और शैक्षिक कार्य चलाये। उन्होंने काम पाने, रोज़मर्रा के जीवन की जटिल कठिनाइयों को हल करने, शिक्षा और नागरिक सक्रियता बढ़ाने में महिलाओं की सहायता की।

पूर्व में विशेष महिला क्लब बनाये गये, जहां शैक्षिक कार्यों और साक्षरता कोर्सों के अलावा उन्होंने ऐसे औद्योगिक व्यवसायों में पारंगत होने में औरतों की सहायता की, जो उनके लिए बिल्कुल नये थे।

ग़ैर-रूसी जातियों के उत्पीड़न और असमानता का उन्मूलन अक्तूबर क्रांति की एक महान उपलब्धि थी।**

जातीय प्रश्न पर अपने सभी दस्तावेज़ों में सोवियत सरकार ने रूस की जातियों की पूर्ण मुक्ति तथा उन्हें ग़ुलाम बनाने की शर्मनाक नीति के स्थान पर महान मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित स्वैच्छिक और सच्चे सहबंध में जातियों को एकजुट करने की नयी नीति की घोषणा की।

क्रांति की रक्षा के निकायों की स्थापना

समाजवादी राज्य का निर्माण तीव्र वर्ग संघर्ष में हो रहा था। सत्ताच्युत वर्गों – ज़मींदारों, पूंजीपतियों और कुलकों – ने नयी सत्ता का कड़ा प्रतिरोध किया। समाजवादी क्रांति की विजय के पहले दिनों में ही उन्होंने अपनी सत्ता बहाल करने की कोशिश की, अनेकानेक षड्यंत्र,

---

* व्ला० इ० लेनिन, मेहनतकश औरतों की पहली अखिल रूसी कांग्रेस में दिया गया भाषण, २६ नवम्बर, १६१८।

** देखें अध्याय ७।

विद्रोह, उकसावे, तोड़-फोड़ संगठित किये तथा नयी सत्ता के खिलाफ़ लांछन अभियान छेड़ दिया।

मंत्रालयों और संस्थाओं के नौकरशाहों तथा कर्मचारियों ने खुली तोड़-फोड़ की नीति चलायी। उन्होंने घोषणा की कि वे सोवियत सत्ता को नहीं मानते और इस्तीफ़ा दे दिया। तोड़-फोड़ को भड़कानेवालों ने सामाजिक जीवन को अराजकतापूर्ण और अस्त-व्यस्त बनाने, उत्पादन को कच्चे माल से, नगरों को रोटी से वंचित करने की कोशिश की। तोड़-फोड़ करनेवालों में कुछ अध्यापक, डाक्टर तथा अन्य पेशेवर लोग भी शामिल थे।

विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए क्रांति की रक्षा सोवियत राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बन गयी। प्रतिक्रांति के दमन के लिए दृढ़ कार्रवाइयां की गयीं। नवम्बर १९१७ में जन कमिसार परिषद ने अदालतों पर एक आज्ञप्ति की घोषणा की। अदालतों और प्रोक्यूरेटरों की पुरानी प्रणाली समाप्त कर दी गयी, न्यायाधीशों और असेसरों की नियुक्ति निर्वाचन के आधार पर की जाने लगी, अदालतों की सुनवाई खुले रूप में होने लगी, प्रतिवादी को क़ानूनी सहायता का अधिकार दिया गया, आदि। बुर्जुआ पुलिस के स्थान पर मज़दूर-किसान मिली-शिया क़ायम की गयी।

दिसम्बर १९१७ में प्रतिक्रांति, तोड़-फोड़ और मुनाफ़ाखोरी से निपटने के लिए एक विशेष निकाय – अखिल रूसी असाधारण आयोग (चेका) – क़ायम किया गया। लेनिन के सुझाव पर फ़ेलिक्स द्ज़ेर्जीन्स्की उसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये। वह एक अनुभवी, अडिग और निडर क्रांतिकारी, अनिन्द्य रूप से ईमानदार व्यक्ति थे तथा भूमिगत कार्य और ज़ारशाही के कठोर कारावास की अग्निपरीक्षाओं से गुज़र चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने चेका में जांचे-परखे बोल्शेविकों को भेजा था। उसने पार्टी की केंद्रीय समिति के सीधे निदेशन में काम किया। क्रांति के शत्रुओं से अनम्य संघर्ष और साथ ही मानवीयता तथा न्याय चेका कर्मियों के अनिवार्य सिद्धांत थे। अपने कार्यकलाप में चेका व्यापक मेहनतकश जनसाधारण पर आश्रित था, इसी में उसकी शक्ति थी।

सोवियत सत्ता ने गृहयुद्ध न भड़कने देने की कोशिश की और अपने शत्रुओं के प्रति उदारता का रुख तक अपनाया। मिसाल के लिए, अस्थायी सरकार के सभी भूतपूर्व मंत्रियों को पैरोल पर छोड़ दिया गया,

ज़ारशाही के जनरल कोर्नीलोव को, जिसने अगस्त १९१७ में प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह संगठित किया था, गोली नहीं मारी गयी।

इसके बावजूद प्रतिक्रांतिकारियों ने सर्वहारा सत्ता के मानवीय रुख़ की उपेक्षा की और आतंकवाद का रास्ता अपनाया। १ जनवरी, १९१८ को उन्होंने लेनिन की हत्या करने का प्रयास किया। आतंकवादियों के गिरोह ने उनकी कार पर गोलियां चलायीं। गोलियां कार पर कई जगह लगीं, उसकी खिड़कियों के शीशे टूट गये। सौभाग्य से लेनिन बाल-बाल बच गये। जून १९१८ में अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्षमंडल के सदस्य, प्रेस, आंदोलन और प्रचार के कमिसार व० वोलोदार्स्की की हत्या कर दी गयी। ६-७ जुलाई, १९१८ को वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने मास्को में विद्रोह भड़का दिया। उन्होंने मास्को स्थित जर्मन राजदूत काउंट मिरबाख़ की हत्या करके विद्रोह का संकेत दिया। सोवियत सत्ता के इन शत्रुओं ने इसके ज़रिये जर्मनी और सोवियत जनतंत्र के बीच युद्ध भड़काने की योजना बनायी थी। जुलाई १९१८ में अनेक विदेशी दूतावासों और श्वेत रक्षकों की सहायता से समाजवादी-क्रांतिकारियों ने मध्य रूस के २३ नगरों में सोवियत-विरोधी विद्रोह संगठित किये। ये सभी विद्रोह तेज़ी से कुचल दिये गये क्योंकि उनके नेताओं – वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों – को मेहनतकश जनसाधारण का समर्थन नहीं प्राप्त था।

अक्तूबर क्रांति की विजय के बाद के पहले महीनों में मास्को और दूसरे नगरों में प्रतिक्रांतिकारी अराजकतावादी संगठनों के जाल का भंडाफोड़ किया गया। रूस में विदेशी राज्यों के दूतों के समर्थन से सोवियत सत्ता के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचनेवाले कुछ अन्य प्रतिक्रांतिकारी संगठनों का भी पर्दाफ़ाश और उन्मूलन किया गया।

३० अगस्त, १९१८ की सुबह को पेत्रोग्राद असाधारण आयोग के अध्यक्ष मोइसेई उरीत्स्की की हत्या कर दी गयी। उसी दिन शाम को लेनिन की हत्या करने का भी प्रयास किया गया। उस दिन लेनिन मास्को के मिख़ेल्सोन कारख़ाने (आजकल व्लादीमिर इल्यीच नामक कारख़ाना) के मज़दूरों के समक्ष भाषण करने आये थे। सभा के बाद, जब लेनिन अपनी कार की ओर जा ही रहे थे कि समाजवादी-क्रांतिकारी आतंकवादी काप्लान ने उनपर गोली चलाकर बुरी तरह से घायल कर दिया। क्रांति के नेता की हत्या करने के इस घिनौने प्रयास ने सारे

देश को दहला दिया। प्रतिक्रांतिकारी तत्वों ने सोवियत सत्ता से संघर्ष की व्यापक योजना बनायी थी।

प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों के इस श्वेत आतंक के जवाब में ५ सितम्बर, १९१८ को सोवियत सरकार ने "लाल आतंक के बारे में" एक प्रस्ताव स्वीकार किया। यह प्रतिक्रांति के विरुद्ध अपनी रक्षा करने का क्रांति का पवित्र अधिकार था।

मेंशेविकों और समाजवादी-क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने बुर्जुआ प्रति-क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सोवियत सत्ता के ख़िलाफ़ काम किया, चेका और क्रांतिकारी अदालत की स्थापना पर शोरगुल मचाया। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी पर "आतंकवाद" और "गृहयुद्ध" शुरू करने का दोष लगाया। इसका उत्तर देते हुए लेनिन ने कहा: "अगर हमारा कोई अपराध है तो वह यह कि हम बुर्जुआ साम्राज्यवादी प्रणाली के दानवीय रूप से विश्वासघाती प्रतिनिधियों के प्रति अत्यधिक मानवीय, अत्यधिक नेक थे।"*

फ़ेलिक्स द्ज़ेर्जीन्स्की के नेतृत्व में चेका कर्मियों ने प्रतिक्रांति के ख़तरनाक केन्द्रों को नष्ट कर दिया। सर्वहारा अधिनायकत्व के राज्य ने बड़ी कठिनाई से जीती जनता की स्वतंत्रता को सत्ताच्युत शोषकों के एक छोटे-से गिरोह के अतिक्रमण से दृढ़तापूर्वक बचाने में गहन मानवतावाद तथा सच्चा जनवाद प्रदर्शित किया।

विदेशी शत्रुओं और घरेलू प्रतिक्रांति से क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा करने के लिए सोवियत राज्य और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण करना आरंभ किया।

सर्वहारा अधिनायकत्व का सार और कार्यभार

महान अक्तूबर क्रांति की विजय ने पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के काल का सूत्रपात किया। समाजवादी क्रांति मज़दूर वर्ग की सत्ता की स्थापना करती है, जो अन्य मेहनतकश संस्तरों के साथ उसके सहबंध

---

* व्ला० इ० लेनिन, मज़दूरों, सैनिकों और किसानों की सोवियतों की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस में किया गया भाषण, २५ जनवरी, १९१८।

पर आधारित होती है। फलस्वरूप नये राज्य, मज़दूरों और किसानों के राज्य, सर्वहारा अधिनायकत्व के राज्य की स्थापना होती है। अपने ऐतिहासिक स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से यह सर्वथा नये प्रकार का राज्य होता है। सर्वहारा अधिनायकत्व ऐतिहासिक रूप से नियमसंगत है और सर्वहारा के वर्ग उद्देश्यों, उसके विश्वव्यापी ध्येय – पूंजीवाद का, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण तथा सामाजिक और जातीय उत्पीड़न के सभी रूपों का उन्मूलन – को पूरा करने के लिए आवश्यक है। रूस में सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना जनगण के सशस्त्र विद्रोह के ज़रिये संपन्न समाजवादी क्रांति के परिणामस्वरूप हुई। लेकिन कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों में सर्वहारा अधिनायकत्व, अर्थात मेहनतकशों की सत्ता की स्थापना समाजवादी क्रांति के शांतिपूर्ण विकास के परिणामस्वरूप भी हो सकती है। रूस में सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना सोवियत जनतंत्र के रूप में हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनेक देशों में सर्वहारा अधिनायकत्व का एक नया रूप – लोक जनवाद – अस्तित्व में आया।

पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि उग्र वर्ग संघर्षों से भरी होती है। सत्ताच्युत शोषक वर्ग अपने प्रभुत्व की बहाली के लिए उन्मादपूर्वक प्रतिरोध करते हुए जीतोड़ कोशिश करते हैं। इसके अलावा, जैसा लेनिन ने उल्लेख किया, सत्ता से वंचित बुर्जुआ वर्ग अब भी अपने कुछ लाभों को बनाये रखता है और कुछ समय तक वह उसे उलटनेवाले सर्वहारा वर्ग से शक्तिशाली बना रहता है। बुर्जुआ वर्ग अब भी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के साथ संबंध रखता है, अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ बनाये रखता है, उसके पास पैसा, अनुभव और शिक्षा होती है, उसके पास संगठन और प्रबंध के तरीक़ों की जानकारी, विशेषज्ञ, आदि होते हैं। शोषक इन लाभों का इस्तेमाल मेहनतकशों की सत्ता को उलट देने के लिए करते हैं।

इसलिए सर्वहारा अधिनायकत्व का राज्य अपने विकास की पहली मंज़िल में सत्ताच्युत शोषक वर्गों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए विवश होता है ताकि नयी सत्ता को सुदृढ़ बनाया जा सके। सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के कड़े प्रतिरोध के उत्तर में बलप्रयोग का सहारा लेता है। क्रांतिकारी विकास को पीछे मोड़ने का प्रयास करनेवाले विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध भी बलप्रयोग संभव है।

क्रांतिकारी बलप्रयोग अपने विकास की निश्चित अवधियों में क्रांति की आवश्यक और नियमसंगत कार्रवाई है, लेकिन "सर्वहारा जनसाधारण का संगठन, मेहनतकशों का संगठन इस क्रांति की बहुत अधिक गहन और स्थायी विशिष्टता तथा उसकी विजय की शर्त था और बना रहता है"*।

बुर्जुआ वर्ग के आक्रमण को विफल करने के साथ सर्वहारा अधिनायकत्व अपने मुख्य कार्यभार – नये समाज का निर्माण संगठित करना, नये सामाजिक संबंध विकसित करना, उत्पादक शक्तियों का विकास और श्रम उत्पादकता की वृद्धि सुनिश्चित करना – को प्राथमिकता प्रदान करने लगा। इन कार्यभारों को पूरा करने के लिए मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण, शोषक वर्गों और जातीय उत्पीड़न को समाप्त करना, मेहनतकश जनसाधारण के जीवन और सांस्कृतिक स्तरों को ऊंचा उठाना तथा नये मानव का विकास करना आवश्यक था। इसी की ख़ातिर समाजवादी क्रांति संपन्न की जाती है और मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में मेहनतकशों की सत्ता की स्थापना की जाती है।

समाजवादी समाज के निर्माण के अपने मुख्य कार्यभार को पूरा करते हुए सोवियत सत्ता ने अर्थव्यवस्था को संगठित और निर्मित करने, संस्कृति और शिक्षा को विकसित करने के लिए बड़ा कार्य चलाया।

लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, उनकी भौतिक स्थिति को बेहतर बनाने, ग़रीबी, सामाजिक असमानता मिटाने के प्रति हित-चिंता सोवियत सत्ता का एक महत्वपूर्ण कार्यभार था।

केवल इन कार्यों को पूरा करने के बाद ही पुराने समाज के स्थान पर नये, समाजवादी समाज की स्थापना की जा सकती थी। अधिकांश जनता के नाम पर शासन करते हुए नये राज्य ने समाजवाद के निर्माण, राजकीय और सामाजिक मामलों के प्रबंध में व्यापक जनसाधारण की भागीदारी को सुनिश्चित बनाया। इसी में सर्वोच्च प्रकार का जनवाद अपनी अभिव्यक्ति पाता है।

मेहनतकश जनसाधारण ने, जो पहले की सभी क्रांतियों में पुराने सामाजिक संबंधों को केवल नष्ट कर सके थे, पहली बार मज़दूर वर्ग

* व्ला० इ० लेनिन, अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के विशेष अधिवेशन में य० म० स्वेर्दलोव की स्मृति में भाषण, १८ मार्च, १९१९।

के नेतृत्व में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए रचनात्मक कार्य-कलाप में भाग लिया।

नये राज्य में राजनीतिक नेतृत्व करनेवाला मज़दूर वर्ग नये समाज का निर्माण अकेले ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसने पहले ग़रीब किसानों और फिर बाद में सभी मेहनतकश किसानों से सहबंध का सहारा लिया। लेनिन ने एकाधिक बार ज़ोर दिया कि सर्वहारा का अधिनायकत्व सर्वहारा वर्ग – मेहनतकशों के हरावल – और अनेक ग़ैर-सर्वहारा संस्तरों के बीच वर्गीय सहबंध का एक विशेष रूप है। मज़दूर और किसान सोवियत समाज में दो मुख्य वर्ग थे और उनके सुदृढ़ सहबंध पर सोवियत सरकार का भाग्य निर्भर करता था।

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को कोटि-कोटि किसानों और छोटे मालिकों, लाखों कर्मचारियों, नौकरशाहों, बुर्जुआ बुद्धिजीवियों को पुनर्शिक्षित करना तथा पुरानी आदतों और परंपराओं से मुक्त होने में उनकी सहायता करना था।

इसके साथ ही स्वयं मज़दूरों को भी पुनर्शिक्षित करना, उनके टुटपुंजिया पूर्वाग्रहों पर क़ाबू पाने में सहायता करना, सभी श्रमिकों की चेतना में मौलिक परिवर्तन सुनिश्चित करना, श्रम और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति नया रुख़ विकसित करना, श्रम अनुशासन को सुदृढ़ करना तथा उनकी सक्रियता, रचनात्मकता और पहल बढ़ाने में सहायता करना आवश्यक था।

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अंतर्वस्तु को प्रकट करते हुए लेनिन ने उसके बहुविध कार्यभारों को दिखाया: "सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व पुराने समाज की शक्तियों और परंपराओं के ख़िलाफ़ अनवरत संघर्ष है – ख़ूनी और रक्तहीन, हिंसापूर्ण और शांतिमय, सैनिक और आर्थिक, शैक्षिक और प्रशासनिक।"*

अतः सर्वहारा अधिनायकत्व का मुख्य ध्येय देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबंधों और संस्कृति को समाजवादी आधारों पर रूपांतरित करना है। इस ध्येय – समाजवाद के निर्माण के ध्येय – के पूरा होने

---

* व्ला० इ० लेनिन, '"वामपंथी कम्युनिज़्म" – एक बचकाना मर्ज़', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ६, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८५, पृ० २७८।

पर सर्वहारा अधिनायकत्व का ऐतिहासिक ध्येय पूरा हो जाता है और वह अपना स्थान संपूर्ण जनगण के राज्य को दे देता है।

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और जनवाद

बुर्जुआ राजनीतिज्ञ और प्रचारक सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का चित्रण ऐसे करते हैं जैसे कि उसमें बलप्रयोग का ही राज हो, जैसे कि वह एक अजनवादी राज्य हो। नयी सत्ता के सार की इस दुर्भावनापूर्ण तोड़-मरोड़ का उद्देश्य वास्तविक समाजवाद की आकर्षण-शक्ति को कमज़ोर बनाना है।

जनसाधारण सदियों से राजनीतिक स्वतंत्रताओं और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष चलाते आ रहे हैं। लेकिन शोषक समाज में घोषित जनवादी सिद्धांत मूलत: प्रभुत्वशाली वर्ग की ही सेवा करते हैं। इतिहास में पहली बार समाजवाद ने जन-सत्ता, समानता और स्वाधीनता के सिद्धांतों पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था के युगों पुराने सपने को साकार कर दिया है।

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की वैज्ञानिक, वस्तुगत धारणा के दो पहलू हैं: पहला, मेहनतकशों के लिए, यानी अधिसंख्य आबादी के लिए व्यापक जनवाद और समाजवाद के निर्माण के दौरान मज़दूर वर्ग द्वारा इन मेहनतकशों का राजकीय निदेशन; दूसरा, सत्ताच्युत वर्गों, यानी अल्पसंख्य आबादी पर राजनीतिक प्रभुत्व। इसी वजह से लेनिन ने संक्रमण काल के राज्य को "**नये ढंग** का जनवादी (सर्वहारा वर्ग और आम तौर से संपत्तिहीनों के लिए) और **नये ढंग** का अधिनाय-कीय (बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध)"* राज्य कहा।

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व, अर्थात मज़दूर वर्ग के राजनीतिक प्रभुत्व और जनवाद के बीच एक सहज संबंध है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्वयं जनवाद का सर्वोच्च रूप है। मज़दूर वर्ग और अन्य सभी मेहनतकशों के संयुक्त प्रयासों, यानी जनवादी कार्रवाई से ही समाजवाद के शत्रुओं का दमन तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व

---

* वही, खंड ७, पृ० ५२।

के कार्यभारों को पूरा किया जा सकता है।

मजदूरों और अन्य सभी मेहनतकश जनसाधारण के बीच सहबंध जनवादी तरीक़ों – समझाने-बुझाने, स्पष्टीकरण, सांगठनिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्य, श्रमिक जनसमुदाय के हित में आर्थिक नीति के अनुसरण – से प्राप्त किया जाता है। यह सब सोवियत राज्य को जनता का राज्य कहलाने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।

काउत्स्की तथा अन्य मार्क्सवादी ग़द्दारों ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के स्थान पर तथाकथित "शुद्ध जनवाद", सबके लिए सुविधाजनक जनवाद रखने की कोशिश की। लेनिन ने इसे "लफ़्फ़ाज़ी" कहा। वर्गीय समाज में जनवाद केवल वर्गीय ही हो सकता है। अमूर्त जनवाद नहीं होता, क्योंकि वह वर्ग-विशेष के हित में सत्ता के प्रयोग की एक विधि है।

शब्दश: अर्थ में जनवाद का मतलब जन-सत्ता है। इसका तात्पर्य यह कि सत्ता वास्तव में जनता के हाथों में या कम से कम उसके बहुमत के हाथों में हो और जनसाधारण, यानी मेहनतकश लोग उसका प्रयोग करते हों, और कि इस समाज के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हों चाहे उनकी जातीयता, लिंग, धर्म और सांपत्तिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो।

सोवियत सत्ता की शक्ति और सुदृढ़ता इस बात में है कि वह व्यापक जनसाधारण के लिए जनवाद को शोषकों के ख़िलाफ़ सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी अधिनायकत्व से संयुक्त करती है। इसीलिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, जिसने जनता के लिए जनवाद का विस्तार किया और जनसत्ता को वास्तव में कार्यान्वित किया, जनवाद का सर्वोच्च रूप है।

समाज में कोई भी सामाजिक परिघटना "शुद्ध रूप" में नहीं होती। समाजवाद – यह जनवाद है। लेकिन उसका विकास पुराने समाज से होता है। लेकिन जैसे ही समाजवाद का अभ्युदय होता है, वह आंतरिक और विदेशी शत्रुओं से अपनी रक्षा करने को विवश हो जाता है। उसे विगत के अवशेषों – सामाजिक असमानता, जातीय कलह, स्वार्थवाद, धनलोलुपता, सत्तालोलुपता और पूंजीवाद के बहुत से अन्य दोषों – पर क़ाबू पाना होता है। इसी वजह से नयी प्रणाली रातों-रात

वैसी नहीं बन जाती, जैसी कि चाही जाती है।

जनवाद के बिना समाजवादी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। राजकीय प्रशासन और सामाजिक जीवन में मेहनतकश जन-साधारण की व्यापक तथा सक्रिय भागीदारी, मज़दूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों की बढ़ती पहल और सृजनात्मक प्रयास से ही समाजवाद के सफल निर्माण को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाजवाद की विजय जनवाद के सर्वतोमुखी विकास की आवश्यक शर्त है। अपनी बारी में जनवाद समाजवाद के विकास की आवश्यक शर्त है, जो समाजवाद के निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार है। जनवाद का गहनीकरण और विस्तार समाजवादी राज्य की राजनीतिक प्रणाली के विकास का एक वस्तुगत नियम है।

अपने विकास की प्रारंभिक अवधि में सोवियत राज्य को जनवाद को कुछ सीमित करना पड़ा था। इसे सत्ताच्युत शोषक वर्गों के विकट प्रतिरोध ने आवश्यक बना दिया था। क्रांति के शत्रुओं ने सोवियत सत्ता निकायों के सामान्य कार्यकलाप में बाधा डालने तथा पूंजीवाद की बहाली के लिए परिस्थितियां निर्मित करने का प्रयास करते हुए प्रेस सहित संघर्ष के सभी साधनों का इस्तेमाल किया। अतः वर्ग संघर्ष के दौरान कड़ी प्रेस सेंसरशिप लागू करना, शत्रुतापूर्ण तत्वों के मताधिकार को सीमित करना आवश्यक था, ताकि उन्हें सोवियत सत्ता की जनवादी संस्थाओं को जनता और नयी व्यवस्था के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का अवसर न मिले। किंतु स्वभावतः सोवियत राज्य के इस अनुभव को निरपेक्ष नहीं बना देना और समाजवादी समाज की स्थापना का सामान्य नियम नहीं घोषित करना चाहिए।

देश-विशेष में वर्ग संघर्ष की ठोस विशिष्टताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। विदित है कि कुछ ससाजवादी देशों ने मताधिकार को सीमित नहीं किया या अगर किया भी तो बहुत कम। लेनिन के शब्दों में, "मताधिकार को सीमित करने का प्रश्न अधिनायकत्व का आम प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से एक विशिष्ट प्रश्न है।"*

सोवियत सत्ता विगत की किसी भी सत्ता से अतुलनीय रूप से जनवादी है। लेनिन के शब्दों में, वह "सबके लिए खुली सत्ता है, अपने

---

* वही, खंड ८, पृ० ११२।

सारे काम जनता की नज़रों के सामने करती है, जनता की पहुंच के भीतर है, जनता से प्रत्यक्षतः उत्पन्न हुई है, जनता की, उसकी इच्छा की सीधी और प्रत्यक्ष साधन है।"*

सोवियत सत्ता का जनवाद इसमें है कि वह केवल अपने को मेहनतकशों के व्यापक अधिकारों की घोषणा करने तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि उनके कार्यान्वयन के लिए भौतिक परिस्थितियों का निर्माण भी करती है। सार्वजनिक भवन, छापेखाने, काग़ज़, सभी जन सूचना साधन जनता को दे दिये जाते हैं।

अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि सोवियत सत्ता ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर दिया और इस तरह व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों को सुनिश्चित बनाया; उसने जातीय उत्पीड़न का उन्मूलन किया और सोवियत संघ की सभी जातियों की समानता को सुनिश्चित बनाया।

सोवियत जनवाद ने दुनिया में पहली बार मेहनतकश जनसाधारण के लिए सोवियतों के ज़रिये देश के प्रशासन में सक्रिय भाग लेने की असीमित संभावना प्रदान की।

मेहनतकश लोगों द्वारा सोवियतों में अपने प्रतिनिधियों के कार्यकलाप पर नियंत्रण के विभिन्न रूप और विधियां प्रचलित थीं, जिन्होंने देश के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालने के लिए जनता की संभावनाओं को व्यापक बनाया।

सोवियतों के ढांचे में विधायी और कार्यकारी सत्ता संयुक्त थी। इसने कार्यकारी सत्ता की अत्यधिक स्वतंत्रता, सर्वशक्तिमत्ता से, जो बुर्जुआ राज्यों की अभिलाक्षणिकता है, बचाव की गारंटी की। सोवियतों ने राजकीय मशीनरी और जनसाधारण के बीच निकट संपर्क को सुनिश्चित किया।

सोवियत जनवाद ने श्रमिक की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया। उसने उसे अपने जीवन का सचेत निर्माता, अपने देश का स्वामी बनाया। सोवियत संघ के विकास की प्रत्येक नयी मंज़िल जनवाद के विकास के लिए व्यापकतर संभावनाएं प्रदान करती है।

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'अधिनायकत्व के प्रश्न के इतिहास में योगदान', १९२०।

समाज के राजनीतिक संगठन में पार्टी की भूमिका

सभी राजकीय, राजनीतिक और सामाजिक संगठन मिलकर समाजवादी समाज की राजनीतिक प्रणाली बनाते हैं।

उसमें जन प्रतिनिधियों की सोवियतें, जो सोवियत संघ का राजनीतिक आधार बनाती हैं, और ट्रेड-यूनियनें, कोम्सोमोल, सहकारिताएं और श्रमिक जनों के अन्य स्वैच्छिक सार्वजनिक संगठन आते हैं। इस प्रणाली में सोवियत जनगण की जांची-परखी हरावल, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख स्थान है। पार्टी सामान्य नेतृत्व करती, घरेलू और विदेश नीति में सोवियत राज्य के समूचे कार्यकलाप का मार्गदर्शन करती और समाज के विकास का सामान्य संदर्श निर्धारित करती है। वह अपनी कांग्रेसों में देश के विकास की अवस्था के अनुरूप विज्ञानसम्मत नीति तैयार करती है। पार्टी की नीति सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की प्रणाली में आनेवाले सभी संगठनों के कार्यकलाप का आधार है। सभी पार्टी संगठन सोवियत संघ के संविधान के ढांचे में काम करते हैं।

पार्टी का नेतृत्व संपूर्ण श्रमजीवी लोगों के हितों की पूर्ति करता है, क्योंकि वह उनकी इच्छा, मौलिक आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। पार्टी समाज से ऊपर नहीं है, बल्कि उसका हरावल है, जो मज़दूरों, सामूहिक फ़ार्मों के किसानों और बुद्धिजीवियों के अत्यधिक चेतनशील हिस्से को स्वैच्छिक आधार पर एकजुट करता है। जनता के बीच काम करते हुए पार्टी अपने सदस्यों के ज़रिये श्रमिकों की मनोदशा और इच्छा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करती है और फिर उपयुक्त निर्णय लेती तथा देश के समक्ष सामान्य कार्यभार प्रस्तुत करती है।

समाजवादी समाज में कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका का यह अर्थ नहीं है कि वह राजकीय मशीनरी का स्थान लेती हैं। लेनिन ने पार्टी और सोवियत सत्ता के कार्यों का ठीक-ठीक विभाजन करने, सोवियत निकायों और उनके कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी और स्वतंत्रता बढ़ाने और पार्टी को सभी राजकीय निकायों का नेतृत्वकारी काम सौंपने पर ज़ोर दिया।

जहां तक सार्वजनिक संगठनों – ट्रेड-यूनियनों, युवक और सृजनात्मक संगठनों – का सवाल है, तो पार्टी यह मानकर चलती है कि उनमें से प्रत्येक को निश्चित सार्वजनिक कार्य पूरा करना और अपने तरीक़े से

समाजवाद के निर्माण में योगदान करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी सार्वजनिक संगठनों का स्थान नहीं लेती, न ही उनके स्वतंत्र कार्य को बाधित करती है। प्रत्येक सार्वजनिक संगठन की अपनी संरचना, संचालन के निर्वाचित अवयव, अपनी नियमावली होती है। पार्टी इन सभी संगठनों के कार्यकलाप की मुख्य दिशा और ध्येय निर्धारित करने में उन्हें सहायता करती है। सार्वजनिक संगठनों के पार्टी नेतृत्व का अर्थ उनकी भूमिका को ज़रा भी कम करना नहीं है। मेहनतकशों के सामाजिक-राजनीतिक संगठनों का सर्वोच्च रूप होते हुए पार्टी सार्वजनिक जीवन में उन्हें अधिक सक्रिय भाग लेने में समर्थ बनाती तथा जन संगठनों की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती है।

समाजवाद के विरोधी पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका को जनवाद को सीमित और समाप्त करने के रूप में, पार्टी का अधिनायकत्व स्थापित करने के रूप में चित्रित करते हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सभी सार्वजनिक संगठनों की समान भागीदारी की हिमायत करते हैं। परंतु कम्युनिस्ट पार्टी मात्र संगठनों में से एक नहीं है, बल्कि वह तो मज़दूर वर्ग, सभी मेहनतकशों के राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च रूप है। वह सोवियत समाज की राजनीतिक प्रणाली की नाभिक है। समाज के राजनीतिक संगठन में पार्टी की वस्तुगत स्थिति और समाजवाद के निर्माण में उसकी ऐतिहासिक भूमिका द्वारा पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका निर्धारित होती है।

बुर्जुआ सिद्धांतकार दावा करते हैं कि एक पार्टी के रहते कोई जनवाद नहीं हो सकता, कि बहुदलीय प्रणाली और दलों के बीच संघर्ष ही जनवाद के चिह्न हैं। वे सोवियत रूस में एकदलीय प्रणाली की स्थापना के वास्तविक कारणों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं। ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा करते हुए वे दावा करते हैं कि रूसी कम्युनिस्टों ने जानबूझकर सभी विरोधी पार्टियों को एक ओर धकेल दिया और अपना अधिनायकत्व, सत्ता का एकाधिकार क़ायम कर लिया।

वास्तव में, लेनिन की पार्टी सोवियत रूस में एकदलीय प्रणाली को समाजवादी समाज के राजनीतिक संगठन का सामान्य नियम नहीं मानती थी। वह सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से अन्य ऐसी पार्टियों के सहयोग में काम करने की संभावना को मानती थी और मानती है, जिन्हें श्रमिकों के विभिन्न संस्तरों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन यह सह-

योग केवल तभी संभव है जब ये पार्टियां व्यापक मेहनतकश जनसाधारण के हितों के लिए, जनवाद और समाजवाद के लिए उसके साथ मिलकर सक्रिय और सुसंगत रूप से संघर्ष करने हेतु तैयार हों।

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय के बाद रूस के कम्युनिस्टों ने सोवियत सत्ता के सामाजिक आधार को विस्तारित करने के लिए जनवादी पार्टियों से सहयोग करने के लिए क़दम उठाया।

क्रांति की विजय की घोषणा करनेवाली सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस के ६४९ प्रतिनिधियों में ३९० (दो-तिहाई) बोल्शेविक, १६० समाजवादी-क्रांतिकारी, ७२ मेंशेविक और छोटे पार्टी ग्रुपों के कुछ प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च विधायी निकाय – केंद्रीय कार्यकारिणी समिति – का चुनाव किया, जिसमें ६२ बोल्शेविक, २९ वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी, ६ मेंशेविक-अंतर्राष्ट्रीयतावादी, ३ उक्राइनी समाजवादी और १ अतिवादी शामिल थे। कांग्रेस में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के नाते बोल्शेविक एक पार्टी की सरकार बनाने का अधिकार रखते थे। फिर भी, उन्होंने वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों को पहली सोवियत सरकार में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने यह पेशकश अस्वीकार कर दी।

किसानों पर अपना प्रभाव बनाये रखने का प्रयास करते हुए सात वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी दिसम्बर १९१७ में सोवियत सरकार में शामिल हुए। पर २३ फ़रवरी, १९१८ को जर्मनी के साथ ब्रेस्त शांति-संधि के हस्ताक्षर का विरोध करते हुए तथा मार्च में उसकी पुष्टि के ख़िलाफ़ बोलते हुए वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने अपने को बोल्शेविकों के साथ एकता से स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा वे सरकार से बाहर निकल आये। १९१८ की गर्मी में वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने अपने हाथों में सत्ता हड़प लेने के लिए मास्को में प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह संगठित किया। विद्रोह के कुचल दिये जाने के बाद सोवियतों की पांचवीं कांग्रेस ने, जो इन दिनों मास्को में हो रही थी, वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों के उस हिस्से को सोवियतों से अलग करने का निर्णय स्वीकार किया, जो अपनी केंद्रीय समिति की राजनीतिक लाइन का समर्थन कर रहा था। वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टी ने अपनी सोवियत-विरोधी नीति से मेहनतकश किसानों को परे धकेल दिया और इस प्रकार अपना राजनीतिक आधार खो दिया तथा राजनीतिक मंच से उसका पटाक्षेप हो

गया। अन्य टुटपुंजिया पार्टियां भी, जिनके नेताओं ने कठोर गृहयुद्ध के दौरान प्रतिक्रांतिकारियों और हस्तक्षेपकारियों का साथ दिया, जनता की नज़रों में गिर गयीं और उसने उन्हें ठुकरा दिया।

ये तथ्य दिखाते हैं कि सोवियत रूस में एकदलीय प्रणाली इसलिए नहीं क़ायम हुई कि बोल्शेविक ग़ैर-सर्वहारा पार्टियों से सहयोग नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि ग़ैर-सर्वहारा पार्टियों ने अपने को क्रांति से पृथक् कर लिया, समाजवाद के ध्येय के प्रति ग़द्दारी की। टुटपुंजिया पार्टियों के विघटन ने समाजवादी जनवाद के विकास को कठिन बनाने के बजाय आसान ही बनाया।

राजनीतिक पार्टियों की संख्या ही इस बात की कसौटी नहीं हो सकती कि कोई सामाजिक प्रणाली जनवादी है या नहीं। उनका वर्ग सार ही मुख्य चीज़ है। बहुदलीय प्रणाली वाले बहुत-से पूंजीवादी देशों में संविधानों में घोषित मानवाधिकारों का पालन नहीं किया जाता है और प्रगतिशील संगठनों तथा मानवाधिकारों के लिए लड़नेवालों को बड़ी निर्ममतापूर्वक तंग किया जाता है।

हाल के ऐतिहासिक अनुभव ने दिखाया है कि समाजवाद की राजनीतिक प्रणाली में कई राजनीतिक पार्टियां शामिल हो सकती हैं। पर ये सभी पार्टियां कम्युनिस्ट और मज़दूर पार्टियों की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार करती हैं तथा अपने देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, समाजवाद के निर्माण में सक्रिय हिस्सा लेती हैं।

अतः मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी की नेतृत्वकारी और मार्गदर्शक भूमिका की स्वीकृति और सुनिश्चयन समाजवादी निर्माण का सामान्य नियम तथा समाजवादी क़िस्म की संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एकदलीय या बहुदलीय प्रणाली संबंधी प्रश्न का समाधान देश-विशेष में विद्यमान ऐतिहासिक परिस्थितियों पर पूर्णतः निर्भर करता है।

सोवियत राज्य का परिष्कार

समाजवादी राज्य एक गतिशील, विकासमान संघटन है। समाजवाद के निर्माण की अवधि में सोवियत सत्ता का सामाजिक आधार – मज़दूर

वर्ग के नेतृत्व में मज़दूरों और किसानों का सहबंध – निरंतर मजबूत हुआ है, समाजवादी राज्यत्व पूर्ण बना है, समाजवादी जनवाद विकसित और विस्तारित हुआ है तथा राजकीय एवं सामाजिक जीवन के संवैधानिक सिद्धांत सुदृढ़ हुए हैं। पार्टी द्वारा सोवियत सत्ता के विकास के मार्गदर्शन ने राज्य को समाजवाद के निर्माण का एक मुख्य साधन बनाने में सहायता की।

समाजवादी निर्माण के कार्यभारों के जटिल होने, देश के औद्योगीकरण के कार्यान्वयन, कृषि के सामूहिकीकरण, सांस्कृतिक क्रांति, समाजवाद की उपलब्धियों की रक्षा के साथ-साथ सोवियत राज्य की भूमिका भी बढ़ती गयी। पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण को अमली जामा पहनाना था, वास्तविक समाजवादी समाज का निर्माण करना था।

लेनिन ने लिखा कि मज़दूरों और किसानों को अवश्य ही समझना चाहिए कि "अब सब कुछ **व्यावहारिक कार्य** पर ही निर्भर करता है, कि ठीक वह ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची है, जब सिद्धांत का व्यवहार में रूपांतरण हो रहा है, जब सिद्धांत व्यवहार से प्राणशक्ति पा रहा है, व्यवहार द्वारा संशोधित किया तथा परखा जा रहा है"।* उन्होंने मार्क्स के इस कथन की याद दिलायी कि "असली आंदोलन का हर क़दम दर्जनों कार्यक्रमों से अधिक महत्वपूर्ण है"।

जैसे-जैसे समाजवादी निर्माण व्यापक होता गया, वैसे-वैसे राज्य के आर्थिक और संगठनात्मक कार्य का महत्व भी बढ़ता गया। आर्थिक विकास की एकीकृत राजकीय योजना तैयार करने के लिए फ़रवरी १९२१ में राजकीय योजना आयोग (गोसप्लान) क़ायम किया गया। राजकीय मशीनरी को पूर्ण बनाने तथा सभी राजकीय संस्थाओं के कार्यों के नियंत्रण के लिए क़दम उठाये गये। इस उद्देश्य से मज़दूर और किसान निरीक्षण कमिसारियत (राबक्रिन) की स्थापना की गयी। बाद में उसे पार्टी के केंद्रीय नियंत्रण आयोग में मिला दिया गया, जिसने मज़दूर और किसान निरीक्षण कमिसारियत की प्रतिष्ठा बढ़ा दी।

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'प्रतियोगिता कैसे संगठित की जानी चाहिए?', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ७, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८४, पृ० ४१२।

मज़दूरों और किसानों के निरीक्षण ने राजकीय मशीनरी को सुदृढ़ और किफ़ायती बनाने, नौकरशाही और अनुशासनहीनता को मिटाने में सहायता की। इन कार्यों को निपटाने में मेहनतकश जनसाधारण, ट्रेड-यूनियनों और कोम्सोमोल ने सक्रिय भाग लिया। सोवियतों का पार्टी नेतृत्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

पार्टी ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास के संचालन में सुधार करने, सभी राजकीय निकायों, अधिकारियों, सार्वजनिक संगठनों और सोवियत नागरिकों द्वारा संविधान के कड़ाई से पालन हेतु नियंत्रण संगठित करने और राजकीय अनुशासन तथा समाजवादी क़ानून को मज़बूत बनाने के लिए सोवियतों के कार्य को निर्दिष्ट किया।

वर्ष प्रति वर्ष राजकीय मशीनरी के कार्य में सुधार होता गया, उसकी संरचना, कार्य की शैली और विधियां उत्कृष्ट बनती गयीं। इस उद्देश्य से राजकीय कर्मीवृंद के प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षा संस्थान खोले गये, कोर्स शुरू किये गये। श्रम के वैज्ञानिक संगठन पर विशेष साहित्य और पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की गयीं।

सोवियत संघ में राजकीय मशीनरी, आर्थिक निकायों में काम पर राजनीतिक रूप से सक्रिय मज़दूरों को रखने की विधि व्यापक रूप से व्यवहार में लायी गयी। उच्चतर टेक्नोलाजिकल संस्थानों के न्यूनीकृत कार्यक्रम के आधार पर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कोर्स संगठित किये गये। उत्पादन से अलग हुए बिना डेढ़-दो साल के ऐसे प्रशिक्षण कोर्सों में पढ़ने के बाद वे इंजीनियरी डिप्लोमा के साथ प्रबंधक बन जाते थे। पहली पंचवर्षीय योजनावधि में पदोन्नति की यह विधि बड़ी प्रचलित हुई।

सोवियत मज़दूर वर्ग ने ऐतिहासिक रूप से एकदम छोटी अवधि में अपने प्रशासनिक और आर्थिक प्रबंध निकाय स्थापित कर लिये। यह एक विशाल सामाजिक उपलब्धि थी। व्यवहार में समाजवाद के निर्माण ने बुर्जुआ सिद्धांतकारों के इस जड़सूत्र पर विनाशकारी प्रहार किया कि मज़दूर वर्ग उत्पादन प्रबंध का संगठन स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता।

इन सभी और अन्य क़दमों ने राजकीय मशीनरी के कार्य में काफ़ी सुधार किया, समाजवादी जनवाद को अधिक व्यापक बनाया।

सोवियत संघ में वर्ग शक्तियों के सहसंबंध में क्रमिक परिवर्तन और सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण ने १९३५ के शुरू में सोवियतों के

चुनावों से संबंधित उन प्रतिबंधों को हटाने में समर्थ बनाया, जो क्रांति की विजय के बाद लगाये गये थे। इसने जनवाद को और विस्तारित किया, मज़दूरों और सामूहिक किसानों के सहबंध को मज़बूत बनाया और कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोवियत सत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ा दी।

सोवियत जनवाद को पूर्ण बनाने में ट्रेड-यूनियनों के अधिकारों का विस्तार बड़ा महत्व रखता था। सामाजिक बीमा, श्रम सुरक्षा, अखिल संघीय विश्रामगृहों और सैनेटोरियमों से संबंधित सभी मामले उन्हें दे दिये गये। ट्रेड-यूनियनों, अर्थात स्वयं मज़दूरों को श्रम संगठन, मज़दूरी भुगतान, सामुदायिक और डाक्टरी सेवाओं पर नियंत्रण और कुप्रबंध को दूर करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस तरह वर्ष प्रति वर्ष देश के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में मज़दूर वर्ग की भूमिका बढ़ती गयी, मेहनतकश जनसाधारण और उनके सार्वजनिक संगठनों के अधिकार विस्तारित होते गये।

२. समाजवाद के निर्माण के काल में सामाजिक संबंध

सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में मज़दूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका को सुनिश्चित करना और नगरों तथा देहातों में पूंजीवादी तत्वों के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष के लिए, उनके उन्मूलन के लिए कृषक वर्ग के साथ उसके सहबंध को सुदृढ़ करना समाजवाद के निर्माण के काल में सामाजिक नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार था। इस उद्देश्य से सर्वहारा राज्य ने पूंजीवादी संपत्ति – शोषक वर्गों की उत्पत्ति का आधार – ज़ब्त कर ली। स्वभावतः इस कार्य को एक ही झटके में नहीं पूरा किया जा सकता था।

इस नीति का कार्यान्वयन वर्ग संरचना पर निर्भर करता है जो अपनी बारी में देश की आर्थिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है। संक्रमणकालीन अवधि में सोवियत अर्थव्यवस्था में पांच विभिन्न आर्थिक प्रणालियां काम कर रही थीं: पितृसत्तात्मक (अधिकांशतः जीवन-निर्वाह वाली) अर्थव्यवस्था, लघु माल उत्पादन (बाज़ार से जुड़ी कृषक अर्थव्य-

वस्था), निजी पूंजीवाद, राजकीय पूंजीवाद और समाजवाद।

क्रांति की विजय के बाद के पहले वर्षों में सोवियत रूस में लघु माल उत्पादन की प्रधानता थी। १६२४ में कुल राष्ट्रीय उत्पाद में उसका हिस्सा ५२ प्रतिशत था। समाजवादी क्षेत्र, जिसका हिस्सा ३६ प्रतिशत था, मुख्य क्षेत्र था, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसे निर्णायक स्थिति प्राप्त थी। उस समय निजी पूंजीवादी उत्पाद का हिस्सा ६ प्रतिशत था।

अर्थव्यवस्था की बहुक्षेत्रीय संरचना के उन्मूलन के फलस्वरूप समाज की वर्गीय संरचना में गहन परिवर्तन आये। यह जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में संक्रमण काल का मर्म रही है।

वर्ग संघर्ष और उसके कारण

सोवियत रूस के प्रत्येक सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में एक ऐसा निश्चित वर्ग या सामाजिक संस्तर था, जो न केवल अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को बनाये रखने, बल्कि उन्हें बढ़ाने और मज़बूत बनाने की भी कोशिश कर रहा था। १६२४ में आबादी में विभिन्न वर्गों और सामाजिक समूहों का हिस्सा इस प्रकार था: मज़दूर और कर्मचारी–१४.८ प्रतिशत, सामूहिक फ़ार्मों के किसान और सहकारी दस्तकार–१.३ प्रतिशत, अलग-अलग खेती करनेवाले किसान और दस्तकार–७५.४ प्रतिशत और पूंजीपति, व्यापारी तथा कुलक–८.५ प्रतिशत।

जहां तक उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व पर आधारित अर्थव्यवस्था के कुछ रूप मौजूद थे, वहां तक पूंजीवाद की जड़ें और उसकी पुनःस्थापना के लिए परिस्थितियां भी विद्यमान थीं। फलतः पूंजीवाद की बहाली का ख़तरा बना हुआ था, वर्ग संघर्ष के लिए, पूंजीवादी तत्वों द्वारा सर्वहारा राज्य का समाजवादी रूपांतरण की नीति के विरोध के लिए ज़मीन बनी हुई थी।

सर्वहारा राज्य को सत्ताच्युत वर्गों के ज़बर्दस्त प्रतिरोध पर न केवल उनका तख़्ता उलट दिये जाने के शीघ्र बाद की अवधि में, बल्कि संपूर्ण संक्रमणकालीन अवधि में भी काबू पाना पड़ा था। लेनिन ने

ज़ोर देते हुए लिखा कि जबतक संक्रमण काल पूरा नहीं हुआ है "शोषकों को अनिवार्य रूप से बहाली की आशा बंधी रहती है, और वह आशा बहाली की कोशिशों में परिवर्तित हो जाती है"*।

बुर्जुआ वर्ग, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का समर्थन प्राप्त था, समाजवाद का मुख्य शत्रु था। सत्ता में आने के बाद मज़दूर और किसान "सामाजिक शांति" की स्थिति नहीं अपना सके क्योंकि सत्ताच्युत शोषक वर्गों ने समाजवाद के निर्माण का अनम्यतापूर्वक विरोध करना जारी रखा।

ग्रामीण बुर्जुआ वर्ग – कुलक – मेहनतकश लोगों का ख़तरनाक और अनम्य शत्रु था। सोवियत सत्ता के पहले वर्षों में कुलकों ने अनाज की अनिवार्य वसूली की निरंतर तोड़-फोड़ संगठित की ताकि समाजवादी औद्योगीकरण की जड़ खोदी और देश में भुखमरी पैदा की जा सके।

राज्य को कुलकों का अनाज ज़ब्त करने तथा उनकी खेती पर कर बढ़ाने जैसे असाधारण क़दम उठाने पड़े। उस काल में किसानी अर्थव्यवस्था में कुलक फ़ार्मों का हिस्सा ४-५ प्रतिशत था और वे देश के कुल कृषि करों का ३०-४० प्रतिशत चुकाते थे। सोवियत सत्ता ने भाड़े पर मज़दूर लगाने और लगान पर ज़मीन लेने के कुलकों के अधिकारों को सीमित कर दिया।

सोवियत राज्य द्वारा उठाये गये क़दमों ने अनाज की आवश्यक राशियां जमा करने और शहरी आबादी तथा लाल सेना को अनाज सप्लाई बढ़ाने की संभावना दी।

मेहनतकश किसान सोवियत रूस में संक्रमण की अवधि में सबसे बहुसंख्यक वर्ग थे। छोटे मालिक की अपनी मानसिकता की वजह से किसानों का आचरण द्विविध था। पराये श्रम का शोषण न करनेवाले मेहनतकशों के नाते किसान सर्वहाराओं के सहज मित्र थे। लेकिन साथ ही छोटे मालिक होने के नाते वे ढुलमुलपन प्रकट करते हैं और बुर्जुआ वर्ग के पक्ष में मुड़ जा सकते हैं।

बुर्जुआ वर्ग ने उनके इस ढुलमुलपन का सोवियत-विरोधी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। पर सोवियत राज्य ने बुर्जुआ वर्ग के इन प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब दिया, मज़दूरों और किसानों के महबंध

---

* वही, खंड ८, पृ० ११०।

को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक क़दम उठाये।

आज सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों तथा बहुत-से विकासमान देशों का अनुभव भी पुष्ट करता है कि एक भी ऐसा देश नहीं है, जहां प्रतिक्रियावादी शक्तियां क्रांतिकारी, जनवादी और समाजवादी परिवर्तनों का प्रतिरोध न करें। विजयी जनगण और उनके राजनीतिक हरावल को पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के प्रयासों को दबाने के लिए ही नहीं, बल्कि बाद में समाजवाद के निर्माण के दौरान शोषकों के प्रतिरोध को दबाने के लिए भी मज़बूत और दृढ़ शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक मेहनतकश जनगण के विरोधी वर्ग बने रहते हैं तब तक वर्ग संघर्ष कभी-कभी उग्र रूप धारण करते हुए संक्रमण काल में भी जारी रहता है।

लेनिन सोवियत राज्य के अनुभव के आधार पर संक्रमण काल में वर्ग संघर्ष के पांच मूल रूप निर्धारित किये: *

१) **सत्ताच्युत वर्गों के प्रतिरोध का दमन।** बुर्जुआ वर्ग, ज़मींदार, पुरानी आर्मी के बड़े अफ़सर, सत्ताच्युत सरकार के बड़े नौकरशाह और अन्य कर्मचारी पूंजीवाद की बहाली के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के साथ सहबंध बनाने के लिए तैयार रहते हैं। वे राष्ट्रीय हितों के प्रति गद्दारी करने और बाहरी फ़ौजी हस्तक्षेप तक का समर्थन करने में नहीं हिचकिचायेंगे, जैसा कि सोवियत रूस में १९१८-२० में हुआ था।** सत्ताच्युत वर्गों के प्रतिरोध का दमन सोवियत राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार था। यह संक्रमण काल का एक वस्तुगत नियम था।

२) **गृहयुद्ध** संक्रमण काल में वर्ग संघर्ष का सबसे उग्र रूप है, जिसे सामान्यत: सत्ताच्युत वर्ग शुरू करते हैं। सोवियत संघ का अनुभव दिखाता है कि गृहयुद्ध विदेशी फ़ौजी हस्तक्षेप से मिल जाता है। बेशक, गृहयुद्ध और हस्तक्षेप संक्रमण काल में वर्ग संघर्ष के आवश्यक रूप नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर पूर्वनिर्धारित हैं। विश्व समाजवादी प्रणाली की स्थापना के बाद, जो प्रतिक्रांति के निर्यात में बाधा उपस्थित करती

---

* देखें, व्ला० इ० लेनिन, 'सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व', १९१९।

** देखें अध्याय २।

है, गृहयुद्ध और हस्तक्षेप सामान्य नियम नहीं हैं।

३) **टुटपुंजिया वर्ग को "तटस्थ बनाना"** समाजवाद के निर्माण की अवधि में, खास तौर से उसकी प्रारंभिक अवधि में, वर्ग संघर्ष का एक विशिष्ट रूप है। टुटपुंजिया वर्ग (किसान, दस्तकार, कारीगर) मज़दूर वर्ग से जुड़ा होता है। इसके साथ ही लघु माल उत्पादक बुर्जुआ माल-मुद्रा संबंधों की प्रणाली में खिंच जाते हैं और इस वजह से बुर्जुआ वर्ग की ओर लुढ़क जाते हैं। लघु माल उत्पादन में पुराने समाज की शक्तियां और परंपराएं जीवित रहती हैं। टुटपुंजिया वातावरण दक्षिणपंथी और वामपंथी तथा अराजकतावादी प्रवृत्तियों के जन्म के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। क्रांति के घरेलू और विदेशी शत्रुओं ने मेहनतकशों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए टुटपुंजिया वर्ग के ढुलमुलपन का बारंबार इस्तेमाल करने की कोशिश की।

"तटस्थ बनाने" की नीति का मतलब टुटपुंजिया वर्ग को समाजवाद के पक्ष में लाने के लिए सोवियत सत्ता, कम्युनिस्ट पार्टी और मज़दूर वर्ग का सक्रिय संघर्ष था। टुटपुंजिया तत्वों के "तटस्थीकरण" ने संक्रमण काल के अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य – किसानों और अन्य ग़ैर-सर्वहारा संस्तरों के साथ मज़दूरों के सहबंध को मज़बूत बनाना, उन्हें नये जीवन के सक्रिय निर्माताओं में बदलना – को पूरा करने में सहायता की।

४) **बुर्जुआ वर्ग का "इस्तेमाल"** संक्रमण काल में वर्ग संघर्ष का एक रूप है। यह एक वर्ग के रूप में उसका दमन करने के कार्य का विरोध नहीं करता। पार्टी ने समाजवाद के हित में बुर्जुआ विशेषज्ञों के इस्तेमाल, श्रम प्रक्रिया में जनता के लाभ के लिए उनकी पुनर्शिक्षा को संभव माना।

५) **मेहनतकशों में नये अनुशासन की भावना पैदा करना** समाजवाद के निर्माण की अवधि में वर्ग संघर्ष का एक विशिष्ट रूप है। सत्ता पर क़ब्ज़ा करने के बाद मज़दूर वर्ग और अन्य श्रमजीवी लोगों को न केवल समाज को, बल्कि अपनी मानसिकता को भी बदलना था। मुख्य चीज़ थी निजी और सार्वजनिक हितों के बीच अंतर्विरोध को दूर करना तथा उन परंपराओं और प्रथाओं को त्यागना, जो शोषकों के युगों पुराने प्रभुत्व के दौरान क़ायम हुई थीं।

श्रम के प्रति नये रुख का विकास सर्वोपरि महत्व का कार्य है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। सार्वजनिक संपत्ति, सामाजिक

जीवन के नियमों के प्रति सम्मान की भावना में मेहनतकशों को पुनर्शिक्षित करना, उनमें कम्युनिस्ट नैतिकता और आचार के सिद्धांतों की गहन समझ विकसित करना भी कोई कम जटिल नहीं है।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के दौरान सोवियत सत्ता को वर्ग संघर्ष कृत्रिम रूप से भड़काने की त्रोत्स्कीपंथी वामपंथी-दुस्साहसिकतावादी नीति के ख़िलाफ़, विशेष रूप से किसानों और टुटपुंजिया वर्ग की भूमिका को तोड़ने-मरोड़ने और समाजवाद के निर्माण में उन्हें खींचने की संभावना से इन्कार करने के प्रयासों के ख़िलाफ़ ज़बर्दस्त संघर्ष चलाना पड़ा था। त्रोत्स्कीपंथियों की यह नीति नयी प्रणाली के सामाजिक आधार को संकीर्ण बना देती तथा नये जीवन के निर्माण में सक्रिय भागीदारी से किसानों को पृथक कर देती।

संक्रमण काल में उसकी ठोस परिस्थितियों और बुर्जुआ वर्ग की वास्तविक शक्ति को ध्यान में रखे बिना वर्ग संघर्ष के "विलुप्त होने" के बारे में दक्षिणपंथी अवसरवादी विचार भी सर्वथा ग़लत और ख़तरनाक थे। दक्षिणपंथी अवसरवादियों ने पूंजीवादी तत्वों से संघर्ष को त्यागने का सुझाव दिया और माना कि वे स्वयं समाजवाद में शांतिपूर्ण ढंग से "घुलमिल" जायेंगे। वस्तुगत रूप से इस दृष्टिकोण ने पूंजीवाद के पुनर्जीवन और बहाली का मार्ग खोल दिया। त्रोत्स्कीपंथियों और दक्षिणपंथी अवसरवादियों की विचारधारात्मक तथा सांगठनिक पराजय संक्रमण काल के अंतर्विरोधों पर क़ाबू पाने की एक महत्वपूर्ण शर्त थी।

अत: मरणासन्न पूंजीवाद और नवोदित समाजवाद के बीच अनम्य संघर्ष पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के काल में सामाजिक संबंधों की अभिलाक्षणिकता है।

सोवियत संघ में समाजवाद की विजय

संक्रमण काल में सामाजिक-आर्थिक नीति के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप सोवियत संघ में समाजवाद की विजय हुई। सोवियत संघ में क़ायम नये समाज ने सुदृढ़ आर्थिक आधार पाया – समाजवाद के भौतिक-तकनीकी आधार का निर्माण किया गया। पहले की बहुप्रणालीय सोवियत अर्थव्यवस्था पर अंतिम रूप से क़ाबू पा लिया

गया। १९३७ में देश के कुल उत्पादन कोष में राज्य, सामूहिक फ़ार्मों और सहकारिताओं की संपत्ति, यानी सार्वजनिक संपत्ति का हिस्सा ९८.७ प्रतिशत था।

समाजवाद के निर्माण का मुख्य राजनीतिक ध्येय – शोषक वर्गों का, उद्योग और कृषि में उत्पादन के औज़ारों और साधनों पर निजी स्वामित्व का उन्मूलन – भी पूरा हो गया। १९३७ तक समाजवादी उद्यम कुल औद्योगिक उत्पाद के ९९.८ प्रतिशत का उत्पादन कर रहे थे। देहात में ९३ प्रतिशत किसान सामूहिक फ़ार्मों में शामिल हो गये थे, जो कृषियोग्य ज़मीन के ९९.१ प्रतिशत हिस्से पर खेती कर रहे थे। खुदरा व्यापार शत-प्रतिशत समाजवादी हो गया था। ऐतिहासिक रूप से अल्प अवधि में सोवियत संघ अग्रणी औद्योगिक देश बन गया और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से उसका यूरोप में पहला और दुनिया में दूसरा स्थान हो गया।

समाजवाद की विजय ने सोवियत समाज की सामाजिक संरचना में मौलिक परिवर्तन ला दिया। निम्नलिखित आंकड़े इसका प्रमाण हैं।

सोवियत समाज की वर्ग संरचना (प्रतिशत):

	१९१३	१९३९
मज़दूर और कर्मचारी	१७	५०.२
सामूहिक फ़ार्मों के किसान		
और सहकारीकृत		
दस्तकार	–	४७.२
अलग खेती करनेवाले		
किसान और दस्तकार		
बुर्जुआ लोग, ज़मींदार,	६६.७	२.६
व्यापारी और कुलक	१६.३	–

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के फलस्वरूप उत्पादन के समाजवादी संबंधों, साथीवत सहयोग और समाजवादी पारस्परिक सहायता के संबंधों की स्थापना हुई। सोवियत समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक बन गया। यह एकता सोवियत राज्य की सुदृढ़ता

का नया स्रोत, उसके विकास की प्रेरक शक्ति बन गयी। शोषक वर्गों के उन्मूलन के बाद सोवियत संघ में दो मैत्रीपूर्ण वर्ग – मज़दूर वर्ग और सामूहिक कृषक वर्ग – रह गये। नया, जन सोवियत बुद्धिजीवी संस्तर बना। शक्तिशाली उद्योग के निर्माण के दौरान सोवियत मज़दूर वर्ग परिमाणात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ा। उत्पादन साधनों से वंचित एक वर्ग से वह संपूर्ण जनता के साथ उनका स्वामी बन गया।

मज़दूरों और कर्मचारियों की संख्या १९२८ में १ करोड़ ७६ लाख से बढ़कर १९३९ में ५ करोड़ हो गयी। मज़दूर वर्ग का जातीय गठन भी बदल गया। सोवियत सत्ता के प्रारंभिक वर्षों में देश का सर्वहारा वर्ग मुख्यत: रूसी और उक्राइनी मज़दूरों से बना था। लेकिन पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनावधियों में सभी सोवियत जनतंत्रों में अपने मज़दूर वर्ग की तेज़ी से वृद्धि हुई।

समाजवाद के निर्माण के दौरान मज़दूरों का सांस्कृतिक और तकनीकी स्तर काफ़ी ऊंचा उठा। मज़दूर वर्ग समाज का नव-प्रवर्तक बना। देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक उत्पादन में उसके प्रमुख स्थान, उसकी क्रांतिकारिता, अनुशासनबद्धता, संगठनबद्धता और सामूहिकतावाद ने समाजवाद के निर्माण में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका निर्धारित की। मज़दूर वर्ग ने अपने हरावल – कम्युनिस्ट पार्टी – के ज़रिये अपने इस ऐतिहासिक ध्येय को अमली जामा पहनाया।

समाजवाद ने कृषक वर्ग की, जिसका क्रांति के पहले देश की आबादी में बड़ा हिस्सा था, संरचना और सामाजिक स्थिति को मूलत: बदल दिया। किसान एक नया, समाजवादी वर्ग बन गये। मज़दूरों और बुद्धिजीवियों के साथ छोटी आदिम खेतीबारी के कल के ये मालिक समाजवादी राज्य की संपूर्ण सामाजिक संपदा के स्वामी बन गये।

सामूहिक फ़ार्मों में शामिल होकर किसानों ने अपने को शोषण के सभी रूपों से मुक्त कर लिया, गांव का ग़रीब किसानों, मंझोले किसानों और कुलकों में विभाजन सदा-सर्वदा के लिए बंद हो गया। वर्ग संरचना की दृष्टि से किसान समरूप वर्ग हो गये। खेती का काम औद्योगिक श्रम की तरह बनने लगा। ट्रैक्टर ड्राइवर, कम्बाइन हार्वेस्टर चालक, मैकेनिक, आदि जैसे नये पेशे प्रकट हुए। पहली पंचवर्षीय योजनावधि में ही कृषि ने माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त लगभग ७० हज़ार विशेषज्ञ पाये।

बुद्धिजीवी वर्ग के गठन और मामाजिक भूमिका में भी काफ़ी

परिवर्तन आया। समाजवाद ने उनके समक्ष जनता की सेवा के लिए असीमित संभावनाएं खोल दीं, उन्हें पूंजीपतियों पर उत्पीड़नभरी, अपमानजनक आश्रितता से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया।

बुद्धिजीवी संस्तर की सामाजिक संरचना में परिवर्तन दो कारणों से हुआ: पहला, मज़दूर वर्ग और कृषक वर्ग ने ऐतिहासिक रूप से अत्यल्प अवधि में अपने बीच से ऐसे बहुसंख्य अध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक दिये, जो समाजवाद के ध्येय के प्रति समर्पित थे। दूसरा, पुराने बुद्धिजीवी नये समाज के आधार के निर्माण में मज़दूर वर्ग के साथ सहयोग के अपने अनुभव से समाजवाद के लाभों के क़ायल हो गये और उनका मुख्य हिस्सा समाजवाद के लिए ईमानदारी से काम करने लगा।

समाजवादी निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए मज़दूरों, किसानों और जन बुद्धिजीवियों के बीच सघन सहयोग बन गया।

सोवियत जनगण की बिरादराना दोस्ती, समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारधारा के आधार पर बने नये जातीय संबंध सोवियत संघ में समाजवादी कायापलट के प्रमुख परिणाम थे।*

समाजवाद के निर्माण के वर्षों में सोवियत जनगण की भौतिक स्थिति में आमूल परिवर्तन हुए। १६३० के अंत में बेरोज़गारी का सदा-सर्वदा के लिए उन्मूलन कर दिया गया और विश्व में सबसे छोटा कार्य-दिवस लागू किया गया। मज़दूरों के वेतन में, सामूहिक किसानों की नक़दी और जिंसी आय में वृद्धि हुई। सार्वजनिक उपभोग कोषों में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप मेहनतकशों की वास्तविक आय बढ़ी। इन कोषों से निःशुल्क डाक्टरी सहायता, शिक्षा, मेहनतकशों की योग्यताओं में सुधार, स्कूल-पूर्व संस्थानों में बच्चों की देख-रेख, बुढ़ापा पेंशन, भत्ते, वज़ीफ़े, सैनेटोरियमों और विश्रामगृहों में मुफ़्त या रियायती सुविधाओं को सुनिश्चित बनाया जाता है।

नये संविधान की स्वीकृति

दिसम्बर १६३६ में सोवियत संघ के नये संविधान में गहन सामाजिक परिवर्तनों और समाजवाद की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को क़ानूनी रूप से पुष्ट किया गया। संविधान ने सोवियत संघ में समाजवाद की विजय

* देखें अध्याय ७।

के तथ्य को प्रतिबिंबित किया, समाजवादी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निर्धारित कीं। संविधान के अनुसार, श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें सोवियत संघ का राजनीतिक आधार बनीं। समाजवादी आर्थिक प्रणाली और उत्पादन साधनों पर समाजवादी स्वामित्व (जिसके दो रूप थे: राजकीय स्वामित्व और सामूहिक फ़ार्मों का व सहकारी स्वामित्व) आर्थिक आधार बने।

संविधान ने घोषणा की कि श्रम प्रत्येक हृष्ट-पुष्ट नागरिक के कर्तव्य और सम्मान का मामला होगा और वितरण के समाजवादी सिद्धांत "प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार, प्रत्येक को उसके श्रमानुसार" को सुदृढ़ बनाया।

संविधान ने देश में मौलिक वर्ग परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया। उसने सोवियत नागरिकों के जनवादी अधिकारों को विस्तारित किया, श्रम के अधिकार, आराम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में भरण-पोषण के अधिकार को विधिक रूप प्रदान किया।

संविधान ने अंत:करण, भाषण, प्रेस, सभाओं की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक संगठनों – ट्रेड-यूनियनों, सहकारिताओं, युवा, खेल, रक्षा, आदि संगठनों – में संघबद्ध होने के अधिकार की गारंटी की। उसने सोवियत समाज में कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका को विधिक रूप से मजबूत बनाया।

संविधान ने समाजवादी जनवाद की उच्चतर अवस्था – सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों, सर्वोपरि रूप से राज्य के प्रशासन में सभी वर्गों तथा सामाजिक संस्तरों की समानता, सोवियतों के लिए चुनने तथा चुने जाने का अधिकार और जातियों की वास्तविक समानता – प्रतिबिंबित की।

संविधान ने सोवियत संघ के नागरिकों के कर्तव्य – सोवियत राज्य के क़ानून, श्रम अनुशासन का कड़ाई से पालन करना, सामाजिक कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करना, सामाजिक समाजवादी संपत्ति की रक्षा करना, उसे सुदृढ़ बनाना, समाजवादी आचार के नियमों का सम्मान करना, समाजवादी मातृभूमि की रक्षा करना – सुस्पष्टत: निर्धारित किये।

१९३६ में नये सोवियत संविधान की स्वीकृति और चुनाव प्रणाली

15*

के आगे जनवादीकरण के परिणामस्वरूप सोवियत समाज के जीवन में गहन राजनीतिक परिवर्तन हुए।

* * *

सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवस्था बना – पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि पूरी हुई। सोवियत संघ में समाजवाद की विजय ने क्रांतिकारी मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत की सर्वशक्तिमत्ता को पुनः सिद्ध कर दिया। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम (१९६१) में कहा गया: "समाजवाद, जिसकी अनिवार्यता की मार्क्स और एंगेल्स ने भविष्यवाणी की, जिसकी योजना लेनिन ने तैयार की, सोवियत संघ में एक वास्तविकता बन गया है।"

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने समाजवाद के निर्माण के वस्तुगत नियमों को अमल में लाया है। सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों के अनुभव ने दिखा दिया है कि समाजवाद का निर्माण समाजवाद का मार्ग अपनानेवाले सभी देशों के लिए कई सामान्य वस्तुगत नियमों पर आधारित है।

ये वस्तुगत नियम हैं: कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना ; कृषक वर्ग और मेहनतकश जनसाधारण के अन्य संस्तरों के साथ मज़दूर वर्ग का सहबंध ; जातीय उत्पीड़न का उन्मूलन और जातियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना ; उत्पादन साधनों के पूंजीवादी, निजी स्वामित्व के स्थान पर समाजवादी, सार्वजनिक संपत्ति की स्थापना ; समाजवाद और कम्युनिज़्म की स्थापना तथा जनता का जीवन-स्तर उठाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियोजित विकास ; कृषि का धीरे-धीरे समाजवादी रूपांतरण ; समाजवादी राज्य का सुदृढ़ीकरण और विदेशी तथा घरेलू शत्रुओं से समाजवादी क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा ; देश-विशेष के मज़दूर वर्ग की अन्य देशों के मज़दूर वर्ग के साथ एकजुटता और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद।

अक्तूबर क्रांति के बाद सोवियत संघ में समाजवाद की विजय विश्वव्यापी महत्व की एक घटना थी। उसने दिखाया कि समाजवादी विकास के ज़रिये ही चहुंमुखी राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति संभव है।

अध्याय ७

समाजवाद के निर्माण की अवधि में जातीय संबंध

१. जातियों के बीच मैत्री और बिरादराना सहयोग की नीति

सामाजिक जीवन की एक अत्यंत उग्र, जटिल और कठिन समस्या – जातीय समस्या का समाधान सोवियत जनगण की एक ऐसी उपलब्धि है, जिस पर वे उचित गर्व कर सकते हैं।

रूसी राज्य दुनिया में सर्वाधिक बहुजातीय राज्य था, जहां १३० से अधिक जातियां और नृजातीय समूह रह रहे थे और सामाजिक-आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में थे। उत्पीड़ित जातियां आबादी का आधा से अधिक बनाती थीं और वे दोहरे उत्पीड़न – सामाजिक तथा जातीय – की शिकार थीं।

क्रांति-पूर्व विगत ने कठिन विरासत छोड़ी थी: देश के दूर-दराज़ के इलाक़े आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए थे, जातियों के पारस्परिक संबंधों में अविश्वास व्याप्त था और आबादी लगभग शत-प्रतिशत निरक्षर थी।

ज़ारशाही रूस में सभी अल्पसंख्यक जातियां राजनीतिक अधिकारों से वंचित थीं, उनकी जातीय संस्कृति और भाषा पर पाबंदी थी। जातीय इलाक़ों की अर्थव्यवस्था एकतरफ़ा स्वरूप की थी: वह मुख्यत: रूसी बुर्जुआ वर्ग और ज़मींदारों की आवश्यकताओं को ही पूरा करती थी।

ज़ारशाही ने एक जाति के दूसरी जातियों पर दावों का, गोत्रीय और क़बीली शत्रुता तथा कलहों का इस्तेमाल जातियों के बीच फूट पैदा करने और उन्हें एक-दूसरे के निकट आने से रोकने के लिए किया।

लेनिन के शब्दों में, ज़ारशाही "जातियों का कारागार" थी। रूसी मज़दूर वर्ग इस कारागार को नष्ट करने के संघर्ष में मुख्य शक्ति था।

१६१६ में स्वीकृत पार्टी कार्यक्रम ने जातीय संबंधों के क्षेत्र में पार्टी नीति का सार सटीक रूप से प्रकट किया। उसमें अंशतः कहा गया था : "ज़मींदारों और बुर्जुआ वर्ग का तख्ता उलटने के लिए संयुक्त क्रांतिकारी संघर्ष चलाने हेतु सर्वहाराओं और अर्ध-सर्वहाराओं को निकट लाने की नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।" "उन राज्यों के सर्वहारा वर्ग के प्रति उत्पीड़ित देशों में मेहनतकश जनसाधारण के" अविश्वास को दूर करने के लिए "जिन्होंने उन्हें उत्पीड़ित किया है, किसी भी जातीय समूह के सभी विशेषाधिकारों को समाप्त करना, जातियों की पूर्ण समानता को सुनिश्चित करना, उपनिवेशों और असमान जातियों के अलग होने के अधिकार को मान्यता देना आवश्यक है।"

लेनिन ने माना कि क्रांति की विजय के बाद सर्वहारा के लिए बड़ा राज्य रखना उपयुक्त होगा, उसे शत्रुतापूर्ण पूंजीवादी घेरेबंदी में अस्तित्व के अपने अधिकार की रक्षा करने की अधिक बड़ी संभावना प्राप्त होगी। उन्होंने लिखा कि अगर हम निरपवाद रूप से सभी उत्पीड़ित और असमान जातियों के लिए अलग होने की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, तो "इस कारण नहीं कि हम उनके अलगाव के हक में हैं, बल्कि केवल इस कारण कि हम बलात संयोजन से भिन्न रूप में **स्वतंत्र, स्वैच्छिक** एकजुटता और घुलने-मिलने के हामी हैं। **बस यही** एक कारण है!"*

राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में नारे की अंतर्राष्ट्रीयतावादी अंतर्वस्तु पर ज़ोर देते हुए लेनिन ने महान रूस के कम्युनिस्टों का अलग होने के जनगण के अधिकार के लिए संघर्ष करने और उत्पीड़ित जातियों के कम्युनिस्टों का रूसी मज़दूर वर्ग और सभी जातियों के मेहनतकशों के साथ अंतर्राष्ट्रीयतावादी सहबंध के नारे का समर्थन करने तथा जातीय प्रश्न के हल के बारे में सभी जातीय पूर्वाग्रहों का विरोध करने का आह्वान किया। बुर्जुआ प्रभुत्व के तहत जातीय उत्पीड़न अनिवार्य है, अतः उसका उन्मूलन जातीय मुक्ति की महत्वपूर्ण शर्त है। केवल सामाजिक मुक्ति ही जातीय मुक्ति, जातियों की समानता और आत्मनिर्णय ला सकती है।

---

*व्ला० इ० लेनिन, 'मार्क्सवाद का विकृत रूप तथा साम्राज्यवादी अर्थवाद', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ६, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १६८३, पृ० १६८।

जातीय प्रदेशों में क्रांति की विजय

पेत्रोग्राद में समाजवादी क्रांति की विजय के बाद पुरानी सरकार की शक्तियों को चकनाचूर करना और संपूर्ण रूस में सोवियत सत्ता की स्थापना करना आवश्यक था।

सोवियत सत्ता द्वारा घोषित जातियों की स्वाधीनता और समानाधिकार की नीति ने रूस के दूर-दराज़ के जातीय इलाक़ों में सोवियतों के लिए अधिकांश मेहनतकशों के समर्थन को सुनिश्चित किया।

बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां बोल्शेविक पार्टी और अन्य सार्वजनिक संगठन मज़बूत थे और जहां ग़रीब किसानों के साथ सुदृढ़ सहबंध में सहयोग करनेवाले उच्चतः संगठित मज़दूर थे, सोवियत सत्ता की स्थापना सामान्यतः शांतिपूर्ण तरीक़े से हुई। परंतु दूसरे क्षेत्रों में सोवियत सत्ता अस्थायी बुर्जुआ सरकार के स्थानीय निकायों और बुर्जुआ प्रतिक्रांतिकारी, राष्ट्रवादी ताक़तों के सशस्त्र प्रतिरोध को कुचल करके विजयी हुई।

१६१८ के शुरू में कुछ जातीय प्रदेशों में समाजवादी क्रांति विजयी हुई। १६१७-१६१८ में बेलोरूस, उक्राइना, बाल्टिक जनतंत्रों – एस्तोनिया, लिथुआनिया और लाटविया – में सत्ता सोवियतों के हाथों में आ गयी।

ट्रांसकाकेशियाई जनतंत्रों में सोवियतों की सत्ता के लिए संघर्ष कठिन परिस्थितियों में चला। यहां सोवियत सत्ता के लिए संघर्ष का केंद्र बाकू था। १६१८ के शुरू में रूसी मज़दूरों के समर्थन से बाकू गुबेर्निया में जन कमिसार परिषद के नेतृत्व में बाकू कम्यून क़ायम किया गया। लेकिन उस समय बुर्जुआ राष्ट्रवादी पार्टियों – जार्जियाई मेंशेविकों, आर्मेनियाई दाश्नाकों, और अज़रबैजानी मुस्सावातवादियों – ने विदेशी साम्राज्यवादियों के समर्थन से "ट्रांसकाकेशियाई कमिसारियत" बनायी, जो वास्तव में बुर्जुआ राष्ट्रवादी अधिनायकत्व थी और ट्रांसकाकेशियाई क्रांतिकारी आंदोलन के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रही थी।

बाकू कम्यून को ब्रिटिश और तुर्की फ़ौजों ने कुचल दिया। सितम्बर १६१८ में समाजवादी-क्रांतिकारियों और ब्रिटिश हस्तक्षेपकारियों ने ट्रांसकास्पियन में २६ बाकू कमिसारों को गोली मार दी।

अज़रबैजान, जार्जिया और आर्मेनिया में सोवियत सत्ता के लिए मेहनतकश जनसाधारण का संघर्ष कुछ वर्षों तक चला। किंतु लाल सेना

और रूसी जनगण की सहायता से प्रतिक्रियावादी सरकारों का तख़्ता उलट दिया गया। नवम्बर १९२० में अज़रबैजान में और फ़रवरी १९२१ में आर्मेनिया और जार्जिया में सोवियत सत्ता स्थापित हो गयी।

१९२२ के प्रारंभ में उन्होंने ट्रांसकाकेशियाई सोवियत फ़ेडरेशन बनाया, जो समान, प्रभुतासंपन्न जनतंत्रों का स्वैच्छिक संघ और सोवियत जनतंत्रों के बीच संबंधों का एक नया प्रकार था।

परिणामस्वरूप, भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के भूक्षेत्र पर निम्नलिखित सोवियत जनतंत्र क़ायम किये गये: रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र, उक्राइनी सोवियत समाजवादी जनतंत्र, बेलोरूसी सोवियत समाजवादी जनतंत्र और आर्मेनिया, जार्जिया तथा अज़रबैजान को संयुक्त करनेवाला ट्रांसकाकेशियाई समाजवादी संघात्मक सोवियत जनतंत्र।

मध्य एशिया और कज़ाख़स्तान में भी, जहां उद्योग आरंभिक अवस्था में थे और सर्वहाराओं की संख्या बहुत कम थी, सोवियत सत्ता की स्थापना के लिए संघर्ष कठिन परिस्थितियों में चला। तुर्किस्तान क्षेत्र* में सोवियत सत्ता की स्थापना नवम्बर १९१७–मार्च १९१८ में हुई। लेकिन इसके बाद ज़बर्दस्त गृहयुद्ध चला जिसने प्रतिक्रांतिकारियों को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। सोवियत सत्ता की स्थापना के बाद तुर्किस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र (१९१८) की स्थापना हुई, जो रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र का अंग बना। आगे चलकर वहां रहनेवाली जातियों और नृजातीय समूहों के जीवंत हितों को ध्यान में रखते हुए सोवियत मध्य एशिया का जातीय और भूक्षेत्रीय विभाजन किया गया। फलस्वरूप, आज के उज़्बेक, तुर्कमान, ताजिक, किर्गीज़ और कज़ाख़ सोवियत समाजवादी जनतंत्र बने।

उत्तरी काकेशिया, दक्षिणी उराल, साइबेरिया और सुदूर पूर्व के जातीय प्रदेशों में भी सोवियत सत्ता की स्थापना स्थानीय राष्ट्रीय

---

*अक्तूबर क्रांति के पहले वर्तमान सोवियत मध्य एशियाई जनतंत्रों का भूक्षेत्र और कज़ाख़ जनतंत्र के दक्षिणी प्रदेश तुर्किस्तान का भूक्षेत्र बनाते थे। – सं०

बुर्जुआ वर्ग के साथ संघर्ष में हुई।

इस प्रकार, २५ अक्तूबर, १९१७ से १९१८ के वसंत तक की अवधि में संपूर्ण देश में सोवियत सत्ता की स्थापना हो गयी थी, लेकिन कुछ जातीय प्रदेशों में १९२०-२१ में। सोवियत सत्ता की स्थापना "केवल बड़े नगरों और कारखानेवाले स्थानों में ही नहीं, बल्कि देश के दूर-दराज़ के इलाक़ों में भी हो गयी"।*

बेलोरूस और बाल्टिक से लेकर प्रशांत तक और आर्कटिक तट से लेकर कास्पियन सागर तक देश के समूचे भूक्षेत्र पर सोवियत सत्ता की विजय के बड़े महत्व पर ज़ोर देते हुए लेनिन ने कहा: "...हम वस्तुतः इस वजह से असाधारण आसानी से जीत पा रहे थे कि फल पक गया था, कि जनता बुर्जुआ वर्ग से समझौतेपरस्ती के अनुभव से गुज़र चुकी थी। हमारा नारा 'सभी सत्ता सोवियतों को', जिसे जनता व्यवहार में अपने लंबे अनुभव से जांच-परख चुकी थी, उसके रक्त और मांस का अंग बन गया था।"** अक्तूबर क्रांति ने रूस के कोटि-कोटि मेहनतकश जनगण को प्रेरित किया और उन्हें पुरानी सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष में खींचा।

जातीय प्रश्न के समाधान में पहले क़दम

रूस में समाजवादी क्रांति की विजय जातियों के बीच नये सामाजिक संबंधों की विजय की द्योतक थी। उसने लेनिनीय जातीय नीति के सिद्धांतों, समाजवाद के निर्माण में जातियों की बिरादराना दोस्ती और सहयोग की नीति को अमल में लाने की संभावना सुनिश्चित की।

---

* व्ला० इ० लेनिन, मज़दूरों, किसानों और लाल सेना के प्रतिनिधियों की मास्को सोवियत में भाषण, १२ मार्च, १९१८।

** रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की असाधारण सातवीं कांग्रेस में प्रस्तुत की गयी केंद्रीय समिति की राजनीतिक रिपोर्ट, ७ मार्च, १९१८।

नयी जन सत्ता को निम्नलिखित कार्यभार पूरे करने थे: विगत से विरासत में मिली जातीय असमानता का ख़ात्मा करना; सभी जातियों के वास्तविक समानाधिकारपूर्ण और चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करना; एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादराना सहबंध में सभी जातियों और नृजातीय समूहों को एकजुट करना; स्वतंत्र और समानाधिकारपूर्ण जातियों का एक समाजवादी राज्य में स्वैच्छिक संघ बनाना और उनके प्रयासों को नये समाज के निर्माण में लगाना।

लेनिन ने लिखा: "मज़दूर पुरानी दुनिया, जातीय उत्पीड़न, जातीय कलह और जातीय पृथकता के मुक़ाबले में एक नयी दुनिया, सभी जातियों के मेहनतकशों की एकता की दुनिया, एक ऐसी दुनिया पेश करते हैं, जिसमें न तो किसी विशेषाधिकार के लिए, न ही मनुष्य द्वारा मनुष्य के उत्पीड़न के लिए कोई स्थान है।"*

समाजवादी विचार में जातीय प्रश्न के समाधान का अर्थ है जातीय उत्पीड़न के सभी रूपों का उन्मूलन करना, जातियों, नृजातीय समूहों की सच्ची समानता, स्वतंत्रता और चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित बनाना, उनके पारस्परिक संबंधों में विरोध को मिटाना और अधिक विकसित जातियों द्वारा विकास में पिछड़ी हुई जातियों को सहायता प्रदान करना। ये सभी कार्यभार समाजवादी निर्माण की प्रक्रिया में हल किये जाते हैं।

सोवियतों की दूसरी कांग्रेस ने जातीय कार्यक्रम और नीति को कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष निकाय – जातीय मामलों की जन कमिसारियत – का गठन किया। राज्यों के इतिहास में पहली बार पहली सोवियत सरकार ने एक ऐसे विशेष निकाय का गठन किया, जो जातियों को ग़ुलाम बनाने, उन्हें दबाने का साधन नहीं, बल्कि उत्पीड़ित जातियों को मुक्त कराने, उनके बीच शत्रुता और अविश्वास को दूर करने, पहले की उत्पीड़ित पिछड़ी हुई जातियों और नृजातीय समूहों को उनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के चहुंमुखी विकास में सहायता करने का साधन था।

जातीय प्रश्न पर सोवियत सत्ता के सभी पहले दस्तावेज़ों ने रूस की जातियों की पूर्ण मुक्ति, महान मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित

---

*व्ला० इ० लेनिन, 'मज़दूर वर्ग और जातीय समस्या', १९१३।

उनके स्वैच्छिक और सम्मानपूर्ण संघ की घोषणा की।

२ (१५) नवम्बर, १९१७ को सोवियत सरकार ने 'रूस की जातियों के अधिकारों की घोषणा' स्वीकार की। वह कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार की जातीय नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थी, जिसने रूस की उत्पीड़ित जातियों की मुक्ति को क़ानूनी तौर पर पुष्ट किया। घोषणा में जातीय प्रश्न पर सोवियत सरकार की नीति के मूल सिद्धांत एलान किये गये:

"१. रूस की जातियों की समानता और संप्रभुता।

२. अलग होने और स्वतंत्र राज्य बनाने की हद तक आत्मनिर्णय का रूस की जातियों का अधिकार।

३. सभी जातीय और जातीय-धार्मिक विशेषाधिकारों और प्रतिबंधों का ख़ात्मा।

४. रूस के भूक्षेत्र में रहनेवाले जातीय अल्पसंख्यकों और नृजातीय समूहों का स्वतंत्र विकास।"

२० नवम्बर (३ दिसम्बर), १९१७ को प्रकाशित 'रूस और पूरब के सभी मेहनतकश मुस्लिमों से' सोवियत सरकार की अपील का बहुत बड़ा महत्व था। उसने विधिवत घोषणा की कि मुस्लिमों के सभी विश्वास, प्रथाएं, जातीय और सांस्कृतिक संस्थाएं स्वतंत्र और अलंघनीय हैं। अपील में कहा गया कि सोवियत सरकार फ़ारस और तुर्की के संबंध में उन सभी गुप्त और असमान संधियों को रद्द करती है, जिन्हें ज़ारशाही सरकार ने संपन्न किया था और जिनकी अस्थायी सरकार ने पुष्टि कर दी थी। उसने पूरब के जनगण का साम्राज्यवादी दास बनानेवालों के ख़िलाफ़ विद्रोह करने और अपने भाग्य का मालिक बनने का आह्वान किया।

सोवियत सरकार के एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ – 'मेहनतकश तथा शोषित जनता के अधिकारों का घोषणापत्र' (जनवरी १९१८) – में कहा गया कि समाजवादी प्रणाली के आधार पर "रूस की तमाम जातियों के मेहनतकश वर्गों का वास्तव में स्वतंत्र तथा स्वैच्छिक और इस कारण और भी अधिक दृढ़ तथा स्थिर संघ" बनाया जा रहा है।

रूसी संघात्मक जनतंत्र के पहले संविधान (१९१८) ने सभी जातियों के स्वतंत्र आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की और उसे

सुनिश्चित बनाया तथा सभी जातियों के समान अधिकारों को स्वीकार किया तथा उन्हें सुदृढ़ बनाया। इसने व्यापक जनसाधारण में बड़ा उत्साह पैदा कर दिया और सोवियत जनतंत्र की जातियों का बिरादराना संघ बनाने और उसे मज़बूत करने के लिए सीमांत इलाक़ों में रहनेवाली जातियों को प्रेरित किया।

सोवियत सरकार ने न केवल जातीय उत्पीड़न और बलप्रयोग की नीति से परहेज़ करने की घोषणा की, बल्कि पहले के उत्पीड़ित जनगण को अपने भाग्य का – संघ में रहने या उससे अलग होने, प्रशासन, जातीय-राजकीय निर्माण, अन्य जातियों से संबंध के प्रश्नों का – स्वयं निर्णय करने का अधिकार भी प्रदान किया।

पहले के पिछड़े हुए प्रदेशों, ख़ास तौर से सोवियत पूरब में जातीय नीति ने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा। उन जनतंत्रों में, जहां अपना मज़दूर वर्ग नहीं था, समाज के राजनीतिक संगठन के संक्रमणकालीन रूपों – जैसे कि किसान सोवियतें – का व्यापक इस्तेमाल किया गया। करोड़ों की मुस्लिम आबादी में ज़बर्दस्त धार्मिक पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए सोवियत सत्ता ने अस्थायी तौर पर ही सही स्कूलों को मुल्लाओं की देखरेख में रहने दिया और जन न्यायालय क़ायम करने में स्थानीय परिस्थितियों को नज़र में रखा। इस नीति ने सोवियत सरकार और रूसी जनता के प्रति भूतपूर्व उत्पीड़ित जातियों के विश्वास को जीतने में समर्थ बनाया। सोवियत सत्ता के सुदृढ़ होने के साथ-साथ देश के सीमांत इलाक़ों की जातियों और रूसी जनगण के बीच एकता भी मज़बूत होती गयी। जीवंत हितों, वर्ग चेतना, समाजवाद के निर्माण में साझे उद्देश्यों और कार्यभारों ने विभिन्न जातियों और नृजातीय समूहों के सहबंध को निर्धारित किया, उसे मज़बूत बनाया। लेनिन के शब्दों में, "यह संधियों पर आधारित सहबंध नहीं, बल्कि शोषकों के ख़िलाफ़ शोषितों की एकजुटता पर आधारित सहबंध है।"*

---

*व्ला० इ० लेनिन, नौसेना की प्रथम अखिल रूसी कांग्रेस में भाषण, ५ दिसम्बर, १९१७।

सोवियत जनगण के सहयोग का समारंभ

अक्तूबर क्रांति की विजय के बाद रूस के जनगण और सोवियत समाजवादी जनतंत्रों के जनगण के बीच सहयोग का कोई स्थायी आधार नहीं था।

१०वीं पार्टी कांग्रेस (१९२१) ने संपूर्ण संक्रमण काल, यानी समाजवाद का निर्माण पूरा होने तक की संपूर्ण ऐतिहासिक अवधि के लिए विज्ञानसम्मत जातीय नीति तैयार की।

वास्तविक असमानता का पूर्ण उन्मूलन जातीय संबंधों के क्षेत्र में मौलिक महत्व का कार्यभार था। इस उद्देश्य से सबसे पहले जातीय प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना की गयी, वहां सोवियत राज्यत्व का विकास किया गया, उसे मज़बूत बनाया गया। वहां मातृभाषाओं में काम करनेवाले स्थानीय सरकारी निकाय, अदालतें, प्रेस, सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल खोले गये। जातीय कर्मियों और विशेषज्ञों, नये जीवन के चेतनशील और सक्रिय निर्माताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया।

समाजवाद के निर्माण के काल में न केवल जातियों और नृजातीय समूहों के बीच अविश्वास और अलगाव को दूर करने, वरन् सभी जातियों के मेहनतकशों के बीच मैत्री और दोस्ताना सहायता पर आधारित प्रशासनिक और विधायी निकायों की उच्चत: कारगर प्रणाली की स्थापना करने का भी कार्यभार प्रस्तुत हुआ था। सोवियत संघ की जातियों के बीच यह सहयोग क़दम-ब-क़दम बढ़ता और पूर्ण बनता गया।

विदेशी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के वर्षों में बने सोवियत जनतंत्रों के सैनिक तथा राजनीतिक सहबंध ने उसकी समाप्ति के बाद आर्थिक सहबंध का रूप ले लिया, जिसने इन जनतंत्रों और सोवियत रूस के बीच आर्थिक संबंध क़ायम करना तथा जनतंत्रों के बीच द्विपक्षीय समझौते करना संभव बना दिया। इसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहाली के संगठन कार्य में बड़ी भूमिका अदा की। वास्तव में रूसी संघात्मक जनतंत्र की वित्त, विदेश व्यापार, संचार तथा डाक और तार कमिसारियतें ऐसे संयुक्त निकाय बन गयीं, जिन्होंने समझौतों के आधार पर सभी जनतंत्रों में आर्थिक विकास को समन्वित किया। आगे चलकर सोवियत

जनतंत्र विदेशनीति और राजनयिक प्रश्नों को सुलझाने में अपने प्रयासों को एकजुट करने लगे।

फ़रवरी १९२२ में मास्को में सोवियत जनतंत्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जेनोआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन* में सोवियत जनतंत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व तथा रक्षा करने का अधिकार रूसी जनतंत्र की सरकार को देने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा, रूसी प्रतिनिधिमंडल को सभी सोवियत जनतंत्रों की ओर से बातचीत करने और संधियों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया।

यह भूतपूर्व उत्पीड़ित जातियों के रूसी जनता के प्रति विश्वास का नया प्रदर्शन था।

विकासमान समाजवादी निर्माण की परिस्थितियों में द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर अर्थव्यवस्था के केंद्रीय प्रबंध को सुनिश्चित करना और राष्ट्रव्यापी पैमाने पर योजनाबद्ध आर्थिक विकास में संक्रमण कार्यान्वित करना कठिन बन गया। १० वीं पार्टी कांग्रेस ने जातीय प्रश्न पर प्रस्ताव में ज़ोर दिया कि साझे आर्थिक, राजनीतिक और रक्षात्मक हित साम्राज्यवादी दासता और जातीय उत्पीड़न से बचने के एकमात्र मार्ग के रूप में सभी सोवियत जनतंत्रों के एक राजकीय संघ को अनिवार्य बनाते हैं।

लेनिन ने राष्ट्रों के बीच नये संबंधों की स्थापना में बड़ी सावधानी, लचीलेपन और सहनशीलता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने सीख दी कि बड़ी जातियों को, जिनके शासक वर्गों ने क्रांति के पहले उत्पीड़नकारी नीति का अनुसरण किया, छोटी जातियों के हितों को ख़ास तौर से तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि जातीय अन्याय सर्वहारा वर्ग की एकजुटता में जितनी बड़ी बाधा है उतनी और कोई चीज़ नहीं। उन्होंने लिखा कि "जिन जातियों की जातीय भावना को 'ठेस' पहुंची है, वे सबसे अधिक समानता और इस समानता

---

*जेनोआ सम्मेलन (अप्रैल-मई १९२२) – आर्थिक और वित्तीय प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सम्मेलन के संगठनकर्ताओं ने रूसी सोवियत जनतंत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को उसमें भाग लेने के लिए निमंत्रित किया था। – सं०

के अतिक्रमण को महसूस करती हैं, भले ही यह अतिक्रमण उनके सर्वहारा साथियों ने मज़ाक़ में कियाँ हो या यह उनकी असावधानी के कारण हुआ हो।"*

कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत जनता को बड़े बहुजातीय राज्य के लाभ समझाये। केवल सभी जनतंत्रों के एक संघ की परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के केंद्रीयकृत प्रबंध को संगठित करना तथा समाजवाद के निर्माण के अन्य तात्कालिक कार्यभारों को पूरा करना संभव है।

२. जातीय प्रश्न के बारे में लेनिनीय नीति की विजय

सोवियत संघ की स्थापना

लेनिन मानते थे कि सोवियत जनतंत्रों के संघ की स्थापना और सुदृढ़ीकरण देश में समाजवाद के निर्माण तथा सभी जनतंत्रों की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक था।

लेनिन ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस (जून १९२०) द्वारा स्वीकृत जातीय और औपनिवेशिक प्रश्नों पर अपनी थीसिसों, 'जातियों या "स्वायत्तीकरण" का प्रश्न' संबंधी अपनी टिप्पणियों (दिसम्बर १९२२) और कुछ अन्य कृतियों में सोवियत जनतंत्रों के एकीकरण के मूल सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया।

१९२२ तक सोवियत जनतंत्रों के एक राज्य में एकीकरण के लिए सभी वस्तुगत परिस्थितियां, वास्तविक पूर्वावश्यकताएं क़ायम हो गयी थीं।

समाजवादी क्रांति के परिणामस्वरूप सभी जनतंत्रों में सोवियत सत्ता की स्थापना हो गयी। उनका एक साझा उद्देश्य – समाजवाद

---

*व्ला० इ० लेनिन, 'जातियों या "स्वायत्तीकरण" का प्रश्न', १९२२।

और कम्युनिज़्म का निर्माण करना – था। समाजवादी क्रांति ने उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की। सोवियत जनतंत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी एकीभूत रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) का अविच्छेद्य अंग थी। सभी सोवियत जनतंत्रों की समरूप सामाजिक-आर्थिक संरचना थी।

सोवियत जनतंत्रों का एक राज्य में एकीकरण जातीय प्रश्न पर कम्युनिस्ट पार्टी की लेनिनीय नीति के कार्यान्वयन का परिणाम था।

एक राज्य में एकजुट होने की इच्छा स्वयं सोवियत जनतंत्रों ने प्रकट की थी। उक्राइनी समाजवादी जनतंत्र के पार्टी और सोवियत संगठन एक राज्य की स्थापना के प्रवर्तक थे और बेलोरूसी तथा ट्रांसकाकेशियाई जनतंत्रों ने उनकी पहल का समर्थन किया।

अगस्त १९२२ में पार्टी की केंद्रीय समिति ने एक आयोग की स्थापना की, जिसे रूसी संघात्मक जनतंत्र और अन्य सोवियत जनतंत्रों के बीच संबंध के बारे में प्रश्न तैयार करने का काम सौंपा गया।

लेनिन ने "स्वायत्तीकरण", अर्थात स्वायत्तता के आधार पर सभी सोवियत जनतंत्रों को रूसी संघात्मक जनतंत्र में शामिल करने की स्तालिन की योजना का अनम्य ढंग से विरोध किया। "स्वायत्तीकरण" ने स्वतंत्र जनतंत्रों के संप्रभु अधिकारों को ध्यान में नहीं रखा था और यह महाशक्तिवादी अंधराष्ट्रवाद तथा स्थानीय राष्ट्रवाद को ही बढ़ा सकता और रूस के प्रति पहले की उत्पीड़ित जातियों के अविश्वास की भावना को पुनः जगा सकता था। अधिकांश जनतंत्रों ने भी "स्वायत्तीकरण" के विचार का समर्थन नहीं किया।

"स्वायत्तीकरण" के दोष को प्रकट करते हुए लेनिन ने संघीय राज्य की स्थापना के लिए एक भिन्न सिद्धांत पेश किया: नये राजकीय रूप – सोवियत समाजवादी जनतंत्रों का संघ – में रूसी संघात्मक जनतंत्र सहित सभी सोवियत जनतंत्रों का स्वैच्छिक एकीकरण। पोलिटब्यूरो के सदस्यों को एक पत्र में उन्होंने लिखा: "...हम अपने को उक्राइनी जनतंत्र और अन्य जनतंत्रों के साथ समानाधिकारपूर्ण मानते हैं तथा समान आधार पर उनके साथ एक नये संघ, एक नये फ़ेडरेशन में प्रविष्ट करते हैं।"* जातियों की संप्रभुता के कड़े पालन में, उनकी

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की स्थापना के संबंध में', १९२२।

पूर्ण समानता में लेनिन ने उनकी परस्पर निकटता तथा राज्यों के एक संघ में उनके स्वैच्छिक एकीकरण की मुख्य शर्त देखी।

६ अक्तूबर, १६२२ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केंद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसने उक्राइना, बेलोरूस, ट्रांसकाकेशियाई जनतंत्रों के फ़ेडरेशन और रूसी संघात्मक जनतंत्र के बीच उनमें से प्रत्येक के "संघ" से स्वतंत्रतापूर्वक अलग होने के अधिकार को बनाये रखते हुए उन्हें 'सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ' में एकजुट करने के लिए एक संधि करने की आवश्यकता स्वीकार की। यह अधिकार जनतंत्रों के स्वैच्छिक तथा समानाधिकारपूर्ण एकीकरण की गारंटी और आवश्यक शर्त था।

अक्तूबर पूर्णाधिवेशन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव और केंद्रीय समिति के एक आयोग द्वारा तैयार की गयी और सोवियत संघ की स्थापना पर घोषणा तथा संधि को कम्युनिस्टों और व्यापक मेहनतकश जनगण के बीच खुली बहस के लिए पेश किया गया।

सोवियत संघ की स्थापना संबंधी तैयारी के सभी कार्य महाशक्तिवादी अंधराष्ट्रवादियों और स्थानीय राष्ट्रवादियों के खिलाफ़ तीव्र संघर्ष में चले।

"अखिल राजकीय हितों" की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में लफ़्फ़ाज़ी करते हुए महाशक्तिवादी अंधराष्ट्रवादियों ने समाजवादी निर्माण में जातीय कारकों को नज़रअंदाज़ किया और जातीय प्रदेशों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को कृत्रिम रूप से अवरुद्ध करने की कोशिश की।

स्थानीय राष्ट्रवादियों ने जातीय जनतंत्रों के संघ का विरोध किया, अपने को अपने राष्ट्र के भीतर बंद करने की कोशिश की, जो जनगण के विभाजन की ओर ले जाता। वे आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विदेशी साम्राज्यवादियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार थे, जो वास्तव में सोवियत सत्ता के ख़ात्मे और बुर्जुआ-ज़मींदार शासन की बहाली की ओर ले जाता।

बहुत-से जनतंत्रों में स्थानीय राष्ट्रवाद प्रकट हुआ। कुछ ऐसी सामाजिक शक्तियां बुर्जुआ राष्ट्रवाद की वाहक थीं, जिन्होंने समाजवाद की स्थापना के खिलाफ़ संघर्ष के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का इस्तेमाल किया।

कम्युनिस्ट पार्टी ने सिखाया कि क्रांति द्वारा मुक्त कराये गये जनगण की जातीय आत्म-चेतना और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्तियों के बीच सुस्पष्ट भेद किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जातीय गौरव जातीय अहंकार में, जातीय संकीर्णता में और अंततः राष्ट्रवाद में न बदलने पाये।

राष्ट्रवाद जातीय विशिष्टताओं की अतिरंजना में, दूसरी जातियों और नृजातीय समूहों के प्रति अहंकार और घमंड में, अखिल राजकीय हितों के अनादर में प्रकट होता है।

राष्ट्रवाद के अवशेष विगत के प्रति "वर्गेतर" दृष्टिकोण, यानी देश के प्राचीन इतिहास के आदर्शीकरण और सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय परंपराओं तथा प्रथाओं के प्रति अनालोचनात्मक दृष्टिकोण में भी प्रकट होते हैं।

राष्ट्रवादी अवशेष बहुत टिकाऊ होते हैं। इसके विभिन्न कारण हैं: पुरानी परंपराओं का बने रहना, धार्मिकता और दैनंदिन जीवन की विशिष्टताएं। साम्राज्यवादी प्रचार और उत्प्रवासी राष्ट्रवादी तत्व इन अवशिष्ट भावनाओं को भड़काते हैं।

पार्टी ने दो विचलनों – महाशक्तिवादी अंधराष्ट्रवाद और स्थानीय राष्ट्रवाद – से दृढ़ संघर्ष करने का आह्वान किया। पार्टी ने महाशक्तिवादी अंधराष्ट्रवाद को मुख्य ख़तरा माना, क्योंकि उसने समाजवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीयतावादी संघर्ष के झंडे के नीचे एकजुट जनगण की एकता को नष्ट करने का ख़तरा पेश किया।

पोलिटब्यूरो के सदस्यों को एक पत्र में लेनिन ने लिखा: "मैं महान रूसी अंधराष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ मरते दम तक युद्ध की घोषणा करता हूं... इस बात पर बिल्कुल दृढ़तापूर्वक डटे रहना चाहिए कि संघीय केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता रूसी, उक्राइनी, जार्जियाई, आदि बारी-बारी से करें। **बिल्कुल**!"*

कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा सोवियत जनगण में कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारों के विकास को, मेहनतकशों को सोवियत देशभक्ति, सोवियत मातृभूमि पर गर्व की भावना में, राष्ट्रवाद, अंधराष्ट्रवाद और जातीय संकीर्णता की सभी अभिव्यक्तियों के प्रति

---

*व्ला० इ० लेनिन, 'महान शक्ति के अंधराष्ट्रवाद के विरुद्ध संघर्ष के संबंध में ले० बो० कामेनेव को पत्र', १९२२।

अनम्यता की भावना में शिक्षित करने को बड़ा महत्व दिया।

व्यापक मेहनतकश जनसाधारण भ्रातृत्व, समानता, पारस्परिक सहायता और संप्रभुता पर आधारित संघीय राज्य के महत्व को समझते थे। सभी जनतंत्रों, मज़दूरों, मेहनतकश किसानों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने एकजुट राजकीय संघ के बारे में लेनिन के विचार का समर्थन किया। समूचे देश में सच्चा अखिल राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन आरंभ हो गया। पार्टी की केंद्रीय समिति, सोवियत सरकार और अखबारों के संपादकों को संबोधित मेहनतकशों के अनेकानेक पत्र तथा बड़ी-बड़ी सभाओं में स्वीकृत प्रस्ताव मिले, जिनमें राजकीय संघ के निर्माण के विचार का समर्थन और पुष्टि बड़े उत्साहपूर्वक की गयी थी। सम्मेलनों और सभाओं में सभी जातियों के प्रतिनिधियों ने रूसी जनतंत्र की नेतृत्वकारी भूमिका पर ज़ोर दिया, क्योंकि रूसी जनगण ने समाजवादी क्रांति की विजय, गृहयुद्ध में विजय में, सोवियत जनतंत्रों के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था। सोवियत जातियां अपने विकास में रूसी जनतंत्र के अनुभव और उसकी चहुंमुखी सहायता पर आश्रित थीं। जातीय जनतंत्रों में सोवियतों की कांग्रेसों ने, जिन्होंने सोवियत संघ की स्थापना का एकमत से समर्थन किया, उनकी मनोदशा को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने सोवियतों की पहली असाधारण कांग्रेस के लिए पूर्णाधिकारप्राप्त प्रतिनिधि चुने।

३० दिसम्बर, १६२२ को मास्को में सोवियतों की पहली कांग्रेस शुरू हुई। उसमें २२१४ रूसी, उक्राइनी, बेलोरूसी, आर्मेनियाई, जार्जियाई, अज़रबैजानी, उज़्बेक, ताजिक, आदि प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में ४४.४ प्रतिशत मज़दूर, २६.८ प्रतिशत किसान और २८.८ प्रतिशत कर्मचारी और बुद्धिजीवी थे।

कांग्रेस ने सोवियत संघ की स्थापना के बारे में घोषणा और संधि की एकमत से पुष्टि की और उन्हें स्वीकार किया। घोषणा में कहा गया कि यह संघ समानाधिकारपूर्ण जातियों का स्वैच्छिक संघ है, कि प्रत्येक जनतंत्र के लिए संघ से अलग होने के अधिकार की गारंटी की गयी, कि संघ के द्वार सभी वर्तमान और भावी समाजवादी सोवियत जनतंत्रों के लिए खोले रखे गये, कि नया संघ राज्य अक्तूबर १६१७ में ही निर्धारित जातियों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और बिरादराना सहयोग के सिद्धांतों का सुयोग्य मूर्तरूप होगा, कि वह विश्व पूंजीवाद

के ख़िलाफ़ संघर्ष का दुर्ग होगा।

संधि में राजकीय सत्ता के अखिल संघीय उच्च निकायों के संगठन की व्यवस्था थी और उसने उनके अधिकारों की मोटी रूपरेखा पेश की। उसने वह सीमा भी निर्धारित की, जिसके भीतर संघीय जनतंत्रों ने स्वेच्छापूर्वक और समान ढंग से अपने अधिकार संघ को दे दिये।

संधि में इस बात की व्यवस्था थी कि विदेशनीति और विदेश व्यापार, सशस्त्र सेनाएं, परिवहन, डाक और तार सेवाएं संघ सरकार के अधिकारक्षेत्र में रहेंगी, जिनके लिए अखिल संघीय जन कमिसारियतें (मंत्रालय) क़ायम की जानेवाली थीं। वित्त, अर्थव्यवस्था, खाद्य सप्लाई और श्रम से संबंधित सभी मामले संघीय और जनतंत्रीय सरकारों के अधिकारक्षेत्र में रहने दिये गये, जिनके लिए संघीय-जनतंत्रीय कमिसारियतें क़ायम की गयीं। आंतरिक मामलों, शिक्षा, न्याय, कृषि, जन स्वास्थ्य और सामाजिक बीमे से संबंधित सभी प्रश्न जनतंत्रीय सरकारों के कार्यक्षेत्र में रखे गये। इस उद्देश्य से जनतंत्रीय कमिसारियतें क़ायम की गयीं।

कांग्रेस ने सोवियत संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव किया। उसने लेनिन को जन कमिसार परिषद का अध्यक्ष चुना। दुनिया में पहली बार एक बहुजातीय समाजवादी राज्य – सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ – की स्थापना की गयी। जनवरी १९२४ में सोवियतों की दूसरी कांग्रेस ने आयोग द्वारा तैयार किये गये सोवियत संघ के संविधान की पुष्टि की। इस कार्रवाई ने एकीभूत सोवियत बहुजातीय राज्य की संवैधानिक स्थापना को पूरा किया।

सोवियत संघ की स्थापना लेनिनवादी विचारों की विजय थी।

१०० से अधिक जातियां और नृजातीय समूह जातीय जनतंत्रों के एक संघ में शामिल हुए। यह सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विचारों की विजय थी।

सोवियत संघ की स्थापना विश्वव्यापी महत्व की घटना थी। सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के अतिक्रमणों से रक्षा का एक अभेद्य दुर्ग बन गया। इसने समाजवादी जातियों की एकजुटता की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया, सोवियत जनगण की अटूट मैत्री को मज़बूत बनाया तथा समाजवादी राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खोल दीं।

सोवियत जनतंत्रों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानता का उन्मूलन

सोवियत संघ की स्थापना ने सोवियत जनतंत्रों के बीच सहयोग के विकास में गुणात्मक रूप से एक नयी अवस्था का सूत्रपात किया, उनके आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को विस्तारित किया और गहन बनाया।

ज़ारशाही की जातीय उत्पीड़न की नीति का नतीजा यह हुआ था कि अक्तूबर क्रांति की विजय के समय तक रूस की बहुत-सी जातियां आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास की अत्यंत निम्न अवस्था में थीं। बहुत-सी जातियां (लगभग ३ करोड़ व्यक्ति), ख़ास तौर से मध्य एशिया में, विकास की पूंजीवादी अवस्था में भी नहीं पहुंची थीं और उनका अपना कोई औद्योगिक सर्वहारा वर्ग नहीं था। उनमें से कुछ ने पितृसत्तात्मक-गोत्रीय जीवन पद्धतियों को बनाये रखा था।

सोवियत राज्य ने विगत से विरासत में मिली जातियों और नृजातीय समूहों की असमानता को मिटाना शुरू किया। उसके समक्ष पहले की पिछड़ी जातियों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने तथा उन्हें अधिक विकसित जातियों के स्तर पर ऊंचा उठाने का कार्यभार प्रस्तुत था।

संघीय जनतंत्रों की असमानता पर सिर्फ़ पिछड़ी जातियों को अधिक विकसित जातियों के सर्वहारा वर्ग की कारगर और निस्स्वार्थ सहायता से ही क़ाबू पाया जा सकता था। पूंजीवाद से कतराकर समाजवाद का निर्माण करनेवाली जातियों को विशेषकर बहुत बड़ी सहायता प्रदान करना अनिवार्य हो गया था।

पहले के पिछड़े हुए प्रदेशों में औद्योगिक केंद्र क़ायम करने और स्थानीय आबादी से कर्मीवृंद प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से रूस के केंद्रीय औद्योगिक क्षेत्रों से विभिन्न कारख़ानों और फ़ैक्टरियों को अज़रबैजान, आर्मेनिया, जार्जिया और मध्य एशियाई जनतंत्रों में ले जाया गया। १६२२ से १६२५ तक की अवधि में रूसी संघात्मक जनतंत्र और उक्राइना से कोई २० औद्योगिक उद्यम मध्य एशियाई और ट्रांसकाकेशियाई जनतंत्रों में ले जाये गये।

इसके साथ ही जातीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने तथा वैज्ञानिक

और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने के लिए बड़े रूसी नगरों से विशेषज्ञ, सुयोग्य मज़दूर, अध्यापक, डाक्टरी कर्मी, वैज्ञानिक जातीय जनतंत्रों और प्रदेशों में भेजे गये। जातीय जनतंत्रों से युवाजनों को मास्को, लेनिनग्राद और दूसरे रूसी नगरों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भेजा गया। मिसाल के लिए, १६२६-२८ के शिक्षा वर्ष में मास्को में टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूटों में ग़ैर-रूसी विद्यार्थियों का हिस्सा २५ प्रतिशत, आर्थिक इंस्टीट्यूटों में ३३ प्रतिशत और कृषि इंस्टीट्यूटों में २० प्रतिशत था।

जातीय क्षेत्रों में कृषि की बहाली और विकास के लिए क़दम उठाये गये। रूसी संघात्मक जनतंत्र और उक्राइना में बनी कृषि मशीनें और सोवियत संघ में अन्य जनतंत्रों में बने या विदेशों से आयातित ट्रैक्टर देश के कृषि-उत्पादन में सभी जनतंत्रों के अंश को ध्यान में रखते हुए उनके बीच बांटे गये।

सोवियत सरकार ने सिंचाई और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा पशु-पालन के विकास के लिए मध्य एशियाई और ट्रांसकाकेशियाई जनतंत्रों को बड़ी सहायता प्रदान की। खानाबदोश आबादी के जीवन को संगठित करने पर बड़ा ध्यान दिया गया।

जातीय प्रदेशों में निरक्षरता का उन्मूलन करने और मेहनतकशों के सामान्य सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बड़ी सहायता प्रदान की गयी। १६२० से जातीय जनतंत्रों में उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूट और जातीय सांस्कृतिक संस्थाएं क़ायम की जाने लगीं।

क्रांति के पहले तुर्किस्तान क्षेत्र में केवल दो प्रतिशत आबादी साक्षर थी। १६०६ में पत्रिका 'वेस्तनिक वोस्तोका' ('पूरब का अग्रदूत') ने अपने पृष्ठों पर दावा किया कि इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने में ४,६०० वर्ष लग जायेंगे। लेकिन समाजवादी प्रणाली के तहत भूतपूर्व तुर्किस्तान क्षेत्र में निरक्षरता १६४० तक समाप्त कर दी गयी थी।

सोवियत पूरब में नारियों की मुक्ति क्रांति की एक महान उपलब्धि थी। पार्टी संगठनों और स्थानीय सोवियतों द्वारा चलाये गये बड़े शिक्षा कार्यों के फलस्वरूप स्त्रियां अपने घरों की चहारदीवारी से बाहर निकल आयीं, अपने को समानाधिकारपूर्ण नागरिक समझने लगीं, फ़ैक्टरियों में काम करने लगीं, अपने लोगों के सामाजिक जीवन में हिस्सा लेने

लगीं। बड़ी कठिनाइयों और बुर्जुआ राष्ट्रवादियों के प्रतिरोध के बावजूद नारी मुक्ति आंदोलन सफल हुआ।

बुर्जुआ जालसाज़ दावा करते हैं कि सोवियत रूस ने जातीय प्रदेशों से मुनाफ़े ऐंठे। लेकिन निम्न तथ्य ऐसे दावों की निराधारता को सिद्ध कर देते हैं: १९२४-२५ के वित्तीय वर्ष में संघीय बजट में मध्य एशियाई जनतंत्रों से प्राप्त आय का अंश १, ६३, ००, ००० रूबल था, जबकि उनके विकास पर संघीय बजट से ३, २७, ००, ००० रूबल ख़र्च किये गये। १९२५-२६ के वित्तीय वर्ष में ये आंकड़े क्रमश: १,७९,००,००० रूबल और ७,२१,००,००० रूबल थे।

कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य की सतत हितचिंता तथा रूसी और अन्य जातियों की निस्स्वार्थ सहायता के परिणामस्वरूप भूतपूर्व पिछड़ी जातियों के विकास में एक नयी अवस्था आरंभ हुई। जातीय जनतंत्रों में समग्र रूप में सोवियत संघ से अधिक उच्च औद्योगिक विकास की दर के आधार पर आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के स्तरों का समानीकरण प्राप्त किया गया।

यदि १९१३ के मुक़ाबले में १९४० में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में ११.७ गुनी वृद्धि हुई, तो कज़ाख़स्तान में २० गुनी, जार्जिया में २७ गुनी, किर्गीज़िया में १५३ गुनी और ताजिकिस्तान में ३२४ गुनी वृद्धि हुई।

१९३७ तक जातीय जनतंत्रों में कृषि का सामूहिकीकरण पूरा हो गया था। सामूहिक फ़ार्म प्रणाली की विजय ने पहले की उत्पीड़ित जातियों के आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को तेज़ी से दूर किया, जातीय विविक्ति पर क़ाबू पाने में समर्थ बनाया।

ज़ारशाही द्वारा अपने भाग्य पर मरने के लिए छोड़ दी गयी उत्तर और उत्तर-पूर्व की छोटी जातियों की जातीय-राजकीय व्यवस्था के लिए बड़ा कार्य किया गया। उन्हें चहुंमुखी सहायता प्रदान करने के लिए जून १९२४ में रूसी जनतंत्र की अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्रों की जातियों की सहायतार्थ एक विशेष समिति – उत्तरी समिति – क़ायम की गयी। उत्तर की छोटी जातियों (चुक्ची, नेन्त्सी, ऐवेंकी, कोर्याक, ख़ांती, आदि) को करों से मुक्त कर दिया गया, उन्हें आसान शर्तों पर ऋण दिये गये, उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए स्कूल खोले गये, डाक्टरी सुविधाएं स्थापित की गयीं। राजकीय

व्यापार और सहकारिताओं ने सट्टेबाज़ों और सूदख़ोरों को उखाड़ दिया। सोवियत सत्ता के दो दशकों में ४० से अधिक जातियों ने अपनी लिपियां पायीं।

अत: अपने पारस्परिक सहयोग और सहायता के कारण सोवियत जातियों ने ऐतिहासिक रूप से अल्प अवधि में सच्ची समानता प्राप्त कर ली। यह लेनिनीय जाति नीति की विजय थी।

जातीय प्रश्न के समाधान के लिए किये गये विशाल कार्य के परिणामों का उल्लेख करते हुए सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया: "पारस्परिक बिरादराना सहायता, सर्वप्रथम महान रूसी जनगण की सहायता के आधार पर सभी सोवियत जातीय जनतंत्रों ने अपने आधुनिक उद्योग क़ायम किये, अपने जातीय कर्मीवृंद और बुद्धिजीवी तैयार किये तथा रूप में जातीय और अंतर्वस्तु में समाजवादी संस्कृति विकसित की। पहले की पिछड़ी बहुत-सी जातियों ने विकास की पूंजीवादी अवस्था से बचकर समाजवाद में प्रवेश किया।"

पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि में सोवियत जातियों के जीवन में आये राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने उनकी एकता और दोस्ती को मज़बूत बनाया। समाजवादी जातियों और उप-जातियों का विकास, देश की सभी जातियों को एक समाजवादी परिवार में एकजुट करनेवाले नये, समाजवादी जातीय संबंधों की स्थापना इन परिवर्तनों का महत्वपूर्ण परिणाम थे। इस प्रकार, सोवियत संघ में संक्रमण अवधि के अंत तक भविष्य में जनगण के एक नये ऐतिहासिक समुदाय – सोवियत जनगण – की स्थापना के लिए आधारशिला रखी जा चुकी थी।

जातीय प्रश्न के समाधान में सोवियत संघ का अनुभव संपूर्ण मानवजाति की सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह अनुभव दिखाता है कि जातीय उत्पीड़न के उन्मूलन के बिना, समानता और बिरादराना दोस्ती की स्थापना के बिना नया समाज सफलतापूर्वक नहीं निर्मित किया जा सकता। समानाधिकारपूर्ण जातियों का एक समाजवादी राज्य संघ में स्वैच्छिक एकीकरण मज़दूर वर्ग की, सभी जातियों के मेहनतकशों की शक्ति दसगुनी बढ़ा देता है। सोवियत संघ में जातियों के बीच दोस्ती की विचारधारा की विजय हुई है, जो सोवियत जनगण के विश्वदृष्टिकोण का एक अविच्छेद्य अंग है।

अध्याय ८

शांति के लिए संघर्ष – समाजवाद के लिए संघर्ष

१. सोवियत राज्य की विदेशनीति का लेनिनीय सिद्धांत

किसी भी राज्य की विदेशनीति अंततः सामाजिक-आर्थिक प्रणाली द्वारा निर्धारित होती है और हमेशा शासक वर्ग के हितों को प्रतिबिंबित करती है।

समाजवादी सत्ता की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के साथ विदेशनीति मानवजाति के इतिहास में पहली बार मेहनतकशों की सेवा करने लगी, संपूर्ण मेहनतकश जनगण के हितों को व्यक्त करने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने समाजवादी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप के सिद्धांत तैयार किये, उनकी अंतर्वस्तु, विधियां और रूप निर्धारित किये। सोवियत विदेशनीति राष्ट्रीय हितों और सत्तारूढ़ मज़दूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को सुसमन्वित करती है। लेनिन ने समाजवादी विदेशनीति के सिद्धांतों को तैयार करने में विशाल योगदान किया।

समाजवादी राज्य की विदेशनीति के विज्ञानसम्मत सैद्धांतिक आधार

अक्तूबर क्रांति के पहले ही लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशनीति के क्षेत्र में वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांतों की आधारशिला रखी। क्रांति की विजय के बाद उन्होंने दुनिया में मज़दूरों और किसानों के पहले राज्य की वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका विकास किया, उन्हें मूर्तरूप प्रदान किया। बाद के वर्षों में इन सिद्धांतों ने कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के विदेशनीतिक

कार्यकलाप में व्यावहारिक रूप से पुष्टि पायी।

समाज के बारे में मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत, जो विदेशनीति को सामान्य नीति के एक संघटक अंग के रूप में देखता है, सोवियत विदेशनीति का व्यापक अर्थ में सैद्धांतिक आधार बनाता है। लेनिन ने ज़ोर दिया कि "विदेशनीति को गृहनीति के मुक़ाबले में रखना तो दूर, 'विदेशनीति' को सामान्यतः राजनीति से अलग करना बुनियादी तौर पर ग़लत, अमार्क्सवादी तथा अवैज्ञानिक विचार है।"* विदेश और गृहनीति एक-दूसरी से सघनतः जुड़ी हुई हैं तथा एक-दूसरी को प्रभावित करती हैं।

नीति संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर आर्थिक प्रश्नों के सीधे संबंध में विचार करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक मूल तत्व है। यह उनकी गहन पारस्परिक निर्भरता को प्रकट करना संभव बनाता है। लेनिन की यह सुप्रसिद्ध प्रस्थापना कि राजनीति अर्थव्यवस्था की संकेंद्रित अभिव्यक्ति है, अर्थनीति को राजनीति से पृथक् करने तथा राजनीति की सक्रिय भूमिका को कम करने के प्रयासों के ख़िलाफ़ लक्षित है।

विदेशनीति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण मांग करता है कि उसकी अंतर्वस्तु का विश्लेषण वर्ग दृष्टिकोण से किया जाये। देश-विशेष की सरकार की सभी विदेशनीतिक घोषणाओं और कार्रवाइयों का मूल्यांकन सर्वप्रथम उन वर्गों तथा सामाजिक संस्तरों को दृष्टि में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिनके हितों को वे व्यक्त करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठोस ऐतिहासिक परिस्थितियों और वास्तविक तथ्यों के लेखे-जोखे, इन परिघटनाओं की गत्यात्मकता, विकास की दृष्टि से छानबीन की मांग करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक शक्तियों के निरंतर बदल रहे संबंध और संघर्ष के रूपों को प्रकट किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशनीति में वैज्ञानिक सिद्धांतों के रचनात्मक प्रयोग ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने, उनके

---

*व्ला० इ० लेनिन, 'मार्क्सवाद का विकृत रूप तथा "साम्राज्यवादी अर्थवाद"', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड ६, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८४, पृ० १९५।

विकास की मूल प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करने तथा एक यथार्थवादी और विज्ञानसम्मत विदेशनीति तैयार करने में सोवियत संघ को समर्थ बनाया।

सोवियत विदेशनीति के मूल सिद्धांत

लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने समाजवादी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार के अनुरूप विदेशनीति के दो मूल सिद्धांत तैयार किये: पूंजीवादी दुनिया के मेहनतकशों के साथ, अन्य समाजवादी देशों के साथ और अपनी राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुक्ति के लिए संघर्षरत जनगण के साथ अंतर्राष्ट्रीयतावादी एकता का सिद्धांत ; पूंजीवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत साथ-साथ सोवियत राज्य की विदेश नीति में सक्रिय हैं और एक-दूसरे से सघनतः जुड़े तथा एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

कम्युनिस्ट विदेशनीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विचार को वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के संस्थापकों ने सूत्रित किया था। अपने अस्तित्व के प्रारंभ से ही मार्क्सवाद-लेनिनवाद ने सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद को, सभी जातियों और देशों के मज़दूरों की एकजुटता, एकता और भ्रातृत्वपूर्ण सहबंध को समाजवाद तथा कम्युनिज़्म के साझे ध्येय के लिए सर्वहारा के वर्ग संघर्ष की सफलता की एक मुख्य शर्त माना।

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद मज़दूरों और किसानों के पहले समाजवादी राज्य की विदेशनीति की आधारशिला बना, एक ऐसी नीति, जिसने न केवल सोवियत रूस, वरन् सारी दुनिया के मेहनतकशों के हितों को भी भली भांति ध्यान में रखा।

अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत से साम्राज्यवाद द्वारा उत्पीड़ित जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन भी सीधे जुड़ा हुआ है। लेनिन ने बड़े ही साफ़ ढंग से दिखाया कि साम्राज्यवाद के युग में औपनिवेशिक और अर्ध-औपनिवेशिक जनगण का राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, समाजवाद की विजय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के संघर्ष से एक क्रांतिकारी धारा में मिलता है। इसीलिए उन्होंने ज़ोर दिया कि सर्वहारा वर्ग की विदेशनीति सभी साम्राज्यवा-

इसके साथ ही, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सहयोग के साथ विभिन्न सामाजिक प्रणालियों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक संघर्ष की भी पूर्वकल्पना करता है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व विश्वव्यापी पैमाने पर समाजवाद और पूंजीवाद के बीच शांतिपूर्ण प्रतियोगिता के लिए परिस्थितियां क़ायम करता है; यह उनके बीच वर्ग संघर्ष का एक विशिष्ट रूप है।

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। वे जनवाद, शांति और समाजवाद के लिए संघर्षरत जनगण के हितों के अनुरूप हैं। वे सोवियत विदेशनीति का मूलाधार बनाते हैं। उनमें से एक का कार्यान्वयन सीधे-सीधे दूसरे को भी प्रभावित करता है।

२. सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण को सुनिश्चित बनाने हेतु सोवियत राज्य के विदेशनीतिक कार्यकलाप

शांति संबंधी आज्ञप्ति – सोवियत विदेशनीति का कार्यक्रम

लेनिन द्वारा लिखित और ८ नवम्बर (२६ अक्तूबर), १९१७ को सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत शांति संबंधी आज्ञप्ति सोवियत विदेशनीति का पहला कार्यक्रम विषयक दस्तावेज़ थी। उसमें घोषित सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नयी नीति के समारंभ के द्योतक थे। मानवजाति के इतिहास में पहली बार एक देश–सोवियत संघ–की विदेशनीति मेहनतकशों की सेवा करने लगी। शोषक राज्यों की विदेशनीति से भिन्न सोवियत विदेशनीति आरंभ से ही जनसाधारण पर अवलंबित थी और जनवादी थी। सोवियत रूस की सरकार ने गुप्त राजनय के ख़ात्मे तथा जनता की पीठ के पीछे सांठगांठ से इन्कार के बारे में घोषणा की। ज़ारशाही और अस्थायी सरकार द्वारा की गयी सभी गुप्त और असमान संधियां रद्द कर दी गयीं, उनके पूरे मूलपाठ प्रकाशित किये गये और सारी दुनिया के लोगों ने अपनी नज़रों से देख लिया कि किनके हितों की ख़ातिर करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान किया था। सोवियत विदेश नीति के जनवाद ने कथनी और

करनी, दोनों ही में सभी छोटे-बड़े राष्ट्रों, सभी नस्लों और जातियों की समानता की स्वीकृति में अपना मूर्तरूप पाया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण क़दमों को क्रियान्वित करते हुए सोवियत राज्य ने न केवल दूसरे देशों की सरकारों, बल्कि सीधे उनके जनगण को भी संबोधित किया।

शांति संबंधी आज्ञप्ति और बाद के विदेशनीतिक दस्तावेज़ों में सोवियत सरकार ने विधिवत घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में उसके सभी कार्यकलाप जातियों की समानता और संप्रभुता, अलग होने तथा स्वतंत्र राज्य बनाने की हद तक उनके स्वतंत्र आत्म-निर्णय के अधिकार, सभी जातीय और जातीय-धार्मिक विशेषाधिकारों और प्रतिबंधों से इन्कार तथा जातीय अल्पसंख्यकों और नृजातीय समूहों के स्वतंत्र विकास पर आधारित होंगे।

राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के घोषित सिद्धांत के पूर्णतः अनुरूप सोवियत सरकार दिसम्बर १९१७ में फ़िनलैंड राज्य की, जो अब तक रूसी साम्राज्य का एक अंग था, स्वतंत्रता को मान्यता देनेवाली पहली सरकार थी।

शांति संबंधी आज्ञप्ति में निरूपित सोवियत संघ की विदेशनीति ने दुनिया के अधिकांश जनगण, सभी मेहनतकशों, सभी स्वतंत्रताप्रेमी और प्रगतिशील जनों के मूल हितों को अभिव्यक्त किया। लेकिन आज्ञप्ति में प्रस्तुत कार्यभारों को पूरा करना आसान नहीं था। १० नवम्बर, १९१७ को अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए लेनिन ने कहा: "शांति के लिए संघर्ष शुरू हो रहा है। यह संघर्ष कठिन और अनम्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद हमारे ख़िलाफ़ सभी शक्तियों को लामबंद कर रहा है...।"* पूंजीवादी राज्यों द्वारा की गयी घेरेबंदी में समाजवादी राज्य के लिए अपने अस्तित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संघर्ष करना और साथ ही देश में समाजवाद का निर्माण करना एक अत्यंत महत्व-पूर्ण और कठिन काम था।

---

* व्ला० इ० लेनिन, अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक, ४ (१७) नवम्बर, १९१७।

सोवियत राजनयिक मशीनरी की स्थापना

सरकार की स्थापना के तुरंत बाद ही सोवियत राज्य की विदेश राजनीतिक मशीनरी का संगठन आरंभ हो गया। ज़ारशाही रूस के विदेशी मामलों के मंत्रालय की जगह विदेशी मामलों की जन कमिसारियत क़ायम की गयी, जिसका काम मज़दूरों और किसानों के राज्य की नयी, शांति नीति का संचालन करना था।

उस समय राजनयिक कर्मीवृंद संबंधी प्रश्न उग्र रूप से प्रस्तुत हुआ। विदेशी मामलों के पुराने मंत्रालय में काम करनेवाले राजनयिकों ने सोवियत सत्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण स्थिति अपनायी, उसका बायकाट किया। इस वजह से पार्टी ने सोवियत राजनयिकों के चुनाव और प्रशिक्षण पर निरंतर बड़ा ध्यान दिया। विदेशी मामलों की जन कमिसारियत की मशीनरी को ध्यान में रखते हुए लेनिन ने कहा: "...यह मशीनरी हमारी राजकीय मशीनरी का एक असाधारण अंग है। हमने पुरानी ज़ारशाही मशीनरी से एक भी ऐसे आदमी को उसमें नहीं घुसने दिया है, जिसका कुछ प्रभाव हो। उसमें जिन लोगों को कोई अधिकार प्राप्त हैं, वे सभी कम्युनिस्ट हैं।"* अनुभवी पार्टी कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय भागीदारों – जैसे गेओर्गी चिचेरिन, लेव काराख़ान और मक्सिम लित्विनोव – को राजनयिक पदों पर नियुक्त किया गया।

लेनिन ने सोवियत राजनयिक कार्यकलाप का सीधे संचालन किया। सोवियत रूस के सभी महत्वपूर्ण विदेशनीतिक क़दम उनकी सीधी और सक्रिय भागीदारी से तैयार और क्रियान्वित किये गये। लेनिन सोवियत सत्ता के आधारभूत विदेशनीतिक दस्तावेज़ों के लेखक थे। सोवियत सत्ता के पहले वर्षों में वह स्वयं सोवियत सरकार या विदेशी मामलों की जन कमिसारियत के नोटों, अपीलों और वक्तव्यों के मसविदे तैयार करते थे, उनका संपादन करते थे, तैयार किये जानेवाले दस्तावेज़ों की अंतर्वस्तु के बारे में विस्तृत निर्देश देते थे, सोवियत राजनयिकों के लिए निर्देश तैयार करते थे, विदेशी दूतों, दूतावासों के प्रधानों,

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'जातियों या "स्वायत्तीकरण" का प्रश्न', १९२२।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते और मिलते थे। लेनिन की पुस्तकों और लेखों, पार्टी कांग्रेसों और सोवियतों की कांग्रेसों में दिये गये उनके भाषणों में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का चहुंमुखी विश्लेषण और सोवियत राजनयिक कार्यकलाप का गहन सैद्धांतिक आधार पेश किया गया है।

लेनिन और उनके निकट के सहयोगियों के व्यक्तिगत ध्यान और चिंता के कारण विदेशी मामलों की जन कमिसारियत सोवियत सरकार की वर्गगत समाजवादी विदेशनीति का एक सुदक्ष, कारगर, वैचारिक रूप से मज़बूत तथा प्रखर अस्त्र बन गयी।

रूस को साम्राज्यवादी युद्ध से निकालने के लिए संघर्ष

साम्राज्यवादी युद्ध को समाप्त करना या रूस को उससे बाहर निकालना सोवियत सरकार की विदेशनीति की एक अत्यंत जटिल समस्या और तात्कालिक कार्यभार था। शुरू से ही सोवियत सरकार की नीति मुट्ठीभर शासकों द्वारा अपने हित में चलाये जानेवाले अपराध-पूर्ण और प्रतिक्रियावादी युद्धों के ख़िलाफ़ संघर्ष करने और सभी न्याय-संगत युद्धों, यानी "पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ उत्पीड़ित वर्गों की रक्षा में, उत्पीड़कों के ख़िलाफ़ मुट्ठीभर देशों के साम्राज्यवादियों द्वारा उत्पीड़ित जातियों की रक्षा में, विदेशी हमलावरों से समाजवादी क्रांति की रक्षा में"* युद्धों का समर्थन करने की थी। साम्राज्यवादी, लुटेरू युद्ध को सोवियत सरकार ने "मानवजाति के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा अपराध" घोषित किया और सभी युद्धरत राष्ट्रों और उनकी सरकारों से समामेलनों और हर्जानों के बिना सार्विक, न्यायसंगत और जनवादी शांति के बारे में बातचीत तत्काल शुरू करने का प्रस्ताव किया।

लेकिन एंटेंट देशों (ग्रेट ब्रिटेन, फ़्रांस, आदि) और अमरीका ने सोवियत सरकार के शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया और सार्विक

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'कृषि समस्या पर फ़्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी की थीसिसों की बाबत', १९२१।

शांति-संधि संपन्न करने को असंभव बना दिया। सोवियत सरकार जनगण की इच्छा को पूरा करते हुए जर्मनी तथा उसके मित्र-राष्ट्रों के साथ शांति वार्ताएं शुरू करने के लिए विवश थी। बातचीत के दौरान सोवियत रूस पर लुटेरू और अपमानजनक शांति थोपने का जर्मन साम्राज्यवादियों का इरादा स्पष्ट हो गया।

विद्यमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ने ज़बर्दस्त और ख़तरनाक रूप से हिंसक जर्मन साम्राज्यवाद के सामने पीछे हटने तथा शांति की कठिन शर्तें मानने के लिए सोवियत रूस को मजबूर किया। युद्ध से तबाह देश और थकी सेना युद्ध नहीं जारी रख सकते थे। मातृभूमि और क्रांति को बचाने के लिए शांतिपूर्ण मुहलत की ज़रूरत थी ताकि सोवियत सत्ता को मज़बूत बनाया जा सके, साम्राज्यवादी हमलावरों से देश की रक्षा करने में समर्थ लाल सेना की स्थापना की जा सके। प्रतिक्रांतिकारियों ने शांति वार्ताओं के ख़िलाफ़ उन्मादपूर्ण आंदोलन कर दिया। सोवियत रूस को जर्मन साम्राज्यवादियों से युद्ध की ओर धकेलते हुए विदेशी और रूसी बुर्जुआ वर्ग ने इस तरह से क्रांति का गला घोंटने तथा पुरानी व्यवस्था बहाल करने की उम्मीद की थी।

युद्ध और शांति संबंधी सवाल को अविलंब हल करना आवश्यक हो गया था। स्थिति इस वजह से भी और पेचीदा हो गयी कि पार्टी के भीतर "वामपंथी कम्युनिस्टों" का एक ऐसा गुट बन गया था, जो शांति वार्ताओं को विफल करने की नीति चला रहा था। इस स्थिति का "वामपंथी" दुस्साहसिकतावादी त्रोत्स्की ने समर्थन किया, जो उस समय विदेशी मामलों के जन कमिसार थे और कुछ समय के लिए ब्रेस्त-लितोव्स्क शांति वार्ता में सोवियत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। एक देश में समाजवाद की विजय की संभावना से इन्कार करते हुए वामपंथी कम्युनिस्टों और त्रोत्स्की ने घोषणा की कि रूस में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व और अक्तूबर क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा केवल तभी की जा सकती है जब समाजवादी क्रांति सारी दुनिया में विजयी हो जाये। यह क्रांति, उनके मतानुसार, विश्व साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध द्वारा भड़कायी जानी चाहिए।

पार्टी ने वामपंथी लफ़्फ़ाज़ी के आवरण में छिपायी गयी इस ग़लत और अत्यंत ख़तरनाक स्थिति की अनम्य ढंग से निन्दा की।

शांति वार्ताओं के दौरान जर्मन साम्राज्यवादियों द्वारा थोपी गयी

कठिन शर्तों और पार्टी के भीतर तीव्र संघर्ष के बावजूद शांति की लेनिनीय नीति विजयी हुई। जर्मनी के साथ शांति-संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस शांति-संधि के कारण सोवियत जनतंत्र को वह अल्प मुहलत मिल गयी, जो विदेशी हस्तक्षेप का जवाब देने के लिए आवश्यक थी।

शांति-संधि के हस्ताक्षर का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी था। इस कार्रवाई से सोवियत सरकार ने साम्राज्यवादी युद्ध के ख़िलाफ़ संघर्ष में सारी दुनिया में जनगण की स्थिति को सुदृढ़ बनाया।

ब्रेस्त शांति-संधि पूंजीवादी राज्यों के गुट (जिसका नेतृत्व कैसर का जर्मनी कर रहा था) के साथ समाजवादी राज्य का पहला विदेश-नीतिक समझौता ही नहीं, बल्कि समाजवाद की स्थितियों को मजबूत बनाने के हित में विभिन्न साम्राज्यवादी गुटों के बीच अंतर्विरोधों का पहला सफल उपयोग भी थी। एंटेंट और अमरीका से युद्धरत जर्मन गुट के साथ कठिन शांति-संधि पर हस्ताक्षर करके सोवियत रूस समाजवादी क्रांति और सोवियत जनतंत्र के पहले निर्णायक महीनों में साम्राज्यवादी शक्तियों के संयुक्त आक्रमण से बच गया। पार्टी और सोवियत सरकार ने कठिन और बड़ी क़ुर्बानियों* की क़ीमत पर सोवियत सत्ता तथा अक्तूबर क्रांति की संपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियों को बचा लिया।

विदेशी हस्तक्षेप पर विजय में सोवियत राजनय का योगदान

पहले विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में सोवियत रूस की स्थिति तेज़ी से बदल गयी। एंटेंट और अमरीका ने सोवियत रूस में हस्तक्षेप करने के लिए आंतरिक प्रतिक्रांतिकारियों से सांठगांठ बनायी।**

---

* ब्रेस्त संधि के अनुसार सोवियत रूस ने लिथुआनिया, लाटविया, एस्तोनिया, उक्राइना, बेलोरूस के एक हिस्से, अर्दागान, कार्स और बातुम नगरों को खो दिया। सोवियत सत्ता को अपनी सेना और नौसेना को भंग करना तथा जर्मनी को ६ अरब मार्क का हर्जाना चुकाना पड़ा था। – सं०

** विस्तृत विवरण के लिए देखें अध्याय २।

सोवियत रूस ने हस्तक्षेपकारियों और प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को नष्ट कर दिया तथा लंबे काल के लिए शांति प्राप्त कर ली। इसका बड़ा श्रेय सोवियत विदेशनीति को भी था, जिसने सारी दुनिया को रूस के जनगण के लिए शांतिपूर्ण जीवन का निर्माण करने की संभावना प्राप्त करने की सोवियत सरकार की गहन इच्छा को प्रदर्शित कर दिया।

उन सीमावर्ती राज्यों के साथ, जो पहले रूस का अंग थे, शांतिपूर्ण और अच्छे पड़ोसी जैसे संबंधों की स्थापना के लिए सोवियत राजनयिक प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत रूस को अलग-थलग करने की साम्राज्यवादी योजनाओं को विफल करने में मौलिक भूमिका अदा की। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सुसंगत रूप से पालन करते हुए सोवियत सरकार ने अगस्त-सितम्बर १६१६ में एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया* और फ़िनलैंड की बुर्जुआ सरकारों से राज्यों के रूप में उनकी स्वतंत्रता की मान्यता के आधार पर शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया। बाल्टिक देशों के साथ शांति प्राप्त करना आसान नहीं था, जिनके शासक हलक़े सोवियत रूस के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख़ अपनाये हुए थे तथा पश्चिम की नीति का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन, जैसा कि लेनिन ने १६१६ के अंत में लिखा, "महाशक्तियों का प्रयास, जिनके प्रभाव में निस्संदेह छोटे देश हैं, छोटे देशों को हमारे विरुद्ध लामबंद करने का महाशक्तियों का प्रयास विश्व साम्राज्यवाद के हितों तथा छोटे देशों के हितों के अंतर्विरोध के कारण विफल रहा है।"** २ फ़रवरी, १६२० को एस्तोनिया के साथ शांति-संधि पर हस्ताक्षर किये गये, जिसे लेनिन ने उचित ही "यूरोप की खिड़की" कहा। ऐसी ही संधियां लिथुआनिया

---

* १६१६ में विदेशी हस्तक्षेपकारी फ़ौजों ने सोवियत बाल्टिक जनतंत्रों के भूक्षेत्र पर क़ब्ज़ा कर लिया। उन्होंने लाटविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया में सोवियत सत्ता का तख़्ता उलटने और बुर्जुआ वर्ग का अधिनायकत्व क़ायम करने में सहायता की। – सं०

** व्ला० इ० लेनिन, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के आठवें अखिल रूसी सम्मेलन में केंद्रीय समिति की राजनीतिक रिपोर्ट, २ दिसम्बर, १६१६।

(१२ जुलाई, १९२०), लाटविया (११ अगस्त, १९२०), फ़िनलैंड (१४ अक्तूबर, १९२०) और पोलैंड (१८ मार्च, १९२१) के साथ भी की गयीं। सोवियत रूस के पश्चिमी पड़ोसियों के साथ संबंधों का नियमन सोवियत रूस के प्रति शत्रुता भड़कानेवाली साम्राज्यवादी शक्तियों के निरंतर प्रयासों की परिस्थितियों में सोवियत विदेशनीति की एक निर्विवाद उपलब्धि था। एस्तोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, फ़िनलैंड और पोलैंड के साथ शांति-संधियों के हस्ताक्षर का अर्थ था सोवियत रूस के इर्द-गिर्द तथाकथित "सफ़ाई घेरे" का निर्माण करने की योजनाओं पर पानी फिर जाना। उसने विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक प्रणालियों वाले राज्यों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की संभावना के बारे में लेनिन की प्रस्थापना को व्यावहारिक रूप से सिद्ध कर दिया।

पूर्वी देशों के साथ नये संबंधों की स्थापना

लेनिन की शांति संबंधी आज्ञप्ति, मेहनतकश और शोषित जनगण के अधिकारों की घोषणा, रूस की जातियों के अधिकारों की घोषणा, रूस और पूरब के सभी मेहनतकश मुस्लिमों से सोवियत सरकार की अपील ने सभी पराधीन देशों के मेहनतकशों को स्पष्टत: दिखा दिया कि दुनिया में एक ऐसे राज्य का अभ्युदय हुआ है, जिसका सिद्धांत सभी राज्यों और जातियों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और समानता की स्वीकृति और समर्थन है।

१९२१ में पूरब के देशों के साथ हस्ताक्षरित समानाधिकारपूर्ण संधियां सोवियत राज्य द्वारा घोषित विदेशनीतिक सिद्धांतों का व्यावहारिक कार्यान्वयन थीं। अक्तूबर क्रांति तथा विदेशी आक्रमणकारियों पर लाल सेना की विजयों से प्रेरित होकर उन देशों के जनगण ब्रिटिश दमन के ख़िलाफ़, राजकीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए संघर्ष करने हेतु उठ खड़े हुए। ईरान, तुर्की और अफ़ग़ानिस्तान के साथ, जो बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों पर बहुत निर्भर थे, वार्ताएं चलाने में सोवियत सरकार ने उन्हें समानाधिकारपूर्ण संप्रभु देशों के रूप में देखा।

जनवरी १६१८ के अपने नोट में सोवियत सरकार ने ईरान के प्रति सोवियत रूस की नीति के सिद्धांतों को स्पष्टतः दिखाया। २६ जून, १६१६ को उसने ईरान की सरकार और जनगण से एक अपील की। उसमें सोवियत सरकार ने ज़ारशाही सरकार के ऋण दायित्वों संबंधी ईरान के सभी भुगतानों को रद्द करने तथा ईरान की राजकीय परिसंपत्तियों पर उस नियंत्रण को त्यागने की तत्परता व्यक्त की, जिसे पहले ज़ारशाही और ब्रिटिश सरकारें परस्पर समझौते के आधार पर करती थीं। सोवियत सरकार ने कास्पियन सागर को ईरानी जहाज़रानी के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया और रूसी रियायती अधिकारों–राजकीय और निजी, दोनों ही–को समाप्त कर दिया। उसने ईरान में रूसी बट्टा और उधार बैंक को उसकी सारी संपत्तियों, ज़ारशाही रूस द्वारा ईरान में निर्मित रेलवे, मोटर मार्गों और बंदरगाहों तथा ईरानी भूक्षेत्र पर रूस के स्वामित्व में सभी डाक और तार सुविधाओं को बिना किसी मुआवज़े के ईरानी जनगण को हस्तांतरित करने की भी घोषणा की। ईरान में रहनेवाले रूसी नागरिकों को प्राप्त सभी विशेषाधिकारों के खात्मे की घोषणा की गयी।

सोवियत सरकार के इस क़दम का अर्थ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीति से पूर्ण विच्छेद, सभी जातियों की समानता की स्वीकृति के आधार पर समाजवादी राज्य की सर्वथा नयी नीति का कार्यान्वयन था। उसने रूसी-ईरानी संबंधों के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात किया।

तरह-तरह की बाधाओं के बावजूद २६ फ़रवरी, १६२१ को सोवियत-ईरानी संधि हस्ताक्षरित हुई। उसने ईरान की स्वतंत्रता और संप्रभुता को स्वीकार किया, ईरान के साथ ज़ारशाही सरकार द्वारा की गयी उन संधियों, कन्वेंशनों और समझौतों को रद्द कर दिया, जो ईरानी जनता के अधिकारों का अतिक्रमण करते थे, और रूस तथा ईरान के बीच सामान्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की।

संधि में उन आर्थिक प्रस्तावों पर व्यवस्थाएं भी शामिल थीं, जिन्हें सोवियत सरकार ने २६ जून, १६१६ के अपने नोट में किया था। सोवियत सरकार द्वारा ईरानी जनगण को सुपुर्द की गयी संपत्ति का मूल्य लगभग ६० करोड़ रूबल स्वर्ण था। ईरान में ज़ारशाही रूस को प्राप्त सभी विशेषाधिकारों और छूटों से सोवियत सरकार का

स्वैच्छिक इन्कार एक महाशक्ति और एक छोटे देश के बीच संबंधों के इतिहास में अभूतपूर्व था।

अफ़ग़ानिस्तान पहला देश था, जिसके साथ सोवियत संघ ने २७ मई, १६१६ को राजनयिक संबंध स्थापित किये। सोवियत जनतंत्र ने राष्ट्रीय स्वावलंबन की रक्षा में अफ़गान जनगण को कारगर सहायता प्रदान की, अफ़ग़ानिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी जैसे संबंधों की स्थापना की, जिनकी बाद के वर्षों में की गयी समानाधिकारपूर्ण संधियों और समझौतों में पुष्टि हुई और उन्हें मज़बूत बनाया गया। २८ फ़रवरी, १६२१ को मास्को में सोवियत-अफ़ग़ान संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने दो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की। दोनों देशों ने एक-दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार किया और उसका सम्मान करने का दायित्व ग्रहण किया। यह पहली समानाधिकारपूर्ण संधि थी, जिसे अफ़ग़ानिस्तान ने एक महाशक्ति के साथ की थी।

जून १६२१ में सोवियत सरकार ने काबुल में अपने प्रतिनिधि को उन देशों के प्रति एक सुस्पष्टतः निर्धारित नीति का अनुसरण करने का निर्देश दिया, जो अफ़ग़ानिस्तान की भांति अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। निर्देश में कहा गया था कि "हमारी नीति सभी जातियों के बीच शांति और सहयोग की नीति है। वर्तमान समय में, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़ी पूरब की जातियां विदेशी आर्थिक उत्पीड़न से पीड़ित हैं, समाजवादी सोवियत रूस उनका एकमात्र मित्र है।" रूस ने अफ़ग़ानिस्तान को रूस में भी और अन्य देशों में भी ख़रीदे गये मालों का अपने भूक्षेत्र से स्वतंत्र तथा निःशुल्क परिवहन का अधिकार दिया। सोवियत संघ अफ़ग़ानिस्तान को वित्तीय और दूसरी आर्थिक सहायता भी देने को सहमत हुआ। १६२३ के अंत तक सोवियत सरकार ने सोवियत-अफ़ग़ान संधि के तहत सहायता संबंधी अपने सभी दायित्वों को पूरा कर दिया था। सोवियत सहायता ने अफ़ग़ानिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

आगे चलकर सोवियत राज्य और पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित और विस्तारित हुए।

सोवियत रूस द्वारा घोषित विदेश और जातीय नीति के नये सिद्धांत तुर्की के साथ उसके संबंधों द्वारा भी पुष्ट हुए। अक्तूबर क्रांति के बाद पहले महीनों में तुर्की जर्मनी की तरफ़ से रूस के ख़िलाफ़

लड़ रहा था। वह ब्रेस्त संधि का एक भागीदार था। ब्रेस्त संधि का उल्लंघन करते हुए तुर्की के शासक हलक़ों ने सोवियत काकेशिया में हस्तक्षेप किया। पर तुर्की युद्ध की अग्नि-परिक्षाओं को नहीं झेल सका और पराजित शक्तियों के बीच निकला। उसके समक्ष विभाजन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता की पूर्ण क्षति का ख़तरा प्रस्तुत हो गया था।

सामरिक पराजय और रूस में अक्तूबर क्रांति के विचारों के प्रभाव में तुर्की में आंतरिक प्रतिक्रिया तथा एंटेंट के साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन फैल गया, जिसका नेतृत्व मुस्तफ़ा कमाल-पाशा ने किया। सोवियत रूस ने तुरंत इस आंदोलन का समर्थन किया। अतातुर्क ("तुर्कों का पिता") की उपाधि धारण करनेवाले जनरल मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में तुर्की की क्रांतिकारी सरकार ने अप्रैल १९२० में सोवियत सरकार से दोस्ताना संबंध क़ायम करने का प्रस्ताव किया और उससे साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ़ संघर्ष में तुर्की जनगण का समर्थन करने का निवेदन किया। लेनिन और सोवियत सरकार के नाम अपने पत्र में अतातुर्क ने लिखा: "हम अपने समूचे कार्य और अपनी सभी कार्रवाइयों को रूसी बोल्शेविकों के कार्य-कलाप से संयुक्त करने का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, जिनका उद्देश्य साम्राज्यवादी सरकारों के खिलाफ़ संघर्ष करना और सभी शोषितों को उनके शासन से मुक्त कराना है।" सोवियत सरकार फ़ौरन बातचीत चलाने को सहमत हो गयी। इस बात के बावजूद कि ब्रिटेन और फ़्रांस ने धमकियों और आश्वासनों के ज़रिये तुर्की की क्रांतिकारी सरकार को सोवियत रूस के साथ बातचीत चलाने से रोकने के लिए कोई कोर-कसर न उठा रखी, १६ मार्च, १९२१ को मास्को में मैत्री और भ्रातृत्व की सोवियत-तुर्की संधि हस्ताक्षरित हुई। दोनों पक्षों ने सभी पुरानी संधियों को रद्द घोषित किया। अपनी ओर से सोवियत सरकार ने घोषणा की कि वह तुर्की और ज़ारशाही सरकारों के बीच की गयी पहले की संधियों के तहत सभी वित्तीय और अन्य दायित्वों से तुर्की को स्वतंत्र मानती है।

तुर्की के लिए सोवियत-तुर्की संधि का बड़ा महत्व था। उसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में उसकी स्थितियों को सुदृढ़ बनाया, तुर्की सरकार के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत में उतनी ही अनुकूल शर्तें प्राप्त करने की संभावना को सुनिश्चित किया।

मास्को संधि पर हस्ताक्षर होने के साथ-साथ रूसी और तुर्की प्रतिनिधिमंडल तुर्की को १ करोड़ रूबल स्वर्ण की वित्तीय सहायता देने के बारे में समझौते पर भी पहुंच गये। सोवियत रूस ने तुर्की को न केवल वित्तीय, वरन् भौतिक सहायता देने की भी संभावना पायी, भले ही स्वयं वह कठिन काल से गुज़र रहा था, जब ख़राब फ़सल और भुखमरी ने विदेशी हस्तक्षेप के कुपरिणामों को और बढ़ा दिया था।

साम्राज्यवादी शक्तियों से दोनों देशों के संघर्ष के वर्षों में संधि द्वारा क़ायम सोवियत-तुर्की संबंधों ने राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध में तुर्की जनगण की विजय तथा सोवियत संघ और तुर्की जनतंत्र के बीच दोस्ताना संबंधों के सुदृढ़ीकरण में सहायता की।

मंगोलिया के साथ सोवियत रूस के संबंध क्रांतिकारी एकजुटता का ज्वलंत उदाहरण थे। सोवियत जनगण ने मंगोलियाई जनगण को विदेशी आक्रमणकारियों और आंतरिक सामंती प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध उनके न्यायसंगत संघर्ष में विजय पाने में अमूल्य सहायता प्रदान की। मैत्रीपूर्ण संबंध क़ायम करने के बारे में सोवियत-मंगोलियाई समझौते पर ५ नवम्बर, १९२१ को मास्को में हस्ताक्षर हुए। वह मंगोलियाई जन राज्य द्वारा एक विदेशी शक्ति के साथ की गयी पहली समानाधिकारपूर्ण संधि थी, ऐसी संधि, जिसने पूंजीवादी अवस्था से बचकर समाजवादी मार्ग पर मंगोलिया के विकास में सहायता की। इस समझौते ने ज़ारशाही सरकार द्वारा मंगोलिया पर थोपी गयी पहले की संधियों के ख़ात्मे की पुष्टि की और स्वतंत्र सहयोग तथा मैत्री के लिए दोनों देशों के जनगण की इच्छा की घोषणा की। पक्षों ने अपने भूक्षेत्र पर ऐसे किसी भी गिरोह को कार्य न करने का दायित्व अपने ऊपर लिया, जो दूसरे पक्ष का शत्रु हो और व्यापारिक, विधिक तथा पारस्परिक हित के अन्य प्रश्नों के विनियमन की विधियां निर्धारित कीं। समझौते ने ज़ारशाही रूस को मंगोलिया के ५० लाख रूबल स्वर्ण के ऋण को ख़ारिज कर दिया।

समझौते पर हस्ताक्षर सुदूर पूर्व में शांति के सुदृढ़ीकरण और सोवियत तथा मंगोलियाई जनगण के बीच दोस्ताना संबंधों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क़दम था।

उत्पीड़ित जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को सोवियत रूस

का चहुंमुखी समर्थन और पूरब के देशों के साथ नये, समानाधिकारपूर्ण संबंधों की स्थापना सोवियत विदेशनीति के सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद तथा उसके गहन क्रांतिकारी सार की अभिव्यक्ति थी।

पूंजीवादी देशों के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंधों की स्थापना के प्रयास

विदेशी हस्तक्षेप और गृहयुद्ध की समाप्ति के साथ सोवियत रूस ने अपने ऐतिहासिक विकास की एक नयी अवधि – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहाली और समाजवाद के निर्माण की अवधि – में प्रवेश किया। समाजवादी निर्माण के कार्यभारों की सफल पूर्ति ऐसी बाह्य परिस्थितियों की स्थापना पर बहुत निर्भर करती थी, जो देश को पूंजीवादी देशों के नये हस्तक्षेप के प्रयासों से बचायें और सोवियत जनगण को अपनी सारी शक्ति घरेलू समस्याओं के समाधान में लगाने की संभावना प्रदान करें।

समाजवादी क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा, सोवियत संघ की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक शक्ति का सुदृढ़ीकरण और शांति के लिए उसका सुसंगत संघर्ष राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारक थे। विद्यमान ऐतिहासिक परिस्थिति में विभिन्न सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वस्तुगत आवश्यकता, विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया के आगे विकास की पूर्वशर्त था।

शांति की सुरक्षा और समाजवाद के निर्माण के लिए अनुकूल विदेशनीतिक परिस्थिति की स्थापना में सोवियत राज्य और पूंजीवादी देशों के बीच संबंधों के नियमन का बड़ा महत्व था। गृहयुद्ध के वर्षों में ही लेनिन ने पूंजीवादी देशों की आर्थिक सहयोग में दिलचस्पी पैदा करके उनके साथ संबंधों के नियमन का विचार पेश किया था। १९२१ में पार्टी की दसवीं कांग्रेस ने युद्ध से शांतिपूर्ण निर्माण में संक्रमण की अवधि में पार्टी के कार्यभारों को सूत्रित किया और ज़ोर दिया कि सोवियत विदेशनीति को प्राप्त नयी शांतिपूर्ण मुहलत को स्थायी शांति में बदलने, सोवियत रूस के अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक अलगाव को समाप्त करने तथा सभी देशों के साथ अधिक स्थिर,

स्थायी शांतिपूर्ण संबंध क़ायम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। 'पूंजीवादी घेरे में सोवियत जनतंत्र' नामक प्रस्ताव में कहा गया कि "संधियों और समझौतों के आधार पर सोवियत जनतंत्र और पूंजीवादी देशों के बीच नये संबंधों की स्थापना की संभावना का सर्वप्रथम जनतंत्र की उत्पादक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, मुख्य उत्पादक शक्ति–मज़दूर वर्ग–की स्थिति को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।" सोवियत राजनय ने पार्टी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यभार को पूरा करने हेतु सक्रिय कार्रवाई आरंभ की और इसमें उसने निश्चित सफलताएं पायीं।

ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों का हस्ताक्षर पूंजीवादी देशों के साथ सामान्य संबंधों की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग था। सोवियत रूस अपने विदेश व्यापार संबंधों को विश्वसनीय रूप से विस्तारित कर रहा था, जो नवोदित राज्य के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से मौलिक महत्व रखते थे। सोवियत रूस के राजनीतिक और आर्थिक अलगाव की दीवार में दरार पैदा की जा चुकी थी।

साम्राज्यवादी राज्यों के मोर्चे में दरार

पूंजीवादी देशों के साथ आर्थिक सहयोग की स्थापना को आसान बनाने का प्रयास करते हुए सोवियत सरकार ने २८ अक्तूबर, १९२१ को ज़ारशाही सरकार के युद्धपूर्व ऋणों को निश्चित शर्तों पर स्वीकार करने की अपनी तत्परता के बारे में घोषणा की और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया, जो रूस पर विदेशी दावों और विदेशी राज्यों पर सोवियत दावों पर विचार करेगा तथा रूस और उसके विरोधियों के बीच शांति की शर्तें तैयार करेगा।

शीघ्र ही पश्चिम की बड़ी पूंजीवादी शक्तियां भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता को मान गयीं। ६ जनवरी, १९२२ को कैन में एक बैठक में उन्होंने ऐसा सम्मेलन बुलाने और सोवियत रूस को निमंत्रित करने संबंधी एक प्रस्ताव पास किया।

सम्मेलन अप्रैल-मई १९२२ में जेनोआ (इटली) में हुआ। सोवियत

प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में सभी सोवियत जनतंत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व किया और वह उनके नाम पर कोई भी समझौता या संधि कर सकता था। उसने ज़ारशाही सरकार के युद्धपूर्व ऋणों को मानने की तत्परता व्यक्त की बशर्ते कि रूस को नया ऋण दिया जाये और सोवियत राज्य को क़ानूनी मान्यता मिले। सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी संपत्ति-मालिकों को रूस में उनकी क्षतियों के लिए कुछ हर्जाना देने के बारे में घोषणा की, लेकिन अपनी बारी में उसने हस्त-क्षेपकारी फ़ौजों और रूसी श्वेत रक्षकों द्वारा देश को पहुंचायी गयी क्षतियों के लिए भी हर्जाने का दावा किया।

पर साम्राज्यवादियों की अपनी ही योजनाएं थीं। वे समान आधार पर सोवियत रूस से सहयोग करना नहीं चाहते थे और आर्थिक तथा राजनीतिक दबाव के ज़रिये देश पर औपनिवेशिक निज़ाम थोपने की आशा करते थे। उन्होंने रूस के सभी ऋणों का भुगतान करने तथा भूतपूर्व विदेशी मालिकों को राष्ट्रीयकृत संपत्तियां लौटाने की मांग की। साम्राज्यवादियों के दावे यहां तक बढ़ गये थे कि उन्होंने सोवियत वित्त पर, रूस की संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी विदेशी नियंत्रण क़ायम करना चाहा।

सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने साम्राज्यवादी दावों को दृढ़तापूर्वक ठुकरा दिया और उनके लुटेरे स्वरूप का पर्दाफ़ाश किया। उसने विभिन्न सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार की भी रक्षा की। अपनी घोषणा में सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने ज़ोर दिया कि वर्तमान ऐतिहासिक युग में पुरानी और उदीयमान नयी सामाजिक संरचनाओं का साथ-साथ बने रहना संभव है, कि स्वामित्व की इन दो प्रणालियों के राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग अनिवार्यत: आवश्यक है।

सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने शस्त्रास्त्रों की सामान्य कटौती करने तथा युद्ध के अत्यंत बर्बर साधनों – विषैली गैसों और वायुमंडल में सशस्त्र संघर्ष पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रश्न पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव रखा। पूंजीवादी देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इन प्रश्नों पर बहस से इन्कार करने के बावजूद जेनोआ सम्मेलन में सोवियत प्रतिनि-धिमंडल द्वारा प्रस्तुत शांतिपूर्ण सहयोग तथा निरस्त्रीकरण के व्यापक कार्यक्रम ने सभी देशों और जनगण को विश्व के पहले समाजवादी

राज्य की विदेशनीति का स्वरूप और उद्देश्य दिखा दिये।

१६ अप्रैल, १९२२ को जेनोआ के उपनगर रपाल्लो में सोवियत जनतंत्र और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संधि का हस्ताक्षरित होना जेनोआ सम्मेलन के कार्य के दौरान सोवियत राजनय की एक बड़ी सफलता थी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई, आर्थिक सहयोग के चहुंमुखी विकास के बारे में सहमति पर पहुंचा गया। पक्षों ने सभी युद्ध-दावों को पारस्परिक तौर पर रद्द कर दिया। जर्मनी ने सोवियत रूस में राष्ट्रीयकृत संपत्तियों की क्षतिपूर्ति के दावों को छोड़ दिया। अपनी बारी में सोवियत रूस ने युद्ध हर्जानों को छोड़ दिया। संधि में दोनों देशों के बीच संबंधों में सर्वाधिक कृपापात्र राष्ट्र के सिद्धांत के पालन और पारस्परिक लाभ के आधार पर आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों के विस्तार की व्यवस्था थी।

रपाल्लो संधि दो विरोधी प्रणालियों – समाजवादी और पूंजीवादी – के देशों की समानता को स्वीकार करनेवाला पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ थी। इस संधि के हस्ताक्षर ने सोवियत रूस के ख़िलाफ़ बड़े पूंजीवादी देशों के संयुक्त मोर्चे को तोड़ने में सहायता की। उसने सोवियत जनतंत्र की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मज़बूत बनाया।

हालांकि जर्मनी को छोड़कर बड़े पूंजीवादी देशों ने सोवियत सरकार को आधिकारिक मान्यता देने और उसके साथ राजनयिक संबंध क़ायम करने से इन्कार किया, दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (पहले जेनोआ में और बाद में हेग में) में पूर्णाधिकारप्राप्त देश के तौर पर सोवियत रूस की भागीदारी उनके द्वारा वास्तविक मान्यता की द्योतक थी।

सोवियत राज्य की विदेशनीतिक स्थिति का सुदृढ़ीकरण

बड़े पूंजीवादी देशों द्वारा सोवियत रूस के आर्थिक और वित्तीय बायकाट ने देश की अर्थव्यवस्था की बहाली में कठिनाइयां भले ही पेश कीं, लेकिन वह समाजवाद के निर्माण को विफल नहीं बना सका। १९२२ की शरत् में सुदूर पूर्व से जापानी हस्तक्षेपकारियों के निकाल बाहर किये जाने ने एक बार पुनः दिखा दिया कि सोवियत रूस के ख़िलाफ़ सशस्त्र हस्तक्षेप की नीति पर पानी फिरकर ही रहेगा।

२ दिसम्बर, १९२२ को सोवियत सरकार की पहल पर मास्को में एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया गया। उसमें रूसी संघात्मक जनतंत्र के अलावा पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया और फ़िनलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सोवियत सरकार ने सम्मेलन में भाग लेनेवाले देशों की स्थल सेनाओं में सैनिकों की संख्या को पारस्परिक तौर से एक-चौथाई तक घटाने तथा सैन्य व्ययों में बड़ी कटौती करने का प्रस्ताव किया। हालांकि सम्मेलन किसी समझौते पर नहीं पहुंचा, उसने शांति के विचार को प्रचारित करने में सहायता की, निरस्त्रीकरण की समस्या की ओर जनसाधारण का ध्यान खींचा, सारी दुनिया को सोवियत विदेशनीति के शांतिप्रिय स्वरूप को दिखाया और सोवियत राज्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

दिसम्बर १९२२ में सोवियत संघ की स्थापना ने सोवियत राज्य की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति को और मज़बूत बनाया तथा संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक सक्रिय ढंग से प्रभावित करने की संभावना बढ़ा दी।

संसार के पहले समाजवादी देश के आर्थिक और राजनीतिक सुदृढ़ीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तनों ने पूंजीवादी देशों को सोवियत राज्य को मान्यता न देने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। १९२४ का वर्ष सोवियत संघ और दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का वर्ष था। १९२४-२५ में सोवियत संघ ने १३ पूंजीवादी देशों के साथ राजनयिक संबंध क़ायम किये, विभिन्न नये व्यापारिक समझौते किये।

अंततः किस चीज़ ने पूंजीवादी देशों को सोवियत संघ को आधिकारिक मान्यता देने के लिए मजबूर किया? यह सबसे पहले था हथियारों के बल या आर्थिक नाकेबंदी से सोवियत राज्य को मिटाने के प्रयासों का दिवाला, सोवियत संघ की आर्थिक उन्नति और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि, सोवियत संघ के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने में पूंजीवादी देशों के व्यापारिक हलक़ों की दिलचस्पी तथा पूंजीवादी देशों में मेहनतकशों और उत्पीड़ित जनगण के बीच समाजवादी देश की बढ़ती प्रतिष्ठा।

सोवियत संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्राप्त सफलताएं नये समाज के निर्माण के लिए शांतिपूर्ण परिस्थितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु उसके

संघर्ष में आगे का एक बड़ा क़दम थीं। वे पार्टी और सोवियत सरकार की लेनिनीय नीति का नियमसंगत परिणाम तथा सोवियत विदेशनीति की सत्यता की पुष्टि थीं।*

दो युद्धों से तहस-नहस हुई अर्थव्यवस्था की बहाली पूरी करके सोवियत संघ १९२५ में समाजवादी निर्माण के एक मुख्य कार्यभार – समाजवादी औद्योगीकरण – को अमल में लाने लगा। चूंकि शांतिपूर्ण निर्माण की सफलता बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर करती थी, १४वीं पार्टी कांग्रेस ने सोवियत विदेशनीतिक कार्यभारों पर विशेष ध्यान दिया। उसने निम्नलिखित बातों पर ज़ोर दिया: "पहले, नये युद्धों को रोकने और फिर शांति की रक्षा करने की नीति के अनुसार कार्य चलाना ... शांति का विचार हमारी सरकार की नीति, हमारी विदेशनीति का आधार है ... दूसरे, विदेश व्यापार की इजारेदारी के सुदृढ़ीकरण के आधार पर विदेशों के साथ हमारे व्यापार के विस्तार की नीति के अनुसार कार्य चलाना। तीसरे, साम्राज्यवादी युद्ध में पराजित देशों, उन देशों के साथ निकट संपर्क क़ायम करने की नीति के अनुसार कार्य चलाना जो ... महाशक्तियों के प्रभुत्ववादी गुट के विरोधी हैं। चौथे, पराधीन और औपनिवेशिक देशों के साथ सहबंध के लिए कार्य चलाना।"

सोवियत-विरोधी गुट की स्थापना करने के प्रयासों के ख़िलाफ़ संघर्ष

सोवियत संघ में समाजवादी निर्माण की सफलताओं और अन्य देशों में मेहनतकशों पर उनके क्रांतिकारी प्रभाव को साम्राज्यवादी राज्यों के शासक हलक़ों ने संपूर्ण पूंजीवादी प्रणाली को एक ख़तरे के रूप में लिया। सोवियत राज्य की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर एंटेंट के साम्राज्यवादी सोवियत संघ के ख़िलाफ़ पूंजीवादी देशों का संयुक्त मोर्चा बनाने लगे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस गुट का एक प्रमुख संगठनकर्ता था।

ब्रिटिश सरकार की खुली सोवियत-विरोधी कार्रवाइयां, सोवियत व्यापार कार्यालयों पर हमले और सोवियत राजनयिकों के विरुद्ध उकसावेभरी कार्रवाइयां, सोवियत संघ के साथ राजनयिक और व्यापा-

रिक संबंध-विच्छेद (मई १६२७) तथा बाद में पोलैंड और चीन में सोवियत राजनयिकों की हत्याएं – इन सबका उद्देश्य सोवियत संघ के ख़िलाफ़ युद्ध भड़काना था।

लेकिन साम्राज्यवादियों की सारी सोवियत-विरोधी तिकड़मों पर पानी फिर गया। सोवियत संघ ने शांतिप्रिय नीति का सतत अनुसरण किया, जंगबाज़ों का पर्दाफ़ाश किया, सोवियत-विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयासों के विरुद्ध संघर्ष किया और अपनी रक्षा-क्षमता को सर्वतोमुखी रूप से मज़बूत किया।

१६२५-२७ के वर्षों में सोवियत संघ ने जापान, जर्मनी, लिथुआनिया, तुर्की, अफ़ग़ानिस्तान, और ईरान के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण संधियां और समझौते किये। १६२५ के शुरू में सोवियत संघ और जापान के बीच राजनयिक संबंध क़ायम किये गये। सोवियत संघ और जापान के बीच संबंधों के नियमन ने पूंजीवादी देशों द्वारा सोवियत संघ की आधिकारिक मान्यता की अवधि पूरी की तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को काफ़ी मज़बूत बनाया।

उन परिस्थितियों में जब जर्मन शासक हलक़े पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन से निकट संपर्क क़ायम करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे थे, सोवियत संघ और जर्मनी के बीच पांच-वर्षीय तटस्थता और अनाक्रमण संधि का हस्ताक्षर (२४ अप्रैल, १६२६) भी सोवियत विदेशनीति की एक बड़ी सफलता था। सोवियत सरकार बाल्टिक देशों और पोलैंड के साथ भी ऐसे समझौते करने के लिए तैयार थी।

२८ सितम्बर, १६२६ को सोवियत संघ ने लिथुआनिया के साथ तटस्थता संधि पर हस्ताक्षर किये। इस तरह, बाल्टिक देशों को सोवियत-विरोधी गुट में खींचने के इंगलैंड के प्रयास नाकाम हो गये।

पूरब के देशों ने उचित ही सोवियत संघ को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में अपना मित्र माना। इसने सोवियत संघ और उसके पूर्वी पड़ोसियों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के विकास के लिए दृढ़ आधार की स्थापना की।

१७ दिसम्बर, १६२५ को सोवियत संघ और तुर्की के बीच हस्ताक्षरित अनाक्रमण और तटस्थता की संधि ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में और सुधार किया। सोवियत संघ और तुर्की के बीच

राजनीतिक संबंधों के सुदृढ़ीकरण के साथ आर्थिक संबंध भी विकसित हुए। १९२७ में पहले सोवियत-तुर्की व्यापारिक समझौते के हस्ताक्षर के बाद इन संबंधों का बड़ी सफलतापूर्वक विकास हुआ।

सोवियत-अफ़ग़ान संबंध भी विस्तारित हुए। ३१ अगस्त, १९२६ को सोवियत संघ और अफ़ग़ानिस्तान ने तटस्थता और अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किये जिसके परिणामस्वरूप परस्पर राजनीतिक संबंध और भी मज़बूत बने, जो दोनों देशों के लिए बड़ा लाभप्रद था।

सोवियत संघ और ईरान के बीच दोस्ताना संबंध भी सुदृढ़ बनते गये। १ अक्तूबर, १९२७ को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मास्को में गारंटी और तटस्थता के बारे में एक संधि तथा व्यापारिक और अन्य आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

जर्मनी, लिथुआनिया और पूर्वी देशों के साथ की गयी संधियों ने यह सिद्ध कर दिया था कि सोवियत राजनय सोवियत संघ के अधिकांश पड़ोसी देशों, विशेष रूप से एशियाई देशों में ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवादियों के षड्यंत्र को नाकाम करने में सफल रहा था। उन परिस्थितियों में, जबकि साम्राज्यवादी शक्तियां सोवियत संघ के पड़ोसी देशों को सोवियत-विरोधी गुट में खींचने की कोशिश कर रही थीं, इन संधियों का हस्ताक्षरित होना विशेष महत्व रखता था। अफ़ग़ानिस्तान, तुर्की और ईरान के शासक हलक़ों ने उचित ही यह माना कि सोवियत-विरोधी गुट में उनकी भागीदारी उनके राष्ट्रीय हितों से मेल नहीं खाती। पड़ोसी एशियाई देशों ने शांति और जनगण की मुक्ति की सोवियत नीति का सही मूल्यांकन किया।

सोवियत संघ से आर्थिक संबंध बनाये रखने में दिलचस्पी रखनेवाले बहुत-से पूंजीवादी देशों ने भी सोवियत-विरोधी गुट में शामिल होने की इच्छा नहीं व्यक्त की।

इस प्रकार, कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने सोवियत राज्य के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण कार्यभार को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया और सोवियत संघ के विरुद्ध नया सशस्त्र हस्तक्षेप संगठित करने के लिए एक संयुक्त सोवियत-विरोधी गुट की स्थापना करने के साम्राज्यवादियों के प्रयासों को विफल बना दिया। इसके ज़रिये सोवियत संघ में समाजवाद के सफल निर्माण के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को सुनिश्चित बनाया गया। दिसम्बर १९२७ में हुई १५वीं

पार्टी कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत संघ द्वारा प्राप्त बड़ी सफलताओं का उल्लेख करते हुए आगे की अवधि के लिए सोवियत विदेशनीतिक कार्यभार निर्धारित किये। वे निम्नलिखित थे:

१) सोवियत संघ में समाजवाद के आगे विकास की एक मूल शर्त के रूप में शांति नीति – साम्राज्यवादी युद्धों के ख़तरे के विरुद्ध संघर्ष की नीति – को कार्यान्वित करना; २) पश्चिम यूरोप के देशों के मज़दूरों और उत्पीड़ित देशों के मेहनतकशों के साथ सोवियत संघ के मज़दूरों के बिरादराना संबंधों को सुदृढ़ बनाना; ३) सोवियत संघ की आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करते हुए पूंजीवादी देशों के साथ आर्थिक संबंध विकसित करना; ४) देश की रक्षा-क्षमता और सशस्त्र सेनाओं की शक्ति को सुदृढ़ बनाना; ५) आवश्यक आर्थिक भंडारों (अनाज, माल, मुद्रा और सैन्य सामग्री के भंडारों) को संचित करना।

सोवियत निरस्त्रीकरण कार्यक्रम

सोवियत निरस्त्रीकरण कार्यक्रम शांति के लिए और बढ़ते साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों द्वारा उत्पन्न युद्ध के ख़तरे के ख़िलाफ़ संघर्ष में बड़ा महत्व रखता था। उसमें सार्विक और पूर्ण निरस्त्रीकरण की व्यवस्था थी तथा इसे सुनिश्चित बनाने के लिए ठोस क़दम पेश किये गये थे।

इस कार्यक्रम को सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर १९२७ में राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण आयोग में पेश किया था, लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने उसे ठुकरा दिया। तब सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने आंशिक निरस्त्रीकरण का मसविदा पेश किया। पर उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। पूंजीवादी देशों के प्रतिनिधियों की इस स्थिति ने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि उन्होंने अपनी नीति नये विश्वयुद्ध की तैयारियों पर आधारित की थी।

उस समय विश्व शक्तियों के संतुलन की वजह से सोवियत संघ अपने कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने में भले ही सफल न हुआ हो, लेकिन उसने दुनिया के सामने शांति के लिए, पूंजीवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए अपनी इच्छा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों

के हल की एक विधि के रूप में युद्ध को मिटाने की अपनी तत्परता को एक बार पुनः प्रदर्शित कर दिया। पूंजीवादी देशों के व्यापक जनसाधारण की नज़रों में शांति के एक दुर्ग के रूप में सोवियत संघ की प्रतिष्ठा और बढ़ गयी।

विश्व साम्राज्यवाद की आक्रामक नीति के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के सुसंगत और अनम्य संघर्ष, सोवियत संघ की आर्थिक और सैनिक शक्ति के सुदृढ़ीकरण, सोवियत संघ के मेहनतकशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की वृद्धि तथा पश्चिमी देशों में बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों ने भी कुछ पूंजीवादी देशों के शासक हलक़ों को अपनी नीति में तब्दीली करने तथा सोवियत संघ से अपने संबंधों में सुधार करने के लिए विवश कर दिया।

शांति और सामूहिक सुरक्षा के लिए संघर्ष

१९२९ के अंत में पूंजीवादी देशों में व्याप्त आर्थिक संकट ने वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों को उग्र बना दिया। सोवियत संघ की क़ीमत पर अपने को आर्थिक संकट से उबारने का प्रयास करते हुए बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों ने सोवियत-विरोधी षड्यंत्रों और युद्ध की तैयारियों को तेज़ कर दिया।

चौथे दशक में अनेक साम्राज्यवादी देशों में फ़ासिस्ट शासनों की स्थापना के कारण युद्ध का ख़तरा भी बढ़ गया। इन देशों की नीति विस्तार और युद्ध, दुनिया के पुनर्विभाजन और विश्व प्रभुत्व के कार्यक्रम पर आधारित थी। इस वजह से नया युद्ध बचाने के तात्कालिक कार्यभार को कार्यसूची में प्राथमिकता दी गयी।

पहले की भांति ही सोवियत विदेशनीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा करना था जो समाजवादी औद्योगीकरण, कृषि के सामूहिकीकरण की सफल पूर्ति के लिए इतनी आवश्यक थी। आर्थिक रूप से मज़बूत बनते और शांति के लिए सुसंगत संघर्ष करते हुए सोवियत संघ ने यूरोपीय सुरक्षा आंदोलन का नेतृत्व किया।

शांति की सुरक्षा में दिलचस्पी रखनेवाले सभी देशों के प्रयासों को एकजुट करके फ़ासिस्ट आक्रमण को रोकना उस समय अभी संभव था।

इस उद्देश्य से सोवियत संघ ने सामूहिक सुरक्षा का विचार पेश किया, जिसका कार्यान्वयन किसी भी आक्रामक के ख़िलाफ़ विश्वसनीय बाधा बन सकता था।

१९३३ में सोवियत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सम्मेलन में आक्रमण की परिभाषा संबंधी घोषणा के मसविदे को विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें आक्रमण को उचित ठहराने की किसी भी संभावना को कोई स्थान नहीं दिया गया था। हालांकि मुख्य पूंजीवादी देशों ने इस मसविदे को ठुकरा दिया, सोवियत संघ और अन्य १० देशों ने आक्रमण की परिभाषा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये।

सोवियत संघ ने पूर्वी संधि* की स्थापना करने का प्रस्ताव किया, जिनके सहभागी अपने बीच एक संधि करके सीमाओं की अलंघनीयता की पारस्परिक गारंटी करते और संधि के किसी भी सहभागी पर आक्रमण की स्थिति में उसे सहायता देने तथा आक्रामक देश को सहायता देने से इन्कार करने का दायित्व लेते। परंतु संधि के विरोधी देशों ने इस योजना को विफल कर दिया।

यूरोपीय सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना का प्रयास करते हुए सोवियत संघ सितम्बर १९३४ में राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। अपनी विदेशनीति के सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए सोवियत प्रतिनिधि साम्राज्यवादी षड्यंत्रों का पर्दाफ़ाश करने, उनकी सोवियत-विरोधी आक्रामक योजनाओं को विफल करने के लिए राष्ट्र संघ के मंच का इस्तेमाल कर सके।

१९३५ में सोवियत संघ ने फ़्रांस और चेकोस्लोवाकिया के साथ पारस्परिक सहायता संधियां कीं, जिन्हें यूरोपीय सुरक्षा का आधार और फ़ासिस्ट जर्मनी के आक्रमण के रास्ते पर अवरोध बनना चाहिए था। लेकिन साम्राज्यवादी सरकारों ने फ़ासिस्ट जर्मनी को सोवियत संघ से भिड़ाने की योजना बनायी थी और उन्होंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसी वजह से इथियोपिया पर फ़ासिस्ट इटली का आक्रमण, चीन पर सैन्यवादी जापान का आक्रमण और स्पेनी जनतंत्र

---

* पूर्वी संधि को उसमें सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, पोलैंड, लाटविया, एस्तोनिया, लिथुआनिया और फ़िनलैंड को शामिल करते हुए एक पारस्परिक सहायता संधि बनाने की योजना थी। — सं०

में इटली-जर्मन हस्तक्षेप अदंडित रह गये। फ़ासिस्ट आक्रमण का ख़तरा बहुत-से देशों पर छाया हुआ था।

युद्ध के बढ़ते ख़तरे को देखते हुए सोवियत संघ ने शांति की सुरक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखा और आक्रमण के शिकार बने लोगों, ख़ास तौर से आक्रमण के ख़िलाफ़ संघर्षरत स्पेनी * और चीनी ** लोगों को भौतिक सहायता प्रदान की।

प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी हलक़ों के विरोध के बावजूद शांति के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के संघर्ष ने सोवियत राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संवर्धन में बड़ी भूमिका अदा की। न केवल सोवियत राज्य को अलग-थलग करने की उनकी योजनाएं विफल हो गयीं, बल्कि उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी बढ़े। १९३३ से १९३५ तक की अवधि में सोवियत संघ ने अमरीका, अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्पेन, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, कोलम्बिया और लुक्ज़ेम्बर्ग के साथ राजनयिक संबंध क़ायम किये।

इस प्रकार, साम्राज्यवादी उकसावों के विरुद्ध कठिन संघर्ष में सोवियत विदेशनीति ने सोवियत संघ के लिए शांति सुनिश्चित बनाने के अपने मुख्य कार्यभार को पूरा कर लिया था, जो समाजवाद के निर्माण के लिए इतनी आवश्यक थी। समाजवाद की विजय के फलस्वरूप सोवियत संघ द्वारा प्राप्त सफलताओं ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति मज़बूत बनायी। इसने विदेशनीति के अधिक कारगर कार्यान्वयन को संभव बनाया। समाजवाद की विजय के साथ युद्ध, फ़ासिज़्म और प्रतिक्रिया के विरुद्ध, शांति और समाजवाद का समर्थन करनेवाले मेहनतकशों, सभी प्रगति-

---

* अक्तूबर १९३६ से सितम्बर १९३७ तक सोवियत संघ ने स्पेन को जहाज़रानी से हथियारों की २३ खेपें भेजीं। इसके अलावा, उसने खाद्य-पदार्थ, दवाइयां, कपड़े, आदि भी भेजे। – सं०

** १९३८-३९ में सोवियत संघ ने चीन को हथियारों, गोले-बारूदों की सोवियत खेपों के रूप में २५ करोड़ डालर का ऋण दिया। – सं०

शील ताक़तों के आकर्षण और एकजुटता के एक केंद्र के रूप में सोवियत संघ का महत्व बढ़ गया।

* * *

अपने अंतर्राष्ट्रीयतावादी कर्तव्य के प्रति वफ़ादार रहते हुए सोवियत संघ ने शांति तथा पूंजीवादी और पराधीन देशों के मेहनतकशों के साथ बिरादराना सहयोग एवं एकजुटता के सुदृढ़ीकरण की नीति को दृढ़तापूर्वक और अनम्य ढंग से अमल में लाया। यह नीति पूंजीवादी देशों में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के लिए बड़ा महत्व रखती थी और उसने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग और उत्पीड़ित जनगण को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में कई सफलताएं प्राप्त करने में सहायता की और आगे द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में फ़ासिज़्म को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाली फ़ासिज़्म-विरोधी शक्तियों का एकीकरण संभव बनाया।

उपसंहार

सोवियत संघ में समाजवादी समाज का निर्माण सोवियत जनगण की एक असाधारण उपलब्धि था। उसने मानवजाति के विकास पर विशाल प्रभाव डाला।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में लेनिन के उन विचारों की पूर्णतः पुष्टि हो गयी है, जो उन्होंने सोवियत सत्ता के पहले वर्षों में ही व्यक्त किये थे। उन्होंने तब कहा था कि सोवियत संघ मुख्यतः अपनी आर्थिक प्रगति के ज़रिये विश्व-विकास पर प्रभाव डाल रहा है और डालेगा। वस्तुतः आर्थिक सफलता ही पुरानी सामाजिक प्रणाली – पूंजीवाद – पर नयी सामाजिक प्रणाली – समाजवाद – की विजय को सुनिश्चित बनायेगी।

सोवियत संघ में समाजवादी समाज के निर्माण का, एक ऐसे नये समाज के निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है जो पूंजीवादी समाज से हर दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है?

उत्पादन की समाजवादी प्रणाली के लाभों ने अत्यल्प समय में देश के पिछड़ेपन को दूर करना संभव बनाया। ये लाभ पूंजीवादी देशों की तुलना में सोवियत संघ में उत्पादक शक्तियों के अधिक तीव्र गति से विकास में प्रकट हुए। इस तथ्य के बावजूद कि हस्तक्षेपकारियों द्वारा नष्ट किये गये कारखानों, फ़ैक्टरियों, खानों और रेलवे की बहाली में काफ़ी समय और प्रयास लगे, चौथे दशक के अंत तक सोवियत संघ औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया था।

समाजवाद के लाभ ये भी थे कि सभी शोषक वर्गों का उन्मूलन कर दिया गया था और तीव्र आर्थिक प्रगति की सभी बाधाएं दूर कर दी गयी थीं। सामाजिक उत्पादन में हिस्सा लेनेवाले सभी लोगों के मौलिक हितों की एकता क़ायम की गयी।

समाजवादी समाज के निर्माण ने व्यावहारिक रूप से पुष्ट कर दिया कि वह नियोजित आधार पर विकसित होनेवाली, आर्थिक संकटों और मंदियों से मुक्त अत्यंत प्रगतिशील संरचना है, जो लोगों के सार्वजनिक और निजी हितों को अत्युत्तम ढंग से समन्वित करती है। शक्तिशाली समाजवादी राज्य के स्थिर विकास ने समाजवाद की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया, पूंजीवाद के अंतर्विरोधों और त्रुटियों को और प्रकट किया तथा मेहनतकश जनसाधारण की नज़रों में उसकी प्रतिष्ठा को भंग कर दिया।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय महत्व यह भी था कि उसने उसे तथा सभी शांतिप्रिय ताक़तों को फ़ासिज़्म और आक्रामक शक्तियों के ख़िलाफ़, शांति के लिए, मानवजाति पर छा रहे फ़ासिस्ट युद्ध के ख़तरे की परिस्थितियों में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए संघर्ष करने में समर्थ बनाया। सोवियत संघ एक ज़बर्दस्त औद्योगिक शक्ति बन गया, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी, सभी शांतिप्रिय, युद्ध-विरोधी शक्तियां मज़बूत बनीं। हालांकि उस अवधि में समाजवाद और शांति की ताकतें इतनी मज़बूत नहीं हुई थीं कि वे द्वितीय विश्वयुद्ध भड़कानेवालों को रोक सकें, उनकी योजनाओं को विफल कर सकें, फिर भी सोवियत संघ द्वारा साम्राज्यवादी षड्यंत्रों के पर्दाफ़ाश तथा शांति शक्तियों की लामबंदी ने साम्राज्यवाद की घोर आक्रामक ताक़तों – नाज़ी हमलावरों – को युद्ध में पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण ने पूंजीवादी दुनिया के मज़दूर वर्ग पर समाजवादी विचारों और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रभाव को बढ़ा दिया। सोवियत संघ में समाजवादी समाज के निर्माण और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्राप्त सफलताओं ने व्यावहारिक रूप से पुष्ट कर दिया कि मज़दूर वर्ग दुनिया का कायापलट करने और सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने में समर्थ है। इसके साथ ही इन उपलब्धियों ने पूंजीवादी स्वामित्व को बनाये रखते हुए पूंजीवाद के समाजवाद में क्रमशः रूपांतरण, शोषकों और शोषितों के बीच वर्ग सहयोग, पूंजीवाद के तहत मज़दूरों और मालिकों के बीच साझेदारी के बारे में विभिन्न सिद्धांतों की निराधारता को दिखा दिया। समाजवादी निर्माण की सफलताओं ने पूंजीवादी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियों की

प्रतिष्ठा, उनके प्रभाव और सदस्य-संख्या को बढ़ा दिया। मज़दूरों के बीच रोज़मर्रा के अपने काम में वे समाजवाद की सफलताओं का उपयोग कर सकती, पूंजीवादी प्रणाली पर समाजवादी प्रणाली की श्रेष्ठताएं दिखा सकती थीं। इन सफलताओं ने पूंजीवादी देशों में वर्ग संघर्ष को तेज़ करने में सहायता की। बहुत-से पूंजीवादी देशों में मज़दूर वर्ग ने अपनी सरकारों को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में रियायतें देने के लिए मजबूर कर दिया।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय महत्व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पर उसके सफल प्रभाव, साम्राज्यवादी उत्पीड़न के ख़िलाफ़, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में जनगण को समर्थन और सहायता देने की संभावना में वृद्धि में निहित था। सोवियत संघ में जातीय प्रश्न के सफल समाधान, सामाजिक-आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन में मंगोलियाई जनगण को सोवियत जनगण की सहायता और तुर्की, अफ़ग़ानिस्तान, चीन, ईरान, आदि देशों के जनगण के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष को समर्थन ने सोवियत संघ के प्रति उत्पीड़ित जनगण की सहानुभूति बढ़ा दी और सारी दुनिया में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को तेज़ कर दिया।

समाजवादी समाज के निर्माण में सोवियत लोगों की सफलता ने पूंजीवादी देशों के प्रगतिशील जनमत पर गहन प्रभाव डाला। विज्ञान और संस्कृति के बहुत-से प्रगतिशील कर्मियों ने नये समाज के निर्माण में सोवियत जनगण के प्रयासों को दिलचस्पी और सहानुभूति के साथ देखा। दो प्रणालियों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के परिणामों की तुलना करके वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वस्तुतः समाजवाद ही जनता के लिए शांति, जनवाद, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति लाता है।

समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को महसूस करते हुए इजारेदार बुर्जुआ वर्ग के घोर प्रतिक्रियावादी हलक़ों ने समाजवाद की जड़ काटने, नयी सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया। उन्होंने सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए नाज़ी हमलावरों को हर तरीक़े से बढ़ावा दिया। अधिकृत यूरोपीय देशों की आर्थिक और औद्योगिक शक्ति पर आश्रित रहते हुए फ़ासिस्ट जर्मनी ने २२ जून, १९४१ को सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया।

यह एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि समाजवाद और साम्राज्यवाद की प्रहारक ताक़तों के बीच विराट टकराव था। इसके नतीजे पर पूरे के पूरे राष्ट्रों और राज्यों, संपूर्ण मानवजाति, संपूर्ण मानव सभ्यता का भविष्य निर्भर था। सोवियत संघ और फ़ासिस्ट जर्मनी तथा उसके पिछलग्गुओं के बीच सशस्त्र टकराव दो विरोधी सामाजिक प्रणालियों के बीच टकराव था और उसका एक सुस्पष्ट वर्ग स्वरूप था। संसार के पहले समाजवादी देश के अस्तित्व, विश्व समाजवाद के भाग्य का फ़ैसला हो रहा था। संघर्ष कड़ा था और कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। इस संघर्ष में मौलिक, सहज लाभों से संपन्न प्रणाली ही विजयी हो सकती थी।

सोवियत संघ की विजय सोवियत जनगण की विशाल सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियों पर निर्भर करती थी। समाजवाद के निर्माण के फलस्वरूप सोवियत संघ ने समाजवादी उपलब्धियों की रक्षा के लिए किसी भी हमलावर से सफल संघर्ष करने हेतु अतुलनीय लाभ प्राप्त कर लिये थे। ये लाभ कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका की बदौलत साकार हुए थे।

नाज़ी जर्मनी से संघर्ष के वर्षों में, जब सोवियत संघ के औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित एक बड़े भाग पर शत्रु ने क़ब्ज़ा कर लिया था, सोवियत उद्योग युद्ध की अग्नि-परीक्षा में खरा उतरा और मोर्चे को विजय के लिए आवश्यक सभी चीज़ों की सप्लाई की।

समाजवादी कृषि ने भी युद्ध-जनित कठिन कार्यभारों को सफलता-पूर्वक पूरा किया। इस तथ्य के बावजूद कि खेती के लिए विकसित विस्तृत क्षेत्र अस्थायी तौर पर शत्रु के हाथों में चले गये थे, कि आबादी का एक बड़ा श्रमक्षम और सुदक्ष हिस्सा मोर्चे पर चला गया था, कि कृषि का भौतिक और तकनीकी आधार कमज़ोर हो गया था, वह युद्ध की कठिन परीक्षाओं में खरी उतरी तथा निजी, छोटी, बिखरी खेती पर सामूहिक फ़ार्म प्रणाली की सुस्पष्ट श्रेष्ठताओं को सिद्ध कर दिया।

अत: युद्ध में फ़ासिस्ट जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय ने समाज-वाद की, उत्पादन की समाजवादी प्रणाली की विशाल जीवन क्षमता और प्रगतिशीलता को दिखा दिया।

समाजवाद की विजय, उसकी उपलब्धियों के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत सोवियत समाज की सामाजिक-वैचारिक एकता, समाजवादी

देशभक्ति, बहुजातीय सोवियत राज्य के जनगण की दोस्ती और कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व थे।

समाजवाद ने व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित कर दिया था कि वह सभी अर्थों में एक अधिक उच्च, अविजेय समाज है। लेकिन सोवियत जनगण ने इस विजय के लिए महंगी क़ीमत चुकायी। युद्ध में २ करोड़ से अधिक सोवियत लोगों की जानें गयीं, नाज़ियों ने १,७१० नगरों और क़स्बों, ७० हज़ार से अधिक गांवों को नष्ट कर दिया, १ लाख से अधिक सामूहिक और राजकीय फ़ार्मों तथा मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों, ८४ हज़ार स्कूलों, तकनीकी स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों, ४० हज़ार अस्पतालों को तहस-नहस कर दिया और लूट लिया एवं ढाई करोड़ लोगों को घरविहीन बना दिया।

नाज़ियों द्वारा संपत्तियों के विनाश और लूट से सोवियत अर्थव्यवस्था और विभिन्न नागरिकों को ६७९ अरब रूबल की क्षति हुई। इतिहास में किसी भी देश को इतनी बड़ी क्षति कभी नहीं हुई। देश राष्ट्रीय संपदा का लगभग एक-तिहाई खो चुका था। युद्ध ने देश के आगे विकास को दस साल से अधिक पीछे धकेल दिया।

आक्रामक साम्राज्यवादी शक्तियों ने आशा लगा रखी थी कि जन-माल की इतनी बड़ी क्षतियां उठाने के बाद सोवियत संघ लंबे समय तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकेगा, दुनिया में अपनी पहले की आर्थिक स्थिति को बहाल नहीं कर सकेगा। अगर किसी पूंजीवादी देश को इतना भारी नुक़्सान पहुंचा होता, तो उसे बहुत पीछे धकेल दिया गया होता और वह अधिक शक्तिशाली देशों का ग़ुलाम बनकर रह जाता। पर सोवियत संघ के साथ ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी आर्थिक प्रणाली के लाभों पर भरोसा करते हुए सोवियत लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपने वीरतापूर्ण श्रम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहाली और उसके आगे विकास को सुनिश्चित बनाया। १९४८ में, यानी युद्ध के बाद ढाई वर्षों में ही सोवियत संघ का औद्योगिक उत्पादन न केवल युद्ध-पूर्व स्तर पर पहुंच गया, बल्कि उससे आगे भी बढ़ गया। १९५० में, अर्थात युद्धोत्तर काल की पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में युद्ध-पूर्व उत्पादन के मुक़ाबले में ७३ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (योजनानुसार ४८ प्रतिशत की वृद्धि होनी थी)। चौथी पंचवर्षीय योजना काल (१९४६-१९५०) में,

जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध-विनष्ट अर्थव्यवस्था को बहाल और आगे विकसित करना था, ६,००० औद्योगिक उद्यम या तो बहाल किये गये या नये सिरे से बनाये गये, यानी उतने जितने कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनावधियों में निर्मित किये गये थे।

कृषि की बहाली तो और भी कठिन और पेचीदा थी। युद्धोत्तर काल में कई प्रदेशों में भीषण सूखे ने युद्ध द्वारा हुई बड़ी भौतिक क्षतियों को बढ़ा दिया। युद्ध के कारण ग्रामीण आबादी में श्रम-समर्थ लोगों की संख्या बहुत घट गयी थी और उद्योग की बहाली ने ग्रामीण युवा-जनों की एक बड़ी संख्या को औद्योगिक परियोजनाओं में खींचने की मांग की। सामूहिक और राजकीय फ़ार्मों को नयी कृषि मशीनों से सज्जित करना आवश्यक था।

उद्योग ने कृषि की मशीनों की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। नवीकृत भौतिक और तकनीकी आधार पर निर्भर करते हुए सामूहिक व राजकीय फ़ार्म किसान श्रम-समर्थ आबादी में कमी के बावजूद १९५० तक कृषि के युद्ध-पूर्व स्तर को प्राप्त करने में सफल हुए। सामूहिक और राजकीय फ़ार्मों तथा मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों का बड़े पैमाने पर बिज-लीकरण शुरू हुआ।

छठे दशक में सोवियत संघ में समाजवादी समाज का आगे विकास हुआ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहाली करके वह विश्वासपूर्वक आगे बढ़ा। बड़े आधुनिक औद्योगिक उद्यम बनाये गये। वोल्गा पर निर्मित बड़े पनबिजलीघरों से बिजली मिलने लगी, जिनमें २१ लाख किलो-वाट क्षमता का वोल्गा लेनिन पनबिजलीघर तथा और भी शक्तिशाली वोल्गोग्राद पनबिजलीघर शामिल थे। विराट ओर्स्क-ख़लिलोवो और चेरेपोवेत्स धातुकर्मक समुच्चय चालू किये गये, २,००० किलोमीटर लंबी स्तावोपोल – मास्को गैस पाइपलाइन बिछायी गयी। १९५२ में पांच सागरों को एक जलपरिवहन में जोड़नेवाली नव-निर्मित वोल्गा – दोन नहर पर यातायात शुरू हुआ।

सफल औद्योगिक विकास ने ट्रैक्टरों और अन्य आवश्यक कृषि मशीनों की सप्लाई काफ़ी बढ़ा दी।

अनाज उत्पादन बढ़ाने पर, जो संपूर्ण कृषि उत्पादन का मुख्याधार था, विशेष ध्यान दिया गया। कज़ाख़स्तान, साइबेरिया, वोल्गा क्षेत्र और देश के अन्य प्रदेशों में परती ज़मीनों को कृषियोग्य बनाया गया,

जो अनाज उत्पादन की वृद्धि का मुख्य स्रोत बन गयीं। यह एक पेचीदा, विशाल कार्य था, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था इसे पूरा करने में समर्थ बन चुकी थी। जिन प्रदेशों में परती ज़मीनों को कृषियोग्य बनाया जा रहा था, वहां बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और कृषि मशीनें भेजी गयीं। पार्टी ने कम्युनिस्टों, नौजवानों से परती ज़मीनों को विकसित करने में सहायता करने की अपील की। लगभग १० लाख स्वयंसेवकों ने, जिनमें ५ लाख युवक और युवतियां थीं, इस अपील के उत्तर में परती ज़मीनों को कृषियोग्य बनाने में हिस्सा लिया। तीन वर्षों (१९५४-१९५६) में लगभग ३ करोड़ ६० लाख हेक्टर परती ज़मीनों को कृषियोग्य बनाया गया और ४०० नये राजकीय फ़ार्म क़ायम किये गये। इनसे देश को दसियों लाख टन अतिरिक्त अनाज मिला। परती ज़मीनों का कृषियोग्य ज़मीनों में विकास सोवियत जनगण के रचनात्मक श्रम के इतिहास में एक अत्यंत ज्वलंत पृष्ठ, पार्टी और जनता का एक महान पराक्रम था।

समाजवादी प्रतियोगिता, जिसने श्रम के प्रति नये समाजवादी रुख़ को व्यक्त किया, आर्थिक विकास योजनाओं की सफल पूर्ति का एक मुख्य कारक थी। कम्युनिस्ट श्रम की टुकड़ियों का आंदोलन समाजवादी प्रतियोगिता का एक नया, उच्चतर रूप था। यह आंदोलन अक्तूबर १९५८ में मास्को-सोर्तिरोवोच्नाया डिपो में शुरू हुआ था, जहां १९१९ में सोवियत जनतंत्र के लिए अत्यंत कठिन समय में डिपो कर्मियों ने पहला कम्युनिस्ट "सुब्बोत्निक" संगठित किया था। कम्युनिस्ट श्रम के प्रवर्तकों का यह आंदोलन बड़ी तेज़ी से सारे देश में फैल गया और अर्थव्यवस्था की सभी शाखाएं इसकी परिधि में आ गयीं।

सोवियत लोगों के अथक श्रम के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी सफलताएं प्राप्त की गयीं। इसने उनके जीवन स्तर को काफ़ी ऊंचा उठाना संभव बनाया। १९५६ में छुट्टी के दिनों के पहलेवाले कार्य-दिवस में वेतन में कटौती किये बिना दो घंटे की कमी की गयी। १६-१८ साल के लड़के-लड़कियों के लिए पूर्ण वेतन के साथ छः घंटे का कार्य-दिवस लागू किया गया। १९६० तक सभी मज़दूरों और कर्मचारियों के लिए सात घंटे का कार्य-दिवस तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकर उत्पादन-शाखाओं में काम करनेवाले मज़दूरों के लिए छः घंटे का कार्य-दिवस लागू किया गया। कम वेतन पानेवाले कर्मचा-

रियों का वेतन बढ़ाया गया, उन पर कर कम किये गये। १९५८ में मज़दूरों और कर्मचारियों की वास्तविक आय युद्ध-पूर्व स्तर (१९४०) से लगभग दुगुनी और सामूहिक फ़ार्म किसानों की आय दुगुनी से ज़्यादा अधिक हो गयी थी। पेंशनरों की भौतिक परिस्थितियां बेहतर बनीं। मेहनतकशों की रिहायशी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोवियत राज्य ने बड़े पैमाने पर गृह-निर्माण शुरू किया।

जनता की सांस्कृतिक मांगों की पूर्ति तथा उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सोवियत राज्य ने कई क़दम उठाये गये। १९५८ में पूरे देश में अनिवार्य आठवर्षीय शिक्षा लागू की गयी। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की संख्या बढ़ गयी। यह यूरोप के समस्त पूंजीवादी देशों की छात्र-संख्या से दुगुना अधिक था। बड़ी संख्या में सांस्कृतिक प्रासाद, क्लब, खेल-सुविधाएं बनीं।

सोवियत विज्ञान ने नयी सफलताएं प्राप्त कीं। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां इसका प्रमाण हैं। १९५७ में सोवियत संघ ने दुनिया के पहले परमाणु हिमभंजक पोत 'लेनिन' का निर्माण किया, जिसे आर्कटिक सागर में समुद्री मार्ग को सुचारु बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी साल सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा। १२ अप्रैल, १९६१ को दुनिया के पहले अंतरिक्ष-यात्री यूरी गगारिन ने अंतरिक्ष-यात्रा की। सोवियत विज्ञान और टेक्नोलाजी की इन असाधारण उपलब्धियों ने समाजवादी प्रणाली की उच्च आर्थिक और वैज्ञानिक क्षमता को प्रमाणित कर दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा साम्राज्यवाद की प्रहारक शक्ति के विनाश और नाज़ीवाद से यूरोपीय जनगण की मुक्ति के फलस्वरूप पूंजीवादी प्रणाली को ज़बर्दस्त आघात पहुंचा और वह क्षीण हो गयी। विभिन्न देशों में जनगण ने विजयी साम्राज्यवाद-विरोधी, जनवादी क्रांतियां संपन्न कीं। इन देशों में जनवादी कार्यभारों की पूर्ति के साथ-साथ मज़दूर वर्ग समाजवादी कायापलट की ओर आगे बढ़ता गया। लोक जनवादी राज्य क़ायम करनेवाले इन देशों के जनगण के मुक्ति संघर्ष के लिए, समाजवादी रूपांतरण करने के लिए सोवियत संघ की सहायता का बड़ा महत्व था।

लोक जनवादी देशों के साथ अपने संबंधों में सोवियत राज्य ने

उनके घरेलू मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया। इसके साथ ही सोवियत संघ के अस्तित्व और उसकी शांतिप्रिय नीति ने इन देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप संगठित करने और जनगण की उपलब्धियों को नष्ट करने की साम्राज्यवादी शक्तियों की कोशिशों पर पानी फेर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लोक जनवादी देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए सोवियत संघ ने इन देशों के जनगण को उनकी उपलब्धियों की रक्षा में सहायता प्रदान की।

दुनिया के पहले समाजवादी देश ने अपने अनुभव बिरादराना देशों के साथ बंटाये। सोवियत राज्य ने समाजवादी देशों के प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया, सोवियत लोगों ने उन्हें अपनी उपलब्धियों, सोवियत समाज के विकास, औद्योगिक उद्यमों, सामूहिक और राजकीय फ़ार्मों के कार्यों से परिचित कराया।

सोवियत संघ और लोक जनवादी देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विकास के फलस्वरूप विश्व समाजवादी बाज़ार का उद्भव और सुदृढ़ीकरण हुआ। सोवियत संघ और लोक जनवादी देशों के बीच वैज्ञानिक और टेक्नोलाजिकल जानकारी का विनिमय हुआ। परियोजनाओं के ख़ाकों, नयी मशीनों और उपकरणों की डिज़ाइनों, टेक्नोलाजिकल विवरणों तथा परिकलनों के रूप में उत्पादन और तकनीकी सहायता प्रदान की गयी।

सोवियत संघ ने इन देशों को कर्मीवृंद के प्रशिक्षण में बड़ी सहायता प्रदान की। लोक जनवादी देशों के हज़ारों नौजवानों ने सोवियत उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा पायी। बिरादराना देशों के मज़दूरों की बड़ी संख्या ने सोवियत फ़ैक्टरियों और कारख़ानों में नयी टेक्नोलाजी में पारंगति प्राप्त की।

अपने आर्थिक संपर्कों और सहयोग के समन्वय के लिए बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ और यूरोप के लोक जनवादी राज्यों ने १९४९ के प्रारंभ में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं का समन्वय आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण रूप था। इसने उपलब्ध उत्पादन और कच्चे माल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, समाजवादी निर्माण की गति तेज़ करना और लोक जनवादी देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना संभव बनाया।

समाजवादी राष्ट्रमंडल का निर्माण और विकास कोई साधारण, आसान काम नहीं था। इसमें कुछ कठिनाइयां पेश आयीं। बिरादराना देशों के साथ पारस्परिक संबंधों में कुछ भूलें हुईं। लेकिन वे अस्थायी थीं। मुख्य बात यह थी कि उनके संबंध अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांतों से जनित कार्यभारों की पूर्ति के प्रति समाजवादी रुख़ से निर्धारित हुए। इसलिए कठिनाइयों पर सामूहिक प्रयासों से क़ाबू पाया गया, भूलें खुले रूप से और ईमानदारी से स्वीकार की गयीं, उन्हें दूर किया गया एवं समाजवादी देशों का भ्रातृत्वपूर्ण सहयोग मज़बूत बनता गया। सभी समाजवादी देशों ने अपने अनुभव से सीखा कि उनकी शक्ति का स्रोत इस सहयोग में ही है। मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता के उनके विकासमान संबंध प्रत्येक देश और संपूर्ण रूप में समाजवादी राष्ट्रमंडल के हितों के अनुरूप थे।

सातवें दशक के शुरू तक सोवियत संघ ने काफ़ी सफलताएं प्राप्त कर ली थीं। १९६० में औद्योगिक उत्पादन में १९४० के औद्योगिक उत्पादन के मुक़ाबले में ५.२ गुनी, उत्पादन साधनों के उत्पादन में ६.६ गुनी और इंजीनियरी तथा धातुकर्मक उत्पादों में नौगुनी वृद्धि हुई। विज्ञान ने भी भारी पग बढ़ाये थे।

दूसरे समाजवादी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी तेज़ गति से विकसित हुईं। कुल मिलाकर, समाजवादी राष्ट्रमंडल की अर्थव्यवस्थाएं विकसित पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से तेज़ गति से विकसित हुईं। फलस्वरूप, १९६० में विश्व के कुल आर्थिक उत्पादन में समाजवादी देशों का हिस्सा ३६ प्रतिशत था।

नाज़ीवाद की पराजय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और समाजवाद के पक्ष में विश्व शक्तियों के संतुलन में मौलिक परिवर्तन, सोवियत संघ और संपूर्ण समाजवादी राष्ट्रमंडल की बढ़ती शक्ति, प्रतिक्रिया के विरुद्ध संपूर्ण शांतिप्रिय शक्तियों का तीव्र संघर्ष, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए विकासमान देशों के रूप में व्यापक "शांति-क्षेत्र" का उदय, औपनिवेशिक प्रणाली का पतन और इस सबके परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद का दुर्बल होना – इस सबका अर्थ यह था कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, जो समाजवाद को पराजित कर सके। सोवियत संघ की आर्थिक और सैनिक शक्ति ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की और अदा कर रही है। इसका अपनी बारी में अर्थ यह था कि सोवियत संघ

में समाजवाद ने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। समाजवाद की पूर्ण विजय का मार्क्सवादी-लेनिनवादी अभिप्राय यह है कि पूंजीवाद की बहाली के ख़िलाफ़ पूर्ण गारंटी पा ली गयी है। इसी वजह से जब तक सोवियत संघ पूंजीवादी घेरे में एकमात्र समाजवादी देश रहा, तब तक इस बात की पूर्ण गारंटी नहीं थी कि साम्राज्यवादी आक्रमण की सूरत में पूंजीवाद की बहाली नहीं होगी। १९४१ में सोवियत संघ पर नाज़ी जर्मनी का आक्रमण ऐसा ही एक प्रयास था।

आज दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो सोवियत संघ में पूंजीवादी प्रणाली को बहाल कर सके। हालांकि घोर प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी ताक़तों की नीति उन्हें सोवियत संघ या किसी दूसरे समाजवादी देश पर आक्रमण की ओर ले जा सकती है, यह आक्रमण विफल होकर ही रहेगा और उसका अंत केवल आक्रामक की पूर्ण पराजय ही हो सकता है।

समाजवाद की पूर्ण विजय समाजवादी समाज के परिष्करण और कम्युनिज़्म में क्रमशः संक्रमण के लिए एक निर्णायक कारक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति सोवियत संघ तथा समाजवादी राष्ट्रमंडल के आर्थिक और सामाजिक विकास की गति और परिणामों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

शस्त्रास्त्रों की होड़ और साम्राज्यवादी ताक़तों की आक्रामक नीति, ख़ास तौर से समाजवादी देशों और स्वतंत्र विकासमान देशों के ख़िलाफ़, दुनिया के जनगण की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ साम्राज्यवादी ताक़तों की आक्रामक कार्रवाइयां सोवियत संघ के जीवंत हितों को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकतीं। इस परिस्थिति में सोवियत संघ अपनी राष्ट्रीय आय के एक बड़े भाग को रक्षा आवश्यकताओं पर और आक्रमण के शिकारों को सहायता देने पर ख़र्च करने को बाध्य है। यह, स्पष्टतः, सोवियत संघ की आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाओं को आमूलतः परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि विद्यमान भौतिक और तकनीकी आधार सभी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभारों की पूर्ति को सुनिश्चित बनाता है। फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज़्म के निर्माण के लिए शांति की परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है। सोवियत संघ साम्राज्यवादी ताक़तों की आक्रामक कार्रवाइयों का पर्दाफ़ाश करता

है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, अन्य जनगण की समाजवादी उपलब्धियों की रक्षा करता है, और आक्रमण से पीड़ित या उसके ख़तरे से ग्रस्त जनगण की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करता है, क्योंकि शांतिपूर्ण परिस्थितियां न केवल सोवियत संघ में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की गति को तेज़ करने के लिए, बल्कि सभी क्रांतिकारी, प्रगतिशील और शांतिप्रिय शक्तियों के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए भी अनुकूल संभावनाएं खोलती हैं और यह मानवजाति के मौलिक हितों से पूरी तरह मेल खाता है।

नियोजित आर्थिक विकास के आधार पर सोवियत जनगण के निस्स्वार्थ श्रम के परिणामस्वरूप सातवें दशक के अंत तक सोवियत संघ में विकसित समाजवादी समाज का निर्माण हो गया। कम्युनिज़्म के मार्ग पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंज़िल पा ली गयी।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अनुसार समाजवाद एक गतिशील, निरंतर विकासमान समाज है, जिसके विकास की प्रत्येक मंज़िल गुणात्मक रूप से नयी विशिष्टाएं प्राप्त करती है। लेनिन ने समाजवाद की ऐसी भ्रामक धारणा की आलोचना की जैसे कि वह कोई जड़ और निर्जीव चीज़ हो। उन्होंने ज़ोर दिया कि केवल समाजवाद के तहत ही सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में तीव्र, सच्ची प्रगति का समारंभ होगा।

सोवियत संघ में समाजवादी निर्माण का अनुभव लेनिनीय विचारों की पूर्णतः पुष्टि करता है।

१९७७ में स्वीकृत सोवियत संघ के नये संविधान ने सोवियत संघ में विकसित समाजवादी समाज के निर्माण को विधिक रूप से सुदृढ़ किया है और उसकी निम्नलिखित विशेषताएं बतायी हैं:

"यह एक ऐसा समाज है, जिसमें प्रबल उत्पादक शक्तियों का और उन्नत विज्ञान तथा संस्कृति का निर्माण किया जा चुका है, एक ऐसा समाज है, जिसमें जनता के कल्याण में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास के लिए अधिकाधिक अनुकूल स्थितियां पैदा हो रही हैं।

"यह परिपक्व समाजवादी सामाजिक संबंधों का समाज है, जिसमें सभी वर्गों और सामाजिक तबक़ों के एक दूसरे के निकट आने और सभी जातियों एवं उपजातियों की विधिगत और वास्तविक समानता तथा उनके बीच बिरादराना सहयोग के आधार पर जनता के एक नये ऐतिहा-

सिक समुदाय – सोवियत जनता – का गठन हुआ है।

"यह मेहनतकश लोगों की, जो देशभक्त और अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं, उच्च संगठनात्मक क्षमता, विचारधारात्मक प्रतिबद्धता और चेतना से परिपूर्ण समाज है।

"यह एक ऐसा समाज है, जिसके जीवन का नियम ही यह है कि प्रत्येक का मंगल-कल्याण सभी की चिंता का और सभी का मंगल-कल्याण प्रत्येक की चिंता का विषय है।

"यह सच्चे जनवाद का समाज है, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था समस्त सार्वजनिक मामलों का कारगर प्रबंध, राज्य के संचालन में मेहनतकश जनता की अधिकाधिक सक्रिय भागीदारी तथा नागरिक के सच्चे अधिकारों और स्वतंत्रताओं का समाज के प्रति उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के साथ समन्वय सुनिश्चित बनाती है।

"विकसित समाजवादी समाज कम्युनिज़्म के मार्ग पर एक नियम-संगत चरण है।"*

विकसित समाजवाद की उत्पादक शक्तियां, आधुनिक सोवियत अर्थव्यवस्था उन उत्पादक शक्तियों और अर्थव्यवस्था से मूलतः भिन्न हैं, जो द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने के ठीक पहले सोवियत संघ में बनी थीं। विकसित समाजवाद की अर्थव्यवस्था की विशिष्टताएं हैं शक्तिशाली आर्थिक और वैज्ञानिक-तकनीकी क्षमता, उत्पादन का उच्च स्तर, वैज्ञानिक-तकनीकी क्रांति की उपलब्धियों तथा समाजवादी आर्थिक प्रणाली के लाभों का समन्वय। औद्योगिक उत्पादों के अधिकांश प्रकारों के उत्पादन की दृष्टि से सोवियत संघ को आज दुनिया में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह इस्पात, तेल, कोयले, धातुकर्तक लेथों, ट्रैक्टरों, रेलवे इंजिनों, सीमेंट, खनिज उर्वरकों, आदि का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है।

संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास और वैज्ञानिक-तकनीकी क्रांति की उपलब्धियों तथा समाज के समाजवादी संगठन के लाभों के समन्वय पर आधारित विकसित समाजवाद की अर्थव्यवस्था लोगों की भौतिक और तकनीकी आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूर्ण ढंग से पूरा करना संभव बनाती है। समाजवादी उत्पादन का मुख्य

---

* सोवियत संघ का संविधान, पृ० ५।

ध्येय, यानी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कम्युनिस्ट पार्टी की व्यावहारिक नीतियों का केंद्र बन गयी है।

सोवियत लोगों का भौतिक और आत्मिक स्तर अतुलनीय रूप से उच्च है। उनकी वास्तविक आय १९४० की वास्तविक आय से छ:गुनी बढ़ी है। उच्च और माध्यमिक विशेष शिक्षा संस्थानों में लगभग १ करोड़ छात्र पढ़ते हैं। यह संख्या ४० साल पहले की संख्या से छ:गुनी अधिक है। सार्विक माध्यमिक शिक्षा में संक्रमण पूरा हो गया है। वैज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टिकोण ने लोगों की चेतना में गहरी जड़ें जमा ली हैं। विज्ञान, साहित्य और कला ने विकास का उच्च स्तर प्राप्त किया है। करोड़ों लोग आत्मिक सृजन, संगीत और ललित कलाओं में लगे हुए हैं और शौक़िया कलात्मक कार्यकलाप में हिस्सा लेते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के सामान्य शैक्षिक और सांस्कृतिक स्तर एक-दूसरे के निकटतर आ रहे हैं।

समाजवादी विचारधारा सोवियत जनगण की विचारधारा, सोवियत संघ के सभी वर्गों और सामाजिक संस्तरों, उसकी सभी जातियों और नृजातीय समूहों की सामाजिक चेतना का आधार बन गयी है।

विकसित समाजवाद की सामाजिक संरचना अपने संघटक अंग के रूप में वही है, जो चौथे दशक के अंत में थी। लेकिन वह गुणात्मक रूप से काफ़ी बदल गयी है।

सोवियत मज़दूर वर्ग सोवियत समाज की नेतृत्वकारी शक्ति है। वह संख्या की दृष्टि से बड़ा है, रोज़गारप्राप्त आबादी में उसका हिस्सा बदल गया है। अगर १९३९ में उसका हिस्सा केवल एक-तिहाई था, आजकल वह दो-तिहाई हो गया है। मज़दूरों की राजनीतिक चेतना और राजकीय मामलों के संचालन में उनकी भागीदारी बढ़ गयी है। सभी स्तरों की सोवियतों के प्रतिनिधियों में मज़दूरों की संख्या पिछले ४० वर्षों में पांचगुनी बढ़ी है। यदि ४० साल पहले सोवियत मज़दूरों के आठ प्रतिशत को उच्च और माध्यमिक (पूर्ण या अपूर्ण) शिक्षा प्राप्त थी, तो आजकल यह संख्या बढ़कर कोई ७५ प्रतिशत हो गयी है।

आज के सामूहिक किसान चौथे दशक के मध्य के सामूहिक किसानों से गुणात्मक रूप से बिल्कुल भिन्न जीवन जीते हैं। आधुनिक सामूहिक किसान की सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्तर औद्योगिक मज़दूर की सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्तर से अधिक मिलता-

जुलता है। सामूहिक मनोवृत्ति, उच्च जागरूकता और समाजवाद के ध्येय के प्रति निष्ठा आज के सामूहिक किसान के लक्षण हैं।

सच्चा समाजवादी जन बुद्धिजीवी वर्ग सोवियत मेहनतकशों का अत्यंत तेजी से बढ़ता दस्ता है, जो बड़ी सीमा तक मजदूरों और किसानों से बना है। जनगण का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठने और समाज में विज्ञान की भूमिका बढ़ने के साथ बुद्धिजीवियों की संख्या भी बढ़ती है। पिछले चार दशकों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगे उच्च और माध्यमिक शिक्षाप्राप्त विशेषज्ञों की संख्या में १२गुनी वृद्धि हुई है।

विकसित समाजवादी समाज की संरचना में परिवर्तन की सामान्य प्रवृत्तियां हैं सभी वर्गों और सामाजिक समूहों का सतत निकटतर आना, उत्पादन के साधनों के प्रति रवैये, श्रम के स्वरूप, उत्पादन के सामाजिक संगठन में भूमिका के अनुसार उनके बीच अंतरों का धीरे-धीरे मिटना।

सोवियत संघ में रहनेवाली सभी जातियों और नृजातीय समूहों की अखंड एकता और बिरादराना दोस्ती विकसित समाजवादी समाज के सामाजिक गठन की लाक्षणिकता है।

सोवियत राज्य बढ़ती सामाजिक समरूपता, नगर और देहात के बीच और शारीरिक तथा मानसिक श्रम के बीच अंतर के उन्मूलन तथा जातियों और नृजातीय समूहों के आगे विकास एवं उनके सामीप्य के लिए प्रयत्नशील है।

विकसित समाजवाद की राजनीतिक प्रणाली राज्य के दैनंदिन मामलों के संचालन में जनसाधारण की व्यापकतम भागीदारी को सुनिश्चित बनाती है। विकसित समाजवादी समाज विकसित समाजवादी जनवाद का समाज है। देश के जीवन के संचालन में जनसाधारण की सतत बढ़ती भागीदारी अब सोवियत समाज के राजनीतिक विकास की मुख्य प्रवृत्ति बन गयी है।

अतः विकसित समाजवाद की अवधि में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का राज्य संपूर्ण जनता के राज्य में विकसित होता है, जो उसके विकास की उच्चतर अवस्था, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में संपूर्ण जनता का एक राजनीतिक संगठन है।

विकसित समाजवाद के राज्य का सार्वजनीन स्वरूप जनवाद के अधिकाधिक व्यापक विकास में, उसकी संस्थाओं के जनसत्ता के अवयवों में रूपांतरण में प्रकट होता है।

वर्तमान समय में सभी स्तरों की सोवियतों के प्रतिनिधियों की संख्या २३ लाख है, जबकि सोवियतों के तहत विभिन्न आयोगों में स्वेच्छापूर्वक काम करनेवाले लोगों की संख्या ३ करोड़ से अधिक है।

समाज के जीवन का विनियमन करनेवाली सभी प्रमुख वैधानिक कार्रवाइयों पर राष्ट्रव्यापी बहस सोवियत संघ में जनवादी प्रक्रिया की स्थायी प्रक्रिया बन गयी है। समाज के जीवन में श्रमिक समूहों की भूमिका और सक्रियता काफ़ी बढ़ गयी है। यह श्रमिकों के निजी हितों और इच्छाओं को समाज के आगे विकास के मुख्य कार्यभारों से जोड़ता है। श्रमिक समूहों की भूमिका को सोवियत संविधान में दर्ज किया गया है।

श्रमिक समूह और सार्वजनिक संगठन उद्यमों के प्रबंध में व्यापक हिस्सा लेते हैं। उन्हें श्रम और रोज़मर्रा के जीवन के संगठन, उत्पादन के विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भौतिक प्रोत्साहन हेतु निर्धारित साधनों के उपयोग संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

विकसित समाजवाद की राजनीतिक प्रणाली की अभिलाक्षणिकता सार्वजनिक संगठनों – ट्रेड-यूनियनों, कोम्सोमोल आदि – और सोवियत समाज की नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती भूमिका है। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत जनगण के महान सृजनात्मक कार्यकलाप का संचालन करती है और उनके अंतिम उद्देश्य – कम्युनिज़्म की विजय – की प्राप्ति के लिए संघर्ष को संगठित, नियोजित, विज्ञान-सम्मत स्वरूप प्रदान करती है।

उत्पादन के प्रबंध, सामाजिक मामलों के संचालन में मेहनतकशों की सहभागिता के संगठन में ट्रेड-यूनियनों की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। उदाहरणार्थ, ट्रेड-यूनियनें १,३०,००० स्थायी उत्पादन सम्मेलनों के कार्यकलाप का निदेशन करती हैं, उनमें सक्रिय ढंग से काम करती हैं। इन सम्मेलनों की कुल सदस्य-संख्या में मज़दूरों का हिस्सा ६४ प्रतिशत है। प्रत्येक वर्ष इन सम्मेलनों में भाग लेनेवाले उत्पादन की कारगरता बढ़ाने के लिए १५ लाख सुझाव पेश करते हैं। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा लाभप्रद है और अपनी बारी में श्रमिकों की सामाजिक तथा दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक संभावना को बढ़ा देता है।

विकसित समाजवाद की राजनीतिक प्रणाली में कोम्सोमोल की भूमिका में वृद्धि इस बात में है कि उसकी पांतों में आनेवाले युवाजनों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसमें वे श्रम और राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कोम्सोमोल उन्हें कम्युनिज़्म के आदर्शों के प्रति वफ़ादारी की भावना में, पुरानी पीढ़ियों की वीरतापूर्ण परंपराओं में शिक्षित करता है और कारनामों के लिए उनके स्वाभाविक आकर्षण को साइबेरिया में विशाल पनबिजलीघरों और बाइकाल-आमूर रेलवे (बाम) जैसी बड़ी परियोजनाओं में रचनात्मक श्रम में सक्रिय भागीदारी से जोड़ता है।

विकसित समाजवाद की राजनीतिक प्रणाली की विशिष्टता है समाजवादी जनवाद के लिए अतुलनीय रूप से व्यापक आधार और नागरिकों के अधिकारों की सुदृढ़ भौतिक गारंटियां। इसका संबंध न केवल श्रम के अधिकार (इसे तो १६३६ के संविधान में ही पुष्ट किया गया था), बल्कि आवास के अधिकार से भी है। मिसाल के लिए, वर्तमान समय में श्रम के अधिकार में अपनी रुचियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदि के अनुरूप पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार शामिल है।

सोवियत संघ में बना विकसित समाजवाद का समाज आज की उच्चतम सामाजिक उपलब्धि है।

इससे कौन-से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कौन-से सबक़ लिये जा सकते हैं?

क्रांतिकारी व्यवहार, इतिहास ने दिखा दिया है कि मेहनतकश जनसाधारण – मज़दूर वर्ग और कृषक वर्ग – समाज का क्रांतिकारी रूपांतरण करने, शोषकों और शोषितों से रहित न्यायसंगत सामाजिक प्रणाली क़ायम करने में समर्थ हैं। मेहनतकश जनसाधारण अपने श्रम से एक ऐसा समाज बनाने में समर्थ हैं, जिसमें वे अपने लिए काम करते हैं, उनकी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है। यह समाज ही समाजवाद है, जो यूटोपिया या कभी पूरा न होनेवाला स्वप्न नहीं, बल्कि जीवंत वास्तविकता है।

समाज का समाजवादी समाज में क्रांतिकारी रूपांतरण, समाजवाद का निर्माण केवल वैज्ञानिक आधार पर, मार्क्सवाद-लेनिनवाद

के आधार पर ही किया जा सकता है। समाज के वैज्ञानिक क्रांतिकारी सिद्धांत के नाते मार्क्सवाद-लेनिनवाद ने सामाजिक विकास और वर्ग संघर्ष के नियमों की खोज की तथा मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसाधारण को मानव समाज के विकास के बारे में ज्ञान से लैस किया, ताकि यह विकास जनसाधारण के हित में हो सके। अन्य सिद्धांतों के आधार पर समाज का रूपांतरण करने के प्रयास असफल रहे, क्योंकि वे अवैज्ञानिक थे।

सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों में समाजवादी समाज के निर्माण ने किसी भी देश के लिए अभिलाक्षणिक समाजवादी क्रांति और समाजवादी निर्माण के मौलिक, सहज लक्षणों को अकाट्य रूप से सिद्ध कर दिया है।

समाजवाद का निर्माण कोई साधारण, आसान काम नहीं है। नये समाज के निर्माण के दौरान कई कठिनाइयां पैदा होती हैं, ग़लतियां की जाती हैं। अतः समाज के क्रांतिकारी रूपांतरण के विशाल और जटिल कार्य में ग़लतियों से बचने के लिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत के निष्कर्षों तथा समाजवादी निर्माण में अन्य जनगण द्वारा संचित अनुभव का सहारा लेना आवश्यक है। यह अनुभव समाज के क्रांतिकारी रूपांतरण के लिए, साम्राज्यवाद और युद्ध के ख़िलाफ़, शांति, सामाजिक प्रगति और समाजवाद के लिए संघर्षरत सभी शक्तियों की एकजुटता, सहयोग और पारस्परिक सहायता के निर्णायक महत्व को प्रमाणित करता है।